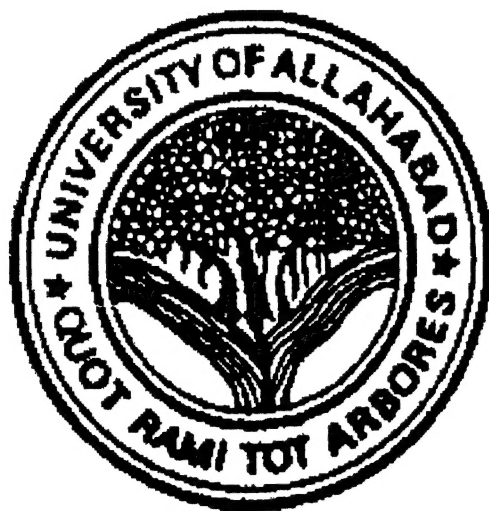


भारत वर्ष में लघु उद्योगों के वित्तीयन का आलोचनात्मक मूल्यांकन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वाणिज्य विषय
की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध



निर्देशक
डॉ० एच० के० सिंह
रीडर

शोधकर्ता
राजकुमार अग्रवाल
एम० कॉम०
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
2003



माता शेरावाली के

चरणों में समर्पित :

त्याग, तपस्या तथा
वात्सल्य की प्रतिमूर्ति
पूज्य माता, पिता,
गुरु को श्रद्धा
एवं स्नेह सहित.....

अनुक्रमणिका

	प्राक्कथन	I-III
अध्याय -	1. प्रस्तावना	1-31
अध्याय -	2. भारत वर्ष में लघु उद्योगों का विकास एवं वर्तमान स्थिति	32-100
अध्याय -	3. भारत वर्ष में लघु उद्योगों के वित्तीयन के स्रोत	101-175
अध्याय -	4. लघु उद्योग बनाम् बृहत् उद्योग	176-220
अध्याय -	5. लघु उद्योग के सम्बन्ध में सरकारी नीति	221-248
अध्याय -	6. लघु उद्योगों का महत्व एवं समस्याएँ	249-271
अध्याय -	7. निष्कर्ष एवं सुझाव	272-303
	स्रोत	304-310
	परिशिष्ट : 1	311-327
	परिशिष्ट : 2	328-335
	परिशिष्ट : 3	336-338

प्राक्कथन

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सर्वाधिक योगदान निः संदेह लघु उद्योगों का ही होता है। उदारीकरण के इस दौर में हमारे देश में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल से बिछ चुका है। ऐसे में लघु उद्योगों को अपना माल विक्रय की अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध हो गई है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में कुल निर्यात का 70-80 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों से ही प्राप्त होता है। ऐसे में लघु उद्योगों की स्थापना करना शत प्रतिशत लाभ का सौदा है। विश्व के प्रायः समस्त राष्ट्र लघु उद्योगों को महत्व देकर ही आर्थिक प्रगति के मार्ग को प्रशक्त कर सके हैं। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे राष्ट्रों में एक ओर बड़े उद्योगों का तो दूसरी ओर लघु उद्योगों का भी महत्व स्वीकार किया जाता है। जापान तो वृहद और लघु उद्योगों के समन्वय का सुन्दरतम उदाहरण है।

मैंने अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तावना, भारत वर्ष में लघु उद्योगों का विकास एवं वर्तमान स्थिति, भारत वर्ष में लघु उद्योगों के वित्तीयन के स्रोत, लघु उद्योग बनाम वृहत् उद्योग, लघु उद्योग के सम्बन्ध में सरकारी नीति, लघु उद्योगों का महत्व एवं समस्याएँ तथा निष्कर्ष एवं सुझाव सहित सात अध्यायों का समावेश किया है।

मैं सर्वप्रथम माँ शेरावाली को प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से यह शोध कार्य मैं पूर्ण कर सका हूँ।

मैं अपने शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ० एच. के. सिंह के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अमूल्य निर्देशन, स्नेहशीलता, सहयोग एवं प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ही मैं अपने इस शोध कार्य को पूर्ण कर सका।

मैं अपने प्रेरणा स्रोत पूज्यनीय माता-पिता जी के चरणों में अपना कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सका।

मैं डॉ० मीरा सिंह(प्रवक्ता)वाणिज्य, उदय प्रताप महाविद्यालय वाराणसी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव एवं अनुभवों के माध्यम से सहयोग प्रदान किया।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो० राज शेखर जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने शोध कार्य सम्पन्न करने हेतु मेरा हमेशा उत्साह वर्द्धन किया।

मैं प्रो० रवेन्द्र राय, डॉ० प्रदीप जैन, डॉ० अन्जनी कुमार मालवीय, डॉ० अजय सिंघल, प्रो० एस. ए० अन्सारी वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग का आभारी हूँ। जिन्होंने सदैव अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मैं डी. कुमार एण्ड कम्पनी के प्रबन्धक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल जी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय अपना सुझाव और सहयोग प्रदान किया है।

मैं अपनी पत्नी रूचि अग्रवाल का आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर अपना सुझाव और सहयोग प्रदान किया है।


मैं आभारी हूँ महाप्रबन्धक राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड, नैनी-इलाहाबाद का जिनके सहयोग से मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सका।

मैं आभारी हूँ अपने परिवार के अन्य सदस्य, एवं रिस्तेदारों का जिन्होंने समय-समय पर उत्साह वर्द्धन किया।

अन्त में मैं सर्वेश कुमार मिश्र एवं अनिरुद्ध मिश्र को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध को सुन्दर ढंग से एवं समय पर मुद्रित करने का कार्य किया।

दिनांक :- 18-12-03

स्थान :- नैनी, इलाहाबाद।


(राज कुमार अग्रवाल)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

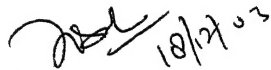


UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD-211002

CERTIFICATE

Certified that the thesis embodies Results of original research work and study carried out under my Supervision by Mr. Raj Kumar Agrawal M.Com.

Department of Commerce
University of Allahabad
Allahabad


Dr. H.K. Singh
(Supervisor)
Department of Commerce &
Business Administration A.U.

प्रस्तावना

आधुनिक बड़े उद्योगों के युग में लघु उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। लघु उद्योगों का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जितना कि बड़े उद्योगों का विकसित राष्ट्रों में होता है। इनमें अपेक्षाकृत कम पूँजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। लघु उद्योगों बड़े उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में भी कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं।

एक देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। इस प्रकार के उद्योग आर्थिक परिवर्तन के दौर में परम्परागत तकनीक से लेकर आधुनिक तकनीक तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। लघु उद्योगों को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें प्राकृतिक मानव एवं पूँजीगत संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग सम्भव बनाया जा सकता है। इससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। लघु उद्योगों के विकास से उद्यमिता देशों की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित किया जा सकता है। इससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। लघु उद्योगों की सहायता से उद्यमिता विकास एवं चातुर्य को भी व्यावहारिक आधार देकर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। इसी तरह सीमित वित्तीय संसाधनों एवं उपयुक्त तकनीक के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है।

लघु उद्योगों का अर्थ **(Meaning Of Small Scale Industry)**- लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है। प्रशासकीय अथवा सरकारी परिभाषा इस सम्बन्ध में तकनीकी सम्भावनाओं को जागृत करने में असफलता सिद्ध हुई है। प्रायः यह कहा जाता है, कि लघु उद्योगों में श्रमोन्मुखी तकनीक **(Labour Intensive Technology)** की प्रधानता होती है। लेकिन इस मापदण्ड ने भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त किया।

एक लघु उद्योगों में विभिन्न प्रकार के तत्व सन्निहित होते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि सभी परिस्थितियों में हो सकता है कि ये तत्व उपलब्ध न हो। सामान्य दृष्टि से एक लघु उद्योग में निम्नलिखित तत्व होते हैं :-

1. प्रबन्ध में विशिष्टीकरण नाम मात्रा का या नहीं होता है। स्वामी एवं प्रबन्धक के रूप में एक साथ ही उद्यमी अपने दायित्व का निर्वाह करता है। व्यवसाय के विभिन्न तत्व जैसे उत्पादन, क्रय, विपणन, वित्त, क्रार्मिक एवं अन्य कार्यों को उद्यमी कुछ सहायकों की मदद से सम्पन्न करता है।
2. व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से उद्यमी का सन्निकट सम्बन्ध होता है। स्वामी एवं प्रबन्धक के रूप में उद्यमी का अपने श्रमिकों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं एवं लेनदारों से प्रत्यक्ष एवं सीधा सम्बन्ध होता है।
3. लघु उद्योगों के स्वामी को एक संगठित प्रतिभूति बाजार के माध्यम से पूँजी तक पहुँच नहीं पाती है।
4. बड़े उत्पादन बाजार में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है।
5. स्थानीय स्वामित्व एवं प्रबन्ध एवं कच्चे माल के स्रोतों तथा व्यापार में उपस्थिति की दृष्टि से उद्यमी का लघु उद्योग में कम जटिल अथवा सरल तकनीकी प्रबन्ध विधि तथा कुछलता का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय कुछलता एवं चातुर्य को अभिज्ञानित (Identified) स्थानीय समुदाय से सन्निकट एकीकरण होता है। सरलता से रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

इसमें अधः संरचनात्मक सम्बन्धी लागत भी नियन्त्रित की जाती है। इसलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है कि लघु उद्योग तकनीकी, प्रबन्ध सम्बन्धी तथा उद्यमिता चातुर्य को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करता है। अति लघु उद्योग एवं लघु उद्योग निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है।

1. अति लघु उद्योग (Tiny Industries)- ऐसे लघु स्तरीय उद्योग जिसमें संयन्त्र एवं मशीनरी पर 25 लाख रुपये तक पूँजी विनियोजन हो एवं उद्योग की स्थापना 50,000 जनसंख्या वाले स्थान पर हो, अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के उद्योग प्रदेशीय उद्योग निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

1. लघु उद्योग (Small Scale Industry). वे उद्योग जिनके संयन्त्र एवं मशीनरी पर पूँजी विनियोजन 3 करोड़ रुपये तक हो लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार संयन्त्र एवं मशीनरी में विनियोग सीमा लघु उद्योगों तथा सहायक औद्योगिक इकाइयों में 3 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

- परिभाषा -

(1) स्माल इण्डस्ट्रीज के बुलेटिन के अनुसार — लघु स्तर के उद्योग एक इकाई है जहाँ 50 से कम श्रमिकों को काम दिया जाता है, यदि काम शक्ति प्रयोग करके किया जा रहा हो या कम से कम 100 श्रमिकों यदि शक्ति के बिना काम करते हैं और पूँजी 5 लाख से अधिक न हो।

नेशनल स्माल कार्पोरेशन ने भी लघु स्तर औद्योगिक इकाई को परिभाषित किया है, यदि एक उद्योग में शक्ति प्रयोग किया जाता है 50 से कम श्रमिक को रोजगार दिया जा रहा है एवं पूँजी 5 लाख से अधिक न हो।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार . लघु स्तर औद्योगिक बोर्ड के द्वारा एक कार्यरूप परिभाषा ग्रहण की गई, जिसके अनुसार, “सभी इकाइयाँ या कार्यालय जिसकी पूँजी विनियोग पाँच लाख से कम है और 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देती है। जब शक्ति प्रयोग हो रही हो।”

इधर एक मिलती जुलती परिभाषा सोसाइटी फार स्पेशल एण्ड एकोनॉमिक स्टडीज इन कैपिटल फार मीडियम एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रमाणित की गई है। जिस प्रकार एक कार्यरत सूत्र सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने लघु स्तर के लिए विचारा था। जैसा एक इकाई जिसके

पास पूँजी विनियोग पाँच लाख से ऊपर है एवं शक्ति प्रयोग की जाती है। तब श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक न हो एवं 100 व्यक्ति शक्ति के साथ काम करते हैं।

भारत में लघु उद्योगों के विकास में वास्तविक गति चतुर्थ योजना के बाद आयी। सन् 1973-74 में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या केवल 4.16 लाख थी, जो छठी योजना के अन्त में 1984-1985 में बढ़कर 12.75 लाख हो गयी। यह संख्या मार्च 1986 में बढ़कर 13.53 लाख हो गयी।

विकासशील देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों की उपयोगिता और भी अधिक होती है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ पूँजी का अभाव है, लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता है।

हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार कर लिया है। तथा स्वतन्त्रता के बाद से इनके विकास का प्रयास किया गया है। भारत सरकार द्वारा सन् 1948 एवं सन् 1956 में घोषित दोनों औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

अतः योजना आयोग ने भी हमारी विकास योजनाओं में इन्हें विशिष्ट स्थान दिया। लघु उद्योगों पर हमारी प्रथम तीन योजनाओं (1951 से 1968 तक) 459 करोड़ रुपये व्यय किये गये। तीन वार्षिक योजनाओं (1966 से 1968) में इन पर व्यय 126 करोड़ रुपये था। चतुर्थ योजना (1969-75) तक की अवधि में कुल मिलाकर 244 करोड़ रुपये इन पर व्यय किये गये।

पाँचवी योजना (1974 से 1979 तक) लघु उद्योगों के विकास पर कुल 535 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिसमें से 310 करोड़ रुपये ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग पर तथा शेष 225 करोड़ रुपये लघु उद्योगों पर व्यय किये गये।

छठी योजना में ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए 1780.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में खादी तथा ग्रामीण उद्योग औद्योगिक बस्तियों, हस्तशिल्प तथा जूट उद्योग सम्मिलित हैं।

सातवीं योजना (1985-90) में लघु उद्योगों के लिए 2,752.74 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया। सन् 1990 तक इस क्षेत्र का कुल उत्पादन 100,100 करोड़ रुपये, रोजगार 4 करोड़ रुपये तथा निर्यात 7,433.90 करोड़ रुपये हो जायेगा।

लघु उद्योगों का अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जो दो शर्तों की पूर्ति करते हैं। प्रथम यदि औद्योगिक इकाइयों में शक्ति का प्रयोग होता है तो उसमें 50 श्रमिक से कम नहीं होना चाहिए। तथा 100 श्रमिक से अधिक नहीं होने चाहिए। कुल विनियोजित पूँजी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

अब लघु उद्योगों की पहचान मशीनों में पूँजी निवेश के आधार पर की गई है। अप्रैल 1991 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, लघु उद्योगों में ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयों सम्मिलित की जाती है जिनमें मशीनों एवं संयन्त्र में पूँजी विनियोग की मात्रा 60 लाख रुपये (पहले यह सीमा 35 लाख रुपये थी) अप्रैल 1991 में सहायक इकाइयों एवं लघुतर इकाइयों की अवधारणा भी परिभाषित की गई जिनमें पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा क्रमशः 75 लाख रुपये और 5 लाख निर्धारित की गई है। फरवरी 1997 में इस सीमा को बढ़ा करके क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का एक विशेष महत्त्व है। इन उद्योगों का महत्त्व इनके बीस सूत्रीय कार्यक्रमों में शामिल के कारण और भी बढ़ गया है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्त्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है, कि लघु उद्योगों द्वारा देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49% भाग का उत्पादन किया जाता है। इन उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता होती है। इन उद्योगों में बड़े उद्योगों की तुलना में पूँजी विनियोग कम होता है एवं इनमें रोजगार अवसर के सृजन की क्षमता अधिक होती है। कृषि व्यवसाय के मौसमी होने के कारण कृषकों को कृषि में पूरे वर्ष कार्य नहीं मिल पाता है। वर्ष में लगभग 200 दिन श्रमिक बेकार रहता है। देश के जिन भागों में केवल एक ही फसल होती है वहाँ कृषकों की दशा और भी खराब है। अतः कृषि

के सहायक उद्योगों के रूप में लघु उद्योगों का विशेष महत्व है। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप अनार्थिक जोतों की अधिकता है। बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों में आवश्यक समन्वय के परिणामस्वरूप लघु उद्योग बड़े उद्योगों के सहायक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकते हैं। लघु उद्योगों द्वारा स्थानीय साधनों, स्थानीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाएँ कराई जा सकती हैं।

बड़े पैमाने के क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद छोटे पैमाने के उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता उपरान्त काल के दौरान विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ 1950 में 16,000 लघु इकाइयों पंजीकृत (Registered) थी, वहाँ इनकी संख्या बढ़कर 1961 में 36,000 हो गयी। पिछले दशक के दौरान, लघु स्तर क्षेत्र ने इस दिशा में उन्नति की है कि साधारण वस्तुओं के बनाने के अतिरिक्त, यह बहुत सी परिमार्जित वस्तुएँ एवं बढ़िया उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक नियन्त्रण उपकरण, माइक्रो वेव हिस्से (Micro-Wave Components) इलेक्ट्रो चिकित्सा उपकरण, टी0 वी0 सेट आदि का निर्माण करने लगा है।

सरकार लघु स्तर क्षेत्र के विकास के लिए वस्तुओं के आरक्षण (Reservation) की नीति अपनाती चली आई है। 1972 के छोटे पैमाने के उद्योगों की अखिल भारतीय गणना (Census of Small Industries) के समय 177 मदें आरक्षित सूची में थी। 1983 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 837 कर दी गयी। इन इकाइयों में 75,00 वस्तुएँ तैयार की जाती हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा 1994-95 में विनिर्माण उद्यमों के सर्वेक्षण (Manufacturing Enterprises Survey) से पता चलता है कि 72.4 प्रतिशत पंजीकृत इकाइयाँ ग्राम क्षेत्रों में एवं केवल 27.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में स्थित थी।

तालिका

छोटे विनिर्माण उद्यमों का स्वामित्व ढाँचा

	दूसरी अखिल भारतीय गणना (1987-88)	विनिर्माण उद्यमों का सर्वेक्षण (1994-95)
एक व्यक्ति का स्वामित्व	81.0 %	97.6%
साझेदारी	17.2%	1.9%
सीमित कम्पनियाँ	1.8%	-
रिपोर्ट न की गयी	-	0.5
कुल	100.0	100.0

कारखाना कानून (Factory Act) के आधीन पंजीकृत इकाइयों का लगभग 98 प्रतिशत एक व्यक्ति स्वामित्व इकाइयाँ थीं एवं केवल 1.9 लगभग साझेदारी के अधीन पंजीकृत थी। 1987-88 में दूसरी अखिल भारतीय गणना में 81 प्रतिशत इकाइयाँ एक व्यक्ति स्वामित्वधीन, 17 प्रतिशत साझेदारी के अधीन एवं केवल 1.8 प्रतिशत सीमित कम्पनियाँ थी परन्तु 1994-95 के विनिर्माण सर्वेक्षण में एक भी इकाई सीमित कम्पनी के रूप में नहीं पायी गयी। अतः लघु उद्योगों के स्वामित्व ढाँचे में एक व्यक्ति स्वामित्व का प्रभुत्व है।

सी.एम.ओ के विनिर्माण उद्यम सर्वेक्षण के (1994-95) अनुसार लघु उद्यमों का पॉचवा भाग (19.8%) लकड़ी की वस्तुओं में लगा हुआ था। 16.5 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं में एवं 15.1 प्रतिशत मरम्मत सेवाओं में लगा हुआ था। ये तीन उद्योग मिलकर कुल इकाइयों का 51.4% थे। सूती वस्त्र हौजरी एवं सिलेसिलाए कपड़े का अन्य मुख्य क्षेत्र था। जिसमें 13.1 प्रतिशत इकाइयाँ थी। इसके बाद पेय पदार्थों एवं तम्बाकू पदार्थों में 9.8 प्रतिशत इकाइयाँ लगी थी। इसके अतिरिक्त लघु स्तर इकाइयाँ ऊन, रेशम पटेशन उद्योग, कागज पदार्थों एवं प्रकाशन चमड़े एवं चमड़े की वस्तुएँ, रसायन पदार्थों, धातु पदार्थों, मशीनरी आदि में कार्य कर रही थी।

लघु उद्योगों का उत्पादन — 1973-74 और 1999-2000 के दौरान लघु स्तर इकाइयों की संख्या 4.2 लाख से बढ़कर 32.25 लाख हो गयी । इसी अवधि में इस क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 40 लाख से बढ़कर 178.5 लाख हो गयी और उत्पादन 72,00 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,78,460 करोड़ रुपये हो गया ।

1980-81 से 1990-91 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र में रोजगार में औसत वार्षिक वृद्धि 5.8 प्रतिशत एवं उत्पादन के 18.67 प्रतिशत होती है। 1990-91 और 1999-2000 के दौरान उत्पादन में वृद्धि दर 15.7 प्रतिशत एवं रोजगार की वृद्धि दर 4% रही। इससे यह विश्वास परिपक्व हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने के लिए लघु स्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 1981-82 की कीमतों पर, छोटे पैमाने के क्षेत्र का उत्पादन 1980-81 में 30,810 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 85,025 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत होती है जो इस काल के दौरान बड़े पैमाने के उत्पादन की 8.7 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से कहीं ऊँची है।

1990-91 और 1999-2000 की नौवीं वार्षिक अवधि के लिए, लघु स्तर क्षेत्र के उत्पादन (1990-91) की कीमतों पर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी (अर्थात् 1,55,340 करोड़ रुपये से 3,12,576) करोड़ रुपये। इस अवधि में रोजगार की वृद्धि दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। दोनों सूचकों से स्पष्ट है कि लघु क्षेत्र का निष्पादन बड़े पैमाने की तुलना में उचित है।

ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि लघु स्तर क्षेत्र के उत्पादन में बड़े पैमाने के क्षेत्र की तुलना में अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई। सत्य है समग्र औद्योगिक उत्पादन में मन्द गति की तुलना में लघु क्षेत्र का निष्पादन सराहनीय है। इस तथ्य का हमारी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के सन्दर्भ में विशेष महत्व है। यदि लघु क्षेत्र को बड़े जोर का धक्का दे दिया जाये तो वह भारत जैसी पूँजी न्यून अर्थव्यवस्था में उत्पाद पूँजी अनुपात की ऊँची दर एवं रोजगार पूँजी अनुपात की ऊँची दर द्वारा एक स्थायीकारी कारण तत्व (Stabilising Factor) बन सकता है।

तालिका

लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइयों का उद्योगवार वितरण

	इकाइयाँ (लाखों में)	कुल का प्रतिशत
लकड़ी की वस्तुएँ	28.73	19.8
खाद्य वस्तुएँ	23.94	16.5
मरम्मत सेवाएँ	21.87	15.1
पेय पदार्थ एवं तम्बाकू पदार्थ	14.27	9.8
विविध विनिर्माण उद्योग	11.59	8.0
हौजरी एवं सिलसिलाए कपड़े	10.94	7.5
सूती वस्त्र	8.19	5.6
अन्य	28.57	11.8
कुल	145.04	100.0

तालिका

लघु स्तर क्षेत्र में रोजगार एवं उत्पादन (उत्पादन करोड रुपये)

वर्ष	चालू कीमतों पर	1990.91 की कीमतों पर	रोजगार (लाखों में)	निर्यात चालू कीमतों पर (करोड रुपये)
1974-75	7200	-	39.7	393
1980-81	28,060	-	71.0	1,643
1990-91	1,55,340	1,55,340	125.3	9,100
1991-92	1,78,699	1,60,156	129.8	13,883
1992-93	20,9300	1,69,125	134.1	17,785
1993-94	2,41,648	1,81,133	139.4	25,304
1994-95	2,93,990	1,99,427	146.6	29,068
1995-96	3,56,213	2,22,162	152.6	36,470
1996-97	4,12,636	2,47,311	160.0	39,249
1997-98	4,65,171	2,68,159	167.2	43,946
1998-99	5,27,515	2,88,807	171.6	48,979
1999-2000	5,78,470	3,12,576	178.5	53,975

वार्षिक चक्रवृद्धि दर

1974-75 से 1980-81	21.4	8.7	8.7	22.6
1980-81 से 1990-91	18.6	11.7	5.8	18.6
1990-91 से 1999-2000	15.7	8.1	4.0	21.9

नोट. 1973-74 से 1980-81 और 1980-81 से 1990-91 के लिए वृद्धि दरों 1981.82 की कीमतों पर परिकलित की गयी है।

लघु उद्योगों के अन्तः राज्यीय वितरण से पता चलता है कि 6 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात में लघु क्षेत्र की कुल इकाइयों का 59% भाग स्थित था। इनके द्वारा कुल रोजगार का 62% रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें कुल अचल परिसम्पत्ति का 66% लगा हुआ था। एवं कुल उत्पादन का 69% भाग उत्पन्न होता था। वे राज्य के लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा शामिल है।

कुछ जिलों में विशिष्टीकरण के कारण भी लघु स्तर की इकाइयों में सकेन्द्रण जान पड़ता है। ऊनी हौजरी की 92% इकाइयों में लुधियाना में थी, सूती हौजरी की 82% इकाइयों लुधियाना, कलकत्ता, एवं दिल्ली में थी। साइकिल की पुर्जों की 62% इकाइयाँ लुधियाना, जालन्धर, हावड़ा, बम्बई में थी। 1987-88 में 2 लाख रुपये से कम अचल पूँजी (Fixed Capital) वाली इकाइयों का अनुपात लघु क्षेत्र में 84% था। इसी प्रकार 10 लाख रुपये से कम उत्पादन वाली इकाइयों का अनुपात 89.2% था।

लघु उद्यम बीते समय में विवादास्पद विषय रहा है। यह विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ राजनीतिज्ञ लघु उद्यमों के प्रबल समर्थक हैं। किन्तु कुछ अर्थशास्त्री एवं उद्योगपति इनके विरोधी हैं। लघु उद्यमों के विकास के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

— ये बड़े पैमाने पर तत्काल काम जुटाते हैं, राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन करते हैं और पूँजी एवं कौशल के साधनों को प्रभावशाली ढंग से गति देते हैं। अन्यथा ये साधन अप्रयुक्त ही रह जाँएँ। योजनारहित नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं में से बहुत सी ऐसी है। जिन्हे देश भर में औद्योगिक उत्पादन में लघु केन्द्रों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव में चार तर्क प्रस्तुत किए गये हैं—

1. रोजगार सम्बन्धी तर्क (Employment Argument) :- कर्वे समिति ने इस युक्ति पर बल देते हुए लिखा है “सफल लोकतन्त्र के लिए स्व-रोजगार (Self-Employment) का सिद्धान्त कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वशासन (Self Government) का रोजगार विषयक युक्ति इस धारणा पर आधारित है कि लघु उद्यमों के श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त युक्ति इस धारणा पर आधारित है कि लघु उद्यमों के श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त पूँजी की इकाई अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम करती है। यह भी माना जाता है, कि बड़े उद्यमों की तुलना में छोटे उद्यमों पर अन्य प्रकार से जो थोड़ी अधिक लागत आती है उसकी हानि की पूर्ति अंशतः लघु उद्यमों के उपरिव्यय पर होने वाली कम लागत से हो जाती है। अतः यह आग्रह किया जाता है कि पूँजी वस्तु उद्योगों एवं सामाजिक तथा आर्थिक आधार संरचना के निर्माण को छोड़कर विकास शील अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में लघु उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि इनमें दुर्लभ पूँजी की अपेक्षाकृत कम मात्रा द्वारा रोजगार का विस्तार किया जा सकता है।

लघु स्तर उद्योगों की रोजगार निर्माण क्षमता बड़े पैमाने के क्षेत्र से 8 गुना है। इसके अतिरिक्त अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वृहद् स्तर क्षेत्र की तुलना में लघु स्तर उद्योगों का उत्पाद पूँजी अनुपात 3 गुना है। चाहे इनकी श्रम उत्पादिकता सापेक्ष दृष्टि से कम है। इस तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्पादन एवं रोजगार दोनों ही दृष्टियों से विनियोग की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा लघु स्तर उद्योगों की पक्ष में बाँटी जानी चाहिए

तालिका

विनिर्माण उद्यमों में पूँजी रोजगार एवं उत्पादन

वर्ष	पूँजी आकार	प्रति श्रमिक अचल पूँजी	प्रति श्रमिक मूल्य वृद्धि	प्रति इकाई अचल पूँजी पूँजी पर मूल्य वृद्धि
1974-75	लघु	3,706	4,790	1.29
	मध्यम	7,935	8,785	1.11
	बड़ी	30,536	13,736	0.43
	लघु	16,582	7,051	0.43
1978-79	मध्यम	27,610	12,521	0.45
	बड़ी	68,166	15,903	0.23

चाहे छोटे पैमाने के उद्योगों में बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के कारण चाहे पूँजी श्रम अनुपात बढ़ रहा है। फिर भी 1978-79 के आँकड़ों से यह पता चलता है कि बड़े उद्यमों में पूँजी श्रम अनुपात छोटे उद्यमों की तुलना में 4 गुना है। उत्पाद पूँजी अनुपात भी छोटे उद्यमों में अनुकूल है।

तालिका

भारतीय उद्योगों में उत्पादक पूँजी रोजगार और मूल्य वृद्धि (1994-95)

प्लान्ट एवं मशीनरी का कुल मूल्य	प्रति कर्मचारी उत्पादक पूँजी	प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि	प्रति पूँजी की इकाई इकाई के लिए मूल्य वृद्धि
1. अति लघु इकाइयाँ (5 लाख रु० से कम)	33,020	25,683	0.78
2. लघुस्तर इकाइयाँ (50 लाख रु० तक)	104,826	64,198	0.61
3. बड़ी इकाइयाँ (50 लाख रु० से अधिक)	5,89,523	1,61,371	0.27

1994-95 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों से पता चलता है कि लघु इकाइयों की तुलना में बड़े पैमाने की इकाइयों में प्रति कर्मचारी उत्पादक पूँजी 5.6 गुना अधिक है। परन्तु पूँजी की प्रति इकाइयो की तुलना में बड़ी इकाइयों में 2.5 गुना अधिक है। 1994-95 का सर्वेक्षण रोजगार एवं उत्पादन की दृष्टि से लघु इकाइयों को बढ़ावा देने का समर्थन करता है ताकि पूँजी न्यून देश उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित कर सके।

2. समानता सम्बन्धी तर्क (Equality Argument):- इस तर्क का सार यह है कि बड़े उद्यमों में होने वाली आय समाज में अधिक व्यापक रूप में वितरित होती है। लघु उद्यमों की आय का लाभ बहुत अधिक लोगों को होता है। जबकि बड़े उद्यमों से आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार लघु उद्यम आय के वितरण में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाने का साधन है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लघु उद्यमों में से अधिकांश एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी संस्थाएँ हैं जिनके फलस्वरूप उनमें मालिक एवं श्रमिकों के बीच सम्बन्ध अधिक सौहार्दपूर्ण रहता है।

3. अन्तर्निहित साधन सम्बन्धी तर्क (Latent re sources Argument): इसका अभिप्राय यह है कि लघु उद्यम अपसंचित धन, उद्यम योग्यता आदि अन्तर्निहित साधनों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं। लघु उद्यमों के कारण छोटे उद्यमकर्ताओं का एक ऐसा वर्ग उभर आता है। जो अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का संचार करता है। धर एवं लाइडल के मतानुसार, “लघु उद्योग में उद्यमकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक मिलता है। लघु उद्यम ऐसे वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार के वातावरण में निजी उद्यमकर्ताओं को स्थानीय उद्यमों और लागत बचाने के उपायों में अपनी अन्तर्निहित प्रतिभा की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् बड़ी संख्या में फर्मों का विकास इस तथ्य का प्रमाण है कि यदि बिजली सम्भरण एवं ऋण सुविधा आदि के रूप में आधारभूत परिस्थितियाँ कायम कर दी जायें तो लघु उद्यम विकसित होकर अन्तर्निहित उद्यम साधनों का उपयोग कर सकते हैं।

4. विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी तर्क (Decentralization Argument): इस तर्क द्वारा उद्योगों के विभिन्न प्रदेशों में फैले होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बड़े उद्योग बड़े शहरों में ही केन्द्रीत रहा करते हैं। छोटे नगरों एवं देहातों को भी आधुनिक औद्योगीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। देश का औद्योगीकरण तभी पूर्ण कहा जा सकता है, जब उद्योग देश भर में दूर-दूर तक फैले हों। यह सच है कि प्रत्येक गाँव में लघु उद्योग आरम्भ नहीं किये जा सकते हैं किन्तु कई ग्रामों में समूह बनाकर उनमें ऐसे लघु उद्योग चलाये जा सकते हैं।

अतः बड़े उद्यमों के साथ-साथ छोटे उद्यमों का विकास भी किया जाना चाहिए। सरकार की स्वीकृत नीति भी यही है। रोजगार सम्बन्धी तर्क में निश्चय ही काफी बल है, किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अन्ततः ऐसे लघु उद्योग स्थापित नहीं करने हैं जो अक्षम हो। दीर्घकाल की दृष्टि से विचार करने पर लघु उद्यमों को जारी रखने का समर्थन केवल उसी अवस्था में किया जा सकता है जब कि उनमें काम करने वाले तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील एवं कार्य कुशल बनने की क्षमता रखते हो। अन्तरिम अवस्था में इन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए एवं सरकार को ऐसी परिस्थितियों कायम करनी चाहिए जिनमें ये उद्योग विकसित हो सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 की औद्योगिक नीति से लेकर 1956-1957 तथा 1980 के औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार करके इनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी उपाय किये गये हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएँ, रियायते, उत्प्रेरणाओं एवं मार्ग दर्शन के रूप में लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किये गये हैं।

लघु उद्योगों के विकास के लिए 1948 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित करने के अतिरिक्त इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई। 1956 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के विकास के लिये बड़े पैमाने के उद्योगों का उत्पादन

सीमित करने का प्रस्ताव किया गया। लघु उद्योगों में उत्पादन के लघु क्षेत्र के लिये सुरक्षित कर दिया गया है। सन् 1968 में ऐसी सुरक्षित सूची में केवल 46 वस्तुएँ थी जिनकी संस्था 1997 के औद्योगिक नीति में बढ़ाकर 504 कर दी गई। लघु उद्योगों के विकास के लिये 247 पिछड़े जिलों में से 101 विशेष पिछड़े जिलों में इन उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार उनके पूँजी विनियोग पर 15% या 15 लाख रुपये (जो भी कम हो) नकद उपादान देने की व्यवस्था करती है। अनेक राज्यों द्वारा भी ऐसा उपादान दिया जाने लगा है जिनमें केन्द्रीय सरकार की योजना नहीं है। इंजीनियर उद्यमियों द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों के लिये बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए गये ऋणों पर देय ब्याज पर उपादान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

लघु उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले माल एवं कल पुर्जों के आयात के लिए लाइसेन्स दिये जाने में इन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ अभाव वाली वस्तुओं के आयात के लिए लघु क्षेत्र के उद्यमियों की खुले सामान्य लाइसेन्स व्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाते हैं। 1984 के अन्त में लघु उद्योगों के लाभ के लिए लाइसेन्स के आधार पर आयात की जाने वाली वस्तुओं में से 467 वस्तुएँ को खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रखा गया है। लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन करो, आय करो, ब्रिकी करो में रियायतें दी जाती हैं। लघु औद्योगिक इकाइयों को 70 निर्धारित वस्तुओं को उत्पादन कर से छूट दी गई है। इन उद्योगों के विकास के लिए अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ तथा प्रेरणाएं दी जा रही हैं। जैसे सुरक्षा जमा राशि एवं अर्नेस्ट मनी को जमा करने की अनिवार्यता से छूट, पंजीकरण शुल्क से मुक्ति तथा आवेदन फार्मों का निःशुल्क वितरण आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों एवं अग्रिमों का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को दिया जाए और लघु उद्योगों के क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के एक प्रमुख अंग के रूप में मान्यता दी जाये। सन् 1985 के अन्त में प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये कुल ऋणों का 35.9% लघु औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त हुआ था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा लघु उद्योगों के 12.25 लाख उद्योगों को 5.1 हजार करोड रुपये का ऋण दिया गया था। लघु उद्योग क्षेत्र को व्यापारिक बैंको, राज्य के वित्तीय निगम, सहकारी बैंको एवं औद्योगिक बैंक द्वारा साख की सुविधाएं प्रदान की जाती है। उपरोक्त संस्थाओं से वित्त प्राप्त करने के अतिरिक्त औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा, बीमा औद्योगिक इकाइयों के लिए मार्जिन धनराशि पर कम ब्याज पर दीर्घ काल के लिए प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक द्वारा 1960 से साख गारण्टी योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये गये ऋणों की गारण्टी प्रदान करता है।

लघु उद्योगों के सहायतार्थ संस्थाएं के रूप में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955 में स्थापित किया गया है। संगठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों में निमित्त वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकारी खरीद को सुगम बनाना था। इन उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में 15% मूल्य की प्रमुखता मिल जाती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु इकाइयों को निःशुल्क टेंडर नोटिस भेज सकता है। निगम की सिफारिश पर कोई भी बैंक आसानी से ऋण स्वीकृत कर लेता है।

सन् 1953 में लघु उद्योग विकास संगठन स्थापित किया गया। लघु उद्योग की विकास सम्बन्धी नीतियाँ तैयार करने में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा विभिन्न विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए राज्यों में लघु उद्योग निगम को स्थापित किया गया है। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन निगमों द्वारा किये जाने प्रमुख कार्यों में औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन एवं विकास में सहायता, कच्चे माल का वितरण, आयात निर्यात में सहायता, औद्योगिक इकाइयों का विकास, लघु उद्योगों को प्रबन्धकीय तकनीकी एवं वित्तीय जानकारी देने के साथ-साथ तत्सम्बन्धी उपलब्ध कराना।

भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों में बनने वाले कच्चे एवं पक्के माल की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने के लिए भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की। बाद में इस संस्थान का

नाम बदलकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रख दिया गया है। यह संस्थान विभिन्न वस्तुओं के आदर्श गुण तथा उनके परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों तथा मानकों के बारे में भारतीय मानक प्रकाशित करना है। लघु उद्योग के उत्पादों के सम्बन्ध में लगभग सभी मामलों पर यह संस्थान जानकारी उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब तक भारतीय मानक संस्थान में छह हजार से भी अधिक भारतीय मानक तय किये हैं। संस्थान की प्रमापीकरण मानक योजना लघु उद्यमियों के खरीददार को यह विश्वास दिलाती है कि इन उद्यमों में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की परीक्षा कर ली गई है।

पूर्व में उद्योगों को लम्बे समय तक उचित दरों पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसके अलावा यदि इन्हें कच्चा माल मिल भी जाता तो उसकी दर इतनी अधिक होती थी कि वे इसे खरीद पाने में अपने आपको असमर्थ पाते थे। इसका लाभ बड़े उद्योग ले जाते थे। इसलिए आयतित कच्चे माल को उचित दर पर लघु उद्योगों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड की 1956 में स्थापना की गई। यह निगम पूर्णतः सरकारी है क्योंकि इसकी स्थापना के लिए सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। साथ ही साथ कच्चे-पक्के माल के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन एवं लघु उद्यमियों को सहायता देने के लिए अनेक निर्यात प्रोत्साहन आयोगों की स्थापना की गई है। अपने सदस्यों को निर्यात नीति में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी उपलब्ध कराना। विदेशी बाजार से सम्बन्धित जानकारी को लघु उद्यमियों तक पहुँचाना है।

लघु उद्योगों के विकास एवं उन पर नजर रखने के लिए देश में प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा उद्योग निदेशालय स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक व्यापारिक समुदाय किसी न किसी संघ या संगठन की स्थापना करता है। लघु उद्योगों की समस्याओं एवं हितों की रक्षा करने के लिए भी एक संस्था की स्थापना की गई है जिसे भारतीय लघु उद्योग संघ कहा जाता है। कहीं कहीं इस संघ को फेडरेशन ऑफ एशोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिला प्रदेश एवं राष्ट्रीय सभी स्तरों पर यह संघ कार्यरत है। लघु उद्योगों

का विकास करने के लिए प्रबन्धन एवं तकनीकी सूचनाएँ आदि के आदान प्रदान की व्यवस्था, लघु उद्योगों के लिए सामूहिक संस्था के रूप में प्रतिनिधित्व करना तथा इन उद्योगों की विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। लघु उद्योगों के बारे में विभिन्न स्रोतों से सूचनाएँ एकत्रित करना। इन सूचनाओं के बारे में औद्योगिक, शैक्षणिक व्यापारिक तथा अनुसंधान संस्थाओं को अवगत कराना तथा उन्हें सहयोग देना। सर्वेक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का संपादन करना।

विज्ञान तथा औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गयी थी। परिषद की स्थापना 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। परिषद का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, उसका मार्गदर्शन तथा समन्वय करना, उद्योग तथा व्यापार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करना। परिषद का प्रमुख उद्देश्य देश में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को संचालित करना।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भी लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किये गये थे। लेकिन वे प्रयास केवल योजना मात्र ही थे और उनके द्वारा उद्योगों का विकास नहीं किया जा सका। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश की राष्ट्रीय सरकार ने देश के विकास में इन उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया। 1948 में घोषित देश की प्रथम औद्योगिक नीति में इन उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। योजना आयोग ने भी अपना मत व्यक्त किया था कि इन उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं में उचित स्थान प्रदान किया जायेगा। इन उद्योगों की उन्नति के लिए सरकार विभिन्न प्रकार से प्रयत्नशील है। पिछले दो दशकों से इस ओर काफी तीव्र गति से काम हो रहा है। इन उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अलग विभाग खोला है जिसे लघु उद्योग विभाग कहते हैं। इस विभाग के निर्देशन एवं परामर्श के लिए एक अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड स्थापित किया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार

ने अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएँ स्थापित की हैं जिसमें अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग की स्थापना अक्टूबर 1952 में की गई। यह बोर्ड हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। इस बोर्ड ने सहकारिता के आधार पर उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया है। सरकार द्वारा लघु उद्योगों को पर्याप्त तकनीकी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इसके लिए औद्योगिक विस्तार सेवा का आयोजन किया है जिसके अन्तर्गत 16 लघु प्रयोगशालाएँ, 7 प्रादेशिक सेवाशालाएँ और 65 विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा नियमित रूप में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इस संस्थान में लघु उद्योग को विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए वर्कशाप और माल की जाँच के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएँ देने का प्रबन्ध किया है। राज्य सरकारों ने "राज्य उद्योग सहायता अधिनियमों" के अन्तर्गत इन उद्योग के लिए ऋण की सुविधाएँ को काफी बढ़ा दिया है। अब इन उद्योगों को राज्य सरकारों से अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तों पर और आसानी से ऋण उपलब्ध होने लगा है। सरकार के अतिरिक्त राज्य वित्त निगमों, भारतीय ऋण समितियों आदि की ओर से भी इन उद्योगों को पहले से कहीं अधिक मात्रा में ऋण सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने सरकार की ओर से 1960 में लघु उद्योगों की सहायता के लिए साख गारण्टी योजना चालू की। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों को गारण्टी जी जाती है।

सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में सहकारी संगठन को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार और योजना आयोग इस बात को स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि इन उद्योगों के स्वस्थ एवं तीव्र विकास में औद्योगिक सहकारी समितियाँ काफी हाथ बँटा सकती हैं। मुख्यतः इन्हीं के माध्यम से ये उद्योग सहकारी सहायता से लाभ उठा सकते हैं। द्वितीय योजना के अन्त में देश 33,266 में औद्योगिक सहकारी समितियाँ थी जिनकी संस्था बढ़कर 1973-74 में 48,000 हो गई। 1966 में औद्योगिक सहकारिता के राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई है। इस संघ का उद्देश्य औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित माल के थोक व्यापार और निर्यात में सहायता देना है।

लघु उद्योग की उन्नति के लिए देश के विभिन्न मार्गों में औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गई हैं। इन बस्तियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को ऋण देती है। इन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को समान रूप से आवश्यक सेवाएँ तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जो उन्हें अलग नहीं मिल सकती जैसे अलग सुविधाजनक स्थान, बिजली, पानी, गैस, रेल से माल उतारने चढ़ाने की सुविधा आदि। इन उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वह है कि इन उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने की व्यवस्था। सरकार इस बात को मानती है कि इन उद्योगों को सरकारी सहायता द्वारा ही बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों को लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखना, इनको अतिरिक्त छूट का अनुदान देना, मील उद्योगों पर उपकर लगाना आदि।

पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को उनके महत्व के अनुरूप उचित स्थान दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन उद्योगों के विकास पर 43 करोड़ रुपये व्यय किये। जून 1955 में कर्वे समिति की नियुक्ति की गई इस समिति ने बताया है कि ये उद्योग अपेक्षित हैं और इनके विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इनके विकास के लिए 6 विशिष्ट बोर्ड की स्थापना की गई और समिति ने वस्त्र उद्योग पर विशेष बल दिया। खादी वस्त्र उद्योग, कृषि उपकरण जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए इन्हें इसी उद्योग में सम्मिलित कर दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन उद्योगों पर लगभग 180 करोड़ रुपये व्यय किये गये। सरकार ने कर्वे समिति की मुख्य सिफारिशों पर अमल करने की चेष्टा की इस अवधि में एक उद्योग विस्तार सेवा विकसित की गई। 66 औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया गया। 1959-60 में औद्योगिक सहकारिताओं की संख्या 29,000 हो गयी। जिनमें 11,200 हैण्डलूम बुनकर समितियाँ थी।

तृतीय योजना और तीन वार्षिक योजनाएँ की अवधि में इन उद्योगों के तीव्र विकास और सुधार का कार्यक्रम रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 240.76 करोड़ रुपये एवं निजी क्षेत्र में 275 करोड़ रुपये व्यय किये। इस योजना अवधि में विभिन्न दिशाओं में विकास करने के कार्यक्रम किये गये। जैसे श्रमिक के उत्पादन में सुधार करना, संस्थागत वित्त की उपलब्धि करना, छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में विकास करना। तीन वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत इन उद्योगों के विकास में 132.6 करोड़ रुपये व्यय किये 1968-69 के अन्त तक राज्य उद्योग निदेशालयों में 1,40,000 लघु स्तरीय इकाइयाँ पंजीकृत थी। जब कि 1962 में लगभग 36,000 इकाइयाँ थी। मार्च 1969 में लगभग 348 औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित हो चुकी हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 293 करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान था, लेकिन 250 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये। इस काल में छोटे उद्योगों की उत्पादन तकनीकी को उन्नत करना, उद्योग के विकेन्द्रीकरण एवं फैलाव को उन्नत करना एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना आदि। पंचम पंचवर्षीय योजना पाँचवी योजना अवधि में गरीबी एवं उपभोग में असमानता को कम करने की दिशा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वित्तीय सहायता देकर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाना, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विस्तार किया गया।

संशोधित पाँचवी योजना में इनके विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 535 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। जिसे बाद में घटाकर 510 करोड़ रुपये कर दिया गया लेकिन योजना के दौरान वास्तविक व्यय 388 करोड़ रुपये का ही हो सका। लघु उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन जो 1974-75 में 538 करोड़ रुपये का था, 1977-78 में बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये हो गया। लघु क्षेत्रों की सहायता के लिए जिले को केन्द्रीय बिन्दु बनाया गया। हर जिले में ऐसा संगठन स्थापित किया गया जो इन उद्योग की सभी जरूरतें पूरी कर सके। इसका नाम जिला उद्योग केन्द्र रखा गया। ये केन्द्र मिलों में कच्चे माल की उपलब्धि,

मशीनरी की आपूर्ति, कच्चे माल की व्यवस्था एवं ऋण दिलाने का प्रबन्ध करते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी उम्मीद की गयी कि वे छोटे ग्रामीण उद्योगों के लिए निश्चित अनुपात में ऋण उपलब्ध कराये जिससे कि इस क्षेत्र के उद्योग वित्तीय साधनों से वंचित न रह जाये।

छठी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को राष्ट्रीय विकास नीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया। इस योजना में इन उद्योगों के विकास हेतु एक विशेष योजना बनाई गयी जिसके अन्तर्गत देश के कुल 5,011 विकास खण्डों में से प्रत्येक खण्ड में प्रति वर्ष निर्धनता रेखा के नीचे के 50 परिवारों को प्रशिक्षित किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न लघु उद्योगों के लिए उत्पादन रोजगार एवं निर्यात के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

सातवीं योजना के प्रारम्भिक प्रपत्र में स्वीकार किया गया है कि उत्पादन रोजगार एवं निर्यात की दृष्टि से इन उद्योगों का अर्थव्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग के रूप में विशेष स्थान है। अतः इस क्षेत्र के विकास की नीतियों को वित्तीय एवं करों की दृष्टि से उधार तथा प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से कुशल बनाया जाना चाहिए। सातवीं योजना में इन उद्योगों पर 2,752 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था।

आठवीं योजना में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण औद्योगिक की नीति पर अधिक बल दिया गया। आठवीं योजना के अन्त में 1996-97 में लघु इकाइयों की संख्या 285 लाख थी। जिनका उत्पादन मूल्य 4,12,636 करोड़ रुपये था। जिसमें 160 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। खादी कपड़े का उत्पादन जो वर्ष 1991-92 में 114 मि. मी. था। वह 1996-97 में बढ़कर 125 मि. मी. हो गया।

नौवीं योजना में लघु उद्योगों को वरीयता क्रम में रखा गया है जिससे कि ग्रामीण विकास को गति मिल सके। इस योजना में तकनीक, उचित तकनीक का हस्तान्तरण एवं प्राप्ति को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा। लघु क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार ने कई नीतियों को लागू करने का निर्णय लिया है जैसे वृहद् एवं मध्यम इकाइयों को लघु स्तरीय इकाइयों की 24% अंश भागीदारी की इजाजत देना एवं लघु

इकाइयों के सम्बन्ध में श्रम कानूनों का सरलीकरण करना आदि।

नौवीं योजना (1997-2002) जिसमें इनका उत्पादन लक्ष्य 2001-02 में 7,25,000 करोड़ रखा गया जब कि 1996-97 में मात्रा 4,12,638 करोड़ था। 1996-97 में 160 लाख व्यक्ति रोजगार पाये हुए थे। 2001-02 में 185 लाख व्यक्ति का लक्ष्य रखा गया। 1996-97 में 39,249 करोड़ रुपये निर्यात था। जब कि 2001-02 में लक्ष्य 78,900 करोड़ रुपये रखा गया।

वर्तमान समय में लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन रोजगार एवं निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र विनियोग क्षेत्र में कुल ब्रिकी में 40% एवं कुल निर्यात में 35% का योगदान करता है। वर्तमान समय में देश की कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 32.85 लाख है जिनमें 1,785 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। 1992-93 में 134.06 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। निर्यात 17,785 करोड़ रुपये का था। 1999-2000 में 178.50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इनके निर्यात 53,975 करोड़ रुपये था। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2000 में लघु इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय घोषित किये हैं। जैसे उत्पाद कर की छूट सीमा में वृद्धि ISQ - 9000 मापन के प्रमाण पत्र के लिए वित्तीय सहायता दशवीं योजना के अन्त तक जारी रखना, साख गारण्टी कोष सुनिश्चित रखना आदि।

सरकार ने कुछ से ही इन उद्योगों की उपयोगिता एवं महत्व को स्वीकार किया है इसके विकास और विस्तार के लिए कदम उठाये गये हैं। इस नीति के अन्तर्गत 1947 में इन उद्योगों के बोर्ड की स्थापना की गई। बाद में इसे तीन अलग-अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया। ये बोर्ड थे— अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (1952) , अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (1952) एवं अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (1953) इन बोर्डों की परिधि से बाहर रह गये उद्योगों के लिए 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी।

दूसरी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग अयोग तथा राज्य स्तरों पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी। जिला एवं ब्लाक स्तर पर उद्योग अधिकारी नियुक्त किये गये। 60 औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गयी। जिन्हें मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयीं। कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया। साख, प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। इस योजना में इस क्षेत्र के विकास पर 175 करोड़ रुपये व्यय किये गये। तीसरी योजना में इस क्षेत्र पर कुल व्यय 241 करोड़ रुपये था। बाद की योजनाओं में इस व्यय में काफी वृद्धि की गयी। परिणामस्वरूप 1999-2000 में लघु उद्योग के क्षेत्र में कुल उत्पादन 5,78,470 करोड़ रुपये निर्यात 53,975 करोड़ रुपये, कुल इकाइयों की संख्या 32.25 लाख तथा इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 178.50 लाख थी।

1997-98 के बजट के पहले लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या 836 थी। इसमें से 15 वस्तुओं पर से आरक्षण हटा लिया गया है। इस समय 821 वस्तुएँ लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। मई 1986 में लघु उद्योगों के विकास विस्तार, विविधीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए पुनर्वित्त सहायता देने के उद्देश्य से लघु उद्योग विकास फंड की स्थापना की गयी। बहुत छोटी लघु इकाइयों की सहायता के लिए राष्ट्रीय इक्विटी फण्ड की स्थापना की गयी है। 1977 में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना का निर्माण किया गया था। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र हैं। संस्थागत साख के लिए लघु क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। मार्च 1998 के अन्त तक लघु उद्योगों को कुल 31,542 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। जो कुल बैंक ऋणों का 16.6% था। 1997 में बैंको द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को दिये गये ऋणों में लघु उद्योगों का हिस्सा 39.9% था। लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 से भारतीय लघु उद्योग विकास (Small Industries Development Bank Of India (SIDBI) की स्थापना की गयी। 1997-98 के बजट में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण का 40% अति लघु इकाइयों के लिए आरक्षित किया गया।

अति लघु इकाइयों में पूँजी निवेश की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गयी बाद में आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर इसे पुनः बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। इस समिति की सिफारिश पर लघु उद्योगों, सहायक उद्योगों तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया था। जिसे पुनः 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लघु उद्योग की उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से गुणवत्ता प्रमाणन योजना शुरू की गयी थी।

आबिद हुसैन समिति की सिफारिश को 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से लघु में निवेश सीमा को 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जाये। लघु उद्योगों के लिए आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाये। लघु उद्योगों में विदेशी पूँजी निवेश की 24% की मौजूदा सीमा को समाप्त किया जाये। लघु उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगले पाँच वर्षों के लिए सरकार द्वारा कुल 2,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की जाये। लघु उद्योगों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र साख के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख का 70% अति लघु इकाइयों को उपलब्ध कराया जाये। लघु उद्योगों के विकास पर नजर रखने के लिए उद्योगमन्त्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाये। सेवा क्षेत्र की लघु स्तरीय इकाइयों को भी लघु उद्योग क्षेत्र में शामिल किया जाय। लघु उद्योग क्षेत्र को लघु स्तरीय उद्यम क्षेत्र के नाम से जाना जाय। एक ही प्रकार के एक ही स्थान पर केन्द्रित लघु स्तरीय उद्यम समूहों के लिए क्रेडिट रेटिंग की प्रणाली विकसित किया जाए।

मीरा सेठ समिति ने 21 जनवरी 1997 को अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया। जिनमें 500 करोड़ के एक राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की जाएँ। गैर सरकारी क्षेत्र के बुनकरों को इस कोष से ऋण दिया जाये। बुनकरों को हथकरघा खरीदने, हैंडयार्न पर सब्सिडी देने आदि के लिए आपदा राहत कोष लागू की जाये।

बैंको को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने एवं लघु उद्योग इकाइयों, विशेषकर निर्यातोन्मुखी एवं लघु इकाइयों को निवेश ऋण के प्रवाह में सुधार लाने हेतु बजट (1999-2000) में नई ऋण बीमा स्कीम की घोषणा हुई। बैंकों द्वारा ऋण उद्योग इकाइयों के लिए कार्यकारी पूँजी की सीमा उनके वार्षिक कारोबार के 20% के आधार पर निर्धारित की जाती है। बैंक की लघु क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने हेतु, लघु क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजनार्थ गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों अथवा अन्य वित्तीय मध्यस्थों के बैंको द्वारा ऋण देने को बैंक के ऋण देने की प्राथमिकता के क्षेत्र की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। लघु उद्योग इकाइयों को दी गयी उत्पाद शुल्क से छूट की सुविधा उन वस्तुओं को भी मिलेगी जिनका ब्रांड ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दूसरे विनिर्माता का है। ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष ऐसे 100 ग्रामीण समूहों की स्थापना करना होगा। जो ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दे सके। विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के सम्बन्ध में अद्यतन विकास का समन्वय करते हुए डी. सी. (लघु उद्योग) के कार्यालय में एक सेल की स्थापना की गयी है। जो हाल की गतिविधियों के सम्बन्ध में उद्योग संघों और एस. एम. ई. इकाइयों की सूचना दे सके। विश्व व्यापार संगठन प्रस्ताव के अनुरूप लघु उद्योगों के लिए नीतियाँ तैयार करे। तथा विश्व व्यापार संगठन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर सके। लघु तथा सहायक उपक्रमों के लिए निवेश सीमा को मौजूदा 3 करोड़ रुपये से घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज का विवरण दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार है कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता में सुधार लाने के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा 50 लाख रुपये बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना। लघु उद्योग मंत्रालय और ए. आर. आई. द्वारा 12 वर्षों में अन्तराल के बाद लघु उद्योगों की तीसरी गणना करना। उद्योग से सम्बन्धित सेवा तथा व्यवसाय उद्यम में निवेश की मौजूदा 5 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना।

प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में दशवी योजना के अन्त तक ISQ 9,000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 7,500 रुपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना। लघु उद्योग संघों को परीक्षण प्रयोगशालाओं के विकास तथा संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जाँच के बाद एक समय 50 प्रतिशत का पूँजी अनुदान दिया जाये। निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए सुझाव सिफारिश प्रदान करने तथा इस क्षेत्र में लागू निष्प्रयोजक कानूनों तथा विनियमों को रद्द करने हेतु सचिव के अधीन समूह का गठन करना। चालू समेकित विकास योजना के कवरेज को बढ़ाना ताकि उस देश में उत्तरोत्तर सब क्षेत्रों की पूर्ति करे और जिसमें 50% आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 50% भूखण्ड अति लघु क्षेत्र हेतु निर्धारित होंगे।

लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी फंड स्कीम बनाई गयी है। ऋण गारंटी स्कीम वाणिज्यिक बैंकों, सही तरीके से कार्य करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गये 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करने के लिए जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा दी गई गारंटी सहित अन्य कोई समपार्श्विक गारंटी नहीं होगी। प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण सम्बद्ध पूँजीगत आर्थिक सहायता स्कीम लागू की गई। जिसमें सरकार ने 20 सितम्बर 2000 को अनुमोदित किया है, जिसमें कतिपय उपक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिन्हें एस. एफ. सी. कहा गया है, लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर 12% की दर से बैंक एडेड पूँजीगत सहायता स्वीकार्य होगी। लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में सुधार लाने के लिए मिश्रित ऋण स्कीम 25 लाख रुपये बढ़ा दी गई है। 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण के प्रवाह की मानीटरिंग के लिए एक समिति गठन की गयी है। लघु सेवाओं और व्यापार (उद्योग सम्बन्ध) उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गयी है।

लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छूट की सीमा को 1 सितम्बर 2000 से दोगुना करके 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2000-02 में नई साख गारण्टी योजना (Credit Guarantee Scheme) के लिए 100 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत समपार्ष्विक प्रतिभूति के बिना साख की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से गठित साख गारण्टी कोष ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust) के साथ अब तक 7 बैंकों ने समझौता किया है। अक्टूबर 2000 में एक साख सम्बद्ध पूँजीगत अर्थसहायता की योजना (Credit Linked Capital Subsidy Scheme) आरम्भ की गयी थी। जिसका उद्देश्य तकनीकी उन्नयन है तथा इसके अन्तर्गत पूँजी पर 12% की अर्थ सहायता की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र को 5,000 करोड़ के ऋण उपलब्ध होने की संभावना है। भारत के कुल लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से चमड़े की वस्तुओं, जूतों और खिलौने से संबंधित 14 वस्तुओं को अनारक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

लघु उद्योगों की प्रगति के बाद भी अभी इनसे अपेक्षित स्तर तक लाभ नहीं मिल सका है। इनको अभी विभिन्न कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। योजना काल में विभिन्न योजनाओं के प्रतिवेदनों में इन उद्योगों के विकास की जो विचारधारा प्रस्तुत की जाती रही है, इसका तत्व यह था कि जो विचार धारा प्रस्तुत की जाती रही है, इसका तत्व यह था कि उनसे उत्पादन क्रियाओं का विक्रेन्द्रीकरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रसार होगा। लेकिन लघु उद्योगों का क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अत्यन्त असमान विकास हुआ है। उदाहरण के लिए भारत के दिल्ली सहित औद्योगिक दृष्टि से 6 विकसित राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही इन उद्योगों का विशेष प्रसार हुआ है। वर्ष 1976 तक पंजीकृत समस्त लघु औद्योगिक इकाइयों को 60 प्रतिशत भाग का लाभ इन राज्यों को मिलता था। इससे यह प्रतीत होता है कि देश के अन्य राज्यों में लघु उद्योगों का सम्यक्

विकास नहीं हो सका। जो असंतुलन का द्योतक है। लघु उद्योगों के सन्दर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण कमी यह है कि इन औद्योगिक इकाइयों में निहित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके परिणामस्वरूप इनकी उत्पादन लागत अधिक हो जाती है। और इस कारण वे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निर्मित सामानों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं।

रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र की बड़ी इकाइयों को कुल ऋण का 69% भाग मिलता है। छोटी इकाइयाँ पर्याप्त साख आपूर्ति के अभाव में कच्चे पदार्थ एवं अन्य कार्यशील कार्यों को वहन नहीं कर पाती है। वित्त सम्बन्धी कठिनाई इन छोटे छोटे उद्योगों की एक प्रमुख समस्या नहीं है। अतएव वित्त सम्बन्धी सुविधाएँ बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशाओं में कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने राज्य उद्योग सहायता अधिनियमों के अन्तर्गत इन उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएँ में व्यापक प्रसार किये हैं। लघु उद्योगों को राज्य सरकारों से अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तों पर ऋण मिलने लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, औद्योगिक विकास बैंक के निर्देशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम भी इन्हें वित्तीय सहायता देते हैं। हाल के वर्षों में लघु उद्योगों के लिए वित्त आपूर्ति त्वरित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंक के राष्ट्रीयकरण, लघु उद्योगों के प्रति अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों के कारण इस क्षेत्र के प्रति अब साख का बहाव बढ़ गया है। लघु उद्योगों के लिए व्यापारिक बैंकों द्वारा जून 1979 तक स्वीकृत ऋण की मात्रा केवल 251 करोड़ रुपये थी, जो दिसम्बर 1989 तक बढ़कर 2,633 करोड़ रुपये हो गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी मार्च 1979 तक 45 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया। राज्य वित्त निगमों द्वारा ग्राम एवं लघु उद्योगों को मार्च 1979 तक दीर्घकालीन एवं मध्यम कालीन ऋण दिया गया। औद्योगिक विकास बैंक एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ग्राम एवं लघु उद्योगों के प्रति किये जाने वाले विकास प्रयासों से इन्हें मिलने वाली वित्तीय सुविधा बढ़ी है। समन्वित की दिशा में एक अत्यन्त सराहनीय प्रयास है।

लघु क्षेत्र को संस्थागत साख सुविधा व्यवस्था में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कोटि में रखा गया है ताकि इस क्षेत्र के लिए संस्थागत साख का प्रवाह बढ़ाया जा सके। लघु आकारीय उद्योगों के उत्पादकता में सुधार के लिए वर्ष 1995 में गुणवत्ता प्रमाणन योजना (Quality Certification Scheme) आरम्भ की गयी है। लघु आकारीय उद्यमों को ISQ - 9,000 या इसी प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति के लिए सहायता भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

यद्यपि योजनाकाल में इन उद्योगों के विकासार्थ भारी मात्रा में विनियोग किया गया। तकनीकी जानकारी का प्रसार किया गया। परन्तु इन उद्योगों के महत्व एवं देश में इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह अपर्याप्त है। छठीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के लिए 1,980 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जो प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 1.0% रही है।

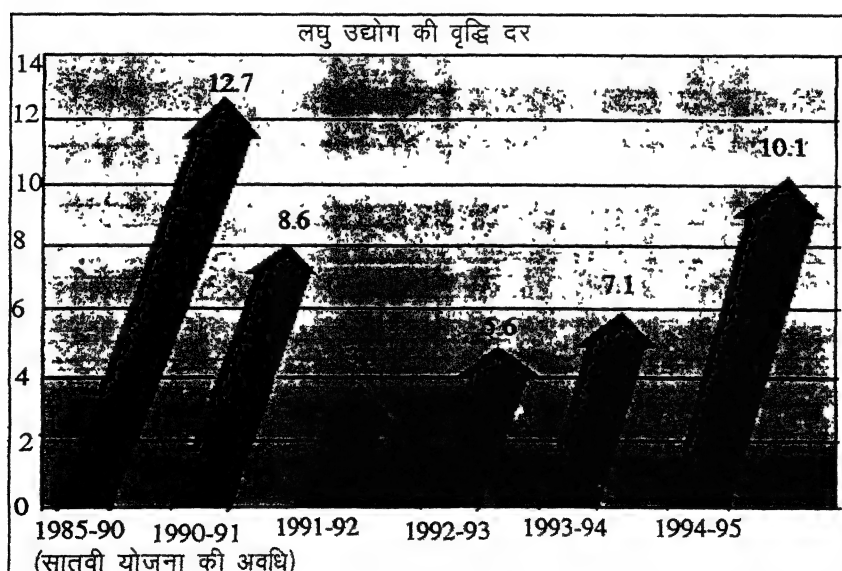
नयी औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है। यह अनुमान किया गया है। कि इस औद्योगिक नीति में किये गये प्रावधानों में लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक सक्षमता आयेगी। तथा वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। लघु उद्योग के क्षेत्र में नयी औद्योगिक नीति में प्रमुख रूप से नयी औद्योगिक नीति की घोषणा और आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह सोचा जाने लगा था कि इससे बड़े और मध्यम आकार के उद्योग की स्थापना अधिक होगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश अधिक सुगम हो जायेगा। अति लघु उद्यमों के लिए विनियोग की सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये कर दी गयी। लघु आकारीय उद्यमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए समता पूँजी में 24% तक अन्य औद्योगिक इकाइयाँ अथवा विदेशी सहयोग की अनुमति दी गयी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से मिलने वाली आर्थिक सहायता को एक ही स्थान पर ऋण की क्रियाविधि के अन्तर्गत लाया गया। नयी औद्योगिक नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 2.0 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए रियायती ब्याज दर की व्यवस्था की गयी है ताकि इन औद्योगिक इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो सके।

દ્વિતીય અધ્યાય

भारत वर्ष में लघु उद्योगों का विकास एवं वर्तमान स्थिति

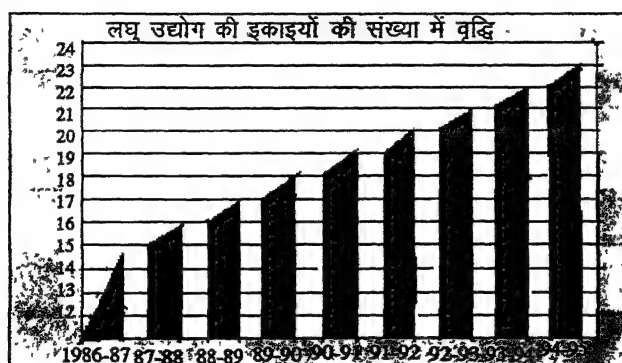
लघु उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विकास का श्रेय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू को जाता है। उनकी कोशिश थी कि वृहद उद्योगों के विकास करने के साथ-साथ उन्हें सहारा देने के लिए लघु स्तर के उद्योगों को भी विकसित किया जाय। लघु उद्योगों का क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का गतिशील एवं सक्रिय क्षेत्र बनकर उभरा है। आज हमारे यहाँ जितना उत्पादन होता है, उसका लगभग 35% लघु उद्योग के क्षेत्र में होता है और यहाँ से होने वाले कुल निर्यात में उसका योगदान 40% से भी अधिक होता है। मूल्य युक्त की बात की जाये तो निर्माण क्षेत्र में युक्त का 40% के लगभग इसी क्षेत्र में है। रोजगार को लें तो इस क्षेत्र का योगदान कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर आता है, इसलिए यहाँ धन लगाने के लिए अर्थव्यवस्था का अच्छा क्षेत्र है।

पिछले कई वर्षों में लघु उद्योग के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। विभिन्न योजना अवधियों में वृद्धि की बहुत ही उचित रही है। लघु स्तर की इकाईयों की अनुमानित संख्या वर्ष 1980-81 में 8.74 लाख थी। जो वर्ष 1994-95 में बढ़कर 22.35 लाख हो गई। इस क्षेत्र में सातवी योजना की अवधि तथा हाल के वर्षों में वृद्धि की जो दरें रहीं हैं निम्न चित्र में दिखाई गई हैं।

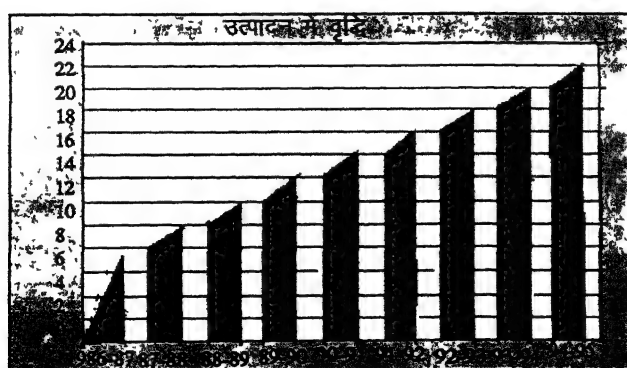


तालिका 1-क उपलब्धि सूचक			
वर्ष	इकाइयों की संख्या (लाख में)	मौजूदा कीमतों में उत्पादन (करोड़ रु में)	रोजगार (लाख में)
1986-87	14.62	72250	101.40
1987-88	15.83	87300	107.00
1988-89	17.12	106400	113.00
1989-90	18.23	132320	119.60
1990-91	19.48	155340	125.30
1991-92	20.82	178699	129.80
1992-93	22.35	209300	134.06
1993-94	23.84	234525	139.36
1994-95	25.71	293990	146.56

चित्र 1.2

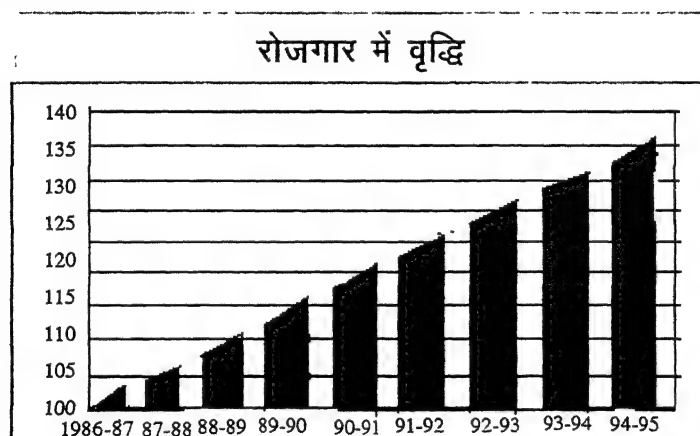


चित्र 1.3



चित्र : 1.4

निम्न चित्र में लघु स्तर की इकाइयों की संख्या और उत्पादन रोजगार निर्यात के सन्दर्भ में उनकी उपलब्धि का आकलन किया गया है। वर्ष 1990-91 से इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत वृद्धि की कम दर देखने को मिली है, जो अगले दो वर्षों तक जारी रही वैसे यह स्थिति सकारात्मक रही है और इसे अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मंदी की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में संक्रमण काल पर विदेशी मुद्रा की कमी, कर्ज में संकुचन, मांग में मंदी, ब्याज में ऊँची दरें, कच्चे माल के अभाव जैसे प्रतिकूल कारकों का असर पड़ा। जब हम इस क्षेत्र की उपलब्धि को समूचे निर्माण तथा उद्योग क्षेत्र में हुई वृद्धि की तुलना में देखते हैं तो लघु उद्योगों के क्षेत्रों के लचीलेपन में विश्वास बनता है। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में अनुमानित वृद्धि दिखाई दी है। आने वाले समयों में इस सकारात्मक स्थिति के और मजबूत होने की संभावना है। इससे लघु उद्योग के क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल हो जायेगा। इसे हम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं :-



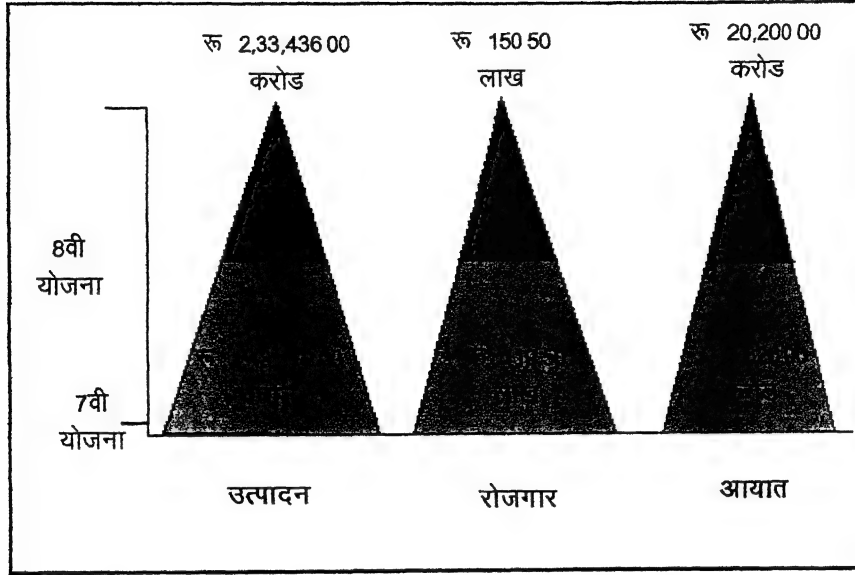
आठवीं योजना की अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र के औसत 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की संभावना है। किन्तु नए शिखरों तक अभी पहुँचना है, लेकिन यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ये लक्ष्य इस मान्यता पर आधारित हैं कि पर्याप्त अतिरिक्त कार्य शील

पूँजी इस क्षेत्र के लिए आठवी पचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध होगी।

लघु उद्योग क्षेत्र में तेरह व्यापक समूह हैं। इन व्यापक समूहों के लिए बनाकर रखी गयी औद्योगिक उत्पादन की सूचियों से यह बात सामने आती है, सनराइज (सूर्योदय) उद्योग क्या है और किन उद्योगों पर सनसेट (सूर्यास्त) हो चुका है। तालिका में यह विश्लेषण दिया गया है।

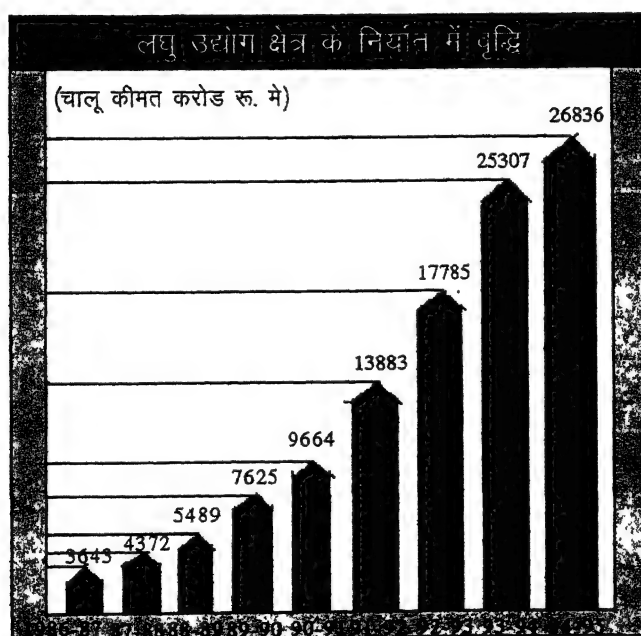
तालिका					
क्रम स	विवरण	प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष के तुलना में			
		1989-90	1990-91	1991-92	92-92
1.	खाद्य उत्पाद	32.06	10.52	0.54	16.56
2.	जूते, चप्पल तथा बुनाई के वस्त्र	25.48	29.87	(3.31)	16.96
3.	लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	13.56	9.73	3.16	(0.53)
4.	कागज तथा कागज के उत्पाद	7.19	11.04	3.93	18.62
5.	चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद	27.99	3.93	17.30	9.82
6.	रबर उत्पाद	2.14	(12.91)	5.70	7.08
7.	रसायन तथा रसायन उत्पाद	12.49	1.64	1.28	17.09
8.	अधातु खनिज उत्पाद	29.2	8.57	9.67	(12.35)
9.	मूल धातु उद्योग	0.67	5.18	13.82	2.38
10.	धातु उत्पाद	1.74	10.30	(10.50)	1.52
11.	गैर विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	1.32	5.90	12.18	3.95
12.	विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	12.55	2.42	6.57	6.83
13.	परिवहन उपकरण	6.15	20.39	23.28	0.85

चित्र



लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात में योगदान

कुल निर्यात का लगभग 30% लघु उद्योग क्षेत्र से सीधे निर्यात होता है। सीधे निर्यात करने वाली लघु इकाइयाँ 5,000 से भी अधिक होंगी। सीधे निर्यात के अलावा, अनुमान है कि लघु उद्योग की इकाइयाँ निर्यात का 15% अप्रत्यक्ष योगदान करती हैं। यह निर्यात व्यापारी निर्यातको, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निर्यात प्रतिष्ठानों के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष निर्यात बड़ी इकाइयों की ओर से निर्यात के ऑर्डर की शक्ल में या निर्यात के योग्य तैयार सामान में इस्तेमाल किए जानेवाले कलपुर्जे के निर्माण की शक्ल में भी हो सकता है। यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य होगा कि लघु उद्योग के निर्यात का 95% से भी अधिक हिस्सा गैर-पारंपरिक उत्पादों का होता है।



पिछले चार दशकों में लघु उद्योगों में विविध क्षमतायें विकसित हो गयीं हैं। 7,500 से

भी ज्यादा उत्पाद लघु उद्योग क्षेत्र में बनाये जा रहें हैं और मौजूदा कीमतों पर इन उत्पादों का सकल मूल्य लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये है। निर्यात के मामले में भी लघु उद्योगों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। अगर परोक्ष निर्यात को भी शामिल कर लिया जाय तो हमारे कुल निर्यात का 40% लघु उद्योग क्षेत्र से ही होता है।

लघु उद्योग के आकार एवं विविधता को ध्यान में रखे कि हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में निवेश के बड़े अवसर उपलब्ध हैं। निर्यात क्षेत्र में तो इसके अवसर और भी हैं। यह अब सम्भव भी है क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नीतियों को आसान कर दिया गया है और अब इसमें लाइसेंस नियन्त्रण भी समाप्त कर दिया गया है। अवसर के क्षेत्र विविध एवं बहुल दोनों हैं। भारत का प्रमुख निर्यातक तो लघु उद्योग क्षेत्र ही है। इन क्षेत्रों में निवेश तथा बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मौजूदा नई क्षमताओं के सहारे काफी लाभ कमाया जा सकता है। लघु उद्योग क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी की भारी माँग है। बड़े उद्योग तथा विदेशी निवेशक इस माँग को पूरा कर सकते हैं।

कुल निर्यात में लघु उद्योग का हिस्सा (रु दस लाख)					
वर्ष	कुल निर्यात	प्रतिशत वृद्धि	लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात	प्रतिशत वृद्धि	लघु उद्योगयोजना का प्रतिशत
1971-72	16080.0	-	1549.9	-	9.6
1972-73	19710.0	22.57	3057.9	97.29	15.5
1973-74	25234.0	28.57	3931.6	28.57	15.8
1974-75	33328.8	32.08	5407.1	33.53	16.2
1975-76	40422.5	21.28	5321.1	(-)1.59	13.2
1976-77	51422.5	27.21	7658.3	43.92	14.9
1977-78	54042.6	5.09	8448.2	10.31	15.6
1978-79	57262.6	5.06	10692.9	26.56	18.7
1979-80	64587.6	12.79	12263.1	14.69	19.0
1980-81	67107.1	3.90	16432.0	33.99	24.5
1981-82	78059.0	16.32	20706.1	26.01	26.5
1982-83	89077.5	14.12	20450.3	(-)1.23	22.9
1983-84	98721.0	10.83	21639.8	5.82	21.9
1984-85	114937.2	16.43	25407.8	17.41	22.11
1985-86	108945.9	(-) 5.45	27691.1	8.99	25.42
1986-87	125666.2	15.34	36436.7	31.58	28.99
1987-88	157412.0	25.26	43729.6	20.01	27.78
1988-89	202952.0	28.93	54896.3	25.54	27.05
1989-90	276814.7	36.39	76257.4	38.91	27.55
1990-91	325533.4	17.60	96641.5	26.73	29.68
1991-92	440048.1	35.29	13883.4	43.03	31.52
1992-93	533505.4	21.14	17784.8	28.10	33.34
1993-94	695469.7	30.35	253070.9	42.29	36.38
1994-95	826741.1	18.87	290681.5	14.86	35.15

नई लघु उद्योग की मुख्य विशेषताएँ

विदेशी निवेशकों के लिए लघु उद्योगों के बारे में

सूचना-पत्रक

- * एक औद्योगिक कम्पनी यानी उद्योग चलाने वाली एक कम्पनी किसी लघु उद्योग में 24% का हिस्सा में निवेश कर सकती है।
- * अगर यह हिस्सा 24% से बढ़ गया तो उस इकाई को लघु उद्योग नहीं माना जायेगा।
- * अनिवासी भारतीय एक व्यक्ति या भागीदार के रूप में कितने भी शेयर ले सकता।
- * रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक शेयरों में विदेशों निवेश की स्वतः अनुमति प्रदान करता है।
- * शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों में विदेशी 100% शेयर तक हो सकता है।
- * अनिवासी भारतीय और विदेशी कम्पनियों (जिनके बड़े हिस्सेदार अनिवासी भारतीय हों) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100% शेयर रखने की छूट है। और वे अपना सारा लाभ भी विदेश ले जा सकते हैं।
- * लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षित किसी उत्पाद को बनाने के लिए कोई बड़ी औद्योगिक परियोजना लगाने चाहता है तो उसे 75% निर्यात का भरोसा देना होगा।

1. इसका प्राथमिक उद्देश्य है इस क्षेत्र को जीवंत बनाना तथा इसकी वृद्धि को गति देना। इसी क्रम में इस क्षेत्र को विनियंत्रित किया जाएगा तथा नौकरशाही से मुक्त किया जाएगा ताकि इसकी वृद्धि क्षमता के अवरोध हट जाएँ।
2. सभी नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं में ऐसा संशोधन किया जाएगा ताकि उनमें लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के हित के विरुद्ध कोई बाधा न रहें।
3. लघुतम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग पैकेज तथा उद्योग से संबंधित सेवा एवं व्यापार उद्यमों को लघु उद्योग के रूप में मान्यता।
4. रियायती कर्ज/ आसान कर्ज के स्थान पर (कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों को छोड़कर) लघु उद्योग को पर्याप्तता के आधार पर समुचित ऋण प्रवाह पर बल।
5. दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान को 24% तक का शेयर लघु उद्योग में रखने की छूट ताकि लघु उद्योग की पहुँच पूँजी बाजार तक हो।
6. लघु उद्योगों के बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करना तथा सीमित साझीदारी कानून बनाने के लिए विधेयक लाना।
7. ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास की एक नई योजना लागू करना।
8. टैक्नोलॉजी डेवलेपमेंट सेल की स्थापना के जरिये बेहतर टैक्नोलॉजी पर बल तथा एस. आईडीओं में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर और सशक्त बनाना।
9. संस्थानों, अन्य एजेंसियों तथा सहयोग संघ पद्धति के जरिये लघु उद्योगों के विपणन (मार्केटिंग) को प्रोत्साहन देना।
10. अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन।
11. निर्यात विकास केन्द्र (एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट सेंटर) की स्थापना के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना मौजूदा समर्थन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
12. गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करना, लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा बेहतर

टैक्नोलॉजी के कार्यक्रम को समर्थन देना।

13. महिला उद्यमियों की परिभाषा में परिवर्तन और महिला उद्यमियों का समर्थन।
14. उद्यमियों विकास कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार।
15. लघु स्तर की उद्यमी स्वतंत्र तथा अवरोधमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें, इसके लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन।

- सभी प्रकार के लघु उद्योगों के लिए समान नीतिगत ढाँचा
- लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए उत्पादों की आरक्षित सूची
- सरकारी खरीद में लघु उद्योग के उत्पादों को खरीद तथा मूल्य में प्राथमिकता।

नये उपायों के प्रेरक : जैसा पहले भी विचार किया जा चुका है कि पूर्व नीतियों के प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं और कुछ परिवर्तन भविष्य में होंगे, इसके संकेत हैं।

बदलते समय के अनुरूप उपाय

1. लघु उद्योग की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए स्थलगत मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीतिगत पैकेज एक हो गया है— चाहे वह इकाई कहीं भी स्थित हो।
2. निवेश सीमा में वृद्धि 35 से 60 लाख रूपए की हो गई हो इसलिए इस क्षेत्र का कवरेज अधिक हो गया है।
3. अलग-अलग इकाई को आर्थिक सहायता देने के बजाय बुनियादी संरचना सहूलियत देने की रणनीति बनायी गई है। इसके चलते पूँजी निवेश सहायता योजना समाप्त कर दी गई है और उसकी जगह विकास केन्द्र योजना तथा समेकित संरचना विकास योजना लागू की गई है।
4. सेवा क्षेत्र को लघु उद्योग में शामिल किया गया है। फिलहाल 5 लाख तक की निवेश सीमा उद्योगों से संबंधित सेवा तथा व्यापार उद्यमों के लिए रखी गई है।

5. ये नीतिगत उपाय बड़े उद्योग तथा लघु उद्योग को निकट लाने के लिए हैं। अब बड़े उद्योग 24% तक की हिस्सेदारी लघु उद्योग में कर सकते हैं।
6. स्पष्ट किया गया है कि लघुतम क्षेत्र को एकमुश्त तथा निरंतर मौद्रिक तथा वित्तीय दोनों सहायता दी जाएगी। लेकिन आधुनिक लघु लघुओं को यह सहायता सिर्फ एक बार दी जाएगी। इस तरह लघु उद्योग क्षेत्र में भी विकास किया जा सकेगा।
7. यह मान्यता निहित है कि अब लघु उद्योग क्षेत्र में संरक्षण / विनियमन की जगह गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी तथा आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा।

आर्थिक सुधार प्रक्रिया के क्रम में उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिर भी नए नीतिगत उपाय नई आर्थिक नीतियों के अनुरूप ही हैं। ये परिवर्तन हैं और ये बदलेंगे नहीं तथा इसकी परिणति नई औद्योगिक पुनः संरचना में होगी। उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते लघु उद्योगों के समक्ष नए अवसर हैं और ये उपाय ऐसे हैं कि लघु उद्योग इन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनें। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनको बढ़ावा, संरक्षण तथा मार्गदर्शन देने की जरूरत पड़ेगी।

राज्य सरकारों एवं लघु उद्योगों का पारस्परिक सम्बन्ध

लघु उद्योग का आकार तथा उनकी विविधता के चलते लघु उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों तथा उनकी संस्थाओं की ही हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकारों ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नीतियों को घोषणा की है। इन नीतियों के अन्तर्गत लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता मिलती है। इस तरह भारत सरकार का नीतिगत ढाँचा केन्द्र सरकार की अन्य संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शन है और इसके चलते सभी के प्रयास एक-दूसरे के पूरक हैं।

लघु उद्योगों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के जरिये सरकार के बीच तालमेल को

संस्थानिक रूप दिया जाता है। यह पंजीकरण योजना स्वैच्छिक है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जिला सहायता की नीति के अन्तर्गत कई लाभ ले सकते हैं। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता भी उन्हें मिल सकती है।

पंजीकरण योजना और लघु इकाइयों को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया का ब्यौरा ब्लॉक 4 एकांक 2 में दिया गया है। विगत वर्षों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के यहाँ पंजीकृत इकाइयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1999 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या 16.37 लाख थी।

लघु उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारें भी नीतियाँ तैयार करती हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करती हैं। ये नीतियाँ राज्य में स्थापित जिला केन्द्रों के माध्यम से लागू की जाती हैं। बुनियादी संरचना विकास, लघु उद्योग निगम, निर्यात निगम तथा अन्य संबंधित संस्थागत एजेंसियों के द्वारा प्रदान की जाती हैं।

महानगरों को छोड़कर देश के प्रायः सभी जिलों के लिए लगभग 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में केन्द्र की 50% सहायता से मई 1978 में शुरू किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र की परिकल्पना जिला स्तर पर एकल रूप से लघु उद्योगों से संपर्क बनाये रखने के लिए गई थी। इस केन्द्र के जरिये लघु उद्योगों को एक ही कार्यालय से सेवाएँ तथा समर्थन दिये जाते हैं। ये केन्द्र राज्य तथा केन्द्र सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करते हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों में लघु उद्योगों का पंजीकरण होता है। इन केन्द्रों का प्रबंध राज्य सरकारें देखती हैं। अब यह योजना राज्य सरकारों को सौंप दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 1993-94 से राज्य सरकारें ही जिला उद्योग केन्द्रों का खर्च बहन कर रही हैं। पिछले पाँच वर्षों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या को निम्न तालिका में दिखाया गया है।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम
31 दिसम्बर तक पंजीकृत इकाइयों की संख्या

क्रम स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1998	1999	1990	1991	1992	1993
1	आंध्रप्रदेश	69,789	78,051	85,470	93,281	1,07,372	1,38,477
2	असम	9,374	11,518	11,366	12,805	14,354	17,103
3.	बिहार	59,886	65,192	71,804	76,779	83,782	92,695
4	गुजरात	65,553	71,299	78,441	85,220	94,879	1,13,593
5.	हरियाणा	61,229	65,166	69,365	74,360	79,953	91,796
6	हिमाचल प्रदेश	9,929	10,565	11,107	11,653	12,165	13,255
7	जम्मू-कश्मीर	17,935	19,080	19,877	21,677	22,653	24,928
8.	कर्नाटक	6,2534	68,300	74,182	80,292	88,513	10,5674
9.	केरल	43,900	49,574	57,738	78,420	86,595	1,16,890
10	मध्यप्रदेश	1,39,700	1,49,239	1,60,896	1,72,545	1,84,245	2,40,556
11	महाराष्ट्र	54,610	53,995	56,837	59,953	68,003	75,580
12.	मणिपुर	2,890	3,719	4,152	4,059	4,310	4,797
13	मेघालय	1,003	1,114	1,233	1,368	1,616	1,765
14	नागालैंड	509	547	580	615	642	704
15.	ओडिसा	16,061	15,251	15,736	16,004	16,505	17,704
16.	पंजाब	96,519	1,06,526	1,15,003	1,24,453	1,34,337	1,34,956
17.	राजस्थान	56,761	58,367	59,931	62,393	64,437	68,872
18.	तमिलनाडु	86,499	96,501	1,07,503	1,16,940	1,33,807	1,83,838
19.	त्रिपुरा	3,252	4,054	4,411	4,967	5,665	7,224
20.	उत्तरप्रदेश	1,45,797	1,61,017	1,85,566	2,17,376	2,47,907	3,00,345
21	सिक्किम	109	131	185	209	224	261
22.	अरुणाचलप्रदेश	365	451	474	525	571	1121
23.	पश्चिम बंगाल	1,31,656	1,34,619	1,37,526	1,39,878	1,42,508	1,44,943
24.	मिजोरम	1,694	2,087	2,245	2,478	2,638	2,693
25	गोवा	4,494	4,794	4,947	5,146	5,381	5,770
26.	अंडमान-निकोबार	537	586	653	795	852	961
27.	चंडीगढ़	2,401	2,512	2,656	2,765	2,844	3,357
28.	दादरा एवं नागर हवेली	272	278	284	282	306	389
29.	दिल्ली	23,817	24,804	25,774	26,228	26,606	28,353
30.	लक्षद्वीप	—	—	104	144	184	264
31.	पांडिचेरी	2,380	2,631	2,893	3,190	3,517	4,023
32.	दमन एवं दिव	228	259	344	385	440	562
कुल		11,71,034	12,62,238	13,69,283	14,98,193	16,37,812	19,43,519

उत्पत्ति

1977 के औद्योगिक नीतिगत विवरण की सिफारिश पर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए। ग्रामीण, पिछड़े इलाकों तथा कस्बों में स्थापित लघु उद्योगों को जिला स्तर पर सहायता प्रदान करनेवाले एक प्रशासकीय ढाँचे के रूप में ऐसे केन्द्रों की स्थापना जरूरी समझी गई। इनका उद्देश्य यह था कि समर्थन सिर्फ महानगरों तथा राजधानियों में एकत्रित रहने के बजाय जिला मुख्यालय तक पहुँचे।

उद्देश्य

लघु उद्यमी को जिन सेवाओं तथा समर्थनों—यानी निवेश के पहले, निवेश के दौरान तथा निवेश के बाद—की जरूरत लघु उद्योग के लिए होती है, वे सभी उसे जिला उद्योग केन्द्र से ही मिल जाएँ। इनमें स्थानीय संसाधन का आर्थिक अन्वेषण, कच्चे माल का प्राबधान, ऋण सुविधाओं का प्रबंध, विपणन व गुणवत्ता निवेश, परामर्श तथा विस्तार सेवाएँ सम्मिलित हैं।

क्रियाकलाप

◆ विनियामक

क. इकाइयों का पंजीकरण

ख. नीति क्रियान्वयन से संबंधित क्रियाकलाप

ग. प्रशासकीय कार्य (कार्य निपटान समेत)

◆ केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निगरानी

◆ सरकारी एजेंसियों से मिलने वाली सहायता के लिए निम्नलिखित मामलों में

सिफारिश :

क. मशीनरी

ख. वित्त

ग. सामग्री की खरीद

घ. पंजीकरण तथा लाइसेंस जारी करना

◆ निम्न मदों के लिए प्रोत्साहन :

क. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना

ख. जिला कार्य योजना

ग. उद्यमिता विकास

घ. सर्वेक्षण

ड. परामर्श

च. अनुरक्षण सेवाएँ (एस्कॉर्ट सर्विसेज)

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उद्योग में परस्पर संपर्क-सम्बन्ध : पंजीकरण योजना केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय हेतु प्राथमिक संस्थागत आधार प्रदान करती है। कई और तरोकों से भी राज्य सरकारों तथा उद्योग समूहों के बीच संबंध बना रहता है। ये निम्नलिखित है :

1. सलाहकार समितियों/शासी बोर्डों में प्रतिनिधित्व : संस्थानों और उद्योगों के बीच निकट सम्पर्क बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों की सलाहकार समितियों/शासी बोर्डों में लघु उद्योग विभाग व उद्योग समूहों से सदस्य बनाये जाते हैं। विभिन्न नीतिगत सलाह निकायों/एजेंसियों में लघु उद्योगों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ आशंकाएँ रही हैं। वित्तीय संस्थानों तथा व्यापार, उद्योग तथा वित्त से संबंधित विभिन्न सलाहकार संस्थानों में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास जारी है।

2. संघों/चैम्बरों/परिषदों के साथ पारस्परिक संपर्क : विभिन्न उद्योग समूहों के साथ पारस्परिक संपर्क की स्वस्थ तथा सतुलित पद्धति मौजूद है। इसे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों और ऐसे अन्य मंचों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

3. राज्यस्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एस.एल.आई.आई.सी.) : राज्य स्तर पर वित्तीय/बैंकों द्वारा प्रदत्त आवधिक ऋण (टर्म लोन) एवं कार्यशील पूँजी की निगरानी, बीमार लघु इकाइयों के पुनर्वास पैकेज की निगरानी और ऋण देनेवाली अन्य कार्यवाहियों के लिए समिति

का गठन किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, लघु उद्योग विभागों तथा राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं।

4. आँकड़ों का संग्रह : विकास आयुक्त लघु उद्योग (कार्यालय) पंजीकृत लघु इकाइयों के दो प्रतिशत को नमूना मानकर लघु उद्योग के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना करता है। पंजीकरण आँकड़ों के आधार पर लघु उद्योग से संबंधित विभिन्न आँकड़ों को भी जमा किया जाता है। लघु उद्योगों की वृद्धि की निगरानी के लिए ये सारे क्रियाकलाप राज्य उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों के सक्रिय सहयोग से पूरा किया जाता है।

लघु उद्योगों के संबंधित द्वितीय अखिल भारतीय गणना (सेंसस) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अनुकरणीय उदाहरण है।

5. राज्य सरकारों को सहायता सेवाएँ : राज्य/जिला पर प्रोत्साहन से जुड़ी एजेंसियों को सलाह एवं सूचना वितरण में लघु उद्योग विभाग के सेवा संस्थान राज्य एजेंसियों को कई प्रकार की सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। यथा :

- ◆ परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल)
- ◆ राज्य संभाव्यता सर्वेक्षण
- ◆ जिला संभाव्यता सर्वेक्षण
- ◆ बाजार संबंधी सूचना
- ◆ व्यापार सूचना
- ◆ उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं परामर्श
- ◆ आधुनिकीकरण अध्ययन
- ◆ संयंत्र अध्ययन

राज्यों की नीतियाँ तथा स्कीम : राज्य सरकारें उद्योग निदेशालयों और जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लघु इकाइयों को तकनीकी और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करती हैं। सहायता और सुविधाओं के मुख्य स्रोत हैं :

- औद्योगिक परिसरों का निर्माण तथा प्रोत्साहन
- बिक्रीकर में आस्थगन/रियायत
- बिजली के लिए रियायती सहायता
- विभिन्न जिलों में स्थापित नई इकाइयों को पूँजीगत सहायता
- शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपांत राशि (मार्जिन मनी) सहायता स्कीम
- औद्योगिक क्षेत्र में भूमि शेडों के आबंटन के लिए हायर परचेज स्कीम
- बिजली, पानी कनेक्शन आदि विभिन्न सुविधाओं में प्राथमिकता
- परामर्श तथा तकनीकी सहायता सेवाएँ

राज्य वित्त निगम लघु इकाइयों को आवधिक ऋण (टर्म लोन) प्रदान करते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम और भूमि विकास निगम उपकरणों को पट्टे पर लेने, संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद, भूमि विकास, औद्योगिक सम्पदाओं का संवर्धन (प्रमोशन) और अन्य विकास प्रयासों में सहायता करते हैं। राज्य वित्त निगमों के उद्देश्यों और क्रियाकलापों की झलक दी गई है।

राज्य सरकारों की लघु उद्योगों से संबंधित नीतियों और प्रोत्साहन की आम संरचना निम्न तालिका में दी गयी है :—

लघु उद्योग के लिए राज्य सरकारों की नीतियों तथा

प्रोत्साहनों की आम संरचना

- औद्योगिक विकास तथा निवेश निगमों द्वारा औद्योगिक, क्षेत्रों का विकास तथा प्रबंधन
- नई इकाइयों के लिए नियत निवेश (अधिकतम सीमा तक ही) के 15 से 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश करना
- इकाइयों को नियत अवधि (पाँच से दस वर्ष) तक विक्रीकर का आस्थगन छूट। इस लाभ की मात्रा नियत पूँजी निवेश और कर दायित्वों के द्वारा सीमित है
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने पर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी महिला एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता योजना
- आसान शर्तों पर शुरुआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपांत राशि (मार्जिनल मनी) सहायता योजना
- आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए फीजिबिलिटी स्टडी। परामर्श पर आई लागत में सहायता देना
- हायर परचेज अथवा पट्टे पर भूमि/शेड का आबंटन
- अनुमति प्रदान करने तथा विवादों के निपटाने के लिए जिला/राज्य स्तर पर अधिकारसंपन्न समितियों का गठन
- पिछड़े/उद्योगविहीन जिलों में अग्रणी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन संयुक्त/सहायता क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य निगमों द्वारा भागीदारी

राज्य वित्त निगमों (एस. एफ. सी.) की विशेषताएँ

- राज्य वित्त निगम जिला स्तर पर लघु और मझले उद्योगों को वित्त प्रदान करने और उनको संवर्द्धित करने के उद्देश्यों से काम करते हैं।
- देश में अभी 18 राज्य वित्त निगम हैं।
- राज्य वित्त निगम औद्योगिक इकाइयों को आवधिक ऋण/पूँजी में हिस्सेदारी/डिबेंचर,

गारंटी तथा बिल ऑफ एक्सचेंज की डिसकाउंटिंग भी करते हैं।

- राज्य वित्त निगम वर्ष भर में 40,000 से भी अधिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अभी 88 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ राज्य वित्त निगम से सहायता प्राप्त हैं।
- राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों के लिए आई.डी.बी.आई./एस.आई.डी.बी.आई की पुनर्वित्त पोषण (रिफाइनेंस) की योजनाएँ चलाते हैं।
- अगस्त, 1993 से राज्य वित्त निगमों को एस.एल. आर. बॉन्ड के माध्यम से और संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी गई है।

लघु उद्योग के लिए राज्य सरकारों की नीतियाँ तथा

प्रोत्साहनों की आम संख्या

- औद्योगिक विकास तथा निगमों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तथा प्रबंधन।
- नई इकाइयों के लिए नियत निवेश (अधिकतम सीमा तक ही) के 15 से 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश सहायता।
- इकाइयों को नियत अवधि (पाँच से दस वर्ष) तक बिक्रीकर का आस्थगन छूट। इस लाभ की मात्रा नियत पूँजी निवेश और कर दायित्वों के द्वारा सीमित है।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपभोग करने पर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी
- महिला एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता योजना।
- आसान शर्तों पर शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपांत राशि (मार्जिनल मनी) सहायता योजना।
- आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए फीजिबिलिटी स्टडी। परामर्श पर आई लागत में सहायता देना।
- हायर परचेज अथवा पट्टे पर भूमि/शेड का आबंटन।
- अनुमति प्रदान करने तथा विवादों के निपटान के लिए जिला/संघीय स्तर पर अधिकारसंपन्न समितियों का गठन।

- पिछड़े/उद्योगविहीन जिलों में अग्रणी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन।
- संयुक्त/सहायता क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य निगमों द्वारा भागीदारी।

योजना काल में लघु उद्योग

(Small & scale industries in Planning)

पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों को उनके महत्व के अनुरूप उचित स्थान दिया गया है। योजनाओं के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम तथा प्रगति का विवरण इस प्रकार है

प्रथम पंचवर्षीय योजना :- प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास पर 43 करोड़ रुपये व्यय किये गये। जून 1955 में कर्बे समिति की नियुक्ति की गई। इन समिति ने बताया कि ये उद्योग उपेक्षित हैं और इनके विकास के लिए 6 विशिष्ट बोर्डों की स्थापना की गई और समिति ने वस्त्र उद्योग पर विशेष बल दिया। खादी वस्त्र उद्योग, कृषि उपकरण जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए इस उद्योग में सम्मिलित कर दिया गया। पहली योजना में लघु उद्योगों पर लगभग 42 करोड़ व्यय किये — इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसे तीन अलग-अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया है। नए स्थापित होने वाले बोर्ड थे। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड अक्टूबर 1952, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नवम्बर 1952, एवं अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड फरवरी 1954 में उन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में राष्ट्रीय सरकार बनने पर लघु उद्योग की ओर ध्यान दिया गया और सबसे पहले 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके लघु उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके विकास के लिए सरकार द्वारा सहयोग एवं प्रेरणा देने की घोषणा की गयी। साथ ही साथ, यह भी कहा गया कि लघु उद्योगों एवं वृहद् उद्योगों में समन्वय स्थापित किया गया।

इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपरोक्त बोर्ड के दायरे के बाहर थे और जिन पर उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 लागू नहीं होता था।

लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा 1949 में स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अप्रैल 1952 में पुनर्गठन किया गया और जुलाई 1954 में नारियल जड़ा बोर्ड की स्थापना की गयी। इस तरह पथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश के 6 बोर्ड काम कर रहे थे और उनके दायरे में लघु उद्योग आते हैं। इन सबको मिलाकर उस समय एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ था। जिनके माध्यम से सरकार ने चार क्षेत्रीय लघु उद्योग संस्थान स्थापित किये। इनकी देश में फैली हुई विभिन्न शाखाओं का कार्य लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वित्तीय साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की थी।

इस योजना अवधि में लघु उद्योगों पर लगभग 180 करोड़ रुपये व्यय किये गये। सरकार ने कर्वे समिति की प्रमुख सिफारिशों पर अमल करने की चेष्टा की। इस अवधि में एक उद्योग विस्तार सेवा विकसित की गयी। प्रत्येक राज्यों में लघु उद्योग सेवाएँ स्थापित की गईं। 66 औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया गया।

इस योजना में 2824 इकाइयों द्वारा 48382 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 50 16 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया। शासन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल से कृषि के साथ साथ प्रदेश के औद्योगीकरण के विकास पर भी बल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, व्यापारिक एवं प्रशासनिक उपाय किये गये। उ० प्र० सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया।

इस पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा लघु उद्योग पर कम ध्यान दिया गया। विकास हेतु 2.90 करोड़ रुपये पूँजी विनियोग का लक्ष्य रखा गया। सन 1955-56 तक 1,060 इकाइयाँ 34.46 करोड़ रुपये का उत्पादन कर 27,550 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में सुधार करना था। 1,647 इकाइयों द्वारा 29,898 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी उद्यमों को बढ़ावा दिया गया और ऊर्जा यातायात संचार में रचनात्मक सहयोग दिया गया। इस योजना की प्रगति निम्न है :-

द्वितीय योजना	1956-57 (करोड़ रु०)	1957-58 (करोड़ रु०)	1958-59 (करोड़ रु०)	1959-60 (करोड़ रु०)	1960-61 (करोड़ रु०)
कुल व्यय का प्रावधान	94.53	79.09	88.77	107.94	93.54

इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपरोक्त बोर्ड के दायरे के बाहर थे और जिन पर उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 लागू नहीं होता था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी। इसके अलावा 1941 में स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 1952 में पुनः गठन किया गया और जुलाई 1954 में नारियल जटा उद्योग की स्थापना की गई। इस योजना अवधि में लघु उद्योगों पर लगभग 180 करोड़ रु० व्यय किये गये। प्रत्येक राज्यों में लघु उद्योग सेवाएँ स्थापित की गयी। 66 औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण किया गया।

इस योजना में 2,824 इकाइयों द्वारा 48,382 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 50.16 करोड़ रु० का उत्पादन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, व्यापारिक तथा प्रशासनिक उपाय किये गये। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया।

मुख्य सुधार निम्न हैं :

1. राज्य सरकार द्वारा एक मुख्यतः दल ग्रामीण एवं लघुस्तर के उद्योगों के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग बनाने के लिए बनाया गया।
2. दो अध्ययन दल देश के विभिन्न प्रदेशों के औद्योगिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के

लिए दल भेजा।

3. सभी जनपद के जिला उद्योग कमेटियों के विचार-विमर्श और सभी जिला के औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सभी जिला मजिस्ट्रेटो से सलाह प्राप्त किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना : तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया कि निम्न मुख्य तथ्यों पर केन्द्रित किया जाए .—

- (क) प्रथम और द्वितीय योजनाओं की प्रगति को पूर्ण करके पुष्ट किया जाए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार योजना के प्रारम्भिक वर्षों में पूरा किया जाय।
- (ख) औद्योगिक कोआपरेटिव उपाय संगठनात्मक आधारित लघु स्तर उद्योगों को सहायता देता है।
- (ग) अधिक संख्या के शिल्पकारों और क्राफ्ट मैन को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से उत्पादन करने के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षण देना।
- (घ) ऊर्जा स्रोतों का विस्तार योजना के साथ समतुल्यता में उद्योगों का विकास एवं मध्यम उद्योगों का विकास एनसलरी पैटर्न पर लघु स्तर उद्योगों के द्वारा करना।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (करोड़ रुपये)

मर्दे	प्रावधान	कुल योग	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65
हैण्डलूम	275	16.8	35.356	46.220	39.504	36.678
लघु उद्योग	839	40.8	170.680	126.758	129.34	176.24
औद्योगिक आस्थान	375	22.9	15.170	52.832	101.420	62.282
हस्तशिल्प	90	5.5	5.903	9.180	12.180	10.368

इस योजना अवधि में 33.83 करोड़ रुपये का विनियोजन कर 4,842 इकाइयों द्वारा 1,14,431 लोगों को रोजगार प्रदान करके 101.49 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया।

ऋण एवं अनुदान के रूप में 77 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 1963-64 में दी गयी।

तृतीय योजना और तीन वार्षिक योजनाएँ - इस योजना में इन उद्योगों के तीव्र विकास एवं सुधार का कार्यक्रम एवं निजी क्षेत्र में 275 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजनाअवधि में विभिन्न दिशाओं में विकास करने के कार्यक्रम किये गये। जैसे, श्रमिकों के उत्पादन में सुधार करना, सस्थागत वित्त की उपलब्धि करना, छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में विकास करना, गाँवों एवं छोटे नगरों में इन उद्योगों का विकास करना तथा कारीगरों की सहकारी समितियों बनाना आदि। तीन वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास में 132-6 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 1968-69 के अन्त तक राज्य उद्योग निदेशालयों में 140,000 लघु सारीय इकाइयों पंजीकृत थी जबकि 1962 में लगभग 360,000 इकाइयों थी। मार्च 1969 में लगभग 348 औद्योगिक बस्तियाँ स्थगित हो चुकी थी। जबकि 1960-61 में इनकी संख्या 66 थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना - इस योजना की अवधि में 239 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान था, लेकिन 250 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये। इस काल में छोटे उद्योगों की उत्पादन तकनीकी को उन्नत करना, उद्योग के विकेन्द्रीकरण एवं फैलाव को उन्नत करना कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना आदि कार्यक्रम थे। जिनमें 11,200 हैण्डलूम घुनकर समितियाँ थी। गाँवों में चलाये जाने वाले उद्योगों को विशेष सहायता दी गयी। इस योजना में साख-तकनीकी परामर्श एवं कच्चे माल के लिए विशेष व्यवस्था की गयी। इस अवधि में मशीन, औजार, सिलाई, मशीनें, बिजली के पंखे मोटरों आदि की विशेष प्रगति हुई है।

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों की स्थापना की गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर उद्योग अधिकारी नियुक्त किए गये। 1955 में शुरू किया जाने वाला औद्योगिक बस्तियाँ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और लगभग 60 औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गयी जहाँ पर कारखानों की स्थापना के लिए बिजली, पानी, यातायात

आदि की सुविधाएँ थी। कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया। औद्योगिक सहकारी समितियों के संगठन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। साख, प्रशिक्षण तकनीकी सलाह, अच्छे औजार आदि के रूप में लघु उद्योगों को सहायता देने की दशा में भी कार्य हुआ।

इस पंचवर्षीय योजना में लघु स्तर उद्योगों के विकास कार्यक्रमों के विस्तार का मुख्य ध्येय निम्नलिखित किया गया –

- 1 लघु उद्योगों की उत्पादन तकनीकी के विस्तार को उन्नत करना। इस प्रकार उनके उत्पादों की किस्म को बढ़ाना।
- 2 उन्हें सहज प्राप्य स्तर पर लाना।
- 3 उद्योगों के विक्रेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना
- 4 कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना

उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए 2,01,000 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एवं तीन वार्षिक योजनाओं की प्राप्ति

इकाई की सं० अनुमानित उत्पादन	विनियोजन (करोड़ रुपये)	(करोड़ रुपये)	रोजगारसं०
तीन वार्षिक योजना	6,14,742 04	1,24,738	128 82
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	12,85,145 94	1,60,027	249 00

इस योजना अवधि में 12,851 इकाइयों द्वारा 249 करोड़ रुपये का उत्पादन कर 1,60,027 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

पंचम वर्षीय योजना :- पाँचवी योजना अवधि में गरीबी और उपभोग में असमानता को कम करने की दिशा में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी विषय में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न प्रकार निर्धारित किये गये थे ।

- 1 सही उद्योगों का चुनाव करना उन्हें सलाहकार तथा विपणन सेवाओं की सहायता देना।

- 2 लघु उद्योगो एव बडे उद्योगो के बीच सम्पर्क स्थापित करना।
- 3 वित्तीय सहायता देना पिछडे क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास को बढावा दिया जाना।
- 4 औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सरचना का विस्तार किया गया।

सशोधित पाँचवी योजना मे लघु उद्योगो के लिए 510 करोड रुपये की व्यवस्था की गयी। 1974 से 1978 के दौरान लघु उद्योगो पर 388 करोड रुपये व्यय किये परिमाणत विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र (Decentralised Sector) मे कपडे का उत्पादन 1977-78 मे बढकर 410 करोड मीटर हो गया। 1974-75 एव 1977-78 के बीच हस्तशिल्पो का निर्यात 194 करोड रुपये से बढकर 440 करोड रुपये हो गया। इसी प्रकार लघु स्तर उद्योगो का उत्पादन को 1974-75 मे 538 करोड रुपये था बढकर 1977-78 मे 1,000 करोड रुपये हो गया।

पाँचवी पचवर्षीय योजना मे लघु स्तर के उद्योगो के विकास का महत्वपूर्ण चरण था इस अवधि के दौरान 42,035 लघु स्तर की इकाइयों बनी।

इस योजना अवधि मे प्रगति निम्नवत हैं –

प्रगति विवरण

वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयो की सख्या	अनुमानित उत्पादन (करोड रुपये मे)	सेवायोजित व्यक्तियों की सख्या
1975-76	29,488	565 00	3,54,970
1976-77	33,587	637 00	3,81,973
1977-78	37,469	782 00	4,33,081
1978-79	42,035	880 00	4,75,180
1979-80	47,943	983 00	5,38,270

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पाँचवी योजना के अन्त तक लघु इकाइयो की सख्या 47943 थी जिसमे अनुमानत. उत्पादन 983.00 करोड रुपया एव 538270 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए।

इस योजना के प्रारम्भ करने का निम्नलिखित उद्देश्य रखा गया –

- (1) लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना।
- (2) उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उधमियों को एक छत्र के बीच उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- (3) लघु उद्योगों के विकास के लिए एवं सर्वेक्षण करना।

छठी योजना (1980-85) में लघु उद्योगों - छठी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को राष्ट्रीय विकास नीति को महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया और यह व्यवस्था की गई कि छठी योजना काल में लघु उद्योगों का विकास उच्च प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार किया जाय कि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हो सके –

- (1) उत्पादन के स्तर में वृद्धि तथा उधमियों की आय में वृद्धि,
- (2) विकेंद्रित विकास द्वारा अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन।
- (3) लघु उद्योगों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग हो जिससे कुल उत्पादन में इसका योगदान बढ़े।
- (4) अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा उधमियों की कार्य कुशलता में वृद्धि।
- (5) लघु उद्योगों की संरचना का निर्माण एवं लघु उद्योगों के उत्पादन कोई नियति को प्रोत्साहन दिया जाए।

छठी योजना (1980-85) में लघु उद्योगों पर वास्तविक अनुमानित परिव्यय 1952 करोड़ रुपये हुआ। इस क्षेत्र को कुल योजना परिव्यय का 1.8 प्रतिशत प्राप्त हुआ। छठी योजना की प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि इस क्षेत्र में उत्पादन 1979-80 में 33,538 करोड़ रुपये था। और यह बढ़कर 1984-85 में 65,730 करोड़ रुपये हो गया। एवं इसी प्रकार इस क्षेत्र से निर्यात को 1989-90 में 2,281 करोड़ रुपये था।

इस योजना के फलस्वरूप 1,10,710 लघु स्तर की इकाइयों की स्थापना की गयी। इस योजना में नई औद्योगिक इकाइयों को ब्रिकी कर से मुक्त किया गया।

इस अवधि में वर्ष कर प्रगति निम्नवत है

वर्ष	लघु एव लघुस्तर इकाइयों की संख्या	आनुमानित उत्पादन (करोड़ रुपये में)	सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या
1980-81	55,896	1,070 00	6,13,813
1981-82	68,426	1,318 00	6,91,145
1982-83	82,037	1,581 00	7,75,149
1983-84	95,847	1,846 00	8,50,149
1984-85	1,10,710	2,143 00	9,20,756

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इस योजनावधि के प्रारम्भ में लघु स्तर की इकाइयों की संख्या 55,896 थी। अन्त में 1,10,710 हो गयी जिसमें 676 00 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया जिसमें उत्पादन 2,143 करोड़ रुपया एव 9,20,756 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में औद्योगिक सेक्टर में केवल 2 3% की वृद्धि दर थी। छठी योजना में 11 8% की वृद्धि हुयी। 4,558 करोड़ रुपये हो गया। जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है। यह 1979-80 में 234 लाख व्यक्ति था। 1984-85 तक बढ़कर 315 लाख व्यक्ति हो गया। जहाँ पर उत्पादन का लक्ष्य मैट्रिक दृष्टि को पार कर किया गया, रोजगार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। छठी योजना में लघु उद्योगों द्वारा 3 26 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना-(1985-90)- सातवी योजना में प्रारम्भिक प्रपत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उत्पादन रोजगार तथा निर्यात की दृष्टि लघु उद्योगों का अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्पूर्ण अंग के रूप विशेष स्थान है। अतः इस क्षेत्र के विकास की नीतियों को वित्तीय एव करो की दृष्टि से उधार तथा प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से कुशल बनाया जाना चाहिये। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस योजना में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामीण

क्षेत्रों में निर्धनता के निवारण के लिए तथा रोजगार के नये अवसरों के सृजन के लिए बनाये गये विशिष्ट कार्यक्रम को इस प्रकार चलाया जाय कि कृषि पर से जनसंख्या का भार कम हो जाये और उसे इन सम्भव होगा जब कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय।

इस योजना के प्रारम्भिक पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अति लघु उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर बैंक वित्त उपलब्ध कराने के लिये साख के प्रवाह को नियन्त्रित एवं नियमित किया जायेगा।

इस योजना में लघु उद्योगों के लिए 2,752 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत था। परन्तु 1985-90 की सातवीं योजना को अवधि के लिये वास्तविक व्यय 3,249 करोड़ रुपये आँका गया। लघु उद्योगों की प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि आधुनिक लघु उद्योगों एवं बिजली करघा कपड़ा बनाने वाले क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की और वे अपने उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात के लक्ष्य को पार कर गये।

1984-85 में आधुनिक लघु स्तर क्षेत्र के 50,520 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर 1989-90 में 92,080 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 127 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई किन्तु खादी ग्राम एवं हथकरघा कपड़े एवं नारियल जटा और नारियल उत्पाद से कम रहा। एक और क्षेत्र जिसमें निष्पादन बढ़कर 1989-90 में 1,14,314 करोड़ रुपये हो गया। अतः स्थिर कीमतों पर इसमें 1984-85 एवं 1989-90 के दौरान 121% की वार्षिक वृद्धि हुई। रोजगार के रूप में वृद्धि दर 44 प्रतिशत थी। निर्यात के संदर्भ में उपलब्धि सराहनीय थी। वर्तमान कीमतों पर लघु उद्योगों के निर्यात जो 1984-85 में 4,558 करोड़ रुपये थे जो बढ़कर 1989-90 में 14,807 करोड़ रुपये हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की संख्या 10,710 थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन इकाइयों के लगाने का एक लाख का लक्ष्य रखा गया जिसके समक्ष 1,05,541 इकाइयों लगायीं गयीं जिनमें 2,043 करोड़ रुपये का अनुमानित उत्पादन हुआ। और 5,24,304 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष बार प्रगति का विकास निम्नलिखित है

वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (करोड़ रुपये में)	सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या
1985-86	1,27,294	2,464 00	10,07,830
1986-87	1,46,187	2,830 00	11,02,295
1987-88	1,67,062	3,234 00	12,00,450
1988-89	1,90,212	3,682 00	13,12,637
1989-90	2,16,251	4,186 00	14,45,060

सातवीं योजना अवधि में जो 105541 इकाइयों लगायी गयी। उनकी वर्षवार प्रगति का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयों की संख्या		अनुमानित उत्पादन (करोड़ रुपये में)	रोजगार संख्या
	लक्ष्य	उपलब्ध		
1985-86	16,000	16,584	321 00	87,074
1986-87	18,000	18,893	366 00	94,465
1987-88	20,000	20,875	404 00	98,165
1988-89	22,000	23,150	448 00	1,12,178
1989-90	24,000	26,039	504 00	1,32,423
योग	1,00,000	1,05,541	2043 00	5,24,304

लघु उद्योगों के वास्ते प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य प्रदान कर रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रगति निम्नलिखित है।

कार्यक्रम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1 लघु एव इकाइयों की कार्यालय	15,884	18,893	20,875	23,150	26,039
2 कालान्तर कार्यालय	34,237	31,082	33,150	31,720	32,454
3 एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड	1,44,599	1,35,723	1,47,146	1,52,144	1,69,271

अर्थात् 26.6% की वार्षिक वृद्धि हुई। सातवी योजना की प्रगति से पता चलता है कि राज्य आधुनिक लघु क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है क्योंकि इनमें उत्पादन एवं रोजगार की वृद्धि दरे ऊँची है। निर्यात के सदर्भ में भी, लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन निगम क्षेत्र की तुलना में बेहतर कमाने वाला क्षेत्र है एवं लघु क्षेत्र के कुल निर्यात का 89% इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

आठवीं योजना-(1992-97) में लघु उद्योग : आठवीं योजना में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण की नीति पर अधिक बल दिया गया। इस योजना में ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए 6 334 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जोकि सार्वजनिक क्षेत्र पर कुल परिव्यय का 1.5% था। किन्तु चालू कीमतों पर वास्तविक परिव्यय 7,094 करोड़ रुपये हुआ जो कि परिव्यय का 14 प्रतिशत था।

उत्पादन के लक्ष्यों एवं इनकी उपलब्धि के रूप में यह कहा जा सकता है कि आठवी योजना के दौरान कच्चे रेशम को छोड़ जिसके उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त में कुछ कमी रही, अन्य सभी क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। लघु-स्तर उद्योगों का उत्पादन 4,18,863 करोड़ रुपये के चरम स्तर पर पहुँच गया। इस प्रकार बिजली करघा कपड़े का उत्पादन 1996-97 में 1,730 करोड़ वर्ग मीटर हो गया जबकि इसका लक्ष्य 1,524 करोड़ वर्ग मीटर था। पारम्परिक उद्योगों-ग्राम उद्योग, हथकरघा कपड़ा एवं हस्तशिल्पो नारियल के तन्तुओं में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए।

जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, ग्राम तथा लघु उद्योग 575 लाख व्यक्तियों को 1996-97 में रोजगार उपलब्ध करा पाया। यह वस्तुतः प्रशंसनीय है। इसमें से आधुनिक लघु-स्तर उद्योगों में 228 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया (अर्थात् लगभग 40%) और पारम्परिक क्षेत्र में 347 व्यक्तियों (अर्थात् लगभग 60%)। आधुनिक क्षेत्र का बढ़ता हुआ भाग इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लघु तथा ग्राम उद्योगों में ऐसे क्षेत्र मजबूत हो रहे हैं। जिनमें उत्पादित (productivity) और कमाई अधिक है। यह एक अभिनन्दनीय प्रवृत्ति है।

लघु एवं ग्राम उद्योगों की एक अत्यधिक प्रशंसनीय उपलब्धि उनका 1996-97 में निर्यात में 52,230 करोड़ रुपये का योगदान है जो कुल निर्यात का 44% है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वीकरण (Globalisation) में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह इस क्षेत्र को प्रोन्नत करने की ओर और अधिक ध्यान दे।

आठवीं योजना का लक्ष्य विवरण

वर्ष	इकाई की संख्या	रोजगार(लाख में)
1990-91	74,303	2 30
1991-92	87,028	2 62
1992-93	98,749	2 93
1993-94	1,12,247	3 30
1994-95	1,27,751	3.70

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2,550 00 करोड़ रुपये पूँजी विनियोजन की 1,65,000 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को लगाये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना अवधि में कार्यक्रम के अन्तर्गत 62,000 कोर्सस के अन्तर्गत 2,80,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

वर्ष	कोसेर्स (संख्या)	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
(लक्ष्य)	62,000	2,80,000
1990-91	856	43,067
1991-92	1,242	56,085
1992-93	1,240	56,000

जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, लघु स्तर क्षेत्र में कुल रोजगार 575 लाख से बढ़कर 666 लाख हो जायेगा। अतः 5 वर्षों में 91 लाख अतिरिक्त रोजगार कायम किया जायेगा। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान देने के कारण इनकी संस्था में काफी वृद्धि हुई है। 1960-61 में 36 हजार इकाइयों लघु उद्योगों के रूप में विद्यमान थी। जिनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते 2002-2003 में 35 72 लाख इकाइयों हो गयी है। यह इकाइयों 560 वस्तुओं का निर्माण करती है। इन लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रारम्भ में 180 वस्तुओं का निर्माण केवल इन्हीं के द्वारा ही करने के लिए सुरक्षित था, लेकिन नयी औद्योगिक नीति, 1977 में इनकी संख्या बढ़कर 504 कर दी गयी। वर्तमान में 674 वस्तुओं का उत्पादन इनके लिए सुरक्षित है। इससे आशा है कि इन उद्योगों का विकास तीव्र गति से होगा।

पिछले चार दशकों में लघु उद्योगों की संस्था में आशातीत वृद्धि हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है —

वर्ष	लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या
1960-61	36 हजार
1974-75	49 हजार
2000-01	3,312 हजार
2001-02	3,442 हजार

नौवीं योजना (1997-2002) :- नौवीं योजना में लघु उद्योगों को वरीयता क्रम में रखा गया है जिसमें से ग्रामीण विकास की गति मिल सके। इनके विकास द्वारा निर्धनता निवारण एवं रोजगार के सृजन में मदद मिलेगी। इस योजना में यह संकेत दिया गया है कि लघु क्षेत्र द्वारा 8,000 वस्तुएँ उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें हाल ही में किए गये अनारक्षणों (Dereservations) को घटा 821 वस्तुओं का उत्पादन आरक्षित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इनमें 200 मदे ऐसी हैं जिनका या तो उत्पादन ही नहीं किया जाता या उनका उत्पादन महत्वहीन है। इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना ने यह उल्लेख किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान 'लघु-स्तर उद्योगों के विकास में अनारक्षित क्षेत्रों (Non-reserved Areas) में उत्पादन आरक्षित क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ है जो लघु-स्तर क्षेत्र की अन्तर्निहित मजबूती और शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि यह क्षेत्र बाजार शक्तियों की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य रखता है।

नौवीं योजना के अनुसार लघु उद्योगों को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे हैं

- (1) उधार का अपर्याप्त प्रवाह
- (2) घिसी-पिटी टेक्नालॉजी, मशीनरी एवं औजारों का प्रयोग,
- (3) गुणवत्ता के घटिया मानदण्ड और
- (4) आधार संरचना सुविधाएँ।

उधार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंकों की विशिष्ट शाखाएँ खोलनी आरम्भ कर दी हैं जो केवल लघु-स्तर-उद्योगों को उधार उपलब्ध कराएँगी।

लघु उद्यम

आठवीं और नवीं योजना के ग्राम तथा लघु उद्योगों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

1996-97		नौवीं योजना (2001-02)			
लक्ष्य प्रत्याशित उपलब्धि		लक्ष्य औसत वार्षिक वृद्धिदर			
क उत्पादन आधुनिक क्षेत्र					
1 लघु स्तर उद्योग	करोड रूपये	4,20,000	4,18,863	7,38,180	12.0
2 बिजली करघा कपडा	करोड वर्ग मीटर	1,524	1,730	3,049	12.0
पारम्परिक क्षेत्र					
3 खादी कपडा	करोड वर्ग मीटर	12.5	12.5	28.0	17.5
4 ग्राम उद्योग	करोड रूपये	4,120	4,120	7,261	12.0
5 नारियल का रेशा	हजार टन	276	271	35	6.7
6 हथकरघा कपडा	करोड वर्ग मीटर	700	700	1,234	12.0
7 कच्चा रेशम	टन	16,250	14,000	20,640	7.9
8 हस्तशिल्प	करोड रूपये	29,620	29,620	52,201	12.0
ख. रोजगार	लाख	585	575	666	3.0
(1) आधुनिक क्षेत्र	लाख	23	228	264	3.0
1 लघु- स्तर उद्योग	लाख	159	159	184	3.0
2 बिजली करघा	लाख	72	69	80	3.0
(2) पारम्परिक क्षेत्र	लाख	351	347	402	3.0
3 खादी एवं ग्राम उद्योग	लाख	66	66	76	2.8
4 हथकरघा	लाख	149	149	173	3.0
5 हस्तशिल्प	लाख	78	71	82	3.0
6 रेशम-कच्चा रेशम	लाख	61	61	71	3.0
ग निर्यात	करोड रूपये	29,004	52,229	1,04,000	14.7

समन्वित आधारसंरचना विकास केन्द्रो (Integrated Infrastructure Development Centres) की योजना के आधीन पिछडे ग्रामीण क्षेत्रो मे आधार संरचना सुविधाएँ कायम की जा रही है। आठवी योजना के दौरान 50 ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए जिनमे से 22 स्वीकृत किए गए है। नौवी योजना के दौरान यह योजना जारी रखी जाएगी ताकि अधिक प्रोत्साहनो एव वित्तीय सहायता के साथ पहाडी क्षेत्रो और उत्तर – पूर्वीय राज्यो मे इस योजना का विस्तार किया जा सके।

नौवी योजना के अनुसार लघु उद्योगो को जिन मुख्य समस्याओ का सामना करना पडता है, वे निम्नलिखित है

- (1) उधार का अपर्याप्त प्रवाह
- (2) घिसी-पिटी तकनालाजी, मशीनरी एव औजारो का प्रयोग,
- (3) गुणवत्ता के घटिया मानदण्ड और
- (4) आधार संरचना सुविधाएँ।

उधार के प्रवाह को बढाने के लिए सरकार ने बैंको की विशिष्ट शाखाएँ खोलनी आरम्भ कर दी है जो केवल लघु-स्तर-उद्योगो को उधार उपलब्ध कराएँगी। समन्वित आधार/संरचना विकास केन्द्रो (Integrated Infrastructure Development Centres) की योजना के आधीन पिछडे ग्रामीण क्षेत्रो मे आधार संरचना सुविधाएँ कायम की जा रही है। आठवी योजना के दौरान 50 ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए जिनमे से 22 स्वीकृत किए गए है। नौवी योजना के दौरान यह योजना जारी रखी जाएगी ताकि अधिक प्रोत्साहनो एव वित्तीय सहायता के साथ पहाडी क्षेत्रो और उत्तर-पूर्वीय राज्यो मे इस योजना का विस्तार किया जा सके। पारम्परिक क्षेत्र मे भी उत्पादन की वृद्धि दर 11 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने की सभावना है। इसमे लघु स्तर क्षेत्र के गतिशील स्वभाव का बोध होता है।

जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, लघु स्तर क्षेत्र मे कुल रोजगार 575 लाख से बढकर 666 लाख हो जायेगा। अतः 5 वर्षो मे 91 लाख आतिरिक्त रोजगार कायम किया जायेगा।

इसमें से आधुनिक क्षेत्र का 36 लाख और पारम्परिक क्षेत्र का भाग 55 लाख होगा। लघु क्षेत्र में रोजगार की समग्र वृद्धिदर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी जोकि नौवी योजना में अर्थव्यवस्था को किसी भी क्षेत्र में कल्पित दर से कहीं अधिक है।

किन्तु लघु स्तर क्षेत्र का सबसे अधिक उत्साहवर्धक पहलू निर्यात का 1996-97 में 52,230 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001-02 में 1,04,000 करोड़ रुपये हो जाना है। अतः निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धिदर 14.7 प्रतिशत होगी। इसमें योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण अशदाता लघु स्तर उद्योग और हस्तशिल्प (Handicrafts) है। ये दोनों मिल कर नौवी योजना में कल्पित निर्यात— वृद्धि का 88 प्रतिशत उपलब्ध कराएँगे। किन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि लघु—स्तर—क्षेत्र द्वारा 2001-02 में प्रत्याशित 1,04,000 करोड़ रुपये के कुल निर्यात में आधुनिक क्षेत्र का भाग 86,950 करोड़ रुपये होगा अर्थात् 83.6 प्रतिशत। अतः इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्यात बढ़ाने के लिए आधुनिक लघु—स्तर क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा। किन्तु पारम्परिक क्षेत्र ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार (Supplementary employment) का स्रोत लगातार बना रहेगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना : दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र पर 44 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। इसे पूरा करने को लेकर स्वयं लघु उद्योग मंत्रालय भी असमजस में है। मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा नीतियों के तहत इन लक्ष्यों को पूरा करना बहुत मुश्किल है।

चालू वित्त वर्ष की मध्यावधि आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पादों के अनारक्षण की वकालत की है। इससे पहले केलकर समूह द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को एक करोड़ रुपये तक के कारोबार पर मिलने वाली उत्पाद शुल्क छूट को घटाकर 50 लाख करने की सिफारिश की थी। इन सभी घोषणाओं के साथ ही लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की बात भी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के दोहरे मानदंडों से लघु उद्योग का अपेक्षित विकास नहीं हो सकता है।

योजना आयोग द्वारा नए रोजगार सृजन को लेकर आहलूवालिया और एस पी गुप्ता समितियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लघु उद्योग क्षेत्र में नए रोजगार सृजन की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। मौजूदा समय में लघु उद्योग क्षेत्र में 1.93 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु क्षेत्र में 44 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग के लिए 12 फीसदी की विकास का दर निर्धारित किया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि योजना आयोग की रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है, वह पूरी तरह से ठीक है। लेकिन मौजूदा नीतियों में यह जिम्मेदारी पूरा करना काफी मुश्किल लग रहा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सबसे बड़ी दिक्कत वित्त पोषण की है। लघु उद्योग क्षेत्र को न सिर्फ बड़ी कंपनियों की तुलना में कम ऋण दिया जा रहा है, बल्कि उनके लिए वित्त पोषण की लागत भी बहुत अधिक है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के चेयरमैन दलबीर सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वित्त पोषण की लागत कम करने के साथ ही अन्य कुछ उपायों पर हाल ही में योजना आयोग की एक बैठक में व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। इस बैठक में लघु उद्योग मंत्रालय ने लघु क्षेत्र को ऋण बढ़ाने और उसकी लागत को घटाने पर जोर दिया है।

लघु उद्यमों के विकास पर एस. पी. गुप्त अध्ययन दल

(S. P. Gupta Study Group on Development of Small Enterprise)

योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा उद्यमों के विकास के लिए डा.एस.पी. गुप्त की अध्यक्षता में मई 1999 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल का गठन करते समय लघु स्तर उद्योग सम्बन्धी संस्थाओं, अर्थशास्त्रियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, लघु क्षेत्र के उद्यमियों और विभिन्न विभागों के सचिवों अर्थात्—लघु उद्योगों एवं कृषि तथा ग्राम उद्योगों के सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग

विकास बैंक और फिक्की आदि के प्रतिनिधि शामिल किये गये । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2001 में प्रस्तुत की ।

अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें

(1) अति लघु (Tiny), लघु और मध्यम क्षेत्र की तीन-स्तरीय परिभाषा

अति लघु (Tiny units) - प्लान्ट एव मशीनरी में 10 लाख रुपये तक के विनियोग वाली इकाइया

लघु स्तर इकाइयां (Small Scale Units)- प्लान्ट एव मशीनरी में 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का विनियोग

मध्यम इकाइया (Medium units)- प्लान्ट एव मशीनरी में एक करोड़ रुपये से दस करोड़ रुपये तक विनियोग वाली इकाइया ।

इन तीन क्षेत्रों के सहायक उपायों (Supportive measures) सम्बन्धी निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर किये जायेंगे । कोशिश यह होगी कि पिछ्दी क्षेत्र को अधिकतम सहायता और सरक्षण दिया जाए इसमें कुछ कम सहायता लघु स्तर उद्योगों की इकाइयों को दी जाए परन्तु मध्यम इकाइयों (Medium units) को कोई सुविधाएँ अथवा सहायता नहीं दी जाएगी, सिवाए इसके कि एक पृथक कोष से आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिया जाए ।

विनियोग की अधिकतम सीमा प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् सशोधित कर बढ़ायी जाएगी । इसके लिए भारत सरकार का थोक कीमत सूचकांक इस्तेमाल किया जायेगा ।

उद्योग से सम्बन्धित सेवा और व्यापारिक उद्यमों (Service and business enterprises) को जिन में अचल पूंजी (Fixed capital) (भूमि तथा भवन को शामिल का) कुल विनियोग 10 लाख रुपये से कम हो, भी लघु स्तर उद्योगों में शामिल किये जाएंगे और इनको भी पिछ्दी क्षेत्र के समान सहायता उपलब्ध करायी जाएगी परन्तु इन उद्यमों में ट्रक-चालको, कारो, भारी गाड़ियों, टैक्सियों, आटोरिक्शा और टैम्पों के मालिक शामिल नहीं किए जाएंगे ।

लघु स्तर उद्योगों की अपेक्षा शब्द "लघु उद्यमों" (Small enterprises) का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके निम्नलिखित अंग होंगे -

- (1) अति लघु औद्योगिक इकाइया
- (2) लघु-स्तर औद्योगिक इकाइया और
- (3) सेवा और व्यापारिक उद्यम

अध्ययन दल ने पहली बार मध्यम स्तर की इकाइयों की परिभाषा प्लान्ट एवं मशीनरी में विनियोग के रूप में की है। ऐसा करना उचित समझा गया है। क्योंकि इस प्रकार लघु स्तर इकाइयों को मध्यम स्तर इकाइयों में उन्नति करने की दिशा प्राप्त होगी।

2 लघु उद्योग क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) के प्रति जागरूकता लानी आवश्यक है। और इसके लिए लघु क्षेत्र पर होने वाले प्रभावों का बोध कराना जरूरी है। विशेषकर यह बात समझनी आवश्यक है कि वि व्या स के दायित्वों के कारण और मदों को खुले सामान्य लाइसेंस (Open General Licence) के अधीन लाना पड़ेगा। इसके लिए लघु स्तर उद्योग मंत्रालय के कार्यालय में एक नया विभाग स्थापित करना होगा जो विश्व व्यापार संगठन और इसके लघु स्तर इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभावों का ध्यान रखे।

3 लघु स्तर क्षेत्र के लिए एक ही व्यापक अधिनियम की आवश्यकता

4 अध्ययन दल ने सिफारिश की कि लघु स्तर क्षेत्र के आरक्षण (Reservations) अपने वर्तमान रूप में जारी रखे जाने चाहिए। किन्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन दल ने सिफारिश की कि गैर-लघु-स्तर इकाइया (Non-SSI units) आरक्षित मदों का उत्पादन कर सकती है। बशर्ते कि वे तीन वर्षों के दौरान अपने उत्पादन के 30 प्रतिशत का निर्यात करें। आज यह सीमा 50 प्रतिशत है।

5 अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि निर्यात-मुख्य उद्योगों (Export-oriented Industries) जैसे चमड़े के उत्पाद, सिले सिलाए कपड़ों, हौजरी, हाथ के औजारों, खिलौनों पैकेज

की सामग्री, आटो के हिस्सो, औषधियों, खाद्य-परिसाधन (Food Processing) आदि में प्लान्ट एव मशीनरी में विनियोग की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर देनी चाहिए।

6 आधारसंरचना विकास (Infrastructure Development) के लिए अध्ययन दल ने 2,000 करोड़ रुपये के संग्रह (Corpus) की सिफारिश की है ताकि लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त आधारसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकें।

7 हाई-टेक उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना-तकनालाजी, तकनालाजी (Bio-technology) और औषधियों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की एक परिपाक आधारसंरचना विकास निधि (Incubation Infrastructure Development Fund) कायम करने की सिफारिश की है। अध्ययन दल के अनुसार यह निधि दसवी योजना में आरम्भ कर दी जाए और परिपाक केन्द्र (Incubation centres) कायम किए जाएं। परिपाक केन्द्र सभी प्रकार की सुविधाएँ और वित्त उपलब्ध कराएँ जिनके द्वारा टेक्नोक्रेट (Technocrats), और पहली पीढ़ी के उद्यमकर्ताओं को हाल ही में विकसित तकनालाजी के आधार पर उत्पादन करने के लिए वित्त और परामर्श प्राप्त हो सके। इस प्रकार के परिपाक केन्द्रों से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

8 लघु-इकाइयों द्वारा पूरित माल के लिए बड़े पैमाने की इकाइयों को भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अध्ययन दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं —

- ⊗ ऐसी बड़ी इकाइयों को जो लघु स्तर क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पूरित माल का भुगतान 120 दिन के विलम्ब के पश्चात् भी नहीं करती, को मोडवैट उधार (MODVAT credit) उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- ⊗ आयकर में संशोधन करना ताकि लघु स्तर उद्योगों को भुगतान न किए गए व्यापारिक व्यय को घटाने की इजाजत न दी जाए।
- ⊗ आढत क्रियाओं (Factoring services) को मजबूत बनाना, और

- ⊗ विलम्बित भुगतान अधिनियम (Delayed Payments Act) के कार्यान्वयन की निगरानी विकास आयुक्त, लघु स्तर उद्योगों द्वारा करवाना।

9 बड़ी और मध्यम इकाइयों के बीच बेहतर सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन दल ने सिफारिश की –

- ⊗ बेहतर तकनालाजी हस्तांतरण (Technology transfer) के लिए विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को लघु स्तर उद्योगों में प्रोत्साहित करना।
- ⊗ अन्य बड़ी इकाइयों के लिए ब्रैण्ड नाम में लघु स्तर उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क (Excise) से छूट को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करना, यह छूट अभी तक ग्राम क्षेत्रों को प्राप्त है।

10 अध्ययन दल ने सीमित साझेदारी कानून (Limited Partnership Act) बनाने की सिफारिश की है ताकि लघु स्तर उद्योगों में अधिक जोखिम पूंजी (Risk Capital) और सीमित दायित्व की धारणा लायी जा सके। बीमार लघु-स्तर इकाइयों के दायित्व का समाधान योजना द्वारा एक बार निपटारा कर देना चाहिए ताकि उनकी परिसम्पत्तियों का प्रयोग किया जा सके। बीमार इकाइयों को एक बार भुगतान में ब्याज को शामिल करके ऋण-राशि के दुगुने से अधिक राशि नहीं देनी होगी। इस प्रकार बीमार-इकाइयों को निकास मार्ग (Exit Route) उपलब्ध हो जाएगा।

11 लघु-स्तर उद्योगों के कड़े परेशान करने वाले विनियामक कानूनों (Regulatory laws) से मुक्त करने के लिए और विभिन्न विभागों के इन्स्पेक्टरों के दौरो से भी बचाने के लिए अध्ययन दल ने कई सिफारिशें की हैं जैसे (क) लघु-उद्यमों के लिए एक एकीकृत कानून, (ख) निरीक्षण की अपेक्षा स्वप्रमाणन (Self-certification) की अनुमति, (ग) विनियामक कानूनों (Regulatory laws) आदि का सरलीकरण।

12 लघु-स्तर क्षेत्र सम्बन्धी आकड़ों का आधार मजबूत करने के लिए अध्ययन दल ने सिफारिश की है (क) चूंकि लघु-उद्यमों की पिछली गणना (Census) 1987-88 में की गयी

थी और इस बीच परिस्थितियां बहुत बदल गयी हैं, इस लिए लघु-क्षेत्र सम्बन्धी एक नयी गणना की जानी चाहिए, (ii) विभिन्न लघु-उद्यमों के समूहों (Clusters) के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र की जानी चाहिए, और लघु-उद्योगों के विकास आयुक्त (Development Commissioner) के कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सैम्पल सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

13 अध्ययन दल ने मानवीय ससाधन विकास के लिए लघु-उद्यमों के बारे में कई सिफारिशें की हैं जिनमें प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन (Skill upgradation), नये प्रबन्धकीय व्यवहार आदि का विकास महत्वपूर्ण है।

14 अध्ययन दल ने राजकोषीय एवं वित्तीय उपायों के रूप में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं

- (i) अतिलघु और लघु-स्तर उद्योगों की इकाइयों के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को प्राथमिकता उधार (Priority lending) के लक्ष्य निर्धारित करना।
- (ii) लघु स्तर उद्योगों की इकाइयों के लिए ऋण की लागत कम करने की आवश्यकता,
- (iii) लघु-स्तर उद्योगों की इकाइयों के लिए अधिक मात्रा में विशिष्टीकृत बैंक शाखाओं की स्थापना करना,
- (iv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के संसाधनों को और मजबूत बनाना ताकि लघु-स्तर उद्योग क्षेत्र के लिए ब्याज की नीची दर पर अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
- (v) 500 करोड़ रुपये से एक विशेष जोखिम पूंजी (Venture capital) प्रकार की निधि स्थापित करना जिसका नाम लघु-निर्माण-निधि रखा जाए जो लघु स्तर इकाइयों को हिस्सा-पूंजी समर्थन प्रदान करे,
- (vi) कार्यविधि का मानकीकरण (Standardisation) और बैंकों के फार्मों का सरलीकरण,
- (vii) वर्तमान उत्पाद-शुल्क की छूट सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये करना,
- (viii) लघु-स्तर उद्योगों की इकाइयों से जो बड़ी इकाइयां माल खरीदे, उन्हें 5 प्रतिशत

काल्पनिक मोडवैट उधार (MODVAT credit) दिया जाए,

- (ix) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु-स्तर उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध उधार की निगरानी,
- (x) लघु क्षेत्र की इकाइयों को उचित लागत पर उधार उपलब्ध कराना अर्थात् प्राथमिक उधार दर (Prime Lending Rate) जमा 3 प्रतिशत,
- (xi) अतिलघु इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सगठित उधार (Composite- loan) की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना,
- (xii) राज्य वित्त निगमों (State Financial Corporations) का पुनर्गठन करना,
- (xiv) समय-सीमा के बीच उधार के आवेदनपत्रों का निपटारा करना।

15. लघु-स्तर उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के तकनालाजी उन्नयन (Technology upgradation)

और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गयीं,

- (i) आवश्यक तकनालाजी के बारे में सूचना एकत्र करने और इसका प्रसार करने के लिए तकनालाजी बैंक (Technology Bank) की स्थापना ,
- (ii) 5,000 करोड़ रुपये की एक तकनालाजी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण निधि स्थापित करना जिसे 5 प्रतिशत का साहाय्य (Subsidy) प्राप्त हो :
- (iii) तकनालाजी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated depreciation) का प्रावधान करना,
- (iv) ऐसी पूँजी वस्तुएँ जिन पर निर्यात-दायित्व या (Export Obligation) है, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाना और तकनालाजी आधुनिकीकरण के लिए 5 प्रतिशत साहाय्य (Subsidy) देना,

16. लघु-स्तर उद्योगों की इकाइयों के लिए अधिक विपणन सहायता

(Marketing Support) उपलब्ध कराने के लिए अध्ययनदल ने सिफारिश की ,

- (i) सरकार द्वारा राजकीय क्रय कार्यक्रम (State Purchase Programme) में सरकारी विभागों द्वारा खरीद में कानूनी रूप से कीमत-प्राथमिकता (Price Preference) जारी रखना।

- (ii) सयुक्त राज्य अमेरिका की भाति लघु-स्तर-उद्योग क्षेत्र से 33 प्रतिशत तक सरकारी क्रय करना।
- (iii) सभी प्रकार के कानसार्टियम उद्योगों (Consortium industries) को उद्योग का दर्जा देना ताकि वे बैंको और वित्तीय संस्थानों से वित्त का लाभ उठा सकें।
- (iv) लघु-स्तर उद्योग क्षेत्र के निर्यात-आदेशों (Export orders) के लिए उचित समय पर संस्थागत वित्त उपलब्ध करना।

अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि ये स्वीकार की जाएँ ताकि लघु-स्तर-उद्योगों की इकाइयों को अधिकतम संभव लाभ प्राप्त हो सके।

गुप्त अध्ययन दल की रिपोर्ट का मूल्यांकन

एस पी गुप्त अध्ययन दल ने लघु-स्तर क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है और विस्तारपूर्वक सिफारिशें की हैं। इस दृष्टि से लघु-स्तर-क्षेत्र को मजबूत बनाने की इच्छा से यह मार्गदर्शी प्रलेख है। पहली बार इस रिपोर्ट में मध्यम क्षेत्र की परिभाषा दी गयी है। जो लघु-स्तर-उद्योगों की इकाइयों को उन्नत होकर इसमें प्रवेश करने का दिशानिर्देश करती है। ताकि वे आरक्षण और अन्य लाभों की बैसाखियों को छोड़ दे जोकि केवल लघु उद्यमों के लिए हैं। इसकी कुछ सिफारिशें जैसे 2,000 करोड़ रुपये की आधारसंरचना विकास निधि 1,000 करोड़ रुपये के परिपाक आधारसंरचना विकास विधि, गारंटी निधि के सग्रह को बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये की तकनालाजी उन्नयन और आधुनिकीकरण निधि स्थापित करना, के वित्तीय गृहयार्थ हैं। यदि सरकार लघु-स्तर को मजबूत बनाना चाहती है। तो इसके लिए पर्याप्त वित्त जुटाना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार-जनन और निर्यात प्रोन्नत करने की भारी क्षमता है।

इसकी कुछ सिफारिशें जो विभिन्न निरीक्षण एजेंसियों को कम करने के सम्बन्ध में की गयी हैं। का विस्तृत अध्ययन होना जरूरी है ताकि उदारीकरण के वातावरण में लघु क्षेत्र

के उद्योगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, लघु-स्तर उद्योग क्षेत्र के लिए एक मात्र व्यापक कानून बनाने की सिफारिशों के लिए एक और अध्ययन दल कायम करना होगा जिसमें श्रम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण और उद्योग मंत्रालय, के सहयोग की आवश्यकता है। चूँकि सरकार ने लघु-स्तर उद्योग के लिए एक अलग मंत्रालय कायम कर दिया है। इस मंत्रालय को लघु-स्तर उद्यमों के लिए व्यापक विधान बनाने का मसौदा तैयार करना चाहिए।

किन्तु आलोचकों ने इस रिपोर्ट में विद्यमान कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया है। मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं।

1 निर्यातोन्मुख लघुक्षेत्र की इकाइयों की विनियोग की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये

से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना-

भारत सरकार ने लघु उद्योग संगठनों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रतिवेदनो पर विचार कर लघु उद्योगों में विनियोग की अधिकतम सीमा जो 1997 में 3 करोड़ रुपये कर दी गयी थी, घटा कर सन् 2001 में 1 करोड़ रुपये कर दी। अध्ययन दल ने निर्यातोन्मुख उद्योगों के नाम पर इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया जो कि आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों से भी कहीं ऊपर है। इस उद्देश्य के लिए बहुत से उद्योग चुने गए हैं जिनमें उल्लेखनीय हैं चमड़े के उत्पाद, सिलेसिलाए कपड़े, हौजरी हाथ के औजार पैकेज की सामग्री, आटो के हिस्से, औषधियाँ, खिलौने, खाद्य-परिसाधन आदि। इस प्रकार एक बड़ी चतुर चाल द्वारा मध्यम क्षेत्र की बहुत सी इकाइयाँ लघु-क्षेत्र में घुसेड़ दी गयी हैं। जबकि मध्यम इकाइयों को उधार एक पृथक निधि में से दिया जाएगा, लघु स्तर क्षेत्र की निर्यात प्रेरित इकाइयाँ जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी में विनियोग 5 करोड़ रुपये तक हुआ है, अपने तकनालाजी उन्नयन के लिए लघु-स्तर-उद्योग के लिए आरक्षित निधि से वित्त प्राप्त करेंगी। से सिफारिशों तार्किक दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं हैं और इसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए।

2. गैर-लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइयों से, जो लघु-क्षेत्र की आरक्षित मदों का उत्पादन करती हैं, निर्यात दायित्व कम करना-

आज गैर-लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइया जो लघु क्षेत्र की आरक्षित मदों का उत्पादन करती हैं। पर यह शर्त लगायी जाती है कि वे अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करेगी। इस सीमाबन्धन को लगाने का उद्देश्य लघु क्षेत्र को बड़े पैमाने के क्षेत्र के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करना था। निर्यात-दायित्व को 30 प्रतिशत तक कम करके अध्ययन दल ने पहुँचाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आरक्षित मदों का लघु-स्तर क्षेत्र के रोजगार में 38 प्रतिशत और उत्पादन में 28 प्रतिशत तक योगदान है। सरकार ने 14 अत्यन्त महत्वपूर्ण आरक्षित मदों पर से आरक्षण हटा कर, लघु स्तर क्षेत्र के हितों को नुकसान पहुँचाया है। हाल ही में सरकार ने सिलेसिलाए कपड़ों को अनारक्षित कर दिया है। यदि लघु उद्योग विरोधी इन नीतियों के साथ, गैर लघु स्तर पर से निर्यात दायित्व को घटा कर 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया जाता है, जो इससे लघु स्तर उद्योगों के हितों पर और अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा जो कि रोजगार का मुख्य स्रोत है।

लघु एवं अति लघु क्षेत्र की सहायता के लिए नीति सम्बन्धी सुझाव

लघु एवं अति लघु क्षेत्र (Tiny sectors) की रूग्णता के लिए दो मुख्य कारण उत्तर दायी हैं—पर्याप्त मात्रा में उधार का उपलब्ध न होना, विशेषकर कार्यकारी पूँजी के लिए और उत्पादों के विपणन से जुड़ी हुई समस्याएँ। इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों सम्बन्धी संस्थाओं ने कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है

- 1 लघु-स्तर इकाइयों में 95 प्रतिशत ऐसी हैं जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी के लिए विनियोग की मात्रा 5 लाख रुपये से कम है।
- 2 यह बड़े खेद की बात है कि 95 प्रतिशत लघु-स्तर इकाइयों जिनमें कुल कारखाना क्षेत्र का 33 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का 3 प्रतिशत से अधिक उधार प्राप्त नहीं कर पातीं।

3 लघु स्तर इकाइयों को उपलब्ध कुल उधार जो 1991-92 में कुल उत्पादन का 7 प्रतिशत था कम होकर 1995-96 में 6.5 प्रतिशत हो गया।

4 “ब्रैण्ड” नामों के अभाव और बड़ी इकाइयों की श्रेष्ठ विज्ञापन सामर्थ्य के कारण लघु-स्तर इकाइयों अपने उत्पादन को प्रभावी रूप में बेचने में सफल नहीं होती।

उधार उपलब्ध की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने नायक समिति (Nayak Committee) नियुक्त की जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री पी आर नायक थे। इसके बाद, दिसम्बर 1997 में श्री एस एल कपूर, भूतपूर्व सचिव, लघु स्तर उद्योग, भारत सरकार को एक अन्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

नायक समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं

- 1 उत्पादन के आधार पर 8.1 प्रतिशत के उधार के विरुद्ध नायक समिति ने इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की सिफारिश की। इस सिफारिश को आबिद हुसैन समिति ने भी अपनी अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र को उधार के प्रवाह पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि लगभग एक दशक के अन्दर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- 2 नियम के रूप में रेहन-प्रतिभूति (Collateral Security) को, जिसके लिए बैंक आग्रह करते हैं, समाप्त कर देनी चाहिए भले ही उधार की राशि कितनी ही हो।
- 3 आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार कुल उधार का 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयों के उपलब्ध करना चाहिए जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी में विनियोग 5 लाख से 20 लाख रुपये के विनियोग वाली इकाइयों को और शेष 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को उपलब्ध होना चाहिए जिन में 20 लाख रुपये से अधिक विनियोग हो।

इस सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक को इसका पर्यवेक्षण करना चाहिए।

वर्तमान स्थिति (Present Position)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र की निष्पादन स्तर बढ़ता जा रहा है, बड़े पैमाने के उद्योगों से भारी स्पर्धा के बाद भी लघु उद्योगों ने स्वतन्त्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या, उत्पादन संरचना रोजगार एवं निर्यात की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में नियोजन काल में लघु उद्योगों के लिए किये गये विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों में इस प्रकार है।

उत्पादन (Production)- भारत में लघु स्तरीय उद्योगों के उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। लघु स्तरीय उद्योग परम्परागत वस्तुएँ बनाने के साथ-साथ आधुनिक अन्य विविध वस्तुएँ लगा है। इन गैर परम्परागत परिमार्जित वस्तुओं में रेडियो, टेप रिकार्डर, पखे, सिलाई मशीन, टीवी सेट, माइक्रोवेव के हिस्से, इलेक्ट्रानिक उपकरण, आदि का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र द्वारा 5,000 से भी अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है।

1979-80 में प्रचलित कीमतों के आधार पर लघु उद्योगों द्वारा कुल 30,935 करोड़ रुपये के सामान का उत्पादन किया गया। जो इस वर्ष के कुल औद्योगिक उत्पादन के कीमत का 49 प्रतिशत था।

इससे यह प्रतीत होता है कि विभिन्न विकास प्रयासों के फलस्वरूप योजनाओं में इन उद्योगों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हाल के वर्षों में यद्यपि परम्परागत एवं आधुनिक लघु उद्यमों में प्रगति हुई है परन्तु मुख्य प्रगति आधुनिक उद्यमों में हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र में 1984-85 में 50,520 करोड़ रुपये की वस्तुओं का उत्पादन हुआ था। जो 1997-98 में बढ़कर 4,12,638 करोड़ रुपये का हो गया।

रोजगार-(Employment) रोजगार की दृष्टि से भी लघु उद्योग क्षेत्र का स्थान अत्यन्त ऊँचा हो गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एक अनुमान के अनुसार 1965 में विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वालों की संख्या 165 लाख थी जिनमें 130 लाख लघु उद्योगों में लगे थे। 1973-74 में लघु उद्योगों में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ाकर 176.4 लाख थी। अकेले हथकरघा उद्योग में 61.50 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। जो वृहद् एवं मध्यम आकार के उद्योगों में लगे कुल श्रमिकों की संस्था से अधिक है। वर्ष 1979-80 में अशकालिक या पूर्ण कालिक व्यवसाय के रूप में लघु उद्योगों में 234 लाख श्रमिक कार्य करते थे, जबकि वृहद् एवं मध्यम आकार के उद्योगों से कुल 45 लाख लोग ही रोजगार पाते हैं।

1984-85 में लघु उद्योगों से कुल 309 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। यह औद्योगिक क्षेत्र के समस्त रोजगार का लगभग 80 प्रतिशत भाग है। बाद के वर्षों में रोजगार अवसरों में अपेक्षाकृत अधिक तीव्र वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु उद्योगों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लघु उद्योगों क्षेत्र में 1984-85 में 9.0 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 1997-98 में 16.0 मिलियन हो गयी। यह रोजगार देने वाला कृषि के बाद अकेला सबसे बड़ा क्षेत्र है।

निर्यात व्यापार (Export Trade) - निर्यात व्यापार से विदेशी विनिमय की प्राप्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत में निर्यात व्यापार में भी लघु उद्योगों का महत्व बढ़ता जा रहा है मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों का में गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है। 1984-85 में लघु उद्योगों क्षेत्र में 2350 करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया गया। इस प्रवृत्ति में प्रतिशत था। लगातार वृद्धि हुई 1996-97 में 39249 करोड़ रुपये की वस्तुएँ लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात की गयीं। भारत के कुल निर्यात व्यापार में लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात का अंश लगभग 35 प्रतिशत था।

लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन

वर्ष	इकाइयों की संख्या(लाख में)	उत्पादन चालू कीमतों पर (करोड़ रुपये में)	रोजगार (मिलियन व्यक्ति)	निर्यात चालू कीमतों पर (करोड़ रुपये)
1984-85	16 0	50,520	9 0	2,350
1991-92	20 8	1,78,690	13 0	13,883
1998-99	31 2	5,27,515	17 0	49,481

तालिका से स्पष्ट है कि लघु उद्योग क्षेत्र से 1998-99 में कुल लगभग 49481 करोड़ रूपए का सामान निर्यात किया गया। उल्लेखनीय पक्ष यह है कि हाल के वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर हुयी है। 1993-94 में इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात से 34.9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। योजनाकाल में पजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या में अत्यन्त तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में 1951 कुल पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 16 हजार थी। इनकी पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या दिसम्बर 1991 बढ़ा कर 20.8 लाख हो गयी। इनकी संख्या में तीव्र का क्रम बना है। दिसम्बर 1996-97 के अन्त तक पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या दिसम्बर 1991 तक बढ़कर 20.0 लाख हो गयी। आठवी योजना में उद्योगों के विकेन्द्रित विकास शिल्पकारों की आय वृद्धि, स्वरोजगार अवसरों का सृजन स्थनीय दक्षता एवं ससाधनों का प्रयोग प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादन प्रविधि में सुधार का लक्ष्य रखा गया। आठवी योजना में लघु उद्योगों के क्षेत्रों में प्रस्तावित उक्त प्रयासों से इस क्षेत्र में अधिक सुधार की सम्भावना है। आठवी योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए निजी क्षेत्र को अधिक सक्रिय बनाने का प्रावधान किया गया।

नयी औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है। यह अनुमान किया गया है कि इस औद्योगिक नीति में किये गये प्रावधानों से लघु उद्योग क्षेत्र से अधिक सक्षमता आयेगी। तथा वे अधिक प्रतिस्पर्धा बन

सकेगे। लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध में नयी औद्योगिक नीति में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं —

- 1 अति लघु उद्यमों के लिए विनियोग की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी। इन उद्यमों की स्थापना के लिए स्थानगत रुकावटों को भी हटा दिया गया है। लघु आकारीय उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए समता पूँजी में 24 प्रतिशत तक अन्य औद्योगिक इकाइयों अथवा विदेशी सहयोग की अनुमति दी गयी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से मिलने वाली आर्थिक सहायता को एक ही स्थान पर ऋण की क्रिया विधि के अन्तर्गत लाया गया।
- 2 नयी औद्योगिक नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए ब्याज दर की व्यवस्था की गयी ताकि इन औद्योगिक इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो सके।
- 3 लघु उद्योग क्षेत्र को सस्थागत साख व्यवस्था में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कोटि में रखा गया ताकि इस क्षेत्र के लिए सस्थागत साख का प्रवाह बढ़ाया जा सके।
- 4 नयी औद्योगिक नीति में यह व्यवस्था की गयी है कि सम्पूर्ण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले साख का 40 प्रतिशत भाग अति लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाये।
- 5 लघु आकारीय उद्योगों के उत्पादकता में सुधार के लिए वर्ष 1995 में गुणवत्ता प्रमाणन योजना (Quality Certification Scheme) शुरू की गयी लघु आकारीय उद्यमों को ISO - 9000 या इसी प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
- 6 नयी आर्थिक नीति उदारीकरण एवं वैश्वीकरण पर बल देती है। इसमें प्रतिस्पर्धा और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नयी औद्योगिक नीति 1991 की व्यवस्था के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश अत्यन्त सरल हो गया

है। आबिद हुसैन समिति 1997 (Expert Committee on Small and Medium Enterprises) ने लघु उद्योगों के विकास कार्य से क्षणात्मक उपायों से पृथक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। समिति के सुझावों के अनुसार अप्रैल 1997 से 15 वस्तुओं को लघु उद्योगों की आरक्षित सूची से बाहर कर दिया गया। लघु उद्योगों क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों में से 58 को 30 मार्च 2000 को घोषित 2000-01 की व्यापार नीति में आरक्षित सूची से खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया। इस प्रकार अब लघु उद्योग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाना आवश्यक हो गया।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उधमिता विकास आवश्यक है। एक सीमा के पश्चात् आयवृद्धि की अधिकांश राशि कोष्ठ वस्तुओं के क्रय पर व्यय होती है। इसलिए श्रेष्ठ वस्तुओं को बनाने एवं प्रतिस्पर्धा कर सकने वाले उधमियों के प्रवेश की आवश्यकता है। इन सन्दर्भ में भारत सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवम् यू.एन.डी.पी. द्वारा सम्मिलित रूप से 1997 में Trade Related Entrepreneur Assistance and Development (TREAD) कार्यक्रम आरम्भ किया।

- 7 ग्रामीण औद्योगीकरण को त्वरित करने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसमें प्रति वर्ष 100 ग्रामीण समूह बनाने का मिशन रखा गया है। इसी प्रकार 1999-2000 के बजट में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए साख प्रवाह बढ़ाने एवं बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा देने हेतु एक नवीन साख बीमा योजना शुरू की गयी है।

लघु उद्योगों के विकास पर योजना आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने लघु उद्योगों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करने इनमें निवेश की सीमा में वृद्धि करने इनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, इन उद्योगों के लिए क्रेडिट गारण्टी फंड योजना के वित्तीय आधार में वृद्धि करने तथा गैर लघु उद्योगों को आरक्षित उत्पादों का उत्पादन करने की सशर्त अनुमति प्रदान करने आदि की सस्तुतियों की है, योजना

आयोग के सदस्य एस पी गुप्ता की अध्यक्षता वाले इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट आयोग के उपाध्यक्ष के सी पन्त को 25 मई 2001 को प्रस्तुत की है।

अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में लघु उद्योगों को मौजूदा दो के स्थान पर तीन श्रेणियों अतिलघु, लघु एवं मध्यम, उद्योगों को वर्गीकृत करने को कहा है अति लघु इकाइयों में निवेश की मौजूदा 25 लाख रुपये की सीमा को बरकरार रखते हुए दूसरी (लघु) श्रेणी के निर्यातोन्मुखी उद्योगों (Export Oriented Industries) में प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा को मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की संस्तुति दल ने की है अध्ययन दल के अनुसार गैर निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए यह सीमा 1 करोड़ रुपये ही रहे, लघु उद्योगों की तीसरी नई प्रस्तावित श्रेणी (मध्यम) में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये तक रखने को अध्ययन दल ने कहा है, किन्तु साथ ही यह भी संस्तुति की है कि ऐसी इकाइयों को लघु इकाइयों के लिए उपलब्ध राजकोषीय एवं अन्य नीतिगत समर्थन प्रदान नहीं किये जाएँ।

लघु उद्योगों के लिए प्रारम्भ की गई क्रेडिट गारण्टी योजना के लिए उपलब्ध कोष के आधार को मौजूदा 125 करोड़ रुपये से बढ़ाने तथा लघु उद्योगों लिए 500 करोड़ रुपये का एक विशेष वेचर फण्ड स्थापित करने को दल ने कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में 811 उत्पाद लघु उद्योगों क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हैं। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुपालन के लिए इनमें से 643 उत्पादों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) के तहत अप्रैल 2001 से लाया जा चुका है। दल के अनुसार ऐसे में इन उत्पादों के आरक्षण का कोई अर्थ नहीं रह गया किन्तु लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों को उत्पादन गैर लघु उद्योगों द्वारा किए जाने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान करने की संस्तुति दल ने की है कि वह अपने उत्पादन का कम से कम 30 प्रतिशत भाग निर्यात करे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपनी आवश्यकता का 33 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों क्षेत्र से खरीदा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि

लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिए वर्तमान में लागू कई तरह के नियमों एवं नियमों एवं कानून के चलते 21 वीं सदी में इन उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की तर्ज पर लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत अधिनियम की आवश्यकता अध्ययन दल में अपनी रिपोर्ट में बताई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रुपये)	उपलब्धि (करोड़ रुपये)
1991-92	2,500	3,038
1992-93	2,500	1,913
1993-94	3,500	शून्य
1994-95	4,000	4,843
1995-96	7,000	362
1996-97	5,000	380
1997-98	4,800	902
1999-2000	5,000	5,371
2000-2001	10,000	1,829
2001-2002	10,000	1,869
2002-2003	12,000	5,687

जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों सहायक उद्योगों तथा निर्यातमुखी इकाइयों की संयन्त्र एवं मशीनरी में पूँजी निवेश की सीमा को क्रमशः 60 लाख रुपये एवं 75-75 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। किन्तु 7 फरवरी 1997 को की गई घोषणा के अनुसार ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयों की निवेश की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया था। किन्तु 17 फरवरी 1999 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने लघु

उद्योगों की माँग पर इस सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया। लघु इकाई के रूप में पहचान के लिए सहायक एवं निर्यातानुसूची इकाइयों के लिए अलग से छूट सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी साख नीति में बैंकों से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लघु उद्योगों की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध कोष का 40 प्रतिशत माँग ऐसी लघु इकाइयों को उपलब्ध कराया जाय जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख तक हो। 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक निवेश वाली इकाइयों को लघु उद्योग क्षेत्र के ऋणों का 20 प्रतिशत एवं शेष इकाइयों को 40 प्रतिशत कोष उपलब्ध कराया जाये।

उपलब्ध क्षेत्र के अग्रिमों में लघु क्षेत्र का हिस्सा मार्च 1998 के अन्त में 27% से गिरकर मार्च 1999 के अन्त में 22.2% रह गया। लघु औद्योगिक विकास सगठन (STDO) द्वारा पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1972 में 2.58 लाख से बढ़कर 2000-2001 में 33.79 लाख हो गयी। जिनके अन्तर्गत लगभग 185.64 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। कुल निर्यातों में लघु इकाइयों का हिस्सा 2000-2001 में 35% था। जबकि औद्योगिक क्षेत्र के सकल उत्पादन में इनका हिस्सा 40% था। 2000-2001 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर 8.09% थी जो औद्योगिक क्षेत्र की 4.9% की विकास दर से अधिक थी।

लघु औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार

वर्ष	उत्पादन (चालू कीमतों पर) (करोड़ रुपये)	निर्यात (करोड़ रुपये)	रोजगार (लाख रुपये)
1991-92	1,78,699	13,883	129.80
1998-99	5,27,515	48,979	171.58
1999-2000	5,72,887	54,200	178.50
2000-2001	645,496	59,978	185.64

सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितम्बर 2005 तक के पाँच वर्ष के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के उद्देश्य से एक नई कैबिरल सब्सिडी योजना लागू की है। SIDBI के माध्यम से लागू की गई इस योजना के तत्व प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए लघु उद्योगों को विशेष ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें 12% राशि सब्सिडी की होगी।

प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारण्टी योजना की घोषणा की थी इसके तहत लघु एवं लघुतर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों जो बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी को उपलब्ध कराने में अक्षम हैं। अब अपने ऋणों की गारण्टी क्रेडिट फंड ट्रस्ट से कराकर ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

लघु एवं अति लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीति पैकेज 2000

(Coraprenensire policy Package for small Scale And Tiny Sector 2000)

30 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री न लघु उद्योग क्षेत्र एवं अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं -

- (i) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए उत्पादन शुल्क की 50 लाख रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना।
- (ii) विनिर्दिष्ट (विनिर्दिष्ट) उद्योगों में प्रौद्योगिक सुधार के लिए ऋणों के सबध में 12 प्रतिशत की ऋण सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (Credit linked Capital Subsidy) उपलब्ध कराना।
- (iii) लघु उद्योगों की तीसरी गणना करना जिसमें रुग्णता एवं उसके कारणों को भी शामिल किया जायेगा।
- (iv) उद्योग से सम्बन्धित सेवा एवं व्यवसाय उद्यम में निवेश की मौजूदा 5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना।
- (v) प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में दशवीं योजना के अन्त तक ISO 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75000 रुपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।

- (vi) सम्मिश्र ऋण (Composite Loans) की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना।
- (vii) चालू समेकित आधारभूत विकास योजना को एव क्षेत्रों में लागू करना तथा सारे देश में इसका विस्तार इस प्रकार करना कि 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो तथा 50 प्रतिशत भूखंड अति लघु क्षेत्रों का उपलब्ध हो।

इस व्यापक नीति पैकेज को लागू करने की दिशा में हाल के महीनों में कुछ कदम उठाए गए हैं। आर्थिक समीक्षा 2000-01 में इन कदमों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बाँटा गया है—

1. संपार्श्विक समस्याओं को हल करने एवं प्रौद्योगिकी सुधार को प्रोत्साहित करने की योजनाएँ (Schemes to Address the problem of Collaterals and encourage technology upgradation). लघु क्षेत्र के उद्योगों का संपार्श्विक (Collateral) प्रदान करने में जो कठिनाई होती है उसका समाधान करने के लिए एक साख गारण्टी फंड (स्कीम) की शुरुआत की गई है। जो इन उद्योगों को वाणिज्यिक बैंको, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 25 लाख रुपए तक दिए गए ऋण की गारण्टी देगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक साख गारण्टी ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी में सुधारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 20 सितंबर 2000 को ऋण सम्बद्ध पूँजी सहायकता स्कीम (Credit Linked Capital Subsidy Scheme) को अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके अधीन लघु उद्योगों के कुछ चुनिंदा उपक्षेत्रों में विशिष्ट राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिए गये ऋणों पर 12% की दर से बैंक एडिड पूँजीगत सहायता दी जायेगी। वित्त मंत्री के अनुसार, इस योजना के अधीन अगले पाँच वर्षों में लघु उद्योगों को 5000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जायेगी।

2 उत्पाद शुल्क छूट की सीमा बढ़ाना (Enhancing the Excise Exemption Limit)

1 सितंबर 2000 से लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क छूट की सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3 ऋण सुविधाओं में सुधार (Improving Credit) मिश्रित ऋण स्कीम के अधीन ऋण

सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

4 निवेश सीमा में वृद्धि (Increasing of Investment Limitation) सरकार ने लघु

सेवाओं एवं व्यापार उद्यमों के लिए निवेश की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है

इन सभी उपायों का मूल रूप में लघु-स्तर उद्यमों की सहायता करना है।

किन्तु अभी भी ऋण के रूप में भारतीय लघु औद्योगिक विकास (SIDBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों को और बढ़ाने की जरूरत है ताकि लघु स्तर इकाइयों की अचल एवं चल पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें। इस बात की यह आवश्यकता है कि निरीक्षण एवं अन्य विनियामक कानून (Regulatory Laws) जो लघु क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को अनुचित रूप से परेशान करते हैं। तेजी से हटाए जाएं। एक अधिक स्वतंत्र वातावरण के साथ यदि उधार एवं आधुनिक आलम्ब उपलब्ध कराया जाय, तो इससे लघु क्षेत्र का विकास त्वरित हो सकता है।

पिछले चार दशकों में लघु उद्योगों की संस्था में आशातीत वृद्धि हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है —

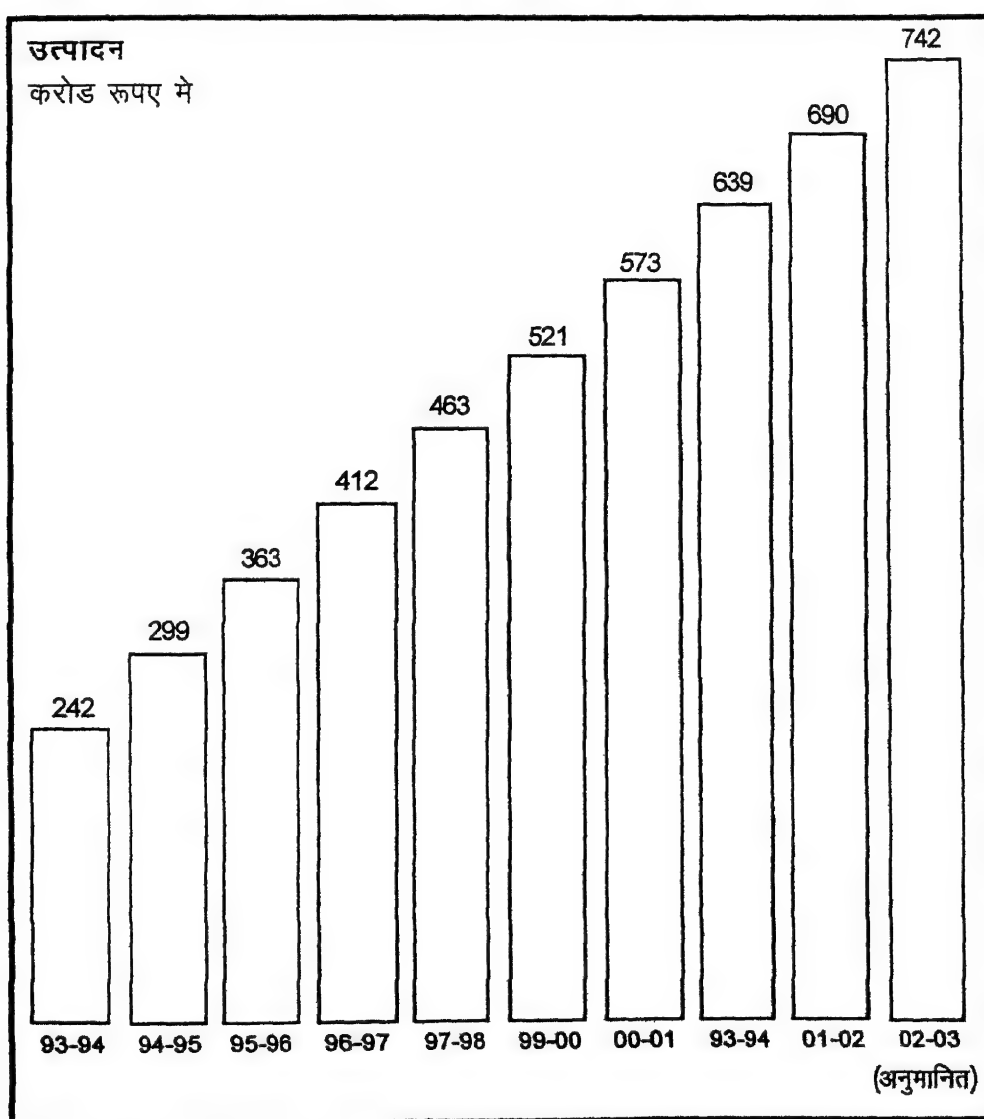
वर्ष	लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या
1960-61	36 हजार
1974-75	49 हजार
2000-01	3,312 हजार
2001-02	3,442 हजार
2002-03	3,572 हजार

2002-03 में लघु उद्योगों ने 7,42,021 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तु का उत्पादन किया और इस वर्ष में इन उद्योगों में 19965 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था।

इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

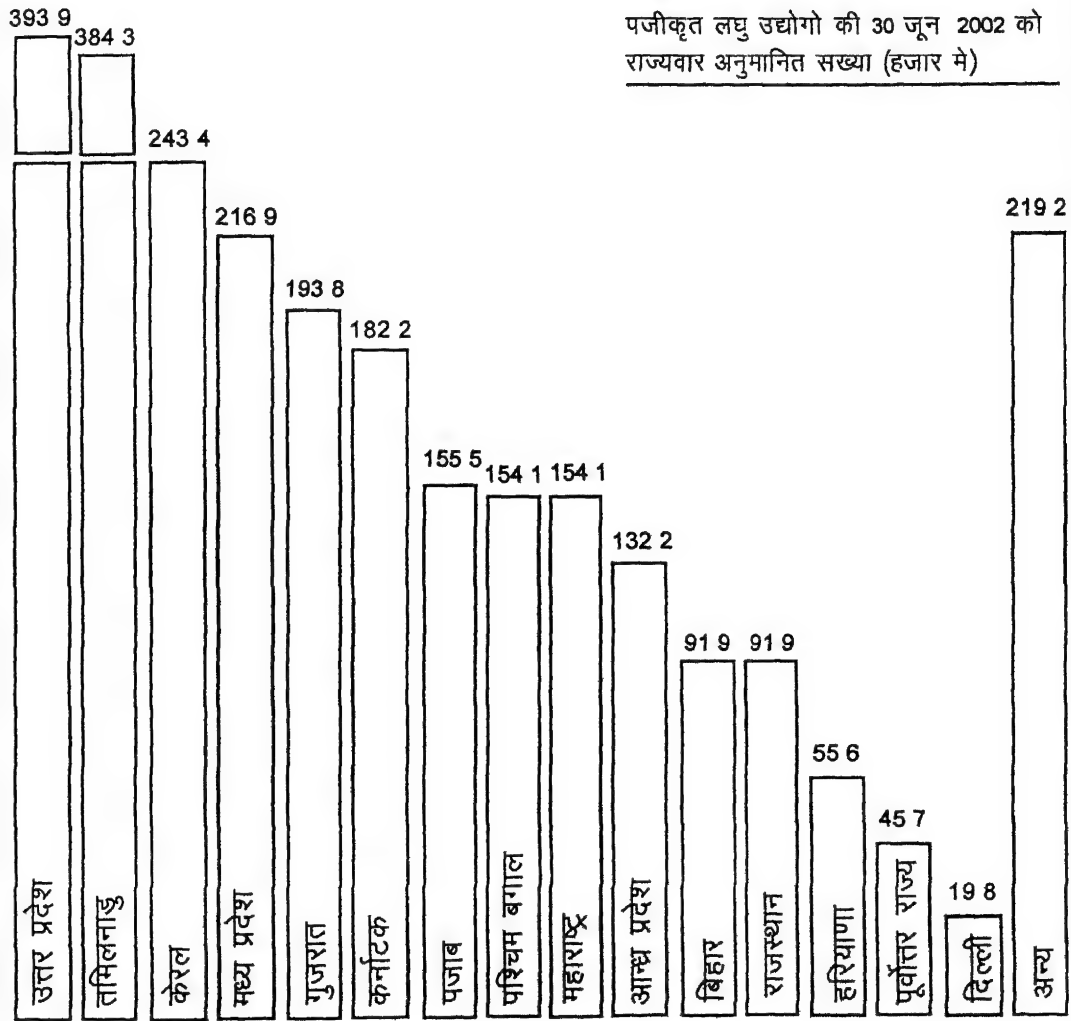
लघु उद्योगों का कारोबार

लघु उद्योगों का वार्षिक उत्पादन (चालू मूल्यों पर)



लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति

पंजीकृत लघु उद्योगों की 30 जून 2002 को
राज्यवार अनुमानित संख्या (हजार में)



लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए निवेश का एक प्रमुख आदान है, इसलिए इस क्षेत्र के बैंको से प्राथमिकता क्षेत्र के उधार में रखा गया है। लघु उद्योग क्षेत्र को व्यापारिक बैंको द्वारा कार्यकारी पूजी प्रदान की जाती है और राज्य वित्त निगम इस क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण उपलब्ध कराते है। छोटे लघु उद्योगो (अति लघु) क्षेत्र का मिश्र ऋणो के रूप में इसी एजेसी से सर्वाधिक ऋण और कार्यकारी पूजी दोनों ही मिलते है। इन सस्थानो की पुनर्वित्त व्यवस्था सिडबी द्वारा की जाती है। लघु उद्योगो क्षेत्रो को ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है

- (i) अति लघु इकाइयो के लिए ऋण अलग से निर्धारित करना ,
- (ii) 5 लाख रु तक के बंधक—मुक्त ऋण (पात्र मामलो में 15 लाख रु तक) ,
- (iii) मिश्र ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख करना ,
- (iv) 25 लाख रुपये तक के बंधक—मुक्त ऋणो की गारंटी के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करना।

लघु उद्योग क्षेत्रो से होने वाले निर्यात को भारत की निर्यात संवर्द्धन रणनीति में बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, इसमें निर्यात प्रक्रियाओ का सरलीकरण शामिल है, और यह अपनी निर्यात आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए लघु क्षेत्र को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी देती है। लघु उद्योगो द्वारा अपने उत्पादो के निर्यात के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई है

- (क) लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादो को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियो में प्रदर्शित किया जाता है और इस सबध में किया गया खर्च सरकार वहन करती है ;
- (ख) लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माता—निर्यातको को एक्सपोर्ट हाउस/ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस/सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के रूप में मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष महत्व दिया जाता है ,
- (ग) लघु उद्योगो इकाइयों को निर्यात संवर्द्धन पूजीगत माल के फायदे उठाये जाने

मिक्सचर, डाईज कोल्ड्स के आयात के लिए पूर्ण लागत बीमा, भाडा (सी आई एफ) मूल्य के प्रतिबधित 20 प्रतिशत के बजाय, पूर्ण लाइसेंस मूल्य की अनुमति दी गई है, लघु उद्योग निर्यातको को नवीनतम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निवेश की सीमा एक करोड रुपये बनी रही। लघु उद्योग मंत्रालय ने उच्च तकनीक और निर्यातोन्मुख उद्योगों की ऐसी विशेष सूची निकाली है जिन्हे प्रतिस्पर्धात्मक बढत बनाए रखने के लिए उचित प्रोद्योगिक उन्नयन में मदद के लिए उनकी निवेश सीमा बढाकर पाच करोड रुपये की जा रही है। लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए उत्पादन शुल्क में छूट की सीमा 50 लाख रुपये से बढाकर एक करोड रुपये कर दी गई है।

ऋण गारंटी योजना के तहत पात्रता की सीमा में भी संशोधन किया गया है। यह सीमा 25 लाख रुपये से घटाकर दस लाख रुपये कर दी गई है। एकीकृत ढाचागत विकास योजना अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ देश के सभी क्षेत्रों पर लागू कर दी गई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निरंतर पूल में उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल क्लस्टर विकास के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए किया जा रहा है। लघु उद्योग विकास संगठन ने एस एस आई एम डी ए योजना शुरू की है, जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन गतिविधियों के विरोध शुरू करने और बार कोडिंग अपनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की योजना जैसी है।

आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया और विश्व संगठन के आगमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तनों ने लघु उद्योग तथा अति लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त 2000 में एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी। इस नीतिगत पैकेज का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाना और देश में और विदेशों में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाना है। पैकेज में आसान ऋण की उपलब्धता, बिना गिरवी रखे 25 लाख रुपये तक के ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।

2002-03 के केन्द्रीय बजट की विशेषताएँ .

- (i) लघु उद्योग क्रेडिट कार्ययोजना की घोषणा।
- (ii) छोटी नवीनताओं के लिए सूक्ष्म वेच पूजी निधि स्थापना का प्रस्ताव।
- (iii) निटवेयर, कुछ खेतहर यंत्रों, मोटर गाड़ी के पुर्जों, कुछ रसायनों और दवाओं आदि जैसी 50 से अधिक मदों का आरक्षण समाप्त करना।
- (iv) पाँच वर्षों की अवधि के लिए लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की 'आमदनी पर कर से पूरी छूट'।
- (v) आयकर, अधिनियम की धारा 54 ई सी के तहत पूंजीगत लाभों में छूट 'सिडबी' द्वारा जारी बांडों में निवेश की जाने वाली राशि पर दी जाएगी।

लघु उद्योग क्षेत्र ने पिछले 50 वर्षों में देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमुख स्थान बना लिया है। इसने सकल घरेलू उत्पाद की समग्र अभिवृद्धि के साथ-साथ रोजगार और निर्यात वृद्धि की दृष्टि से भी योगदान दिया है। 1996-98 से 2001-02 तक की इस क्षेत्र की प्रगति निम्न सारणी में दी गई है

लघु उद्योग क्षेत्र का कार्य निष्पादन

वर्ष	इकाइयों की संख्या (लाख रु में)			उत्पादन (करोड़ रु में)		रोजगार (लाखों में)	निर्यात (करोड़ रु में) चालू मूल्यों पर
	पजीकृत	गैरपजीकृत	कुल	चालू मूल्यों पर	स्थिर मूल्यों पर 1993-94		
1996-97	21 53	6 50	28 03 (5 46)	4,11,858 (13 57)	3,29,935 (11 32)	160 00 (4 24)	39,248 (7 61)
1997-98	22 82	6 62	29 44 (5 03)	4,62,641 (12 33)	3,57,296 (8 43)	167 20 (4 5)	44,442 (13 23)
1998-99	24 06	6 74	30 80 (4 62)	5,20,650 (12 54)	3,85,296 (7 70)	171 58 (2 62)	48,979 (10 21)
1999-2000	25 26	6 86	32 12 (4 29)	5,72,887 (10 03)	4,16,736 (8 16)	178 50 (4 03)	54,200 (10 66)
2000-01	26 72	6 98	33 70 (4 92)	6,39,024 (11 54)	4,51,033 (8 23)	185 64 (4 00)	59,978 (10 66)
2001-02	27 53	7 11	34 64 (4 65)	6,90,522 (8 06)	4,77,870 (5 95)	192 23 (3 55)	N A

टिप्पणी कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष में तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में समग्र औद्योगिक क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर से अधिक ही दर बनी हुई है। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में इसका काफी योगदान है। औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान लगभग 40 प्रतिशत और प्रत्यक्ष निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत है। यह क्षेत्र नई सहस्राब्दी में विकास के माध्यम के रूप में उभरा है। बदले हुए उदारीकृत और प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं जिनमें चुने हुए क्षेत्रों में निवेश सीमा में परिवर्तन करना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता, विदेशी भागीदारी की सुविधा, विकास केंद्रों की स्थापना, क्लस्टरों का विकास, निर्यात सवर्द्धन,

गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन, विश्व सगठन समझौते के निहितार्थों के बारे में लघु उद्योग इकाइयों को सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय क्रमांकन मानकों के इस्तेमाल बार कोडिंग आदि शामिल हैं।

आर्थिक समीक्षा 2002-03 के अनुसार घरेलू मदी के बाद भी लघु क्षेत्र का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2002-03 में सतोषजनक रहा है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में लघु क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की संख्या के 35 72 लाख होने का अनुमान है। जबकि गत वर्ष यह संख्या 34 42 लाख थी। चालू मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2002-03 में लघु क्षेत्र के समग्र उत्पादन का मूल्य 7,42,021 करोड़ रु० आकलित किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 7 5% की वृद्धि दर्शित करता है। स्थिर कीमतों पर भी वित्तीय वर्ष 2002-03 में 7 5% की भी वृद्धि आकलित की गई है। वर्तमान में लघु क्षेत्र में 199 95 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। जो वित्तीय वर्ष 2001-02 की तुलना में 3 9% की वृद्धि दर्शित करता है।

देश के समग्र निर्यात में लघु क्षेत्र की भागीदारी एक तिहाई से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में लघु क्षेत्र के उद्यमियों की तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी।

लघु उद्योगों के लिए सुधारों द्वारा चुनौती

नवीन औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप लघु उद्योगों के सक्षम अपने आप को बनाए रखने की चुनौती उत्पन्न हो गई है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो आयात खोल दिए गए हैं व दूसरी ओर विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में आकर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इन दोनों का परिणाम यह है कि भारत में अब उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी की वस्तु कम मूल्य पर मिलने लगी है, जिससे भारतीय लघु उद्योगों की स्थिति खराब होने लगी है। अनेक उद्योगों ने या तो व्यापार को बन्द कर दिया है या फिर नाम मात्र का व्यापार चल रहा है अर्थात् उत्पादन की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

भारत में 20 उद्योग ऐसे हैं जहाँ नवीन आर्थिक नीति के लागू होने के बाद की देशी कंपनियों का असर तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान लीवर समूह ने प्रतिस्पर्धी टाटा आयल मिल्स सहित कई कंपनियों को अपने समूह में ले लिया है। इसी प्रकार आइसक्रीम बाजार के सहारे 'वाल्स' को जमाया जा रहा है क्योंकि वाल्स ने भारतीय क्वालिटी आइसक्रीम को खरीद लिया है।

रेफ्रिजरेटर उद्योग में भारत की केल्विनेटर व गोदरेज कंपनियों पर क्रमशः अमरीका का वर्ल्डपूल व जी ई की पकड़ है। टेलीविजन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहार आई हुई है। जैसे सोनी, अकाई, नेशनल, पैनासोनिक। वैक्यूम क्लीनर का बाजार अब पूरे तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पकड़ में है। सॉफ्ट ड्रिग उद्योग पर अब कोका कोला का आधिपत्य सा है जो अमरीका की है। कई भारतीय कंपनियों ने अपने व्यवसाय उन्हें बेच दिया है।

संक्षेप में भारत में 20 हजार करोड़ रुपये की टिकाऊ वस्तुओं के उपभोक्ता बाजार में भी अशुभ संकेत मिलना प्रारम्भ हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र की भारतीय कंपनियों का हिस्सा घटकर 35% रह गया है। विदेशी कंपनियों ने रंगीन टेलीविजन, फ्रिज, वाशिंग मशीन और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों में अपना हिस्सा 65 फीसदी बढ़ा लिया है।

बजाज ऑटो के अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक राहुल बजाज और आर पी जी इन्टरप्राइजेज के उपाध्यक्ष सजीव गोयनका ने बताया है कि विदेशी कंपनियाँ अपेक्षाकृत कम कीमत अदाकर भारतीय बाजार पर कब्जा जमा रही हैं। इनका कहना है कि उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध कौशल, निर्यात वृद्धि आदि का जो आकलन किया गया था, वे खरे नहीं उतरे हैं बल्कि इससे कई क्षेत्रों में स्वदेशी उपकरण नष्ट हो गए हैं और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों ने बिना ज्यादा निवेश के ही बाजार पर सम्पूर्ण कब्जा कर लिया है।

स्पष्ट है कि भारतीय उद्योग विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के स्थान पर उनके सामने हथियार डार रहे हैं और अपने उद्योगों को उन्हें बेच रहे हैं जैसे हल्के पेय थम्स अप

माजा, गोल्ड स्पोट, लिम्का भारतीय उद्योगपतियों ने 120 करोड़ रुपये में कोका कोला को बेच दिया। अब बिसलरी मिनरल वाटर को भी बेजा जा रहा है। यह प्रक्रिया देश के लिए हानि कारक है। ऐसा अनुमान है कि अबतक लगभग 5 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं।

यदि भारतीय लघु उद्योग अपनी वस्तु की क्वालिटी में सुधार नहीं कर पायेगा और मूल्यों को भी प्रतियोगी नहीं बना पायेगा तो वह दिन दूर नहीं जबकि लघु उद्योग पूर्णतया बन्द हो जाये। अतः लघु उद्योगों को अपने आप को जीवित रखने के लिए वस्तु की क्वालिटी में सुधार लाना होगा एवं मूल्य प्रतियोगी रखने होंगे।

તૃતીય અધ્યાય

भारत वर्ष में लघु उद्योगों के वित्तीयन का स्रोत

लघु उद्योगों को पूँजी तथा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। राज्य सरकारों ने राज्य उद्योग सहायता अधिनियमों के अन्तर्गत इन उद्योगों के लिए ऋण की सुविधाओं को काफी बढ़ा दिया है। अतः इन उद्योगों को राज्य सरकारों से अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तों पर और आसानी से ऋण उपलब्ध होने लगा है। सरकार के अतिरिक्त राज्य वित्त निगमों, भारतीय ऋण समितियों आदि की ओर से भी इन उद्योगों को पहले से कहीं अधिक मात्रा में ऋण सुविधायें उपलब्ध होने लगी हैं।

लघु उद्योगों का वित्तीयन

(Finance for Small-Scale Industries)

उत्पादन, वितरण तथा विकास के क्षेत्र में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। जिस प्रकार रक्त के अभाव में मानव शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती ठीक उसी प्रकार वित्त के अभाव में औद्योगिक विकास संभव नहीं हो सकता इसलिये इसे उद्योगों के 'संदर्भ' में 'जीवनरूपी रक्त' की संज्ञा दी गयी है। वित्त उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है।

स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में वित्त की समस्या थी जो देश के औद्योगिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती थी परन्तु स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने पर्याप्त पूँजी आधार वाली विशिष्ट वित्तीयन संस्थाओं के एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जो देश के विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग भी शामिल है।

एक नवोदित अर्थव्यवस्था के वित्तीय ढाँचे के सहारे की आवश्यकता होती है, जो कि विकास की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में वित्तीयन की प्रक्रिया में, व्यापारिक बैंकों के महत्वपूर्ण भूमिका है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तथा विकास के

विभिन्न स्तरों पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने विभिन्न तरीकों तथा साधन विकसित किये, विभिन्न संगठनों की स्थापना की, परम्परागत व्यापारिक बैंकिंग की नीति का परित्याग कर और उन्हें विकास बैंकों के रूप में विकसित किया।

उन व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्यमियों को वित्त समग्रता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, मात्र उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ राज्य वित्तीय निगम या उसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं के मध्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध है। कारखाना भवन के निर्माण के लिये, यंत्र और औजारों को क्रय करने के लिये तथा कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साख् स्वीकृत किया जाता है। विस्तार, जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण हेतु भी ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। बैंक एवं अन्य संस्थाएँ निर्यात की भी सुविधा प्रदान करती हैं। जो लघु उद्योगों के लिये होती है। संस्थागत सहायता और आर्थिक घटक उद्यमिता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। जिससे सुदृढ़ आर्थिक विकास संभव हो पाता है।

Central Govt

(1) SSI Boards (2) SIDO (3) SISI's

(4) PPDC's (5) RTC's (6) CFTI's

(7) EDI's (8) NSIC's (9) SIDBI

State Govt

(1) DI's (2) DIC's (3) SFC's

(4) SSIDC's (5) TCO's

SSI's

अन्य

(1) औद्योगिक संगठन

(2) गैर-सरकारी संगठन

औद्योगिक वित्त के प्रकार — क्रियाकलापों की प्रकृति के आधार पर यह तीन प्रकार की होती है।

1 अल्पकालीन वित्त — अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत उन फण्डों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिये किया जाता है। अल्पकालीन वित्त

की आवश्यकता अधिकांशतः सामयिक या अस्थिर कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये होती है।

बैंको से उधार लेना अल्पकालीन वित्त का सबसे प्रमुख तथा प्रचलित साधन है। व्यापारिक साख, किस्त साख और ग्राहको द्वारा अग्रिम आदि अल्पकालीन वित्त के अन्य रूप हैं।

2 मध्यकालीन वित्त— जो वित्त एक वर्ष से अधिक समय के लिये परन्तु पाँच वर्ष से कम समय के लिये प्रदान किये जाते हैं, वे मध्यकालीन वित्त के श्रेणी में आते हैं। स्थायी कार्यशील पूँजी, छोटे स्तर पर किये जाने वाले विस्तार, प्रतिस्थापन, नवीनीकरण आदि उद्देश्यों के लिये मध्यकालीन वित्त सहायक सिद्ध होते हैं।

मध्यकालीन वित्त निम्न साधनों से एकत्रित किया जा सकता है—

- (क) अशो के निर्गमन द्वारा
- (ख) ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा
- (ग) बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर
- (घ) लाभों में से धन संचित करके

3 दीर्घकालीन वित्त—5 वर्ष से अधिक समयावधि के लिये प्रदत्त की गयी वित्त को हम दीर्घकालीन वित्त की श्रेणी में रखते हैं। अचल संपत्तियों को क्रय करने के लिये, नये व्यापार प्रारंभ करने के लिये, वर्तमान व्यापार में विस्तार करने के लिये, यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिये दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है।

दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के निम्न प्रमुख साधन हैं—

- (क) अशो के निर्गमन द्वारा
- (ख) ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा
- (ग) वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर
- (घ) लाभों में से धन संचित करके

लघु उद्योगों की एक विशेष बात यह होती है कि इनकी कुल सपत्तियों में उद्यमियों के व्यक्तिगत कोष एक बड़ी मात्रा में होते हैं। लघु उद्यमियों के स्वामी सामूहिक अर्थात् बड़े उद्योगों के स्वामियों के अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वहन करते हैं। व्यापारिक बैंक, विशिष्ट संस्थाएँ जैसे— State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra, Gujarat Industrial Investment Corporation तथा सहकारी बैंक आदि ऐसे साधन हैं जो इन उद्योगों की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। स्वदेशी बैंकर तथा साहूकार द्वारा भी पूँजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भी ऋण प्रदान करते हैं। स्थायी पूँजी आवश्यकता की पूर्ति State Government, State Financial Corporation, National Small Industries Corporation, State Small Industries Corporation, State Industrial Development Corporation तथा अन्य व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है।

वे साधन जिनसे एक लघु उद्योग कोष के व्यवस्था करता है, उससे अधिक चिट्ठे में प्रदर्शित किये जाते हैं। सामान्यतः ये साधन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हैं—

A आंतरिक	B वाह्य
I <u>चुक्ता पूँजी</u>	IV <u>उधार लेना</u>
a साधारण अंश	a बैंक से
b पूर्वाधिकार अंश	b सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं से
c हरण किये गये अंश	c विशिष्ट संस्थाओं जैसे IDBI, IFCI, ICICI
d अन्य	d अन्य
II <u>संचित कोष</u>	V <u>व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू दायित्व</u>
a पूँजी संचय	a विविध लेनदान
b विकास छूट संचय	b अन्य
c अन्य	

III प्रावधान

a करारोपण

b ह्रास

VI विविध

ये सभी वित्त के साधन लघु उद्योगों के लिये उपलब्ध नहीं हैं। वित्त की उपलब्धता उद्योगों के स्तर, लक्षण समयावधि आदि पर निर्भर करती है। कोष, जो लघु उद्योग निर्माण करती है, कंपनी के लक्षण पर निर्भर करती है— चाहे वह उद्योग प्राइवेट लिमिटेड हो या स्वामित्व सबधी हो।

लघु उद्योगों द्वारा निर्माण किये गये कोष उत्पादक गतिविधियों तथा उन उद्देश्यों के लिये जिनके लिये इन फण्डों को प्रयोग में लाया जाता है पर निर्भर करते हैं।

a. सकल चल संपत्ति— भूमि, भूत, मशीनरी इन सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से ऋण लेकर या वित्तीय संस्थाओं जिसमें बैंक भी शामिल हैं से सामयिक ऋण लेकर की जाती है।

b. कार्यरत पूँजी— कच्चा माल, तैयार माल, चालू कार्य, संचालन व्यय (मजदूरी, वेतन, रोशनी तथा अन्य खर्च) — इन सभी की पूर्ति व्यापारिक बैंक द्वारा माराक्रांति साख या प्रतिज्ञा ऋण के रूप में की जाती है।

c. फण्ड की आवश्यकता (i) संपत्ति को क्रय करने हेतु (ii) विनियोग करने के लिये (iii) देनदारों को भुगतान करने हेतु होती है।

संस्थागत अवलंब ढाँचा— भारत सरकार द्वारा गणित लघु उद्योग बोर्ड लघु उद्योगों के सदर्भ में सभी प्रकार के मुद्दों पर सलाह देने की एक शीर्ष संस्था है। इसका गठन सन् 1954 में समन्वय स्थापित करने तथा इस क्षेत्र को विकसित करने के लिये अंतर-संस्थागत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। 1997 तक उद्योग मंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करते थे परंतु इसके बाद यह बोर्ड, जिसमें राज्य स्तरीय उद्योग मंत्री, चयनित सांसद, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, वित्तीय संस्थाओं के मुखिया, और लघु उद्योग के क्षेत्र

के विशिष्ट सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हैं।

योजना का निर्माण करने, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये पर्याप्त योजनाओं तथा स्कीमों को आरम्भ के लिये Department of SSI और Agra & Rural Industries का गठन भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत की गयी। इन विभागों का कार्य के अंतर्गत ऐसी सस्थाओं का तंत्र बनाते हैं। जो विविध प्रकार के कार्य कर सकें जैसे— प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएँ, विपणन सहायता आदि। केन्द्र/राज्य सरकार, विभिन्न एजेंसी तथा देश में फैले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ऐसे क्रियाकलापों में सहायता की जाती है।

भारत सरकार की फोर्ड फाउण्डेशन टीम की सिफारिशों के आधार पर 1954 में लघु उद्योगों के विकास कमिशनर के कार्यालय की स्थापना की गयी जिसे लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) के नाम से जाना जाता है। 1991 से SIDO Department of SSI और Agra & Rural Industries के अंतर्गत कार्य कर रही है। केन्द्रीय सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने में तथा देश में लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाने में SIDO की महत्वपूर्ण भूमिका है। SIDO का प्रमुख कार्य सभी भारतीय पालिसियों और योजनाओं को प्रस्तुत करना। राज्य सरकार की पालिसियों और योजनाओं को समन्वित करना, केन्द्र और राज्य मंत्री, योजना आयोग, रिजर्व बैंक, वित्तीय सस्थाओं में संपर्क स्थापित करना है। SIDO सनद्धित सस्थाओं के माध्यम से व्यापक पैमाने पर विस्तार की सुविधाएँ प्रदान करता है और सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का संचालन करना है।

राज्य स्तर पर Commisioner/Director of Industries लघु माध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित तथा विकास प्रदान करने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। लघु उद्योगों के क्षेत्र में केन्द्रीय पालिसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है परन्तु प्रत्येक राज्य की अपनी स्वयं की पॉलिसी होती है। राज्य सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों पर भी नजर रखती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्तीय कारपोरेशन, राज्य लघु उद्योग विकास कारपोरेशन, तकनीकी परामर्श सस्थाएँ राज्य स्तर पर कार्य करती हैं जो लघु उद्योगों के

विकास और प्रोत्साहन में सहायता प्रदान कर रही है। अन्य क्षेत्रीय स्तर की एजेंसियाँ निम्न हैं। जो लघु उद्योगों को सहायता प्रदान कर रही हैं, वे हैं State Infrastructure Development Corporation, State Co-operative Banks, Regional Rural Banks, State Department of Industries, State Transport Cor, Agra Industries Cor, Handloom & Handicrafts Co आदि। मानव संसाधन विकास के लिये SIDO से Associated विशिष्ट संस्थाओं का एक जाल है।

स्तर पर गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भी इन उद्योगों के विकास में सहायनीय योगदान किया जा रहा है।

औद्योगिक संगठन लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं और उद्योगों से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिये, उन पर चर्चा करने के लिये एक संघ प्रदान करते हैं। हाल की सरकारी नीतियों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि औद्योगिक संगठन औद्योगिकी विपणन और अन्य सेवाओं Schemes of Assistance (सहायता की परियोजना)– विस्तृत रूप में SFC, SIDC और व्यापारिक बैंकों द्वारा निम्न सहायता प्रदान की जाती है।

- लघु तथा माध्यम वर्ग की नयी परियोजनाओं का वित्तीयन
- लघु तथा मध्यम वर्ग के आधुनिकीकरण का वित्तीयन
- लघु तथा माध्यम वर्ग के पुनर्स्थापना का वित्तीयन
- पूँजी साधन के आयात का वित्तीयन

और अन्य व्यापारिक बैंकों द्वारा वित्तीय कठिनाई की समस्या को ध्यान में रखते हुये यह उधार लेने वाले व्यक्तियों के हित में होगा कि वह इस बात से अवगत हो कि IDBI द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किस सीमा तक पुनः वित्तीयन सहायता में वृद्धि की गयी है। पुनः सहायता में की गयी वृद्धि निम्नलिखित है –

• लघु ईकाई	
(1) SFC's & SIDC's	85
(ii) व्यापारिक बैंक	60
• मध्यम श्रेणी की ईकाई	
(1) SFC's & SIDC's	75
(ii) व्यापारिक बैंक	60
• SIDC's द्वारा दी जाने वाली विदेशी मुद्रा ऋण	100

लघु ईकाईयो को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय सहायता — लघु उद्योगों को ऋण रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु ईकाईयो के लिये ब्याज की 12.5 प्रतिशत वार्षिक है। गैर-पिछड़े क्षेत्रों में स्थित ईकाईयो के लिये 25 लाख तक के लिये ब्याज की दर 13.5 प्रतिशत वार्षिक है तथा 25 लाख से ऊपर की रकम के लिये ब्याज की दर 14 प्रतिशत वार्षिक है।

लघु क्षेत्रों की ईकाईयो पर 5 लाख रुपये तक गैर-सुपुर्दगी भार लगाया जाता है। अन्य नकद ऋणों पर उसके स्वीकृत होने के 12 माह के बाद 1 प्रतिशत की दर से सुपुर्दगी भार लगाया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों के श्रेणी A में आने वाली ईकाईयो पर सुपुर्दगी भार में 50 प्रतिशत रियायत प्रदान की जाती है।

लघु उद्योगों को प्रदान की जाने वाली साख सहायता— लघु क्षेत्र के कारखानों द्वारा आवश्यक कार्यशील साख तथा पूँजी व्यापारिक बैंको, सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्राप्त की जाती है, एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जो मुख्यतया कार्यशील पूँजी प्रदान करती है। किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीनरी की आपूर्ति करके लघु उद्योगों को सहायता राष्ट्रीय स्तर पर **National Small Industries Corporation** द्वारा

तथा राज्य स्तर पर State Small Industries Development Corporations द्वारा प्रदान की जाती है। लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से SIDBI, NABARD तथा IDBI, बैंको तथा अन्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। बैंको द्वारा लघु क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान की जाने वाली साख को प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान की गयी साख की तरह माना जाता है।

व्यापारिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को विकसित करने में अहम भूमिका रही है। बैंक द्वारा लगातार नयी योजनाओं को विकसित किया जा रहा है ताकि इस तीव्र गति से बढ़ते हुये तथा परिवर्तित होते हुये क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

जैसा कि बहुत बड़ी मात्रा में ईकाइयों को अपने समता कम होने के कारण प्रारम्भिक विनियोजन की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जो कि लघु क्षेत्र की ईकाइयों को वित्तीय सुदृढता प्रदान करने की एक अग्रणी संस्था है, वे स्वयं को समता कर इस उद्देश्य से गठित किया है ताकि नये उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के अंतर्गत नये ईकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

साख सूचीबद्ध व्यापारिक बैंको द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान की गयी Outstanding Advances की सुविधा जो कि June 1991 में 16,590 14 करोड़ थी। मार्च 1999 में बढ़ाकर 48483 करोड़ रुपये कर दी गयी। जबकि क्षेत्रीय बैंको की Outstanding Advances की सुविधा जो कि कलाकार, गांवों तथा हथकरघा उद्योग में प्रदत्त की जाती थी। जो मार्च 1990 में 6125 करोड़ रुपये थी, घटाकर मार्च 1999 में 282 04 करोड़ रुपये कर दी गयी।

रिजर्व बैंक द्वारा वितरण प्रणाली को और विकसित करने के लिये लघु उद्योगों को प्रदान की जाने वाली साख सुविधाओं की प्रक्रिया में उदारता लाने के लिये तथा लघु उद्योगों से संबंधित अन्य बातों को विचार करने के लिये S.L.Kapoor की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय

समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा अब तक प्रदान की गयी 126 सिफारिशों में से रिजर्व बैंक द्वारा तात्कालिक क्रियान्वयन किया गया।

रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गयी कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

- (a) इन कोषों का अनुदान करने के लिये शाखा प्रबन्धकों को और अधिक अधिकार प्रदान करना (आबटन सीमा के परे अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करने वाले कोष जोकि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाये गये हों)
- (b) आवेदन प्रक्रिया और सरल बनाना।
- (c) बैंकों को अपनी साख आवश्यकताओं के मानकों को निर्धारण करने की स्वतंत्रता।
- (d) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विशिष्ट शाखाओं का प्रकार।
- (e) मिश्रित ऋण की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देना।
- (f) लोक अदालत की मदद द्वारा वसूली प्रणाली को मजबूत करना।
- (g) औद्योगिक रूप से अविकसित प्रदेशों की साख संबंधी आवश्यकताओं की ओर बैंक द्वारा अधिक ध्यान देना।
- (h) शाखा प्रबन्धकों को छोटी परियोजनाओं का अनुमान लगाने के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों को आयोजन।
- (i) ग्राहक शिकायत प्रणाली में पारदर्शिता लाना और शिकायतों को समाधान करने की प्रक्रिया को सरल करना।

राज्य वित्तीय निगम का लघु उद्योगों के विकास में उच्च प्राथमिकता रही है। राज्य वित्तीय निगम द्वारा सहायता आवंटित करते समय लघु उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी गयी है। 1998-99 के दौरान 73.2 प्रतिशत से अधिक की सहायता को राज्य वित्तीय निगम द्वारा बढ़ा दिया गया है।

बैंकों द्वारा लघु उद्यम के क्षेत्र में निम्नलिखित माध्यमों द्वारा प्रदान की जाती है।

(1) उदारवादी योजना—July 1955 में Imperial Bank of India का State Bank of India द्वारा अधिग्रहण करने के ठीक बाद ही इस बैंक द्वारा लघु उद्योगों का वित्तीयन करने के उद्देश्य से उदारवादी योजना अस्तित्व में लायी गयी। इस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार लघु उद्योगों के वित्तीयन के लिए आवश्यकता पर आधारित सकल्पना को प्रस्तुत किया गया जो कि धारणा से भिन्न थी। एक बार ईकाई की कार्यक्षमता सिद्ध हो जाने पर बैंक द्वारा उनकी उचित साख आवश्यकताओं को पूरा करने में तत्परता दिखायी गयी।

2 योजना— तकनीकी क्षेत्र के उद्यमियों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1967 में एक अनोखी परियोजना अस्तित्व में आई जिसे योजना कहा गया। इसके अंतर्गत न्यूनतम समता योगदान के बिना ही ऐसे लोगों को 100 प्रतिशत वित्त उपलब्ध कराया गया जो योगदान करने में असमर्थ थे। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो तकनीकी रूप से शिक्षित थे। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो तकनीकी शिक्षा तथा बुद्धि के धनी थे परन्तु उन्होंने कोई तकनीकी शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। बाद में इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों से सबध रखने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया जैसे— प्रबंध विशेषज्ञ, Chartered Accountant लागत विश्लेषक इत्यादि।

3 कारीगरों तथा शिल्पियों के लिए वित्तीय सुविधा— प्रारम्भिक दौर में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधुनिक क्षेत्र में स्थिर लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक का ध्यान ग्रामीण उद्योगों तथा कारीगरों के वित्तीयन की तरफ भी गया। ग्रामीण उद्योगों तथा शिल्पकला को पोषित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1962 से Rural Industries Project को अस्तित्व में लाया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य असमानता को दूर किया जा सके। 1969 में बैंक द्वारा एक विशेष योजना लाई गई जिसमें ग्रामीण औद्योगिक परियोजना में लगे कारीगरों और शिल्पियों को सरकार की सहायता से 7500 रु० तक की उदार साख सहायता दी गयी। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी—

- a इसकी शर्तों और परिस्थितियों में सरलता।
- b वित्तीय प्रक्रिया में सरलता तथा वसूली में सरलता।
- c योग्य कारीगरों का चुनाव करने में तथा वसूली में बैंक और सरकार के मध्य समन्वय।

4 रोजगार योजना इस योजना के द्वारा देश में रोजगार की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने 1971 से लघु स्तरीय आर्थिक गतिविधियों का वित्तीयन प्रारम्भ कर दिया गया जिसके अन्तर्गत खादी उद्योग, जूता-चप्पलों का निर्माण, डालिया आदि का निर्माण शामिल है। 5 प्रतिशत वार्षिक की अत्यधिक रियायती दर पर उत्पादन गतिविधियों से संबंधित समाज की कमजोर विभागों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा **Differential Interest Rates Scheme** अस्तित्व में लायी गयी जिससे कि लघु उद्योगों और ग्रामीण शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिला।

ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और बड़ी मात्रा में ग्रामीण कारीगरों तथा शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा 1977 में अपने प्रत्येक स्थानीय मुख्य कार्यालय में ग्रामीण उद्योग विभाग की स्थापना की गयी। ग्रामीण उद्योगों के विकास में लगी एजेंसियों की सहायता से ये विभाग ग्रामीण उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं तथा उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं।

बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों की ओर ध्यान आकर्षित होने के साथ-साथ उन्हें तकनीकी तथा प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गयी। अतः बैंक द्वारा 1973 में ऋणदाताओं को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिये अपने स्थानीय मुख्य कार्यालयों में **Technical Consultancy Cells** की स्थापना की गयी। इस उद्देश्य के लिए बैंक के तकनीकी तथा प्रबंधकीय योग्यता रखने वाले अधिकारियों द्वारा योग्य व्यक्तियों को चयनित किया जाता है। इन अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर एक से दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये बैंक ने प्रतिदिन व्यापारिक संस्थाओं तथा औद्योगिक परामर्श सगठनों से

समझौता किया है। इन विषयों के अंतर्गत वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय प्रबंध, उत्पादन नियोजन तथा नियंत्रण, बजटरी नियंत्रण, लागत तथा विपणन इत्यादि को शामिल किया गया है।

बैंक द्वारा कराये गये सर्वेक्षणों ने परामर्श विभाग की आवश्यकता को उजागर किया है। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा व केवल जरूरतमंद उद्यमियों को परामर्श दिया जाता है। बल्कि बैंक द्वारा लघु उद्यम से संबंधित तथ्यों जैसे लघु उद्यम प्रबंध (जिसमें Accounting System का रख-रखाव इत्यादि शामिल हैं) आदि विषयों पर बुक्लेट भी प्रकाशित किया जाता है।

प्रोत्साहन तथा विकास प्रदान करने वाली गतिविधियाँ – वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त SIDBI विकास तथा लघु उद्योगों को सुदृढ़ करने संबंधी सेवाएँ भी लघु उद्यम क्षेत्र को प्रदान करता है। बैंक द्वारा उठाये गये ऐसे कदम एक ओर तो लघु क्षेत्र की ईकाइयों के संगठन को और सुदृढ़ बनाते हैं तो दूसरी ओर ये रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाते हैं।

(1) उद्यम प्रोत्साहन

- a. ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम
 - b. महिला विकास निधि
 - c. उद्यमिता विकास कार्यक्रम
 - d. प्रचार तंत्र
- (2) मानव संसाधन विकास
- (3) तकनीकी सुधार
- (4) वातावरण तथा गुण प्रबंध
- (5) सूचना प्रसार

वित्त सम्बन्धी कठिनाई इन छोटे-2 उद्योगों की एक प्रमुख समस्या रही है।

अतएव वित्त सम्बन्धी सुविधाएँ बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशाओं में कार्य किया जा रहा है। लघु

उद्योगो उपलब्ध वित्तीय साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

A. गैर सस्थागत स्रोत — (Non Institutional Sources): स्वामित्व पूँजी एवं ऋण पूँजी दोनों ही प्रकार की पूँजी की व्यवस्था व्यक्तिगत साधनों से की जाती है। एकाकी एवं साझेदारी संगठनों में स्वामी अथवा साझेदारी कुछ सीमा तक अपनी निजी पूँजी का विनियोग करते हैं, जिनके द्वारा भूमि एवं मशीनों, आदि के रूप में कुछ स्थिर सम्पत्ति की व्यवस्था की जा सके। प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड रूपी संगठन की दशा में अश-पूँजी जोखिम पूँजी का कार्य करती है। और इसी आधार पर ऋण पूँजी की व्यवस्था की जा सकती है। अतः इसका व्यवसाय के संगठन में विशेष महत्व होता है।

अल्प अवधि के ऋण दर्शनी हुण्डियों के आधार पर दिये जाते हैं जो प्रायः एक माह की होती हैं। अधिक अवधि के ऋण के स्थिर सम्पत्ति की जमानत पर प्रदान किये जाते हैं। साहूकारों एवं महाजनो के अतिरिक्त बिचौलियों व्यापारी लघु उद्योगों को वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं और इस प्रकार उनकी कार्यशील पूँजी की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति इनके द्वारा हो जाती है। माल के विक्रय में भी बिचौलियों व्यापारी पर्याप्त सहायता देते हैं। लघु उद्योगों को व्यक्तिगत सूत्रों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, इसका सही अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस विषय में विश्वस्त सूचनाओं का अभाव है।

फिर भी स्टेट बैंक एवं अन्य वित्तीय सस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों की कार्यशील पूँजी के लिये दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों की अपर्याप्तता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि लघु उद्योगों को प्राप्त होने वाले, महाजनो, साहूकारों, बिचौलियों एवं व्यापारियों का भाग आज भी बहुत अधिक है।

देशी साहूकारों की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न समितियों ने इनके संगठन एवं कार्य-संचालन में उचित परिवर्तन किये जाने के सुझाव समय-समय पर दिये हैं। कुछ बड़े साहूकारों अथवा उनके द्वारा संगठित फर्मों को रिजर्व बैंक से सम्बद्ध किये जाने का सुझाव भी दिया गया है, किन्तु इनकी संख्या इतनी अधिक है तथा इनके संगठन एवं

कार्य-संचालन के तरीको मे इतना अधिक अन्तर है कि इस सुझाव को कार्यरूप मे परिणत करना सम्भव नही हो सका है।' साहूकारो के वित्तीय साधन अत्यन्त सीमित है।

भारत के कुछ भागो मे लघु उद्योगो ने जनता का विश्वास प्राप्त कर जन-निक्षेपो को आकर्षित करने मे सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, बम्बई एव दक्षिण के कुछ क्षेत्रो मे लघु उद्योगपति आकर्षक ब्याज दर देकर जनता का रुपया अपने यहाँ जमा रखते है। किन्तु जहाँ तक इस साधन की उपयोगिकता का प्रश्न है, यह वित्त प्राप्ति का एक अविश्वसनीय साधन है, क्योकि आवश्यकता के समय मे जब वित्त की अधिक आवश्यकता होती है तो यह साथ छोड देता है। जब तक सस्था सम्पन्नता की स्थिति मे होती है तथा इन्हे आकर्षित करने के लिए ऊँचा ब्याज देती रहती है, जन-निक्षेप सहायक होते है। किन्तु जैसे ही सस्था मे कोई सकट उपस्थित हो जाता है, जमाकर्ता अपनी राशि वापस माँगने लगते है और इस प्रकार वे सस्था की स्थिति को और अधिक सकटपूर्ण बना देते है।

1 देशी बैंकर :- केन्द्रीय बैंकिंग ऋण समिति 1929 के अनुसार इम्पीरियल बैंक, विनिमय बैंक व्यापारिक बैंक तथा सहकारी साख समितियो को छोडकर वे सभी व्यक्ति, जो हुण्डियो का व्यवसाय करते है तथा जनता से रुपये का लेन देन करते है, देशी बैंकर कहलाते है। देशी बैंकर कोई भी व्यक्ति है या व्यक्तिगत फर्म है जो ऋण देने के साथ जमा पर रुपया स्वीकार करता है या हुण्डियो का व्यापार करता है या दोनो का कार्य करता है।

इन बैंकरो को महाजन या साहूकार भी कहा जाता है। समय-समय पर ऋण देता है इन साहूकारो या महाजनो के कार्य करने के ढग सरल होते है यह अल्पकालीन माध् यमकालीन एव दीर्घकालीन तीनो प्रकार के ऋण होते है। ऋण जमानत लेकर या बिना जमानत दोनो प्रकार से दिये जाते है। यदि इनके ब्याज समय पर मिलता रहता है तो यह मूलधन की वापसी पर अधिक जोर नही देते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार इन साहूकारो एव महाजनो का कृषि वित्त मे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, परन्तु अब इनके महत्व मे कमी आ गई है। फिर भी आजकल यह कृषि वित्त की लगभग 25

आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

देशी बैंकर बहुत अधिक ब्याज दर से ऋण लेते हैं जो सामान्यतः 18 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक होते हैं लेकिन ऋणी ऋण की रकम किस्तों में चुकाता है तो ब्याज की दर 40 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। साहूकार ऋण देते समय पूरे एक वर्ष की ब्याज अग्रिम रूप में लिखा है कि साहूकारों के लेन देन का ढग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है। अतः सरकार ने इन पर नियन्त्रण लगा दिये हैं जिनके अनुसार प्रत्येक साहूकार एवं महाजन को इस प्रकार का व्यवसाय करने पर रिजर्व बैंक से अनुमति पत्र लेना पड़ता है।

2 बिचौलिए— बिचौलिए व्यापारी एवं कमीशीन एजेंट भी लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। माल के लिये अग्रिम राशि का भुगतान एवं कच्चे माल के उधार विक्रय आदि के द्वारा ये बिचौलिए उद्योगों को वित्तीय सहायता करते हैं।

3 रिश्तेदार :- लघु उद्योगों को आवश्यकता पड़ने पर रिश्तेदार एवं मित्र भी नकद या वस्तुओं के रूप में उधार प्रदान करते हैं। ये साख आपसी सम्बन्धों के आधार पर अनौपचारिक ढग से लिये जाते हैं। ऐसे साख पर ब्याज दर शून्य या मामूली होती है। लघु उद्योगों को व्यक्तिगत साधनों से प्राप्त सहायता के लिये प्रमुख सूचनाओं का आभाव रहा है।

4 जन निक्षेप (Public Deposits):- भारत के कुछ भागों में लघु उद्योगों ने जनता का विश्वास अर्जित करके जन निक्षेपों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। मुम्बई, अहमदाबाद एवं शोलापुर की लघु सूती मिलें आर्कषक ब्याज दरें प्रदान करके जनता का रूपया अपने पास जमा कर लेती हैं। यह स्रोत मात्र अल्प समय का साथी रहा है।

संस्थागत स्रोत

1 वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks):- 1950-51 तक अखिल भारतीय स्तर पर लघु उद्योग वित्तीयन में वाणिज्यिक बैंको का योगदान बहुत कम था। लेकिन अब धीरे-धीरे योगदान बढ़ रहा है। वास्तव में लघु उद्योगों की लाभदायकता में कमी, अप्रभावी प्रबंध, जोखिम पूँजी की कमी, अपर्याप्त हिसाब किताब, उचित जमानत का अभाव होने के कारण वाणिज्यिक बैंक अधिक सहयोग नहीं कर सके। फिर भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में 'लीड बैंक' योजना के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक विशिष्ट तरीके से योगदान कर रहे हैं।

पहले व्यापारिक बैंक लघु उद्योग के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती थी, लेकिन 14 व्यापारिक बैंको का 1969 को एव 6 बैंको का 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् इन बैंको के द्वारा अब कृषि वित्त में योगदान दिया जाने लगा है। यह बैंक अल्पकालीन एव मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करती हैं। 1999-2000 वर्ष में इन सभी व्यापारिक बैंको ने 2,588 करोड़ रुपये की साख़ वितरित किया। विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंको के निक्षेपों में भारी वृद्धि हुई है। 1951-52 में अनुसूचित बैंको के कुल निक्षेप 8,806 करोड़ रुपये हो गये। इसका मुख्य कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना है।

पिछले कुछ वर्षों में इन बैंको के अग्रिम में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1950-51 में अनुसूचित बैंको के अग्रिमों की कुल मात्रा 546.93 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 3 जनवरी 1997 को 2,63,240 करोड़ रुपये हो गई। 1950-51 में ये बैंक अपनी कुल जमाओं का लगभग 62 प्रतिशत अग्रिमों में लगाते थे, अब यह प्रतिशत बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया। 1969 में 14 बड़े बैंको का तथा 15 अप्रैल 1980 के 6 बैंको के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप किसान एव उद्योग पतियों को दिये जाने वाले अग्रिम की राशि में वृद्धि हुई है।

तरलता का अर्थ है माग होने पर नकद रुपये देने की क्षमता। स्पष्ट है कि नकद कोष बैंक का सर्वाधिक तरल साधन है, किन्तु इससे बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती है। नकद

कोष से चूँकि वाणिज्य बैंको को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस कोष में न्यूनतम आवश्यक राशि ही रखी जाती है। वाणिज्य बैंको द्वारा दिया गया उधार एव अग्रिम (Loans and Advances) इनकी सर्वाधिक लाभदायक सम्पत्ति है। उधार एव अग्रिम व्यवसायियों को अधिविकर्ष (Overdraft) या विनिमय बिलों की कटौती के माध्यम से दिया जाता है।

भारतीय बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता है। भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके साथ सम्बद्ध बैंक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैंको का कुल जमाओ एव ऋणों में करीब 90 प्रतिशत हिस्सा है। भारतीय ग्रामीण साख की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए 12 जुलाई 1982 को कृषि ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक (NABARD) की स्थापना की गई। इसने रिजर्व बैंक के कृषि वित्त सम्बन्धी तथा कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के पुनर्वित्त कार्य का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। वाणिज्य बैंक उद्योगों के लिए विकास वित्त (Development Finance) का प्रावधान नहीं कर सकता। क्योंकि इस वित्त की आवश्यकता दीर्घ कालीन है।

वाणिज्य बैंको के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक भी वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वाणिज्य बैंक के तुलना पत्र (Balance Sheet) में बायी ओर दायित्व (Liabilities) तथा दायी ओर सम्पत्ति (Assets) को दिखाया जाता है। तुलना पत्र से यह जानकारी मिलती है कि वाणिज्य बैंको को तीन स्रोतों से कोष प्राप्त होता है।

- 1 प्रदत्त पूँजी यह अशधारियों द्वारा दी गई हिस्सा पूँजी है।
- 2 रिजर्व बैंक यह अवितरित लाभ है।
- 3 जमा — लोगों का जमा बैंक के कोष का सबसे बड़ा स्रोत है। इन सभी स्रोतों से प्राप्त कोष बैंक का दायित्व है क्योंकि इन्हें इनके स्वामियों को लौटाना होता है। ऐसे दायित्वों को वाणिज्य बैंक उधार देकर उन्हें सम्पत्ति में बदल देता है। बैंक ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। इसकी जानकारी इसके सम्पत्ति के वितरण की रचना से ही मिल सकती है।

चूँकि वाणिज्य बैंक अशधारियो (Share Holders) का बैंक है अतः इसे अशधारियो के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहिए। लाभ आय या प्राप्ति तथा लागत का अन्तर है। इसी अन्तर को अधिकतम करने पर लाभ अधिकतम होगा। बैंक की लागत में कर्मचारियों का वेतन, मकान का किराया तथा जमा पर दिया गया ब्याज आदि शामिल हैं।

बैंको को अधिकांश कोष लोगों की जमा द्वारा ही प्राप्त होता है। लोग अपनी बचत को बैंक में तभी तक जमा करते हैं जब तक उन्हें विश्वास रहता है। कि मांग होने पर बैंक अपने नकद की आवश्यकता को पूरा करते रहेंगे। इस प्रकार सम्पत्ति का वितरण करने समय बैंक को लाभदायकता तथा तरलता के मध्य का संघर्ष का सामना करना पड़ता है। भारत में वाणिज्य बैंक को अनुसूचित (Scheduld) तथा गैर अनुसूचित (Non-Scheduld) बैंको में भी विभाजित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम के लागू होने के साथ ही यह विभाजन भी किया जाने लगा। इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी तालिका में शामिल कर लिया है। तालिका में शामिल करने के लिए इन्हें निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं—

- 1 इन बैंको की प्रदत्त पूँजी (Paid up Capital) तथा आरक्षित कोष (Reserves) का योग 5 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।
- 2 कम्पनी अधिनियम 1956 में परिभाषित कम्पनी के अनुसार ही इसे कम्पनी या राज्य सहकारी बैंक का होना चाहिए।
- 3 रिजर्व बैंक को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इन बैंको की समस्त कार्यविधियों का संचालन जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

एक संसोधन द्वारा मार्च 1966 से राज्य सहकारी बैंक की तालिका 2 में सम्मिलित कर लिए गये हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तालिका 2 में शामिल कर लिये जाते हैं। तालिका 2 में शामिल कर लेने से रिजर्व बैंक इन अनुसूचित बैंको को कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। जैसे रिजर्व बैंक से उधार

प्राप्त विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिए अधिकृत व्यापारी का लाइसेन्स आदि। इसके बदले में अनुसूचित बैंको को नकद कोष के रूप में अपनी जमाओं को एक निर्धारित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है।

अनुसूचित बैंको के विपरीत, गैर अनुसूचित बैंक वे हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी तालिका 2 में शामिल नहीं किया है। इन बैंको की प्रदत्त पूँजी तथा आरक्षित कोष का योग 5 लाख रुपये से कम होता है। तालिका 2 में शामिल नहीं होने के कारण इन बैंको को रिजर्व बैंक से वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंको को मिलती हैं। जून 1982 के अन्त में केवल 4 गैर अनुसूचित बैंक थे जब कि 1960 के अन्त में 335 तथा 1969 के अन्त में 14 थे। कुल बैंकिंग का व्यवसाय का नगण्य भाग इन बैंको के द्वारा किया जाता है। 1981 के अन्त में इनका जमा 10 करोड़ से भी कम था। जबकि अनुसूचित बैंको का कुल जमा 43,432 करोड़ रुपया था।

वाणिज्य बैंक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अतः आवश्यक समझा गया है कि कुछ ऐसी विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ होनी चाहिए जो नये उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक पूँजी प्रदान कर सकें, इसलिए विकास बैंको की स्थापना की गयी। इन्हें सर्वाधिक संस्थाएँ (Term Lending Institutions) भी कहा जाता है, क्योंकि ये मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त उद्योगों को प्रदान करती हैं। ऐसी कुछ प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India)
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India)
3. भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम
(Industrial Credit and Investment Corporation of India)
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India)

- 5 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
(Industrial Reconstruction Bank of India)
- 6 राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation)
- 7 राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporation)
- 8 आधारीक सरचना विकास वित्त निगम (Infrastructure Development Finance Corporation)

19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 वाणिज्य बैंको का राष्ट्रीयकरण किया। अप्रैल 1980 में 6 अन्य वाणिज्य बैंको का राष्ट्रीयकरण सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंको की शाखाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में जहाँ पहले बैंक नहीं थे। जून 1969 में वाणिज्य बैंको की शाखाओं की संख्या 8,262 थी जो 30 जून 1998 में बढ़कर 64,280 हो गयी। इसलिए जहाँ जून में 1969 में वाणिज्य प्रति बैंक औसत जनसंख्या 65,000 थी वहाँ जून 1998 में यह जनसंख्या घटकर 10,000 से कम रह गई। बैंक की शाखा में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इन शाखाओं के खुलने पर वाणिज्य बैंको की जमाओं की मात्रा में वृद्धि हुई है। सभी अनुसूचित बैंको का जमा 1970-71 में 5,910 करोड़ रुपये था उसी तरह बैंक शाखा की मात्रा भी 1970-71 के 4,685 करोड़ रुपये से बढ़कर 1980-81 में 25,270 करोड़ तथा 20 नवम्बर 1998 को 3,36,124 करोड़ रुपये हो गयी।

आरम्भिक काल में कृषि के असंगति स्वरूप तथा उत्पादन में व्याप्त अनियमितता के कारण व्यापारिक बैंको ने ग्रामीण शाखा के क्षेत्र में रुचि नहीं दिखायी और उनका ध्यान औद्योगिक क्षेत्र पर केन्द्रित रहा। इसके परिणाम स्वरूप 1950-51 में ग्रामीण शाखा में व्यापारिक बैंको का योगदान केवल 0.9 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये ऋणों में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1969 में 40 करोड़ रुपये (1.3 प्रतिशत) से बढ़कर यह राशि मार्च 1997 में 25,962 करोड़ रुपये (13.2) प्रतिशत हो गयी।

राष्ट्रीयकरण के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों की शाखाओं तथा ग्रामीण वित्त में इसके हिस्से में काफी वृद्धि हुई है। तेजी से हुए इस विस्तार के कारण बैंकों के कामकाज तथा सेवा के स्तर में गिरावट आई है। बैंकों के विस्तार के समय बैंकों की शाखाओं के भौगोलिक प्रसार पर ध्यान नहीं दिया गया। बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों की भी कहीं स्थिति रही। जहाँ देश के दक्षिणी क्षेत्र में ही 50 प्रतिशत से अधिक ऋण दिये गये। वहीं अन्य सभी क्षेत्रों का सम्मिलित हिस्सा 50 प्रतिशत कम रह गया। सातवी योजना के दस्तावेज के अनुसार ऋणों की वसूली की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गयी और बैंक दुर्लभ साधन प्रदान करने के स्रोत न रहकर अनुदान देने वाली संस्था बन कर रह गये तो बैंकों को भविष्य में ऋण प्रदान करने की क्षमता अत्यधिक सीमित हो जायेगी।

जुलाई 1996 में बैंकों के पास कुल जमा राशि 4665 करोड़ रुपये थी जो मार्च 1999 में 7,01,871 करोड़ रुपये की गई। जमा राशि में इस तीव्र वृद्धि में ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन वर्षों में यद्यपि शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों भी जमा राशियों में तेज वृद्धि हुई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जमा का हिस्सा बढ़ा है। बैंकों की जमा राशि में ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि तथा इन क्षेत्रों का झुकाव मियादी जमा की ओर होने के कारण बैंकों की कुल जमा में मियादी जमा का हिस्सा बचा जमा की तुलना में अधिक गति से बढ़ा है।

जुलाई 1996 में कुल बैंक साख की राशि 3,399 करोड़ रुपये थी जो 28 मार्च 1999 को बढ़ कर 3,89,460 करोड़ रुपये हो गई। अर्थात् राष्ट्रीयकरण के बाद से इसमें लगभग 115 गुने की वृद्धि हुई है। लेकिन इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंक जमा राशियों में वृद्धि के अनुपात में साख में वृद्धि नहीं हुई है। यही कारण है कि साख जमा राशि अनुपात 1967 के 768 से गिरकर मार्च 1999 में 53.4 हो गई है।

बैंक साख के क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि लघु उद्योग एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को बैंक साख की कुल बैंक साख में बढ़ती हुई हिस्सेदारी है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व इन क्षेत्रों को बैंक साख का नितान्त अभाव था जबकि मार्च 1999 में इन क्षेत्रों का हिस्सा कुल बैंक साख

मे 43.5 प्रतिशत हो गया। वस्तुतः बैंको के राष्ट्रीयकरण को प्रमुख उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारम्भिक क्षेत्रों को बैंक साख उपलब्ध कराना भी था।

बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद से शाखाओं के विस्तार, जमा राशियों के सग्रह, बैंक साख की उपलब्धता की दृष्टि से बैंकिंग सेवाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्रों को साख की उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं के विस्तार में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। इन उपलब्धियों के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार के कुछ नकारात्मक पक्ष रहे हैं। जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

निर्देशित निवेश (Directed investment) तथा निर्देश साख कार्यक्रम (Directed Credit Programmes) के कारण बैंको की लाभप्रदता में कमी आयी है। बैंक के बढ़ते हुए व्यय के कारण इनमें और अधिक कमी हुई है। यही कारण है कि 1992-93 में घोषित नए मानदण्डों के अनुसार इस वर्ष सभी बैंको की कार्यशील निधि के अनुपात में लाभ ऋणात्मक (-11 प्रतिशत) थे। 1993-94 में इनमें और वृद्धि हुई जबकि 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में क्रमशः 0.4 प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत तथा 0.2 प्रतिशत रहा। इन वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंक तथा कुछ अन्य बैंको ने ही शुद्ध लाभ कमाये। शेष बैंक को हानि उठानी पड़ी है।

मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण तथा भारतीय रिजर्व बैंको से केन्द्र सरकार द्वारा लगातार किये जाने वाले ऋणों के कारण नकद कोष अनुपात (Cash Reserve Ratio) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) को ऊँचे स्तर पर रख गया जिसके कारण जहाँ एक ओर बैंको की साख सृजन की क्षमता प्रभावित हुई है। वहीं बैंको को कम ब्याज दर वाली सरकारी तथा अन्य वित्तीय सस्थाओं की प्रतिभूतियों में निवेश करना पड़ा। इससे इनकी लाभप्रदता प्रभावित हुई।

प्राथमिक क्षेत्रों को साख उपलब्ध कराने में भी बैंको को उच्च लागत का सामना करना पड़ा है। इन क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते समय बैंकिंग के मूलभूत

सिद्धान्तों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तथा प्रतिभूतियों की ओर ध्यान दिये बिना ऋण दिये गये, जिनकी वसूली की दशा अच्छी नहीं रही। इन सब कारणों से जहाँ बैंकों को हानि उठानी पड़ी, वही उनकी सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर नरसिंह समिति ने प्राथमिक क्षेत्रों को दी जाने वाली साख का लक्ष्य कुल साख के 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

1995-96 में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों में से शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या केवल 19 थी। 1998-99 में शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या बढ़कर 25 हो गयी। 1995-96 में सभी 27 बैंकों को कुल मिलाकर 367 37 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। 1998-99 में स्थिति में परिवर्तन हुआ। और सभी बैंकों ने कुल मिलाकर 3257 97 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हुए। 1996 से 1998 के मध्य व्यापारिक बैंकों ने धनात्मक परिणाम दिये। वर्ष 1996 में बैंकों की कुल शाखाएँ 8262 थीं।

योजनाकाल में दीर्घ काल तक व्यापारिक बैंकों की संख्या कमी की प्रवृत्ति रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह नीति रही है। कि कमजोर एवं अक्षम बैंकों का बड़े बैंकों के साथ विलयन कर दिया जाये। विलयन एवं समूहीकरण की इस नीति के कारण बैंकों की संख्या में तीव्र कमी आई। विशेष कमी 1951 से 1974 की अवधि में आई। इस अवधि में व्यापारिक बैंकों की संख्या 566 से घटकर 83 हो गयी। विशेष कमी गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या में कमी से सम्बद्ध रही है। उक्त अवधि में इनकी संख्या 474 से घटकर केवल 9 रह गयी। 1947 के बाद अनुसूचित बैंकों की संख्या बढ़ी है, परन्तु गैर - अनुसूचित बैंकों की संख्या में नितांत कमी होती रही। 1976 के बाद व्यापारिक बैंकों की संख्या में लगातार वृद्धि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बाद हुई।

तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए बैंकिंग प्रणाली को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में अपनाया गया। यह प्रयास 1970 से 'लीड बैंक' स्थापित करके आगे बढ़ाया गया। लीड बैंक योजना राज्यों एवं जिलों में शाखा विस्तार की दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली रही। वर्ष 1976 में ग्रामीण विकास के पटल पर तीव्र परिवर्तन के साथ सरकार ने निर्यात एवं आयात बैंक (Exim Bank) एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (NABARD) वर्ष 1982 में स्थापित किया गया।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य कलापो से यह पता चलता है कि 1990-91 में अधिक काम काज के दौरान समग्र जमा राशियों एवं बैंक ऋण दोनों में ही वृद्धि ऊँची रही है। निम्न तालिका से सफल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन का विवरण इस प्रकार है —

(करोड़ रुपये)

	1992-93	1997-98
A. एकता बैंक ऋण	21,134	41,292
(i) सार्वजनिक खाद्य प्राप्ति	2,073	4,888
(ii) सफल खाद्य भिन्न ऋण	19,061	36,404
1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,806	3,427
2 मध्यम एवं भारी उद्योग	11,546	14,926
3 थोक व्यापार	815	877
4 अन्य क्षेत्र	2,293	5,974
B. निर्यात ऋण	5,062	3,939

देश की लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्राप्त करने की कठिनाई के निदान हेतु सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1991 में श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने लघु आकारीय औद्योगिक इकाइयों के लिए

संस्थागत वित्त के अपेक्षाकृत अधिक प्रवाह की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लघु उद्यमकर्ता यह अनुभव कर सकें कि बैंक उनकी आवश्यकताओं के प्रति सजग हैं। समिति ने सुझाव दिया कि नाबार्ड (NABARD) एवं सिडबी (SIDBI) को लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए अम्बुसमान (ABBUSMAN) पद्धति का प्राधिकरण निर्मित किया जाना चाहिए।

Bank Credit to SSI Sector

(Rs. Crores)

Year end March	Net Bank Credit	Credit to industry	Credit to SSI	Percentage Share of SSI
1991	1,16,301	6,1576	17,118	14.72
1992	1,23,161	65,240	17,830	14.47
1993	1,51,982	78,662	2,0026	13.17
1994	1,64,418	80,482	27,620	13.75
1995	2,11,560	1,02,953	27,612	13.05
1996	2,54,015	1,24,937	31,726	12.49
1997	2,78,402	1,38,548	34,113	12.25
1998	3,24,079	1,61,048	43,508	13.43
1999	3,68,837	1,78,799	48,483	17.88

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के साथ ही मिनदे व्यापारिक बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत साख प्रदान की है। ये बैंक लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक सरलता से ज्यादा साख प्राप्त हो सके। जिसके लिए बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे उन उद्योगों

की क्रियाशीलता की आवश्यकता के आकलन में सरल दृष्टिकोण अपनाये।

2. राज्य वित्तीय निगम (State Financial Corporations)-भारत सरकार द्वारा सन् 1951 में पास किये गये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत इन निगमों को विभिन्न राज्यों में स्थापित किया गया है। अभी तक कुल 18 राज्य वित्त निगमों की स्थापना की जा चुकी है। इन निगमों का उद्देश्य छोटी एवं मध्यम आकार की उन इकाइयों को दीर्घ कालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जो औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त समस्त राज्यों में राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Development Corporation) की स्थापना की जा चुकी है।

लघु इकाइयों को अधिक और उदार ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सरकार ने "एक सस्था से ऋण लेने की योजना" (Single Window Scheme) शुरू की है। जिसके अन्तर्गत एक ही सस्था राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक विकास निगम से छोटे-छोटे उद्योगपति ऋण सम्बन्धी समस्त सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य वित्त निगम तीन प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं —

- (i) औद्योगिक इकाइयों को 20 वर्ष तक अवधि के ऋण देकर।
- (ii) कम्पनियों के अशो तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन करके।
- (iii) अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त होने वाले 20 वर्ष तक की अवधि के ऋणों की गारण्टी करके।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की भाँति राज्य स्तर पर भी लघु एवं मध्यम आकार वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 28 सितम्बर 1951 को राज्य वित्त अधिनियम पारित किया गया। वास्तव में बड़े उद्यमी तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कायम प्रबन्धन की स्थिति में होते हैं, जबकि लघु एवं मध्यम उद्यमियों हेतु राज्य स्तरीय वित्त निगम स्थापित किये गये। राज्य वित्त निगम उन औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। वे मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के

अतिरिक्त सरकारी समितियों सयुक्त हिन्दू परिवारो, साझेदारियों एव एकाकी स्वामित्व वाली व्यावसायिक गृहो को ऋण दे सकते है। सबसे पहले 1953 मे पजाब वित्त निगम की स्थापना की गई। इस समय देश के 18 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एव पश्चिमी बंगाल) मे राज्य वित्त निगमों कार्य कर रही हैं।

प्रत्येक राज्य वित्त निगम का प्रबन्ध एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्यों की संख्या 10 होती हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार 3 सचालक नियुक्त करती है। औद्योगिक वित्त निगम, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, अन्य वित्त संस्थाएँ एव अन्य अशुधारी प्रत्येक एक एक सचालक नियुक्त करते हैं।

राज्य वित्त निगमों के वित्तीय साधन इस प्रकार हैं -

(A) अशु पूँजी - राज्य वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत राज्य निगमों की अधिकृत पूँजी की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपये एव उच्चतम सीमा 10 करोड़ रुपये निश्चित की गई। जिसे अब 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य वित्त निगमों की प्रदत्त पूँजी एवं न्यूनतम लाभांश के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा गारण्टी दी गयी है। राज्य वित्त निगम की अशु पूँजी राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम एव अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सामान्य जनता द्वारा क्रय की जा सकती है।

(B) ऋण पत्र - राज्य वित्त निगम अपनी राज्य सरकार एव रिजर्व बैंक की सलाह पर ऋण जारी कर पूँजी एकत्रित करने का अधिकार रखते हैं।

(C) जमा राशि - राज्य वित्तीय निगम पूँजी प्राप्त करने के लिए जनता के निक्षेप एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसकी राशि सम्बन्धित वित्त निगम की चुकता पूँजी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य वित्त निगम 20 वर्ष के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह ऋण स्थायी सम्पत्ति के 50 प्रतिशत मूल्य तक दिये जा सकते हैं। यह निगम औद्योगिक सस्थाओं के अशो एव ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य कर सकते हैं। इन निगमों ने 1998-99 में 2,494 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। जिसमें से उद्योगों ने केवल 21,23 करोड़ रुपये ही निकाले हैं।

1997-98 तक राज्य वित्त निगमों ने कुल 29,217 करोड़ रुपये के ऋण देना स्वीकार किया तथा 23,123 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये। 1997-98 में इन निगमों ने कुल 2,911 करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया।

यद्यपि इन निगमों द्वारा स्वीकृत एव वितरित वित्तीय सहायता में लगातार वृद्धि हुई है लेकिन कुछ निगमों को छोड़कर, शेष सभी में दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीमित है। इनकी ब्याज दर ऊँची है। तथा प्रतिभूति की शर्तें भी कड़ी हैं। जिससे छोटी इकाइयों को ऋण मिलना कठिन हो जाता है। राज्य वित्त निगमों की पूँजी एव ऋण देने की क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इनकी पूँजी कम है। ऋणों की समानता के सम्बन्ध में निगमों का दृष्टिकोण कठोर है। अतः ये पूर्ण जमानत पर ऋण स्वीकृत करते हैं। जिस कारण ये लघु उद्योगों के वित्तीयन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहे हैं। 31 मार्च 1997 को इन सभी निगमों के कुल पूँजी 1,157 करोड़ रुपये भी जब कि इनकी कुल हानियाँ 1,125 करोड़ रुपये थीं।

3 राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) : देश के कृषि एव ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करने एवं लघु उद्योगों की वित्तीयन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय दिसम्बर 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मन्त्रिमण्डल द्वारा लिया गया था। कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि और कमजोर वर्ग की सहायता के लिए कई योजनाएँ तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम

के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है। यह बैंक कृषि के उन्नयन लघु उद्योगों, गृह एवं ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण योजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सर्वोच्च संगठन है।

इस बैंक की स्थापना के बाद से कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (A R D E) के समस्त कार्य और रिजर्व बैंक के कृषि-साख के मुख्य कार्य इस बैंक के अधीन हो गये। नाबार्ड की अधिकतम पूँजी 100 करोड़ रखी गयी है जो 500 करोड़ रुपये तक बढ़ायी जा सकती है। इसकी पूँजी का आधा भाग केन्द्रीय सरकार ने और आधा भाग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने दिया है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंको की स्थापना एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में की गयी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि, लघु उद्योग उद्योगों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। भूमि विकास बैंको, अनुसूचित व्यापारिक बैंको, राज्य सहकारी बैंको तथा ग्रामीण विकास बैंको के लिए 25 वर्ष तक के दीर्घ कालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। नाबार्ड ने रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों का दायित्व सम्भल लिया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के सभी आयामों के लिए पर्याप्त धन एवं तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करता है।

कृषि एवं ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था होने के कारण ग्रामीण साख के क्षेत्र में इसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 1982 में स्थापना के बाद इसकी परिसंपत्ति एवं देयताओं में वृद्धि हुई है। 1982-86 में इस बैंक की परिसंपत्ति एवं देयताएँ 6,596 करोड़ रुपये थी जो 1996-97 में बढ़कर 22,571 करोड़ रुपये हो गयी। मौसमी कृषि आवश्यकताओं के लिये 1989-90 में 2,807 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे। 1997-98 में यह राशि बढ़कर 5,185 करोड़ रुपये हो गयी। इसके अतिरिक्त अन्य अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 1997-98 में 1,060 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गयी।

निर्माणाधीन ग्रामीण आधारिक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से 1995-96 के बजट प्रावधानों के अन्तर्गत एक ग्रामीण आधारिक संरचना विकास फण्ड (Rural Infrastructure Development Fund RIDF) की स्थापना की गई है। 1995-96 में नाबार्ड ने RIDF-I के अन्तर्गत 2,010 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की। 1996-97 में RIDF-II के अन्तर्गत 2,647 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई जो लक्ष्य (2,500 करोड़ रुपये) से अधिक थी लेकिन मार्च 1997 तक वितरित सहायता केवल 292 करोड़ रुपये थी। 1997-98 में RIDF-III के अन्तर्गत 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। RIDF (IV) 1998-99 के अन्तर्गत 3000 करोड़ रुपये, RIDF-V 1999-2000 के अन्तर्गत 3,500 करोड़ रुपये तक RIDF-VI 2000-2001 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

इस प्रकार 1995-96 से 2000-01 के मध्य 6 वर्षों में ग्रामीण आधारिक संरचना विकास कोष RIDF के अन्तर्गत कुल आबटन 18,000 करोड़ रुपये का किया गया। नाबार्ड द्वारा 1996-97 में सहकारी बैंको तथा राज्य सरकारों को प्रदत्त साख इस प्रकार है -

(राशि करोड़ रुपये में)

साख विवरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	पुनर्भुगतान	बकाया राशि
1 राज्य सहकारी बैंक				
(A) अल्प कालीन	6049.36	6287.74	6409.93	3,382.82
(B) मध्यम कालीन	268.60	57.73	44.39	79.86
2 राज्य सरकार				
(दीर्घ कालीन)	100.58	76.84	21.57	418.47

नाबार्ड अब पुनर्वित्त सहायता के रूप में 25 वर्षों के लिए राज्य उधार विकास बैंक (अब इसे राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है।) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन उधार विनियोग ऋण

प्रदान करने के लिए दे सकता है। ऐसा दीर्घ कालीन ऋण के दायरे में कारीगर लघु स्तरीय इकाइयों भी आते हैं।

1995-96 से 2000-01 के मध्य 6 वर्षों में ग्रामीण आधारिक संरचना विकास कोष RIDF के अन्तर्गत कुल आबटन 18,000 करोड़ रुपये का किया गया। किन्तु इस निधि के आधीन उपयोग स्तर सतोष जनक नहीं है। कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक के तीन मुख्य कार्य हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक के तीन मुख्य कार्य हैं – पुन वित्त (Refinance) सस्थात्मक विकास (Structural Development) तथा अन्य बैंकों के कार्यों का निरीक्षण। इसमें से पुन वित्त के कार्य पर ज्यादा जोर दिया गया अन्य दो कार्यों पर कम ध्यान दिया जाता है। लघु उद्योगों के वित्तीय स्थिति तथा सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली को सुधारने में अभी तक इसे कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये)

उद्योग	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक संचयी
खाद्य उत्पादक वस्त्र	57.7	51.4	62.5	382.1
कागज एवं कागज उत्पाद	19.8	15.6	14.1	141.9
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	7.3	7.9	7.0	36.3
रबड़ एवं रबड़ उत्पादन	4.1	3.5	4.2	73.0
रसायन एवं रसायन उत्पाद	6.9	8.2	9.6	56.1
सेवाएँ	341.5	314.7	34.7	1666.2

4 भारत का औद्योगिक विकास बैंक (INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA):

औद्योगिक विकास बैंक भारत में स्थापित विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की श्रृंखला में नवीनतम एवं विशाल कड़ी है। इसकी स्थापना एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय एवं समन्वयकारी

विशिष्ट वित्तीय संस्था के रूप में हुई है। 30 अप्रैल, 1964 को लोकसभा ने भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना हेतु एक विधेयक पास किया जिसे राज्यसभा ने 7 मई, 1964 को स्वीकार कर लिया। इस बैंक ने 1 जुलाई, 1964 से अपने कार्यों को शुभारम्भ किया। शुरू में इसने भारतीय रक्षित अधिकोष की सहायक संस्था के रूप में कार्य किया। लेकिन 1975 में इसको भारतीय रक्षित अधिकोष से अलग करने का अधिनियम पारित किया। 16 फरवरी, 1976 को इसे एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया। इसकी पूँजी केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गई है।

इसके द्वारा प्रदत्त सहायता प्रायः पुनर्वित्त (Refinance) के रूप में होती है। पुनर्वित्त की ये सुविधाएँ व्यापारिक बैंको, सहकारी बैंको एवं राज्यों के वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों को कुछ वित्तीय सहायता विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत भी प्रदान की जाती है। औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बीज पूँजी योजना (Seed-Capital Scheme) के अन्तर्गत नये उद्यमियों (New Entrepreneurs) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता राज्यों के उद्योग विकास निगम के माध्यम से दी जाती है।

औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में औद्योगीकरण की गति तीव्र करना एवं औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं की स्थापना में सक्रिय भाग लेना है। इस मूलभूत उद्देश्य के साथ ही औद्योगिक वित्त के अभाव को दूर करना एवं औद्योगिक वित्त की समस्या का समाधान करना भी इसके कार्यों का महत्वपूर्ण अंग है।

इस बैंक द्वारा लघु उद्योगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। उद्योगों के अंश एवं ऋण पत्र की गारन्टी देकर एवं अभिगोपन करके वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके द्वारा लघु उद्योगों तथा आधुनिक पद्धतियों को विकसित करने के लिए ऋण दिया जाता है। राज्य वित्त निगमों एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को 3 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लिए दिये गये ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान

करना। उद्योगों के विकास से सम्बन्धित विनियोग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन के विषय में अनुसंधान कार्य एवं सर्वेक्षण करना। किसी उद्योग के प्रवर्तन, प्रबन्ध अथवा विस्तार हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय सेवाएँ उपलब्ध करना। देश की औद्योगिक संरचना की कर्मियों को दूर करने हेतु उद्योगों का नियोजन, प्रवर्तन एवं विकास करना। 1972-73 में इस बैंक के अधिनियम में संशोधन करके कार्य क्षेत्र को काफी बढ़ा दिया है।

30 जून, 2001 तक औद्योगिक विकास बैंक ने अपने कार्यकारी जीवन के 37 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बैंक ने 1999-00 में 28,307 करोड़ रुपये की कुल सहायता स्वीकृत की हैं जब कि वास्तविक वितरण 17,059 करोड़ रुपये की ही हुआ था। इस बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण एवं भुगतानों के बराबर वृद्धि हो रही है। इस बैंक ने अपनी स्थापना से 2000-01 के अन्त तक जो ऋणों की स्वीकृति दी है। उसमें से सबसे अधिक स्वीकृति निजी क्षेत्र को दी है। दिसम्बर 1968 से इसने निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण एवं गारण्टी की योजना प्रारम्भ की है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्तीय सहायता के साथ ही विकासात्मक कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश के सभी पिछड़े राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में 'औद्योगिक' क्षमता सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। विकसित राज्यों में पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण करने के लिए बैंक से सम्बन्धित राज्यों एवं राज्य वित्त निगमों से सम्पर्क स्थापित किया है। और उनको इस सम्बन्ध में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध की है।

औद्योगिक विकास बैंक एक शीघ्रस्थ एवं समन्वयकारी वित्तीय संस्था के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुनर्वित्त के क्षेत्र में इसने लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को विशेष सहायता प्रदान की है। इस वित्तीय योगदान के अतिरिक्त विकास बैंक के कारण देश के अर्द्धविकसित क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य करके इसने देश की औद्योगिक संरचना में अद्वितीय योगदान दिया है।

भविष्य में इस संस्था को अभी बहुत कुछ करना है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में प्रादेशीक असंतुलनों और वित्त के अभाव की समस्या बहुत समय तक बनी रहेगी। बैंक को

चाहिए की पूँजी बाजार में पुनर्जीवन डाले वित्तीय संस्थाओं को औद्योगिक वित्त व्यवस्था में निश्चित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सहायक बनाये।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से सहायता दिलाने में यह बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। इस बैंक की जिम्मेदारियाँ निरन्तर बढ़ रही हैं। आशा है कि अन्य विशिष्ट संस्थाओं के सहयोग से यह संस्था शीर्षस्थ संस्था की भूमिका उचित ढंग से निभाते हुए देश के औद्योगिक विकास में वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगी। औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योगों के वित्तीयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके स्रोत पर वृद्धि की आवश्यकता है।

आई. डी बी आई उद्योग बर सहायता

(करोड रूपये)

उद्योग	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक संचयी
वस्त्र	1343.3	2136.6	2020.7	19924.2
रसायन एवं	1718.6	1764.6	1575.5	17117.2
रसायन उत्पाद				
रिफाइनरी एवं	625.0	1567.7	1846.0	6289.1
तेल शोधन				
मूल धातु	2008.5	2613.3	2578.6	15504.3
इलेक्ट्रानिक	498.1	556.1	984.6	7705.8
उपकरण				
बुनियादी क्षेत्र	2508.9	8092.7	9287.8	33156.7
सेवाएं	595.7	1198.6	1309.6	14369.1
	14942.5	23922.9	25484.7	16934.1

5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

[Small Industries Development Bank of India or SIDBI]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में 1989 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसने 2 अप्रैल 1990 से अपना कार्य प्रारम्भ किया है। इसे लघु क्षेत्र में स्थित इकाइयों के उन्नयन एवं वित्तीय और विकास के शीर्ष बैंक के रूप में स्थापित किया है। लघु इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सिडबी का उद्देश्य विद्यमान इकाइयों की तकनीकी प्रगति एवं आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना, घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लघु इकाइयों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि करना है।

सिडबी की प्राधिकृत पूँजी 250 करोड़ रुपये थी। सिडबी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की लघु उद्योग विकास निधि एवं राष्ट्रीय समता निधि (National Equity Fund) के अन्तर्गत 31 मार्च 1990 तक 4,228 करोड़ रुपये की बकाया राशि से सम्बन्धित परिचालन कार्य अपने पास ले लिया है। 31 मार्च 1999 तक इनकी पूँजी 15,298 करोड़ रुपये हो गई। बाद में बैंक की स्वीकृत पूँजी बढ़ाकर 500 करोड़ तथा प्रदत्त पूँजी 450 करोड़ रुपये हो गई।

1997-98 में सिडबी के पास कुल 13,912 करोड़ रुपये की वित्तीय साधन थे। सिडबी ने 1997-98 तक कुल 36,264 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत एवं 26,702 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये हैं। यह बैंक विद्यमान साख वितरण मध्यमों जैसे राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकार सिडबी की स्थापना से लघु उद्योग के वित्तीय एवं गैर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक विस्तृत आधार वाली संरचना का निर्माण करने का प्रयास किया है। सिडबी को लघु क्षेत्र में स्थित इकाइयों के उन्नयन का निर्माण, वित्त पोषण एवं विकास के

लिए एक प्रमुख वित्तीय सस्था की भूमिका सौपी गई है। साथ ही इसे इस प्रकार के कार्यों में लगी सस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना होगा।

1996-97 के दौरान सिडबी ने 6,485 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जिसमें से 4,585 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वितरण किया। मार्च 1997 के अन्त तक स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता 28,780 करोड़ रुपये थी। जिसमें से 21,461 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई। 1998-99 के दौरान सिडबी ने 450 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। जो पूर्व वर्ष के 405 करोड़ रुपये के लाभ से 11.1 प्रतिशत अधिक है।

सुविधाएँ (Facilities) :-सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधाएँ निम्नलिखित हैं

- 1 बैंको तथा अन्य पात्रता वाली वित्तीय सस्थाओं द्वारा स्वीकृत किये गये दीर्घ कालीन ऋणों के लिए पुनर्वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करना।
- 2 उद्यमियों को राष्ट्रीय समता निधि एवं बीज पूँजी सहायता के अन्तर्गत समता पूँजी की सहायता उपलब्ध करना।
- 3 लघु क्षेत्र के उत्पादन की बिक्री के कारण उपलब्ध अल्पकालीन बिलों के लिए पुनर्कटौती (Rediscount) की सहायता प्रदान करना।
- 4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु क्षेत्र के कच्चे माल एवं विपणन व्यवस्था में लगी अन्य सस्थाओं को ससाधन उपलब्ध कराना।
- 5 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, किराया क्रय एवं लीजिंग सुविधा के विस्तार के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना।
- 6 लघु उद्योग के उत्पाद के निर्यात प्रवर्तन हेतु सहायता उपलब्ध करना।
- 7 लघु उद्योग के विकास तथा प्रवर्तन के लिए तकनीकी एवं अन्य सम्बन्धित समर्थन सेवाओं का विस्तार करना।

नवीनतम् योजनाएँ (New Schemes):

- 1 ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए ग्रामीण औद्योगिक आस्थान की स्थापना के समर्थन देने के लिए पुनर्वित्त योजनाओं को आरम्भ किया गया है।
- 2 खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादों के विपणन के लिए बिक्री वाहन के सम्बन्ध में पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- 3 उदारीकरण तथा सरलीकरण की वर्तमान योजनाओं पर ध्यान देने के साथ साथ उनके सामर्थ्य को वित्तीय एवं अन्य समर्थन सेवाओं से शक्तिशाली बनाने के प्रयास किया गया है।
- 4 भारतीय स्टेट बैंक तथा केनारा बैंक पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में फैक्ट्रिंग के प्रवर्तन करने के लिए सिडवी ने कार्यक्रम बनाया है। इससे लघु इकाइयों को फैक्ट्रिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- 5 वर्तमान सस्थाओं के प्रयासों में सहायता करने के साथ साथ उनके सामर्थ्य को वित्तीय एवं अन्य समर्थन सेवाओं से शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- 6 मध्यम एवं बड़े उद्योगों को सहायक औजार की पूर्ति करने के लिए लघु उद्योगों के अल्प कालीन करने के लिए लघु उद्योगों के अल्प कालीन बिलों के लिए भुनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

विस्तार समर्थन सेवाएँ

- 1 ग्रामीण उद्यमियों, लघु उद्योगों के पारिवारिक प्रबन्धकों तथा उद्यमियों की प्रबन्धकीय चातुर्य को बढ़ाने के लिए योजनाएँ तैयार की गई हैं।
- 2 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अभिज्ञानित कुटीर उद्योग के 100 समूह का चयन किया गया है। जिससे कि दस्तकारों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके।
- 3 तकनीकी परामर्श सगठनों द्वारा 400 परियोजनाओं के बारे में प्रारम्भिक अध्ययन

किया जा रहा है। उनका प्रकाशन शीघ्र ही किया जायेगा।

- 4 ग्रामीण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 6 ग्रामीण विकास खण्डों दक्षिणीअण्डमान विकास खण्ड, मध्य प्रदेश के पेटलावाद विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश के कान्डला विकास खण्ड का चयन गहन विकास हेतु किया गया है।
- 5 सरकार के नीतिगत समर्थन एवं सिडबी के सक्रिय सहयोग से लघु क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।
- 6 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं लघु क्षेत्र के कच्चे माल तथा विपणन व्यवस्था में लगी अन्य सस्थाओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदत्त करने हेतु तत्पर हैं।

सिडबी के दायित्व एवं सम्पत्तियाँ निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है -

सिडबी के दायित्व एवं सम्पत्तियाँ (करोड़ रुपये में)

दायित्व/ सम्पत्तियाँ	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
अश पूँजी	450	450	450	450	450	450
सचय एवं कोष	302	494	750	1,114	2,068	2,622
बॉण्ड एवं ऋणपत्र	856	1,399	1,592	1,984	1,876	2,002
जमा	549	310	124	355	168	299
भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण	1,172	1,381	1,605	1,730	2,005	8,023
भारत सरकार से ऋण	1,356	1,708	1,740	1,738	1,732	8,023
अन्य से ऋण	3,943	3,511	3,827	3,692	3,952	8,023
अन्य दायित्व	825	1,105	1,518	1,978	1,661	1,902
कुल दायित्व	9,453	10,358	11,606	13,041	13,912	15,298

सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग	393	161	138	254	572	1,044
अन्य विनियोग	370	702	724	700	643	1,044
बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋण एवं अग्रिम	6,304	6,482	7,178	7,945	8,625	11,184
औद्योगिक संस्थाओं को ऋण एवं अग्रिम	339	686	917	960	1,088	1,981
विप्लव एवं प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती	1,394	1,669	1,915	2,322	1,933	N A
अन्य सम्पत्तियाँ	653	658	734	860	1,051	1,089
कुल सम्पत्तियाँ	9,453	10,358	11,606	13,041	13,912	15,298

तालिका -2

सिडबी द्वारा वित्तीय सहयोग की स्वीकृति एवं वितरण की राशि
(करोड़ रुपये में)

योजना	1996-97		1997-98		मार्च तक संचय स्वीकृत	1998 राशि वितरित
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित		
(अ) प्रत्यक्ष सहयोग						
(i) प्रत्यक्ष कटौती	1,748.3	1,595.2	1,422.5	1,312.8	7,965.5	7,172.2
(ii) विपणन योजना	12.0	1.4	147.6	48.5	180.4	59.9
(iii) लीजिंग सहयोग	553.0	302.1	258.0	117.4	2,236.8	1,465.5
(iv) गुणवत्ता जाँच केन्द्र	-	-	-	0.1	0.1	-
(v) आधारमूल विकास	237.3	6.0	476.6	113.8	970.2	135.4
(vi) फैक्ट्रिंग सेवा	60.0	44.0	70.0	59.0	279.0	222.0
(vii) अन्य	333.7	180.1	568.7	268.7	1,590.2	710.1
कुल (अ)	2,944.3	2,128.8	2,943.2	1,919.7	1,3141.2	9,765.2

(ब) अप्रत्यक्ष सहयोग

(i) पुन वित्त	2451 0	1941 7	3171 8	2640 2	18048 5	13977 9
(ii) बिलो की पुन कटौती	260.6	176 1	203 2	147 0	1950 8	1359 1
कुल (ब)	2,944.3	2,128.8	2,943.2	1919.7	13,141.2	9,765.2

(स) समता पूँजी समर्थन

(i) बीज पूँजी	-	-	-	-	1 1	1 3
(ii) समता कोष	21 6	15 8	28 8	24 4	70 0	54 0
(iii)समफेक्स योजना	0 2	0 2	0 1	0 1	18 9	16 5
(iv) महिला उद्यम मिधी योजना	0 9	0 8	2 2	1 8	12 5	9 5
कुल (स)	22.7	16.8	31.1	26 3	102.5	81.3

तालिका

योजना	1996-97		1997-98		मार्च 1998 तक कुल सचय राशि	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
(द) ससाधन समर्थन	-	-	-	-	-	-
(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	-	-	-	-	49 0	32 6
(ii)राज्य लघु उद्योग विकास निगम	40 5	28 1	36 2	36 3	233 8	191 0
(iii) अन्य	766.2	293 2	1,098.7	471 2	2,738.1	1,258 7
कुल (द)	806.7	321.7	1,139.9	507.5	3,020.9	1,482.3
कुल योग	6,485.3	4,584.7	7,484.2	5,240.7	36,263.9	26,710.8

उद्देश्य बार सहायता (करोड रुपये)

उद्देश्य	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक सचची
नयी	1,834 2	2,591 5	1,826 4	17,767 8
विस्तार	247 2	347 8	367 5	2,383 5
आधुनिकीकरण	293 7	496 0	557 6	2,340 3
पुनर्वास	2 5	14 9	5 5	69 6
अन्य	374 5	678 5	684 8	2,248 2
	2,752 1	4,128 7	3,441 8	24,809 4

निधियों के स्रोत एवं उपयोग वर्ष 1997-98 के दौरान सिडबी को कुल 6,328 करोड रुपये की निधियों की आवश्यकता हुई। इसमें से बड़ा हिस्सा सवितरणों (75.5%) के लिए था। इसके बाद ब्याज, लाभांश/ अन्य व्यय (13.4%) एवं ऋणों एवं जमा राशि की चुकौती (14.8%) का स्थान रहा। वर्ष के दौरान सिडबी ने 81,333 करोड रुपये की निधियाँ एकत्रित की गईं, जो कि कुल एकत्र की गई निधियों का 88.5 प्रतिशत था।

1998-99 के दौरान अधिकतम सहायता नई परियोजनाओं को (53.1%) दी गयी एवं इसके बाद आधुनिकीकरण (16.2%) तथा विस्तार (10.77%) का स्थान रहा। आधुनिकीकरण एवं अन्य उद्देश्य के लिए मंजूरीयों में क्रमशः 12.4% एवं 5.7% एवं 0.9% में वृद्धि हुई, जब कि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए सहायता पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।

वर्ष 1998-99 के दौरान पुनर्वित्त में लघु उद्योगों का हिस्सा 87.4% था। 1996-97 के दौरान 1,492.4 करोड रुपये, 1997-98 में 2,598.3 करोड रुपये, 1998-99 में 1,924.5 एवं मार्च 1999 के अन्त तक सचची 15,427.6 करोड रुपये था।

1998-99 के दौरान परिचालन वर्ष 1998-99 के दौरान सिडबी द्वारा की गई मंजूरीयों

एव सवितरणो मे क्रमश 18.6% एव 19.9% की वृद्धि हुई जो क्रमश 8,880 करोड रुपये तथा 6,285 करोड रुपये के रहे। मार्च 1999 तक के अन्त मे सिडबी की कुल मजूरियों 45,114 करोड रुपये एव सवितरण 32,987 करोड रुपये के रहे।

स्वीकृत एव सवितरित सहायता

वर्ष	स्वीकृतियाँ	वृद्धि दर %	सवितरण	वृद्धि दर
1990-91	2,408.7	—	1,438.5	—
1991-92	2,846.0	18.2	2,027.4	10.3
1992-93	2,909.2	02.2	2,146.3	5.9
1993-94	3,356.3	15.4	2,672.7	24.5
1994-95	4,706.3	40.2	3,389.8	26.8
1995-96	6,065.6	28.9	4,800.8	41.6
1996-97	6,485.3	6.9	4,584.7	(-) 4.5
1997-98	7,584.2	15.4	5,240.7	14.3
1998-99	8,879.8	18.6	6,285.2	19.9
मार्च 1999 के अन्त तक सचयी	45,143.8	—	32,987.0	—

प्रत्यक्ष सहायता 1998-99 के दौरान प्रत्यक्ष वित्त के अधीन मजूरियों 11.4% की कमी आई जो 2,354 करोड रुपये रहे और ये अस्ति निर्माण हेतु कुल मजूरियों के 26.5% रहे जबकि सवितरणो मे 4.3% की वृद्धि हुई। जो 1848 करोड रुपये हो गये। और अस्ति निर्माण हेतु सहायता के 29.4% रहे। विदेशी मुद्रा ऋणो की मंजूरियों मे 16.6% वृद्धि रही जो 357 करोड रुपये के रहे। जबकि रुपया ऋणो मे 32.9% की कमी आई जो 601 करोड रुपये के रहे।

योजनावार मंजूर सहायता (करोड रुपये)
(तालिका)

(प्रत्यक्ष सहायता)

योजना	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक संचयी
(A) आस्ति सृजन प्रत्यक्ष वित्त				
(i) रुपया ऋण	499 5	895 2	601 1	2,728 7
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	84 5	306 4	357 4	778 1
(iii) प्रत्यक्ष अभिदाय	-	-	-	5 8
(iv) बिल फीस	1,748 2	1,422 5	1,370 1	9,355 6
प्रत्यक्ष भुनाई				
(v) इक्विटी प्रकार की सहायता	22 7	31 0	24 8	127 3
बीज पूँजी उप जोड	2,354.9	2,655.1	2,353.5	12,975.6

अप्रत्यक्ष सहायता

(तालिका)

(i) पुनर्वित्त	2,451 0	3,171 8	4,743 8	22,792 3
(ii) बिल पुनर्भुनाई	260 6	203 2	310 0	2,260 8
(iii) वित्तीय मध्यस्थ सस्थाओ को ससाधन सहायता	853 1	1,189 7	1415 4	4,664 2
(iv) एस एफ सी / एस / सी एन बी एफ सी को	553 0	258 0	50 0	2,286 5
उपजोड	4,117.7	4,822.7	6,519.2	32,804.1

अप्रत्यक्ष सहायता

पुनर्वित्त जिसके अन्तर्गत मजूरियो एव पुन वित्त के बदले ऋण सहायता शामिल है। तथा बैंको द्वारा दी गई सहायता (अल्पावधि ऋण) में क्रमश 49.6 तथा 23%की वृद्धि हुई। जो कि क्रमश 4,744 करोड रुपये एव 3,247 करोड रुपये हो गई। जो की अस्ति निर्माण हेतु मजूरियो एव सेवितरणो में क्रमश 53.5% एव 51.7% रहे। बैंको के पुन वित्त में बैंको से सम्बन्धित हिस्सा 1997-98 के 55.2% से 1998 से 99में बढ़कर 28.1%रह गयी।

उद्योगवार मजूर सहायता (करोड रुपये में)

योजना	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक सचची
खाद्य पदार्थ	238.6	313.0	366.5	2,331.7
वस्त्र	311.2	441.6	338.7	2,795.0
रसायन एव रसायन उत्पाद	344.1	333.2	340.0	2,574.4
मशीनरी बिजली एवं इलक्ट्रानिक उपकरण	363.7	342.4	328.9	2,335.1
विद्युत उत्पादन	439.9	434.4	511.6	3,554.5
सेवाए	904.3	1,519.8	983.6	6365.2

राज्य वार मजूरियो को प्रमुख हिस्सा महाराष्ट्र (18%) तमिलनाडु (10.6%) गुजरात (9.5%), कर्नाटक (8.7%), हरियाणा (6.4%), पश्चिमी बंगाल (6.1%) को मिला सिक्किम (230%), मिजोरम (150%), नागालैंड (66.7%), अरुणाचल प्रदेश (50%), महाराष्ट्र (23.6%), तथा पश्चिमी बंगाल (21.5%) को हुई स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राज्यवार स्वीकृत सहायता (करोड रुपये)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक सचयी
गुजरात	372 1	683 3	457 6	4,278 6
हरियाणा	261 9	430 5	306 3	2,038 2
कर्नाटक	306 0	411 7	418 5	2,915 5
महाराष्ट्र	816 1	700 3	865 5	5,289 9
तमिलनाडु	571 6	532 7	509 4	3,767 5
पश्चिमी	156 6	242 4	294 6	1,352 5
बंगाल	4,500 3	5,551 2	4,810 3	34,143 4

सिडबी की देयताएँ एव आस्तियाँ (करोड रुपये)

देयताएँ	1998 (रुपये)	1999 (रुपये)	देयताएँ	1998 (रुपये)	1999 (रुपये)
(i) चुकता पूँजी	450 5	450 0	(i) नकदी एव बैंक शेष	580 8	386 1
(ii) रिजर्व एव निधियाँ	2,068 0	2,622 2	(ii) निवेश	1,215 3	1,043 7
(iii) भारत सरकार रिजर्व	7,681 0	8,022 9	(iii) ऋण एव अग्रिम	9,713 1	11,183 7
बैंक आई आदि से उधार			(iv) बिलो की भुनाई	1,933 2	1,981 2
(iv) बाड एव ऋण पत्र	1,876 1	2,002 4			
(v) जमा राशियो	168 3	299 0			
अन्य	1,668 7	1,907 9	अन्य	469 7	703 7
	1,3912.1	15,298.4		13,912.7	15,298.1

सिडबी की आय व्यय लेखा (करोड रुपये)

व्यय	1998 (रुपये)	1999 (रुपये)	आय	1998 (रुपये)	1999 (रुपये)
(i) ब्याज का भुगतान	938 7	1,047 6	(i) ऋणों पर ब्याज	1,257 9	1,430 0
(ii) अन्य लाभ	64 6	80 5	(ii) बिलो पर	83 9	92 6
(iii) लाभ	405 2	450 4	(iii) अन्य	48 7	55 9
	1,408 5	1,578 5		1,408 5	1,578 5

सिडबी की स्थायी जमा योजना

SCHEMES

Minimum Deposit @

A.	Cumulative Deposit	10,000/-
B	Quarterly Income	10,000/-
C.	Monthly Income	17,000/-

* Additional amounts in multiples of Rs. 1,000

Interest Rates

The Interest Rate Structure for SIDBI Fixed Deposit

(with effect from June 3,2003)

Duration	Interest Rate %p.a.	Annualised yield% p.a.*	Brokesage for deposit from Individual & H.U.F. %
12 months to 23 months	5 50	5 61	
24 months to 35 months	5 75	6.04	
36 months to 60 months	6 00	6.52	0.20

* In respect of Cumulative Deposit, interest is compounded on quarterly basis
depositors include Association of Persons, Company, Partnership Firms, Soci Corporate
Bodies, Proprietorship etc.

DURATION OF DEPOSIT

The minimum and maximum duration of the deposit is 12 respectively The deposits are accepted for a tenure in multiples of

ELIGIBLE DEPOSITORS

- Resident Individual
- Minors,
- HUFs
- Partnership firms
- Companies
- Bodies Corporate
- Societies
- Association of Personss

6 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

1998-99 के दौरान इस निगमो ने किराया खरीद, उपकरण लीमिंग तथा विपणन सहायता की योजनाये के अन्तर्गत कुल 892 करोड रुपये की सहायता प्रदान की।

योजनावार सहायता (करोड रुपये)

	1996-97	1997-98	1998-99
किराया खरीद	2 6	4 4	13 3
उपकरण लीजिंग	14 4	12 7	10 7
विपणन सहायता	641 8	830 6	868 0
(A)घरेलू विपणन	70 8	87 7	69 1
(B)निर्यात विपणन	16 7	13 8	12 1
(C)कच्चे माल की आपूर्ति	554 3	729 1	786 8

इस दौरान मे वर्ष 1998-99 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 13 करोड रुपये के मूल्य की मशीनरी की आपूर्ति की। मशीनरी का बड़ा हिस्सा 42.9%, इजीनियरिंग उद्योग को मिला।

इसके बाद वस्त्र, परिधान आदि(20.3%), छपाई, सामग्री तथा कागज उत्पाद का 9.8% तथा प्लास्टिक, रबड़ एवं चर्म उत्पाद 8.3 का स्थान रहा। मार्च 1999 के अन्त तक इस निगम में मशीनरी के लिए 297 करोड़ रुपये की किराया खरीद सहायता प्रदान की। वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई विपणन सहायता ने 4.5% की वृद्धि हुई यह 869 करोड़ रुपये की होगी। सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम में सहभागिता के जरिये लघु उद्योगों के उत्पादों का विपणन कार्य 1956 में शुरू किया गया। 1976 में एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के रुपये पुनः प्रतिपादित किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों की संख्या 1997-98 के 913 की तुलना में 1998-99 में बढ़कर 1170 हो गयी। इस निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपयुक्तों में 1670 करोड़ रुपये मूल्य के अधिक प्राप्त किये।

वित्तीय कार्य निष्पादन मार्च 1999 के अन्त में इस निगम की पूँजी, रिजर्व बैंक तथा कुल अस्तियों क्रमशः 151 करोड़ रुपये, 14 करोड़ रुपये तथा 555 करोड़ रुपये थी। इस निगम ने वर्ष 1998-99 के दौरान 177 करोड़ रुपये की कुल आय एवं 3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

(करोड़ रुपये)

वित्तीय विशेषताएँ	1997-98	1998-99
कुल आय	189.6	177.3
लाभ	1.9	3.3
चुक्ता पूँजी	132.0	151.0
रिजर्व	10.6	13.8
अस्तियाँ	450.7	555.4

7 राज्य लघु उद्योग विकास निगम राज्य लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना राज्य सरकार के उपक्रमों के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए की गयी थी। जिससे निगम अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य/ संघ प्राशित क्षेत्रों में लघु, अत्यन्त लघु उद्योग का संवर्धन एवं विकास कर सके।

राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण क्रिया कलाप हैं

- (i) कच्चे माल की व्यवस्था एवं वितरण।
- (ii) किराया खरीद आधार पर मशीनरी की आपूर्ति।
- (iii) लघु इकाइयों के उत्पादों हेतु सहायता करना।
- (iv) औद्योगिक संपदाओं (शेडों का निर्माण सम्बद्ध बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना तथा उनका रख रखाव करना)
- (v) सम्बन्धित राज्य सरकारों की ओर से बीज पूँजी सहायता प्रदान करना।
- (vi) हथकरघा, हस्तकला एवं लघु उद्योग इकाइयों की वस्तुओं के लिए बिक्री स्थल उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्ध।

बदलते माहौल को देखते हुए राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने अपने कार्यकलापों के दायरे को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

यद्यपि राज्य लघु उद्योग विकास निगम के कार्यकलापों में अभी भी मुख्य कार्य, कच्चे माल का वितरण है, ये लघु उद्योगों के विकास के विभिन्न पहलुओं विशेषकर मार्केटिंग पर ध्यान रखते हैं। इस प्रकार वे अति लघु एवं लघु उद्योगों के उनके मार्केट शेयर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। कुछ राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने निर्यात मार्केटिंग पर जरूरत मन्द लघु उद्योग इकाइयों के लिए लघु उद्योग के उत्पादों के प्रदर्शन एवं सूचना प्रसार के लिए केन्द्र खोलते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य लघु उद्योग विकास निगम उनके लिए वेब पेजों का विकास भी कर रहे हैं। और सामान्य निर्यात प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे हैं। चडीगाढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु में स्थित आठ राज्य

लघु विकास निगमों को वर्ष 1998-99 के दौरान के परिचालनों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई।

कच्चे माल का वितरण लघु उद्योगों को कच्चे माल का वितरण राज्य लघु विकास निगमों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक बना रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान उपरोक्त 7 राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा वितरित कच्चे माल का कुल मूल्य 374 करोड़ रुपये रहा। जो वर्ष 1997-98 के दौरान उपरोक्त 7 राज्य लघु उद्योग विकास निगमों द्वारा वितरित कच्चे माल का कुल 374 करोड़ रुपये रहा जो वर्ष 1997-98 के समान ही रहा तथापि सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या 1997-98 के समान ही रहा। तथापि सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या 1997-98 के 7500 की तुलना में 1998-99 में घटकर 6687 रह गयी। राजस्थान में राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा वितरित कच्चे माल के मूल्य में सबसे अधिक 42.3% की वृद्धि हुई। उसके बाद गोवा 33.8%, चंडीगढ़ 26.8%, केरल 21.1% तथा महाराष्ट्र 15.3% का स्थान रहा।

राज्य लघु उद्योग विकास निगम के क्रियाकलाप (करोड़ रुपये)

	1997-98	1998-99
कच्चे माल का वितरण	373.6	373.4
विपणन सहायता	387.7	418.7

विपणन सहायता कच्चे माल के वितरण एवं आपूर्ति के अलावा राज्य लघु उद्योग विकास निगम लघु उद्योगों को उनके उत्पादों का घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों पर मार्केटिंग कर सहायता करते हैं। वे लघु उद्योग इकाइयों के लिए उनकी ओर से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगों व्यापार मेलों में सहभागिता के जरिए एवं सरकारी विभागों/उपक्रमों से बड़े आदेश प्राप्त करते हैं। वे लघु उद्योग इकाइयों के आदेश कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद बिल भुनाई एवं अग्रिम/तत्काल अदायगी की

व्यवस्था के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करते हैं। योजना के अन्तर्गत देशी विपणन के लिए कुल सहायता 1997-98 के 388 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 419 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार की सहायता में केरल में (133.3%) की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद गोवा (50%) एवं मध्य प्रदेश (12.1%) एवं महाराष्ट्र 19.2% का स्थान रहा।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लघु स्तरीय उद्योगों एवं लघु व्यवसाय वित्त (**Small Business Finance**) का स्टेट बैंक के ऋण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1997-98 के दौरान लघु उद्योग इकाइयों को दिया गया अग्रिम बढ़ाकर 10,014 करोड़ रुपये हो गया। जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक था। लघु व्यवसाय के अन्तर्गत खुदरा व्यापारियों व्यक्तियों, परिवहन प्रचालकों को, व्यावसायिकों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के प्रदान किया गया। अग्रिम 1997-98 में 3,711 करोड़ रुपये रहा। जो 1996-97 की तुलना में 32.8 प्रतिशत अधिक था।

लघु एवं मध्यम उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करो कि साथ साथ बैंक अपने प्रौद्योगिकी समूह के मध्यम से तकनीकी उन्नयन में एक उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाता है।

7 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया · रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों की सहायता के लिए 1960 में एक साथ गारण्टी योजना बनायी गयी। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों के ऋण देने वाली संस्थाओं को सम्भावित हानि के विरुद्ध गारण्टी देना है, ताकि लघु उद्योगों को अधिकाधिक साख उपलब्ध हो सके। इस योजना के अन्तर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की गारण्टी करता है। फरवरी, 1970 के एक सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक जिन ऋणों की गारण्टी करता है, उन पर होने वाली हानि का 75% लाख रुपये के ऋण दिये जा सकते हैं। लम्बी अवधि के 25 लाख रुपये के ऋण दिये जा सकते हैं। जिसकी रिजर्व बैंक के गारण्टी संगठन के द्वारा गारण्टी की जाती है।

रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को उदार साख सुविधाएँ देकर उन्हें छोटे-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है । 31

मार्च, 1981 को रिजर्व बैंक ने इस योजना को रद्द कर 1 अप्रैल 1981 से इसके स्थान पर नयी योजना प्रारम्भ की गयी। इसका लक्ष्य इस सभी साख सस्थाओं को गारण्टी देना था। जो लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दे रही थी। पुरानी योजनाओं में जो गलती पायी जाती थी। उन्हें इस योजना से दूर कर दिया गया था। सभी व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम तथा सहकारी बैंक इसमें भाग ले सकते थे। 30 जून 1999 तक 592 साख सस्थाएँ इसमें भाग ले रही थी। इनमें से 92 व्यापारिक बैंक, 110 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, 190 सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम, तथा 3 राज्य विकास एजेंसी थी। 30 जून, 1999 को इस योजना के अन्तर्गत 15232 करोड़ रुपये के ऋणों की गारण्टी दी गयी थी।

निष्कर्ष आर्थिक समीक्षा 2002-03 के अनुसार घरेलू मदी के बाद भी लघु क्षेत्र का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2002-03 में सतोषजनक रहा है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में लघु क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों की संख्या के 35 72 लाख होने का अनुमान है। जबकि गत वर्ष यह संस्था 34 42 लाख थी।

साख चालू मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2002-03 में लघु क्षेत्र के समग्र उत्पादक का मूल्य 7,42,021 करोड़ रुपये आकलित किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित करता है। स्थित कीमतों पर भी वित्तीय वर्ष 2002-03 में 7 5 की भी वृद्धि आकलित की गयी है। वर्तमान में लघु क्षेत्र में 199 65 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। जो वित्तीय वर्ष 2001-02 की तुलना में 3 9 की वृद्धि दर्शित करता है।

दर्शक समग्र निर्यात में लघु क्षेत्र की भागदारी एक तिहाई से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में लघु क्षेत्र के उद्यमियों की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी।

Table
SOURCES AND USES OF FUNDS OF 1,125 SELECTED
SMALLPRIVATE LIMITED COMPANIES

(1)	(Rs Crores) (2)	%share in the total (3)
Sources of Funds		
Internal Sources	468	22.52
<i>A 1 Paid-up capital</i>	9	0 43
<i>B Reserve and surplus</i>	13	0 58
2 Capital reserve	5	
3 Development rebate reserve	16	
4 Others	2	
<i>C Provisions</i>	446	21.46
5 Depreciation	408	19 63
6 Taxation (net of advance of income-tax)	17	0 82
7 Other current	10	0 48
8 Non- current	11	0 53
External Sources	1,610	77.48
<i>D Paid-up capital</i>	100	4 81
9 Net issues	100	4 81
10 Premium on shares	-	-
<i>E Borrowings</i>	898	43.21
11 From banks	543	26 13
12 From Industrial Finance Corporation and State Financial Corporations	-	-
13 From other institutional agencies	27	1 30
14 From Government and semi-Government agenices	5	0 24
15 From others	323	15 54
16 From others	611	29.40
<i>F Trade dues and other liabilities</i>	575	27 67
16 Sundry creditors	36	1 73
17 Others	-	-
<i>G 18 Miscellaneous non-current liabilities</i>	2,078	100.00
19 TOTAL		
Uses of Funds		
<i>H Gross fixed assets</i>	710	34.17
20 Land	31	1 49
21 Buildings	140	6 74
22 Plant and Machinery	420	20 21
23 Capital works in progress	2	0 10
24 Others	116	5 58

(1)	(2)	(3)
<i>I Inventories</i>	514	24.73
25 Raw materials, components, etc	290	13 96
26 Finished goods	193	9 29
27 Work in progress	27	1 30
28 Others	59	2 84
<i>J Loans and other advances and other debtor balances</i>	744	35.80
29 Sundry debtors	598	28 77
30 Others	146	7 02
<i>K</i> 31 Investments	37	1 78
<i>L</i> 32 Other assets	7	0 34
<i>M</i> 33 Cash and bank balances	80	3 85
34 Total	2,078	100 00

Table
ASSISTANCE SANCTIONED TO SMALL-SCALE SECTOR BY SFCS
(Rs crore)

Year	Total	Small-scale Sector	(2) as % of (1)
	(1)	(2)	(3)
1986-87	1,210 8 (28964)	997 6 (27868)	82 4 (96 2)
1987-88	1,305 0 (33510)	1,004 4 (31849)	77 0 (95 0)
1988-89	1,391 1 (34498)	1,117 8 (32804)	80 4 (95 1)
1989-90	1,514 2 (41664)	1,263 1 (40466)	83 4 (97 1)
1990-91	1,863 9 (49177)	1,491 8 (45092)	80 0 (91 7)
1991-92	2,190 3 (43981)	1,871 9 (42554)	85 5 (96 8)
1992-93	2,015 3 (38040)	1,685 7 (36713)	83 6 (96 5)
1993-94	1,908 8 (29641)	1,561 1 (28279)	81 8 (95 4)
1994-95	2,702 4 (31891)	1,920 4 (28331)	71 1 (88 8)
1995-96	4,188 5 (35998)	2,513 3 (30224)	60 0 (84 0)
1996-97	3,544 8 (34445)	2,115 0 (26525)	59 7 (77 1)
1997-98	2,628 6 (25545)	1,767 9 (22182)	67 3 (86 8)
Cumulative upto end March 1998	29,138 8 (673359)	20,545 7 (600639)	70 5 (89 2)

Note Figures in brackets under cols (1) & (2) relate to number of units sanctioned assistance and under col (3) percentage share in respect of unnumber of units

Table
ASSISTANCES SANCTIONED AND DISBURSED

(Rs crore)

Year	Sanctions	Growth rate %	Disbursements	Growth rate %
1990-91	2,408 7	-	1,838 5	-
1991-92	2,846 0	18 2	2,027 4	10 3
1992-93	2,909 2	2 2	2,146 3	5 9
1993-94	3,356 3	15 4	2,672 7	24 5
1994-95	4,706 3	40 2	3,389 8	26 8
1995-96	6,065 6	28 9	4,800 8	41 6
1996-97	6,485 3	6 9	4,584 7	(-)4 5
1997-98	7,484 2	15 4	5,240 7	14 3
1998-99	8,879 0	18 6	6,285 2	19 9
1999-2000	10,265 0	-	6,964 0	-
2000-2001	10,821 0	-	6,441 0	-
Cumulative upto end March 2001	66,229 0	-	46,392 0	19,837 0
(i) Refinance	22,792 3	-	17,225 2	8,749 8
(ii) Bills Redis- counting	2,260 8	-	1,622 9	664 9
(iii) Others	7,115 1	-	4,190 3	1,268 1
(iv) Direct Finance	12,975 6	-	9,948 6	1,960 2

लघु उद्योगों के सहायतार्थ संस्थाएं

1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड —इस संगठन को लघु लिए 1955 में स्थापित किया गया था । संगठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकारी खरीद को सुगम बनाना था । लेकिन कुछ समय के पश्चात इस निगम ने लघु उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तथा मशीनरी को किराया खरीद के आधार पर इन उद्योगों को उपलब्ध कराने का जिम्मा ले लिया । लघु उद्योग निगम निदेशालय द्वारा स्वीकृति मिलने के आधार पर फिलहाल इस कार्य को संपन्न करता है।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार सरकारी खरीद में प्राथमिकता हासिल करने के लिए किसी भी निगम का स्टोर खरीदारी में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। लघु उद्योग इकाइयाँ इस पंजीकरण के माध्यम से जिन लाभों के लिए अधिकृत हो जाती हैं वे निम्नलिखित हैं—

- (1) इकाइयों को सुरक्षा धन देने से छुटकारा मिल जाता है।
- (2) इन उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में 15 प्रतिशत मूल्य प्रमुखता मिल जाती है। इसके कारण सरकारी खरीद में लघु उद्योगों से माल खरीदने को प्रमुखता मिल जाती है।
- (3) निगम की सिफारिश पर कोई भी बैंक आसानी से स्वीकृत कर लेता है।
- (4) लघु उद्योग पतियों को निगम मशीनों की किराया पद्धति खरीद में विशेष तौर पर सहायता देने के लिए प्रयास करता है। मशीन की कीमत और ब्याज की पूरी रकम को सात वर्षों में वापस लौटाना होता है इसके साथ—2 निगम ने लघु उद्यमियों को उत्पादन एवं प्रशिक्षण देने के लिए भी केन्द्रों को स्थापना की है।

1—	केन्द्रीय कार्यालय	इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली—20
2—	क्षेत्रीय कार्यालय	
	पूर्वी क्षेत्र	2,सेट जार्ज गेट रोड कलकत्ता—32
	उत्तरी क्षेत्र	इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली—20
3—	उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	
	इंडो—जर्मन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र,	
	इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली—110020	
	इंडो—अमेरिकन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र,	
	राजकोट गुजरात	

- (1) औद्योगिक विकास तथा आधुनीकीकरण की सहायता देना।
- (2) तकनीकी जानकारी देने के साथ-2 आर्थिक सुविधा जुटाना।
- (3) प्रबधन एव तकनीकी सबधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- (4) कारखाना स्थापित करने हेतु भूमि एव भवन के लिए सहयोग करना।
- (5) सरकारी विपणन मे लघु उधोगो द्वारा भाग लेने के बारे मे जानकारी उपलब्ध कराना।
- (6) उद्योग से सबधित मशीनो की खरीदारी तथा अन्य सुविधाए प्राप्त करने के लिए सलाह देना।

3 राज्य लघु उद्योग निगम — देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा विभिन्न विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए राज्यों में लघु उद्योग निगमों को स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगमों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य है।

- (1) औद्योगिक संस्थान के प्रबंधन एवं विकास में सहायता।
- (2) औद्योगिक इकाई का विकास।
- (3) आयात-निर्यात में सहायता।
- (4) कच्चे माल का वितरण।
- (5) आरक्षित वस्तुओं की बिक्री में मदद।

इसके अलावा, देश के अधिकांश राज्यों में संभव सहायता देने, यहां तक कि देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशी बाजार में बेचने के लिए सहायता देने हेतु स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन स्थापित किए गए हैं। इनके राज्य वार पते निम्नलिखित हैं—

- 1— दि हिमाचल प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला।
- 2— मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सुल्तानिया रोड, भोपाल।
- 3— दि असम स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 1, इंडस्ट्रियल ब्लॉक, गुवाहाटी।
- 4— आंध्र प्रदेश स्माल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बी-1-174, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद-4।
- 5— दि बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, एस0 पी0 वर्मा रोड, पटना-1।
- 6— दि केरल स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पतम कडियार रोड, त्रिवेन्द्रम-4।
- 7— दि उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 14/40 सिविल लाइंस, कानपुर।
- 8— दि पंजाब स्टेट स्माल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, पो0 बा0 11, चडीगढ़।

- 9— दि उडीसा स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड पो0 बा0 85, किला मैदान,
कटक-1।
- 10— दि राजस्थान स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, के-18 दुर्गादास पथ मालवीय
मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर।
- 11— दि कर्नाटक स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस
बिल्डिंग्स इंडिस्ट्रियल एस्टेट, राजाजी नगर, बगलौर।

4 भारतीय मानक सस्थान .— भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगों में बनने वाले कच्चे और पक्के माल की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने के लिए भारतीय मानक सस्थान की स्थापना की। बाद में इस सस्थान का नाम बदलकर 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS)' रख दिया गया।

अब तक भारतीय मानक सस्थान ने छह हजार से भी अधिक भारतीय मानक तय किये हैं। खेलकूद के सामान, साबुन स्याही, खाद्य तेल, पशु चारा, कृषि उपकरण, टाइल्स चमड़े की वस्तुओं आदि के लिए भारतीय मानक सस्थान में मानकों को तय किया है। सस्थान का प्रमाणीकरण मानक योजना लघु उद्यमियों के खरीददार को यह विश्वास दिलाती है कि इन उद्यमों में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की परीक्षा कर ली गई है। सस्थान का चिन्ह हासिल करने के लिए लघु उद्यमी को निम्न प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है —

- 1 भारतीय मानक सस्थान का डायरेक्टर को निर्धारित फार्म के तहत दो प्रतियों में आवेदन करना पड़ता है।
- 2 एक मानक के तहत आने वाली मद हेतु भिन्न-2 आवेदन करना पड़ता है।
- 3 निरीक्षण तथा परीक्षण के परिणाम फार्म के पक्ष में होने की स्थिति में सस्थान योजना का मसौदा तैयार करने के बाद आवेदक के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।
- 4 अब निर्माता को लाइसेंसधारी कहा जाता है और उसे सालाना लाइसेंस शुल्क देना

पडता है। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए रूपये सदा करने होंगे।

यदि लघु उद्यमी को भारतीय मानक सस्थान द्वारा निर्धारित शर्त का पालन करने में कठिनाई महसूस होती है तो वह 'क्यू' चिन्ह लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस चिन्ह को लगाने की सुविधा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों में सफलता पूर्वक चल रही है।

भारत सरकार द्वारा निर्मित अथवा गठित सभी तकनीकी समितियों में लघु उद्योग के प्रतिनिधि को आवश्यक रूप में शामिल किया जाता है। राज्यों के उद्योग निदेशक, लघु उद्योग विकास सगठन तथा राज्यों के उत्पादों के गुणवत्ता संबंधी चिन्ह लगाने वाले केन्द्र इस सस्थान की गतिविधियों को अपने -2 स्तर पर चलाते रहते हैं।

भारतीय मानक सस्थान का पता

मुख्य कार्यालय — बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1

शाखाएँ —

1 54, जनरल पैटर्स रोड, चेन्नई-2।

2 117/418 बी, सर्वोदय नगर, कानपुर-5।

3 5-9-201/2 चिराग अली लेन हैदराबाद-1।

4 5, चौरंगी एप्रोच, कलकत्ता-13।

5 लघु उद्योग सेवा सस्थान — इन सस्थानों को लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा संचालित किया जाता है। इन सस्थानों की स्थापना देश के लगभग सभी प्रदेशों में हो चुकी है। प्रत्येक राज्य तथा दिल्ली के संघीय राज्य क्षेत्र में एक-एक ऐसा सस्थान है। हरियाणा की आवश्यकताओं की पूर्ति नई दिल्ली के संघीय राज्य क्षेत्र। जब कि गुवाहटी स्थित लघु उद्योग सेवा सस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश मेघालय और मिजोरम के लिए भी कार्य करता है। इन सस्थानों की स्थापना लघु उद्योग के विकास को तेज करने तथा इन उद्योगों के उद्यमियों को विभिन्न विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई है। चूंकि लघु उद्यमी आम तौर

पर योग्यता प्राप्त इजीनियर तथा प्रबधको को नियुक्त करने मे सक्षम नही होते इसलिए बडे उद्योगो की तुलना मे जिन कठिनाइयो का सामना लघु उद्योग के उद्यमियो को करना पडता है। सेवा संस्थान उसे दूर करने का प्रयास करता है। इन संस्थानो के प्रमुख कार्य निम्न है -

- 1 प्रबधन तथा उत्पादन मे सुधार लाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाए।
- 2 आदर्श योजना, डिजाइन, तकनीकी पुस्तके, नक्शे आदि की तैयारी।
- 3 प्रबधन तथा तकनीकी सलाह तथा सबधित उद्योग की उन्नति तकनीको का प्रदर्शन।
- 4 आर्थिक अन्वेषण।
- 5 सबधित क्षेत्र मे सर्वेक्षणो की व्यवस्था।
- 6 प्रायोगिक रिपोर्ट और बिक्री सबधी रिपोर्ट की तैयारी।
- 7 लघु उद्योगो मे निर्मित उत्पादो के निर्यात-आयात, बिक्री आदि के सबध मे कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन।

लघु उद्योग सेवा संस्थानो, विस्तार एव उत्पादन केन्द्रो के पते

आन्ध्र प्रदेश-

3-4-812 बरकतपुर रासायनिक परीक्षण और विश्लेषण प्रयोगशाला, रेत और धातु परीक्षण, स्वर्ण विलास, सिरामिक्स परीक्षण इकाई, स्टोन एनेमल करना, विट्रियस-ग्लास ब्लोइंग हैदराबाद-27 और प्रयोगशाला के काच के समान की साधारण वस्तुए।

विस्तार केन्द्र

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 ए-1 इंडिस्ट्रियल एस्टेट सनत नगर
हैदराबाद-18 | इलेक्ट्रो प्लेटिंग और हीट ट्रीटमेट, टूल रूम |
| 2 पापना इडूपेट वाया रेनीगटा
नलिया, जिला चित्तूर | सामान्य इजियनरी तथा धातु परीक्षण, काच की प्लास्टिक और काच के मोती। |
| 3 बी-2 यूनिट इंडिस्ट्रियल एस्टेट
विजयवाडा, जिला कृष्णा | सामान्य इजीयनरी, फाउंडरी वर्कशाप |

असम—

मुख्य लघु उद्योग एवं सेवा सस्थान—

1 ट्रेजरी बिल्डिंग सदर घाट, सिल्वर

2 पासी घाट, ब्यूनि मैदान, गुवाहटी

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान—

सचिवालय का उत्तर खड, डाकघर इम्फाल, मणिपुर

विस्तार केन्द्र

1 राजाबाडी जोरहाट वर्कशाप

2 पार्वती गाव विनसुखिया वर्कशाप

गोवा—

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान

मिराडा बिल्डिंग, मीराबाज पोस्ट बॉक्स स 334 मारगावो गोवा रासायनिक परीक्षण

वर्कशाप

अलकार बिल्डिंग मार्टायर्स, डियास रोड

वर्कशाप, सामान्य इजीनियरी

मझगावो गोवा

दिल्ली और हरियाणा—

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने

टूलखम और सामान्य इजीनियरी, वर्कशाप,

यात्रिक परीक्षण, नई दिल्ली-20

रासायनिक प्रयोगशाला,

विद्युतीय प्रयोगशाला, लेस

ग्राइडिंग आदि। औद्योगिक डिजाइन कक्ष भी

है।

विस्तार केन्द्र

1. रेवाडी (हरियाणा)

जूते और अलौह धातु

2 बाल सहयोग, कनाट सर्कस बेत की लकड़ी का फर्नीचर, शीट मेटल और दर्जी
नई दिल्ली-1 का काम

3 242-1, माडल टाउन धातु परीक्षण
यमुनानगर, जगाधारी (हरियाणा)

जम्मू कश्मीर-

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

1 17-डी, गाधीनगर, जम्मू (सर्दियों के लिए)

2 स्कूल ऑफ डिजाइन्स बिल्डिंग, करन नगर, वर्कशाप और प्रयोगशाला
श्रीनगर (गर्मियों के लिए)

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान

इंडस्ट्रियल स्टेट, जम्मू वर्कशाप

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान (उत्तर प्रदेश)

1 1ई 178/8 इंडस्ट्रियल एस्टेट टूलरूम, सामान्य इजीनियरी और शीट मेटल
नैनी, इलाहाबाद

2 एवागढ हाउस, 121, महात्मा सामान्य इजीनियरी, धातु रेत परीक्षण और
गाधी रोड आगरा रासायनिक प्रयोगशाला

विस्तार केन्द्र

1 एस एन मार्ग, फिरोजाबाद काच परीक्षण

2 सूजर कुड रोड, मेरठ चमड़े को फिर से कमाना और चमड़े का काम

3 रहीम की सराय, अलीगढ टूलरूम, सामान्य इजीनियरी, सॉल्ट वाथ,
परीक्षणके लिए प्रयोगशाला

पश्चिम बंगाल—

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

112 बी टी रोड, कलकता—3

मशीन शाप, ताप उपचार, मृत्तिका वर्कशाप,
विद्युतीय धात्विक ।

विस्तार केन्द्र

1 58/5 बी बीटी रोड कलकता—2

जूते

2 33/1 नार्थ टाप्सिया, रोड, कलकता—46

चमड़ा कमाना

3 चेल्स पुरा रोड, पुराना माल्दा, माल्दा

लोहार गिरी और बढईगिरी

4 टी0 बी0 अस्पताल, के समीप, नव,

पीतल और बेल धातु

द्वीप नाडिया

राजस्थान

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर—1

वर्कशाप और प्रयोगशाला

विस्तार केन्द्र

1 A/2—3 इंडस्ट्रियल एस्टेट डाकघर

इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एनोडाइजिंग मशीन शाप

प्रताप नगर, उदयपुर

2 रोड न AII—2 इंडस्ट्रियल स्टेटफोटा

यात्रिक

7 स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन —देश के लगभग सभी प्रदेशों में फाइनेशियल कारपोरेशन यानी वित्तीय निगमों को स्थापित किया गया है, जिनका प्रमुख कार्य लघु एवं बड़े उद्योगों को उचित ब्याज पर ऋण की सुविधा देना है। इकाई उद्योग निदेशालय में रजिस्टर्ड सस्थाओं के आवेदन—पत्रों पर ही वित्तीय निगम विचार करते हैं। ऋण लेने के लिए निगम के निर्धारित प्रपत्र को जमा किया जाता है। इस प्रपत्र का अध्ययन करने के बाद ऋण मंजूर हो जाता है। ऋण उपलब्ध कराने के लिए अलावा वित्तीय निगम कुछ दूसरे कार्यों के लिए भी सहायक होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं —

- 1 कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को प्रबन्धन तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- 2 निर्यात व्यापार में सहायता देना।
- 3 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देने के अलावा ऋण—पत्र की खरीद।
- 4 इन प्रतिष्ठानों द्वारा शेयर्स, स्टॉक, ऋण—पत्र आदि की जिम्मेदारी लेना।

वित्तीय निगम की ब्याज की दरें आमतौर पर रिजर्व बैंक की ब्याज दरों के अनुपात में रहती हैं। इन दरों से यह निगम एक या दो प्रतिशत अधिक लेते हैं। आमतौर पर इन निगमों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अदायगी के लिए सात से 20 वर्ष का समय तय किया जाता है। वित्तीय निगमों के अलावा लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक सस्थान एवं निगम कार्यरत हैं। इनके राज्यवार पते निम्नलिखित हैं —

- 1 उत्तर प्रदेश फाइनेशियल कारपोरेशन, 7/174 स्वरूप नगर कानपुर ।
- 2 हरियाणा फाइनेशियल कारपोरेशन, चण्डीगढ़।
- 3 उड़ीसा स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, किला मैदान, कटक—1
- 4 केरल स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, बेल्लायाम्बलम, त्रिवेन्द्रम—1।
- 5 आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, पो0 बा0 165, 5—9—194, चिराग अली लेन, हैदराबाद—।
- 6 असम फाइनेशियल कारपोरेशन, क्लेनर क्वार्ट, हाउस, शिलांग—1।

- 7 बिहार स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, फ्रेजर रोड, पटना-1
- 8 दिल्ली स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, सरस्वती भवन, ई ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1।
- 9 मध्य प्रदेश फाइनेशियल कारपोरेशन, शिव विलास, इंदौर-2।
- 10 पंजाब स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, 72,73, सेक्टर 17 बी, बैंक स्क्वायर, चंडीगढ़।
- 11 कर्नाटक, स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, थी सैलीम न 7, पहली मेन रोड गांधी नगर बंगलौर।

8 भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड – पूर्व में उद्योगों को लंबे समय तक उचित दरों पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसके अलावा यदि इन्हें कच्चा माल मिल भी जाता तो उसकी दर इतनी अधिक होती थी कि वे इसमें वे अपने आपको असमर्थ पाते थे। इसका लाभ बड़े उद्योग ले जाते हैं। कच्चा माल उचित दर पर उद्योगों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड की 1956 में स्थापना की गई।

राज्य व्यापार निगम लघु उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले उन वस्तुओं की पहचान कराता है। इसके बाद किसी विदेशी फर्म को थोक में आर्डर देकर इन वस्तुओं को सस्ती दर पर खरीद लेता है। यदि सभी रजिस्टर्ड उद्योग अपने उत्पाद को निगम में पंजीकृत करा ले तो निगम विदेशी मांग की पूर्ति के लिए इन उद्योगों से विदेशी समानों की खरीद के अलावा उनकी बिक्री को विदेशी बाजार में सुनिश्चित करने में मदद देता है। यहाँ यह जानकारी देना आवश्यक है कि लघु उद्योग निर्यात सहायता योजना के तहत केवल कुछेक वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसलिए यही उत्पाद इस योजना का लाभ ले पाते हैं।

लघु उद्योग के लिए निर्यात सहायता योजना के तहत कृषि संबंधी उपकरण और औजार, कटलरी, पाइप फिटिंग, कृत्रिम आभूषण, रेजर ब्लेड, ड्रिलीकैटर, प्रेशर स्टोव, घरेलू तथा कार्यालय का स्टील फर्नीचर, स्टोरेज बैटरियाँ, टेलकम पाउंडर, ऊन के स्वेटर, स्टेनलेस स्टील से बने सर्जरी में काम आने वाले उपकरण, वायुरोधक आदि मशीन शामिल हैं।

एस0 टी0 सी (स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन)

मुख्य कार्यालय — भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली

प्रादेशिक कार्यालय —

महाराष्ट्र निर्मल बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई—20

विशाखापत्तनम 14/37 बीच रोड विशाखापत्तनम

पश्चिम बंगाल स्टैंडर्ड बिल्डिंग, 32 डलहौजी स्क्वेयर साउथ, कलकता—1

तमिलनाडु 119—120 आर्मेनियम स्ट्रीट, चेन्नई—1

उपशाखा कार्यालय

कच्छ बगला न एस डी बी/ 11—12, डा0 आदिपुर, (कच्छ)

बगलौर 38, वसतनगर एक्स्टेंशन, बगलौर छावनी

बेलगाम 31/21 गुड्स शेड रोड, रेल पुल के निकट

कोचीन बिलिंग्डन द्वीप कोचीन

हास्पेट फर्स्ट क्रॉस रोड, पटेल नगर हास्पेट

नागपुर 31/64 राजेद्र नगर, विमाचरेल पोस्ट

विदेशी कार्यालय बुडापेस्ट, नैरोबी, माट्रियल, प्राग

विदेशी शो रूम बैकाक, बगदाद, बेखत, तेहरान

निर्यात प्रोत्साहन परिषद कच्चे माल या पक्के माल के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन तथा लघु उद्यमियों को सहायता देने के लिए अनेक निर्यात प्रोत्साहन आयोगों की स्थापना की गई है। इन आयोगों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं —

- 1 विदेशी बाजार से संबंधित अधिकांश जानकारी को लघु उद्यमियों तक पहुंचाना।
- 2 अपने सदस्यों को निर्यात नीति में समय—समय पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी उपलब्ध कराना।
- 3 विदेशी खरीददार तथा उनकी भारतीय उद्यमियों से उत्पाद संबंधी अपेक्षाएँ एवं मात्रा

आदि की जानकारी अपने पजीकृत आपूर्ति कर्ताओं को देना।

4 छोटे निर्यात कर्ताओं के समानों को विदेशी बाजार में बेचने के लिए मदद पहुंचाना।

इनका पते सहित विवरण निम्नलिखित हैं —

काजू केश्यू एक्सपोर्ट, प्रमोशन कौंसिल वर्ल्ड ट्रेड सेटर, महात्मा गांधी रोड रासायनिक तथा केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, 14—बी,

सबद्ध पदार्थ	एज्रा स्ट्रीट, दुसरा तल्ला, कलकता।—।
लाख	शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, 14/।—बी अजरा स्ट्रीट कलकता
वस्त्र	कौंसिल, रेशम भवन 78, वीर नरीमन रोड मुंबई
चमड़ा	लैडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, मार्बल हॉल 3/38 वेपेरी हाईरोड, चेन्नई—3
सूती वस्त्र	काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, इजीनियरिंग सेटर, 9—मैथ्यू रोड मुंबई
तबाकू	टोबैफो एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, 123 माउट रोड, चेन्नई।
रेशमी और रेयनके	सिल्क एंड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन
जड़ित आभूषण	सेटर, तारदेव, मुंबई
बुनियादी रसायन	बेसिक केमिकल्स, फार्मस्यूटिकल्स एंड
भेषज और साबुन	सोप एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल प्लॉट नं 56, अशोक चेंबर्स, झासी कोरेल, 7 कुपरेट स्ट्रीट मुंबई
वस्तु बोर्ड (कोमोडिटी बोर्ड)	
रेशम	दि सेट्रल सिल्क बोर्ड, 'मेघदूत' 95—बी, मेरीन ड्राइव, मुंबई—2
चाय	दि टी बोर्ड, पोस्ट बॉक्स नं 2172, 14, ब्रेबोर्न रोड, कलकता
इलायची	कार्डमम बोर्ड, 14/44 चितौड रोड, एर्नाकुलम कोचीन
हथकरघा	दि आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, पोस्ट बॉक्स 1004, मुंबई—1

कॉफी	दि कॉफी बोर्ड न 1, विधाना विधि बगलौर
नारियल रेशा	दि कायर बोर्ड, पोस्ट बाक्स 80, एनीकुलम (केरल)
राज्य निर्यात निगम—	
हरियाणा	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम बैंक स्ट्रीट, सेक्टर 17—डी, चडीगढ
पजाब	पजाब निर्यात निगम यूनाइटेड कामर्शियल बैंक बिल्डिंग, तीसरा तल्ला, सेक्टर 17—बी, चडीगढ
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा उद्योग निदेशक, जी टी रोड, उद्योग भवन, कानपुर
गुजरात	गुजरात निर्यात निगम इंडस्ट्रीज हाउस, एचके आर्ट्स कॉलेज के सामने, अहमदाबाद—9
बदरगाहो पर निर्यात संवर्धन कार्यालय—	
मुबई	संयुक्त निदेशक (निर्यात संवर्धन) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात कार्यालय, न्यू मैरीन लाइस, चर्च गेट मुबई—1
एर्नाकुलम	उपमुख्य नियंत्रक (निर्यात संवर्धन) संयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात और कार्यालय, हीडी रोड, एर्नाकुलम (केरल)

9 उद्योग निदेशालय — लघु उद्योग के विकास एवं उन पर नजर रखने के लिए देश के प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों द्वारा उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। ये कच्चे—पक्के माल का वितरण, जमीन भवन और उपकरणों के प्रबंधन से लेकर ऋण दिलाने तक यह निदेशालय कच्चे माल एवं उपकरणों के उपयोग पर भी नजर रखते हैं तथा मागदर्शन देते हैं। शुरुआत में उद्योग निदेशालयों में कुशल अधिकारी नहीं थे। लेकिन धीरे—2 राज्य अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होते गये और उन्होंने विभागों में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की।

किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन राज्य उद्योग निदेशालय या जिला उद्योग सरकारी सहायता अधिनियम के तहत किसी फर्म को ब्याज एक लाख रुपये का अधिकतम ऋण मजूर किया जाता है। उद्योग निदेशक कच्चे माल व वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग पर कड़ी नजर रखते हैं। नजर रखने का यह कार्य जिला उद्योग अधिकारी का होता है।

लघु उद्यमियों को यथा सभव लाभ पहुंचाने के उद्देश्य और अपने राज्य के उद्यमों के हितों की देखरेख करने के लिए सभी राज्यों के उद्योग आयुक्तों ने नई दिल्ली में अपने-2 कार्यालय स्थापित किये हैं।

लघु उद्योगों द्वारा तैयार किए जाने वाले माल की बिक्री के लिए राज्य सरकारों की ने एपोरियम या इसी प्रकार के अन्य विपणन केन्द्र खोले गए हैं। खरीददारी करने समय भी लघु उद्योगों को राज्य सरकारों की प्राथमिक सूची में रखा जाता है। विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशालयों में पते निम्नलिखित हैं —

1 उद्योग निदेशक	आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
2 उद्योग निदेशक	हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
3 उद्योग निदेशक	हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
4 उद्योग आयुक्त	कर्नाटक सरकार, बंगलौर
5 उद्योग निदेशक	त्रिपुरा सरकार, अगरतला
6 उद्योग तथा पूर्ति निदेशक	राजस्थान सरकार, जयपुर
7 उद्योग निदेशक	नागालैण्ड सरकार, कोहिमा
8 उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक	जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर
9 उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक	केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम

10 भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम – खनिज एवं धातुओं का व्यापार करने के लिए सन् 1965 में भारत सरकार ने इस निगम की स्थापना की। इसका कार्य आयात-निर्यात तथा विकास कार्यों की निगरानी व नियंत्रण रखना होता है। इसका पता निम्नलिखित है – प्रधान कार्यालय भारतीय खनिज तथा व्यापार निगम लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, दिल्ली-1

प्रादेशिक कार्यालय

तमिलनाडु 1/155, माउंट रोड, चेन्नई-2

आंध्र प्रदेश 25-15-50, गोदावरी स्ट्रीट, विशाखापत्तनम

राष्ट्रीय परीक्षण गृह यह संस्थान उद्योग तथा व्यापार में होने वाले कच्चे और पक्के माल का परीक्षण का कार्य करता है। किसी भी परीक्षण करने के लिए यह संस्थापन एक निश्चित शुल्क लेता है। परीक्षण गृह का पता इस प्रकार है –

नेशनल टेस्ट हाउस अलीपुर, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

श्रीराम टेस्ट हाउस श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिवर्सिटी इक्लेव, दिल्ली

11 भारतीय लघु उद्योग संघ – प्रत्येक व्यापारिक समुदाय अपनी समस्या व हितों की रक्षा के लिए किसी न किसी संगठन की स्थापना करता है। जिला स्तर व राष्ट्रीय सभी स्तरों पर यह संघ कार्यरत है। हम संघों के उद्देश्य निम्न हैं –

1 व्यवसाय व तकनीकी संबंधी परामर्श सेवाएं जारी करता।

2 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा लघु उद्योगों को उनके बारे में जानकारी देना

3 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान संबंधी कार्यों का सर्वेक्षण।

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के पते –

पंजीकृत कार्यालय :- लघु उद्योग कुटी, 23-बी/2 रोहतक रोड, नई दिल्ली-5

प्रादेशिक कार्यालय – 67-71 तेमरिंड लेन, फोर्ड चैम्बर्स मुंबई 10, जी एम टी, चेन्नई-32 (तमिलनाडु)

विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले लघु उद्योग मण्डल – अखिल भारतीय ऑल इंडिया
मैन्यू फैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन 30, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली-1

दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, 33, डिप्टीगज दिल्ली-6

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 106/377 'पी' रोड कानपुर

चेन्नई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 44 माउट रोड

मुंबई मुंबई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 91-92 पठान स्ट्रीट, मुंबई-4

केरल दि केरल स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन, कोचीन

12 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला – भारत सरकार द्वारा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
की स्थापना 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। इस अनुसंधान का समन्वय एक
यूनिट के रूप में लघु उद्यमियों की मदद तथा सूचना संपर्क स्थापित करता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद देश भर में लगभग 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ
तथा अनुसंधान को स्थापित किया गया है। परिषद का प्रमुख उद्देश्य देश में औद्योगिक तथा
वैज्ञानिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं विकास कार्यक्रम संचालित करना है। प्रयोगशाला, पाशान, पूना-8।

1 राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पाशान, पूना-8

2 राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, हिलसाइड रोड, पूसा नई दिल्ली-12

3 राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला पोस्ट बॉक्स 4, बगलौर-17

4 क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट आसाम

5 राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, राजा प्रताप मार्ग, लखनऊ

6 क्षेत्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, अडयार, चेन्नई-20

7 राष्ट्रीय चीनी संस्थान, नवाबगज, कानपुर

8 केन्द्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा

9 केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, बर्वा रोड, धनबाद (बिहार)

10 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान मोहकमपुर देहरादूर

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा सहायता प्राप्त

- 1 अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अहमदाबाद
- 2 वाकले एक्सपेरीमेंट स्टेशन, सिन्नमारा, जोरहाट (असम)
- 3 ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 41, अशोक नगर, पूना-7
- 4 इंडियन जूट इंडस्ट्रियल, 17, रिसर्च एसोसिएशन, तारातोला रोड, कलकता

13 निर्यात एव ऋण गारंटी निगम— लघु उद्यमियों को अपनी बनाई वस्तु बेचने के लिए पहले से खरीददार होना जरूरी है। चूंकि विदेश में बसे साख इसके बारे में नहीं जानते उन्हें जुटा पाना असंभव है। इसी लिए निगम स्वयं उस खरीददार फार्म की साख के संबंध जानकारी जुटा लेता है और उसे उद्यमी को विदेशों में भेजता। इनके पते निम्न हैं —

प्रधान कार्यालय 4—रेमपोर्ट रो, मुंबई-1 (महाराष्ट्र)

आयात निर्यात का मुख्य नियंत्रक आयात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय 1941 में दिल्ली में स्थापित किया गया। मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली के अतिरिक्त लाइसेंस देने वाली 17 और प्रादेशिक कार्यालय हैं। इनमें के कुछ का तार पता क्षेत्र इस प्रकार है —

लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण या क्षेत्र

तार-पता

- 1 संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात 4,

Conimpextra

कनइम्पेक्स्ट्रा

एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकता, अधिकार क्षेत्र उड़ीसा

कलकत्ता

बिहार, पश्चिम बंगाल

- 2 संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा कस्टम

Conimpextra चेन्नई

हाउस, चेन्नई

- 3 उपमुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, 112/1-बी

Conimpextra कानपुर

बेनझाबर, कानपुर-2 अधिकार क्षेत्र .समस्त उत्तर प्रदेश

चतुर्थ अध्याय

लघु उद्योग बनाम् बृहत् उद्योग (Small Vs. Large Industries)

आज लघु उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके विकास का प्रमुख श्रेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। नेहरूजी की कोशिश थी कि बड़े उद्योग का विकास करने के साथ-साथ उन्हें सहारा देने के लिए लघु स्तर के उद्योगों को भी रखा जाये। लघु उद्योगों का क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का गतिशील और सक्रिय क्षेत्र बनकर उभरा है। आज हमारे यहाँ जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 35% लघु उद्योग के क्षेत्र में होता है, और यहाँ से होने वाले कुल निर्यात में उसका लगभग 40% से भी अधिक होता है। मूल्य युक्त की बात की जाये तो निर्माण क्षेत्र में मूल्य युक्त का 40% के लगभग इसी क्षेत्र में है। रोजगार को ले तो इस क्षेत्र का योगदान कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसलिए यह पैसा लगाने के लिए अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा मित्र है।

पश्चिम के विकसित देशों में छोटे पैमाने पर उत्पादन का संगठन बड़े पैमाने पर उत्पादन का पूरक होता है और इस प्रकार यह भी पूँजीवादी ढंग से ही संगठित होता है। भारत में या लघु उद्योग प्रायः पूँजीवादी ढंग से संगठित नहीं है। छोटे पैमाने पर संगठित औद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग आते हैं। शहरी लघु उद्योग जिनमें मजदूरी के बदले में काम करने वाले श्रमिकों को लगाया जाता है लेकिन शक्ति से चलने वाली मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा ऐसे लघु उद्योग जिनमें आधुनिक मशीनों एवं बिजली का प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि भारत में छोटे स्तर पर औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र एक-सा नहीं है।

जब मजदूरी के बदले में काम करने वाले 10 से 50 तक श्रमिकों की सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं तो वह लघु उद्योग होता है। सम्भवतः इसी परिभाषा को आधार मानकर औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 में उन औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंसिंग से मुक्त रखा गया जिनमें यदि बिजली का इस्तेमाल होता है तो 50 से कम श्रमिक लगे हों और यदि

बिजली का इस्तेमाल नहीं होता तो 100 से कम श्रमिक लगे हो।

एक अन्य मापदण्ड के आधार पर भी लघु उद्योगों को बड़े तथा मध्यम उद्योगों से अलग किया जाता है। यह मानदण्ड औद्योगिक इकाई में स्थिर पूँजी के निवेश से सम्बन्धित है। स्थिर पूँजी के निवेश से सम्बन्धित है। स्थिर पूँजी की सीमा को लगातार ऊपर उठाया गया है। 1975 से पहले वे सारी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें प्लाट व मशीनों में निवेश 7.5 लाख रुपये से कम हो लघु क्षेत्र में शामिल की जाती थी। सहायक औद्योगिक इकाइयाँ (ancillary units) के लिए उच्चतम सीमा 10 लाख रुपये थी। 1 मई, 1975 से इन सीमाओं को क्रमशः 10 तथा 15 लाख कर दिया गया। 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में इन्हें और बढ़ाकर क्रमशः 20 लाख तथा 25 लाख कर दिया गया। मार्च 1985 में परिभाषा में फिर परिवर्तन किया गया। इस परिभाषा के अनुसार वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें प्लाट और मशीनों में निवेश 35 लाख रुपये से कम था लघु क्षेत्र में रखी गई। सहायक औद्योगिक इकाइयों के लिए निवेश की सीमा 45 लाख रुपये थी। अप्रैल 1991 में लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए निवेश सीमा 60 लाख रुपये तथा सहायक औद्योगिक इकाइयों के लिए 75 लाख रुपये कर दी गई। इसके अलावा एक अति लघु क्षेत्र (tiny sector) भी परिभाषित किया गया जिसमें उन औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया जिनमें निवेश की सीमा 5 लाख रुपये तक थी (अगस्त 1991) से पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी। लघु और सहायक इकाइयों के लिए निवेश की सीमा को, आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर, फरवरी 1997 में और बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। अति लघु क्षेत्र के लिए भी निवेश सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई। सरकार के अनुसार, निवेश सीमाओं में यह वृद्धि मुद्रा-स्फीति और अवमूल्यन के कारण रुपये की कीमत में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए की गई। परन्तु फरवरी 1999 में लघु क्षेत्र के लिए निवेश सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया।

लघु उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय इस प्रकार

किये गये हैं—“प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल 459 करोड़ रुपये, तीन वार्षिक योजनाओं में 126 करोड़ रुपये, चतुर्थ योजना में 243 करोड़ रुपये, पंचम योजना में 593 करोड़ रुपये, छठवी योजना में 1,945 करोड़ रुपये, सातवी योजना में 3,249 करोड़ रुपये व आठवी योजना में 7,094 करोड़ रुपये।” इस विवरण से यह स्पष्ट अर्थ निकलता है कि योजनाओं में लघु उद्योगों पर व्यय की गयी राशि में बराबर वृद्धि की गयी है। यह इस बात का द्योतक है कि वर्तमान सरकार लघु उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दे रही है।

सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान देने के कारण इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1961 में 46 हजार इकाइयाँ लघु उद्योगों के रूप में विद्यमान थी जिनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते 1998-99 में 31 21 लाख इकाइयाँ हो गयी है। यह इकाइयाँ 5,600 वस्तुओं का निर्माण करती हैं। इन लघु उद्योगों के विकास हेतु 180 वस्तुओं का निर्माण केवल इन्हीं के द्वारा की करने के लिए सुरक्षित था, लेकिन नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इनकी संख्या बढ़ाकर 822 कर दी गयी है। इससे आशा है कि इन उद्योगों का विकास तीव्र गति से होगा।

1999-2000 में लघु उद्योगों की इकाइयों का उत्पादन 5,80,000 करोड़ रुपये का हुआ है और इस वर्ष में इन उद्योगों में 171 6 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था।

“नवी योजना के अन्तिम वर्ष 2001-2002 में लघु उद्योगों की इकाइयों के उत्पादन का लक्ष्य 7,25,000 करोड़ रुपये का रखा गया है तथा इसी वर्ष 185 लाख व्यक्तियों को इस प्रकार के उद्योग में रोजगार मिले होने की सम्भावना है।

बड़े पैमाने के क्षेत्र से भारी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद छोटे पैमाने के उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता-उपरान्त काल के दौरान विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है, चाहे सरकार से इन्हे पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ 1950 में 16,000 लघु-इकाइयाँ पंजीकृत (Registered) थी, वहाँ इनकी संख्या बढ़कर 30 25 लाख हो गयी। पिछले दशक के दौरान, लघु स्तर क्षेत्र ने इस दिशा में तरक्की की है कि साधारण वस्तुओं को बनाने के अतिरिक्त, यह बहुत-सी परिमार्जित वस्तुएँ एवं

बढ़िया उपकरण जैसे इलैक्ट्रानिक नियन्त्रण उपकरण, माइक्रो-वेव हिस्से(Micro-wave components) , इलैक्ट्रो-चिकित्सा उपकरण, टी वी सैट आदि का निर्माण करने लगा है। इन इकाइयों द्वारा 5,000 से अधिक वस्तुएँ उत्पन्न की जाती है।

सरकार लघु-स्तर क्षेत्र के विकास के लिए वस्तुओं के आरक्षण (Reservation) की नीति अपनाती चली आई है। 1972 के छोटे पैमाने के उद्योगों की अखिल भारतीय गणना (Census of small-Scale Industries) के समय 177 मदे आरक्षित सूची में थी। 1983 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 837 कर दी गयी। इन इकाइयों में 7,500 वस्तुएँ तैयार की जाती है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा 1994-95 में विनिर्माण उद्यमों के सर्वेक्षण (Manufacturing Enterprises Survey) से पता चला कि 72.4 प्रतिशत पंजीकृत इकाइया (Registered units) ग्राम क्षेत्रों में और केवल 27.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में स्थित थी।

छोटे विनिर्माण उद्यमों का स्वामित्व ढांचा

	दूसरी अखिल-भारतीय गणना	विनिर्माण उद्यमों का सर्वेक्षण
	(1887-88)	1994-95
एक-व्यक्ति स्वामित्व	81.0%	97.6%
साझेदारी	17.2%	1.9%
सीमित कम्पनिया	1.7%	—
रिपोर्ट न की गयी	—	0.5
कुल	100.0	100.0

नोट— इनमें कारखाना कानून के अधीन पंजीकृत इकाइया भी शामिल हैं।

कारखाना कानून (Factory Act) के अधीन पंजीकृत इकाइयों का लगभग 98 प्रतिशत

एक—व्यक्ति स्वामित्व इकाइया (Proprietary Units) थी और केवल 19 लगभग साझेदारी के अधीन पजीकृत थी। 1987—88 में, दूसरी अखिल—भारतीय गणना (Second All-India Census) में 81 प्रतिशत इकाइया एक—व्यक्ति स्वामित्वाधीन, 17 प्रतिशत साझेदारी के अधीन और केवल 17 प्रतिशत सीमित कम्पनिया (Limited Companies) थी। परन्तु 1994—95 के विनिर्माण सर्वेक्षण में एक भी इकाई सीमित कम्पनी के रूप में नहीं पायी गयी। अतः लघु उद्योगों के स्वामित्व—ढांचे (Ownership pattern) में एक व्यक्ति स्वामित्व का प्रभुत्व है और एक थोड़ा सा अनुपात साझेदारी इकाइयों के रूप में है।

सी एस ओ के विनिर्माण उद्यम सर्वेक्षण के (1994—95) के अनुसार, लघु—उद्यमों का लगभग पाचवा भाग (19.8%) लकड़ी की वस्तुओं में लगा हुआ था, 16.5 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं में और 15.1 प्रतिशत मरम्मत सेवाओं (Repair Services) में। ये तीन उद्योग मिलकर कुल इकाइयों का 51.4% थे। सूती वस्त्र, हौजरी और सिलेसिलाए कपड़े (Garments) का एक अन्य मुख्य क्षेत्र था जिसमें 13.1 प्रतिशत इकाइया थी, इसके बाद पेय पदार्थों और तम्बाकू पदार्थों में 9.8 प्रतिशत इकाइया लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त, लघु स्तर इकाइया ऊन, रेशम और साशिलिष्ट तन्तुओं (Synthetic fibres), पटसन उद्योग, कागज पदार्थों एवं प्रकाशन, चमड़े और चमड़े की वस्तुओं, रसायन पदार्थों, धातु पदार्थों, मशीनरी (इलैक्ट्रिकल एवं गैर—इलैक्ट्रिकल), परिवहन सामान आदि में कार्य कर रही थी।

लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइयों का उद्योगवार वितरण

	इकाइया (लाखों में) कुल का प्रतिशत	
लकड़ी की वस्तुएँ	28 73	19 8
खाद्य-वस्तुएँ	23 94	16 5
पेय पदार्थ एवं तम्बाकू पदार्थ	14 27	9 8
विविध विनिर्माण उद्योग	11 59	8 0
हौजरी एवं सिलेसिलाए कपड़े	10 94	7 5
सूती वस्त्र	8 19	5 6
अन्य	28 57	11 8
कुल	145 04	100 0

लघु उद्योगों का उत्पादन— 1973-74 और 1999-2000 के दौरान लघु-स्तर इकाइयों की संख्या 4.2 लाख से बढ़कर 32.25 लाख हो गयी। इसी अवधि में इस क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 40 लाख से बढ़कर 178.5 लाख हो गयी और उत्पादन 7,200 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,78,460 करोड़ रुपये हो गयी। 1980-81 से 1990-91 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र में रोजगार में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 5.8 प्रतिशत और उत्पादन में 18.6 प्रतिशत बैठती है। 1990-91 और 1999-2000 के दौरान उत्पादन की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही। इससे यह विश्वास परिवर्धित हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने के लिए लघु-स्तर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 1981-82 में 30,810 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 85,025 करोड़ रुपये हो गया।

लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइयों का उद्योगवार वितरण

	इकाइया (लाखों में) कुल का प्रतिशत	
लकड़ी की वस्तुएँ	28 73	19 8
खाद्य-वस्तुएँ	23 94	16 5
पेय पदार्थ एवं तम्बाकू पदार्थ	14 27	9 8
विविध विनिर्माण उद्योग	11 59	8 0
हौजरी एवं सिलेसिलाए कपड़े	10 94	7 5
सूती वस्त्र	8 19	5 6
अन्य	28 57	11 8
कुल	145 04	100 0

लघु उद्योगों का उत्पादन— 1973-74 और 1999-2000 के दौरान लघु-स्तर इकाइयों की संख्या 4.2 लाख से बढ़कर 32.25 लाख हो गयी। इसी अवधि में इस क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 40 लाख से बढ़कर 178.5 लाख हो गयी और उत्पादन 7,200 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,78,460 करोड़ रुपये हो गयी। 1980-81 से 1990-91 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र में रोजगार में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 5.8 प्रतिशत और उत्पादन में 18.6 प्रतिशत बैठती है। 1990-91 और 1999-2000 के दौरान उत्पादन की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही। इससे यह विश्वास परिवर्तित हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने के लिए लघु-स्तर उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 1981-82 में 30,810 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 85,025 करोड़ रुपये हो गया।

लघु स्तर क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन

(उत्पादन करोड़ रुपये)

वर्ष	चालू कीमतों पर	1990-91 की रोजगार कीमतों पर	निर्यात (चालू कीमतों पर) करोड़ रुपये	
1973-74	7,200	—	39.7	393
1980-81	28,060	—	71.0	1,643
1990-91	1,55,340	1,55,340	125.3	9,100
1991-92	1,78,699	1,60,156	129.8	13,883
1992-93	2,09,300	1,69,125	134.1	17,785
1993-94	2,41,648	1,81,133	139.4	25,304
1994-95	293,990	1,99,427	146.6	29,068
1995-96	356,213	222,162	152.6	36,470
1996-97	4,12,636	2,47,311	160.0	39,249
1997-98	4,65,171	2,68,159	167.2	43,946
1998-99	5,27,515	2,88,807	171.6	48,979
1999-2000	5,78,470	3,12,576	178.5	53,975

वार्षिक चक्रवृद्धि-दर

1974-75 से 1980-81	21.4	8.7	8.7	22.6
1980-81 से 1990-91	18.6	11.7	5.8	18.6
1990-91 से 1999-2000	15.7	8.1	4.0	21.9

नोट 1973-74 से 1980-81 से 1990-91 के लिए वृद्धि-दरों 1981-82 की कीमतों पर परिकलित की गयी हैं।

औसत वार्षिक दर 117 प्रतिशत बैठती है जो इस काल के दौरान बड़े पैमाने के उत्पादन की 87 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से कहीं ऊँची है।

1990-91 और 1999-2000 की 9-वर्षीय अवधि के लिए, लघु-स्तर क्षेत्र के उत्पादन (1990-91 की कीमतों पर) की औसत वृद्धि दर 81 प्रतिशत थी (अर्थात् 1,55,340 करोड़ रूपए से 3,12,576)। इस अवधि में रोजगार की वृद्धि दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। दोनों सूचकों से स्पष्ट है कि लघु-क्षेत्र का निष्पादन बड़े पैमाने के उत्पादन की तुलना में बेहतर है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि लघु-स्तर क्षेत्र के उत्पादन में बड़े पैमाने के क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई। जाहिर है समग्र औद्योगिक उत्पादन में मन्द गति की तुलना में लघु क्षेत्र का निष्पादन सराहनीय है। इस तथ्य का हमारी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के सदर्भ में विशेष महत्व है। छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास से गैर-चिरस्थायी जन-उपभोग की वस्तुओं (Non-durable consumer goods of mass consumption) का उत्पादन उन्नत होता है। इस प्रकार यह अस्फीतिकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। यदि लघु-क्षेत्र को बड़े जोर का धक्का दे दिया जाए, तो वह भारत जैसी पूँजी न्यून अर्थव्यवस्था (Capital scarce economy) में उत्पाद-पूँजी अनुपात की ऊँची दर एवं रोजगार-पूँजी-अनुपात (Employment capital ratio) की ऊँची दर द्वारा स्थायीकारी कारणतत्व (Stabilising factor) बन सकता है।

इस सम्बन्ध में हम लघु-स्तर उद्योगों के निम्न क्षमता-उपयोग (Capacity utilisation) का उल्लेख कर सकते हैं। समग्र लघु-क्षेत्र में क्षमता-उपयोग 53 प्रतिशत था किन्तु कुछ उद्योगों में क्षमता-उपयोग 60 से 80 प्रतिशत के बीच है। इनमें हैं काजू, सिले-सिलाए कपड़े, टाइल और औद्योगिक मशीनरी के पुर्जे। प्लास्टिक उत्पादन जैसे उद्योगों में क्षमता-उपयोग बहुत ही नीचा था (29 प्रतिशत)।

निर्यात- सिले-सिलाए कपड़ों, डब्बाबन्द एवं विधयित मछली, चमड़े की चप्पलें एवं सैडलों, खाद्य वस्तुओं और चमड़े की वस्तुओं में विशेष रूप से निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। 1978 में

निर्यात का मूल्य बढ़कर 845 करोड़ रूपए हो गया और 1999–2000 तक यह 53,975 करोड़ रूपए के रिकार्ड–स्तर पर पहुँच गया। लघु–क्षेत्र से निर्यात का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण इनका अपारम्परिक निर्यात में भाग था। 1999–2000 में कुल निर्यात में लघु–क्षेत्र का भाग 33 प्रतिशत था। इस क्षेत्र द्वारा किए गए मुख्य उत्पाद हैं इजीनियरिंग वस्तुएँ, कमाया हुआ चमड़ा और चमड़े की निर्मित वस्तुएँ, सिले–सिलाए कपड़े, हौजरी और समुद्री उत्पाद।

लघु उद्योगों के अन्तःराज्यीय वितरण से पता चलता है कि छ राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में लघु क्षेत्र की कुल इकाइयों का 59 प्रतिशत भाग स्थित भाग था, इनके द्वारा कुल रोजगार का 62 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया गया, इसमें कुल उत्पादन का 69 प्रतिशत भाग उत्पन्न होता था। वे राज्य जो लघु–स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा शामिल हैं।

कुछ जिलों में विशिष्टीकरण के कारण भी लघु–स्तर की इकाइयों में सकेन्द्रण जान पड़ता है। ऊनी हौजरी की 92 प्रतिशत इकाइयाँ लुधियाना, कलकत्ता और दिल्ली में थी, साइकिलों के पुर्जों की 62 प्रतिशत इकाइयाँ लुधियाना, जालन्धर, हावड़ा बम्बई में थी। 1987–88 में 2 लाख रूपए से कम अचल पूँजी (Fixed capital) वाली इकाइयों का अनुपात लघु–क्षेत्र में 84 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 10 लाख रूपए से कम उत्पादन वाली इकाइयों का अनुपात 89.2 प्रतिशत था और कुल इकाइयों के 88 प्रतिशत में 9 श्रमिकों से कम के लिए रोजगार उपलब्ध था। दूसरे शब्दों में, इन तीनों कसौटियों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि लघु–क्षेत्र में अति लघु इकाइयों का प्रभुत्व है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने में उसके औद्योगिक ढांचे से काफी सहायता मिलती है। जिन देशों में केवल उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग विकसित होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होती है। लोहा व इस्पात, इंजीनियरिंग तथा रसायन उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थापना नहीं होती, अर्थव्यवस्था का आधार कमजोर बना रहता है। आजादी से पहले देश में सूती वस्त्र, जूट, लोहा व इस्पात, चीनी तथा सीमेंट उद्योगों की स्थापना हुई थी। बृहत् उद्योग की स्थिति इस प्रकार है -

कपड़ा उद्योग (Cloth Industry) -

कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा, संगठित एवं व्यापक उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद (G D P) का लगभग 4 प्रतिशत, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20 प्रतिशत व कुल निर्यातों के 30 प्रतिशत की आपूर्ति करता है, जबकि देश के कुल आयात खर्च में इसका हिस्सा केवल 7 प्रतिशत है। यह उद्योग देश के लगभग 35 लाख लोगों के रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र के साथ यह उद्योग करीब 9 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन् 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगायी गयी थी, किन्तु यह मिल लक्ष्य प्राप्ति में सफल न हुई। द्वितीय मिल 'बम्बई स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी' सन् 1854 में बम्बई 'कवास जी एन डाबर' द्वारा स्थापित की गयी सच्चे अर्थों में इस कारखाने में भारत के आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी। सन् 1854 के पश्चात् सूती कपड़ा मिलों की संख्या लगातार बढ़ती गयी।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन व सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बीच बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। बंगाल विभाजन (16 अक्टूबर 1905) के विरुद्ध चले स्वदेशी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन (1920-22), सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930-31), भारत छोड़ो आन्दोलन (1941) आदि ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करके सूती वस्त्र उद्योग के विकास में भरपूर सहयोग दिया। 1947 में देश के विभाजन ने देश के सूती वस्त्र

उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अधिकांश मुस्लिम बुनकर पाकिस्तान चले गये। जिससे यह उद्योग भी दो टुकड़ों में बंट गया। 13 अगस्त 1947 को भारत में 394 सूती वस्त्र मिलें थीं, लेकिन 14 अगस्त को 14 मिलें पाकिस्तान में चली जाने से भारत में 15 अगस्त 1947 को 380 मिलें रह गयीं।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कपास उत्पादन करने वाला 40 प्रतिशत क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और केवल 60 प्रतिशत भारत में रह गया। यही कारण है कि भारत को कपास के आयात के क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। पंचवर्षीय योजनाएँ इस उद्योग के लिए वरदान सिद्ध हुईं, जिनके फलस्वरूप न केवल इस उद्योग पर्याप्त विकास किया, अपितु अन्तराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी छाप छोड़ी है। सरकार ने कपड़ा आदेश (विकास एवं नियमन) 1993 (Textiles Development and Regulation Order 1993) के माध्यम से इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। 31 मार्च 1999 को देश में 1824 सूत/कृत्रिम धागों की मिलें थीं। इन 1824 मिलों में से 192 सार्वजनिक क्षेत्र में, 153 सहकारी क्षेत्र में और 1479 निजी क्षेत्र में हैं। सूती/कृत्रिम धागों की अधिकतर मिलें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में हैं।

भारत का वस्त्रोद्योग मुख्यतः सूत (Cotton) पर ही आधारित रहा है तथा देश में कपड़े की खपत का 58 प्रतिशत भाग सूत से ही सम्बद्ध है। 1990-91 में इनकी क्षमता का प्रयोग 58 प्रतिशत था। जो 1998-99 में बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2000-01 में कुल 40,256 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ था। कपड़े के उत्पादन में 2000-01 में मिल क्षेत्र का हिस्सा 41 प्रतिशत, बिजली करघा (हाजिरी सहित) का हिस्सा 75.8 प्रतिशत तथा हथकरघा एवं अन्य का हिस्सा 20.1 प्रतिशत था। धागे का उत्पादन 2000-01 में 1,824 मिलियन किग्रा हुआ। देश के निर्यात में भी इस उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कुल निर्यातों के लगभग 30 प्रतिशत की आपूर्ति इस उद्योग द्वारा की जाती है।

यहाँ यह बता देना उचित होगा कि एजो रंगो (Azo Dyes) के प्रयोग के कारण जर्मनी ने 1 अप्रैल 1996 से भारत से ऐसे टेक्सटाइल आयात बन्द कर दिये हैं। सरकार ने इसी सन्दर्भ में जून 1997 से एजो रंगो के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया है। इसके बावजूद भी यूरोपीय आयोग ने भारत सहित छ राष्ट्रों से आयातित बिना साफ किये सूत से बने कपड़ों पर औसतन 16.09 प्रतिशत अस्थायी एंटी डम्पिंग शुल्क आरोपित किया है। यह दूसरा अवसर है, जबकि 25 मार्च 1998 से ऐसे कपड़ों पर अस्थायी एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया गया है। USA जैसे हमारे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण वस्त्र उत्पादों के निर्यात में गिरावट आयी है।

वर्ष 1996 में विश्व के कुल टेक्सटाइल्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.9 प्रतिशत थी। टेक्सटाइल मंत्रालय में सन 2005 तक 40 अरब डालर मूल्य का टेक्सटाइल निर्यात वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे विश्व के कुल निर्यात में भारती की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक हो सकेगी। 1998-99 में भारत का टेक्सटाइल निर्यात (जूट एवं हस्तशिल्प) के साथ 12.533 अरब डालर था। वर्ष 1999-2000 के दौरान वस्त्रों का निर्यात मूल्य 13.32 अरब डालर था। वर्ष 2000-01 का निर्यात लक्ष्य 15 अरब डालर का है। कपड़ों के कुल निर्यात में सिले सिलाए वस्त्रों का हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत के बराबर है।

भारत में प्रति व्यक्ति कपड़ों की खपत 2000-01 में 30.7 मीटर वार्षिक थी, जिसमें सूती कपड़ों की प्रति व्यक्ति खपत 14.2 मीटर तथा ब्लेंडेड मिश्रित मानव निर्मित कपड़ों की 16.5 मीटर थी। उन्नत देशों में कपड़ों की वार्षिक खपत 50 से 60 मीटर प्रति व्यक्ति है, अर्थात् विकसित देशों में खपत भारत की तुलना में लगभग दो गुनी है।

टेक्सटाइल्स उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक प्रौद्योगिक उन्नयन निधि की स्थापना की है। 25 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान वाले प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष को 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी किया गया यह राशि उपलब्ध कराने में वित्तीय सहायकों विशेषतः सिडवी की अग्रणी भूमिका रही है।

कपडा मन्त्रालय एवं कृषि मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कपास प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारम्भ 21 फरवरी 2000 को किया गया। जिसमें कपास के अनुसंधान, विकास, विपणन एवं प्रसस्करण के चार लघु मिशन सम्मिलित हैं।

तालिका
भारत में वस्त्र उत्पादन

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्षेत्र	1998—99	1999—2000	2000—2001	2001—02 (अप्रैल—अक्टूबर)
मिल क्षेत्र	1,785 (5 0)	1,714 (4 0)	1,670 (4 1)	889 (3 7)
विद्युत् करघा	26,966 (74 7)	29,561 (75 4)	30,499 (75 8)	18,609 (76 6)
हथकरघा	6,792 (18 8)	7,352 (18 8)	7,506 (18 7)	4,453 (18 3)
अन्य	559 (1 5)	575 (1 5)	581 (1 4)	339 (1 4)
योग	3,610 (100 0)	39,202 (100 0)	40,256 (100 0)	24,290 (100 0)

नोट— कोष्ठक में दी गई संख्या कुल उत्पादन में प्रतिशत भाग को बताती हैं।

वर्ष 2001—02 के बजट में सरकार ने एक टैक्सटाइल पैकेज की घोषणा की थी।

जिसमें निम्नलिखित स्कीमें शामिल थी —

- 1 एकीकृत परिधान पार्को की स्थापना करने की एक योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया जिसमें अनारक्षित रेडीमेड गारमेन्ट उद्योग, सर्वोत्तम आधारभूत आधुनिक इकाइयों स्थापित कर सकेगा इसके लिए 2001-02 के बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
- 2 एक सुदृढ़ और आधुनिक बुनकर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम से निधियाँ उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को 2001-02 में 200 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया।
- 3 कपास प्रौद्योगिकी मिशन को 2001-02 के दौरान जारी रखा जायेगा इसके लिए बजट प्रावधान को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया गया।
- 4 हथकरघा गतिविधियों के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2000 से 'दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ की गयी है।

लोहा एवं इस्पात उद्योग :- आज भारत विश्व का नौवा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। इस उद्योग में 90 हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है और 5 लाख से अधिक लोगो को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आरम्भ 1870 में हुआ था, जब बंगाल आयरन वर्क्स कम्पनी ने झरिया के निकट कुलटी, पश्चिम बंगाल में अपने सयन्त्र की स्थापना की थी। यह कारखाना केवल ढलवा लोहे का उत्पादन कर सका। बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के स्थापना के साथ आरम्भ हुआ। इसके बाद 1919 में बर्न पुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई। यह दोनों इकाइयों निजी क्षेत्र में स्थापित की गयी थी। सन् 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारम्भ किया। स्वतन्त्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के सम्बन्ध में पहली पंचवर्षीय योजना में विचार किया गया। किन्तु इसका काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हो सका जबकि 10-10 लाख टन इस्पात पिण्डों की

क्षमता की परियोजनाएँ भिलाई छत्तीसगढ़ में (सोवियत संघ के सहयोग से), दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में (ब्रिटेन के सहयोग से) और राउरकेला उड़ीसा में (पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से) में स्थापित की गयी। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों — 'टिस्को' तथा 'इस्को' की उत्पादन क्षमता दो गुनी करके क्रमशः 20 लाख और 10 लाख टन कर दी गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 कारखानों में उत्पादन 1956 तथा 1962 के बीच प्रारम्भ हुआ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों का विस्तार किया गया। तथा सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो (बिहार) में एक और इस्पात कारखाने की स्थापना पर जोर दिया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों की वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग किया गया। तथा सलेम (तमिलनाडु), विजयनगर (कर्नाटक) और विशाखपत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में नये इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। सन् 1978 में बोकारो इस्पात संयन्त्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गयी।

1974 में सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की स्थापना की तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गयी। यह भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो एवं बर्नपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयन्त्रों के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है तथा साथ ही साथ दुर्गापुर के एलाय स्टील प्लांट व सनेम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए भी उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्र (इस्को) का स्वामित्व 14 जुलाई 1976 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। अब यह कम्पनी सेल के नियन्त्रण में है।

सेल ने जनवरी 1986 में इस्पात और पेट्रो मैंगनीज का उत्पादन करने वाला लघु इस्पात संयन्त्र महाराष्ट्र इलेक्ट्रोमैल्ट अपने अधिकार में ले लिया और 1 अगस्त 1986 को कर्नाटक सरकार के नियन्त्रण वाली बीमार इकाई विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड इस्पात लिमिटेड को भी अपने अधिकार में ले लिया। पिछले 10 वर्षों से सेल प्रायः बढ़ते हुए लाभ की स्थिति

को प्रदर्शित कर रहा है। 31 मार्च 1999 को सेल की अधिकृत पूँजी 5 हजार करोड रुपये तथा चुकता पूँजी 4,130 40 करोड रुपये थी।

तालिका

लोहे और इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन में)

मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अप्रैल-दिसम्बर)
1 तैयार माल का उत्पादन	27 17 (140)	29 27 (77)	21 98 (-03)
(a) मुख्य उत्पादक	11 27 (137)	12 49 (107)	9 50 (19)
(b) गौण उत्पादक	15 90 (142)	16 78 (55)	12 48 (-20)
2 कच्चे लोहे का उत्पादन	3 18 (61)	3 40 (6.8)	2 88 (89)
(a) मुख्य उत्पादक	1 23 (-94)	0 96 (-213)	0 78 (73)
(b) गौण उत्पादक	1 95 (189)	2 43 (245)	2 11 (95)
3 कुल उत्पादन (1 + 2)	30 35	32 67	24.86

नोट— कोष्ठक में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष की समान अवधि में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

विगत कुछ वर्षों में इस्पात उद्योग के उत्पादन को तालिका 4 में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2000-01 में इस्पात की खपत 26 65 मिलियन टन थी, जबकि 1999-2000 में यह 25 01 मिलियन टन थी। वर्ष 2000-01 में तैयार इस्पात का निर्यात 2 67 टन था। जो

1999—2000 में 260 मिलियन टन था। लोहे और इस्पात से बनी सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात की वर्तमान में पूरी छूट है। वर्ष 2000—01 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का आयात 18 मिलियन टन था।

लघु इस्पात संयंत्र :— बिजली की इस्पात भट्टियाँ, जिन्हें सामान्यतः लघु इस्पात संयंत्र कहा जाता है, रददी (स्क्रैप) धातु और स्पन्ज लोहे से इस्पात तैयार करती हैं, ये संयंत्र हमारे देश के इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण भाग हैं, एकीकृत इस्पात संयंत्र प्रायः विशाल मात्रा में नम इस्पात का उत्पादन करते हैं, जबकि लघु इस्पात संयंत्र नम इस्पात के साथ-साथ मिश्र इस्पात भी तैयार करते हैं, जिसका एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन महंगा पड़ता है। 1999—2000 में इस क्षेत्र ने 700 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था, जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में लोहे और इस्पात को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (VSP)

यह भारत में तट निकट स्थित पहली एकीकृत इस्पात योजना है, जिसे दक्षिण क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में बन्दरगाह के पास स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन कच्चे इस्पात की है, इस परियोजना द्वारा निर्मित पिग इस्पात और वायर रॉड की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। इस परियोजना में लगभग 15000 कर्मचारी कार्य करते हैं तथा वर्ष 1996—97 में इसकी उत्पादकता 186 टन प्रति व्यक्ति वार्षिक के लगभग थी, जोकि भारत के किसी भी इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया था, 1999—2000 में इस कारखाने में 294 लाख टन धातु, 266 लाख टन तरल इस्पात, 238 लाख टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ।

लौह तथा इस्पात उद्योग की समस्याएँ

1 सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की अकुशलता।

- 2 प्रशासित कीमतों की समस्या।
- 3 क्षमता का अल्प प्रयोग।
- 4 मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता।
- 5 कोकिंग कोल की कमी।

चीनी उद्योग (Sugar Industry) :- चीनी उद्योग देश की प्रमुख कृषि पर आधारित उद्योगों में से एक है कुटीर उद्योग के रूप में इसका विकास 3000 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है, किन्तु बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास 20 वीं सदी से प्रारम्भ हुआ, कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय वृहत्तम उद्योग है, यह उद्योग न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, बल्कि उप-उत्पादों तथा सह-उत्पादों से सम्बन्धित उद्योगों को विकसित करने की क्षमता भी रखता है। 2000-2001 में देश में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 493 थी जबकि 1950-51 में इसकी संख्या 138 है, इन मिलों में से 271 मिले सहकारी क्षेत्र में हैं, वर्ष 1999-2000 में चीनी की वार्षिक खपत 154.2 लाख टन होने का अनुमान था जिसमें से 46 लाख टन की आपूर्ति सावित्र के जरिए की जाती थी। 2000-2001 के दौरान चीनी की उत्पाद 184-21 लाख टन था जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन था वर्ष 2001-2002 में चीनी का उत्पादन था वर्ष 2001-2002 में चीनी का उत्पादन 175 लाख टन होने की आशा की जाती है वर्ष 2000-2001 के दौरान 12.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया जबकि 1999-2000 में 30,012 टन चीनी का आयात किया गया था।

भारत विश्व में चीनी उत्पादन एवं उसकी खपत करने वाला सबसे बड़ा देश है और चीनी उत्पादन में अकेले महाराष्ट्र राज्य का उत्पादन एक-तिहाई से अधिक है। देश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक है।

अभी तक चीनी मिलों की स्थापना के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य था, किन्तु 20 अगस्त, 1998 को सरकार ने इन उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त करने की घोषणा कर दी। गन्ने

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित साविधिक न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त राज्य सलाहकारी कीमते भी राज्यो द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि साविधिक न्यूनतम कीमतों से ऊँची होती है। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 'कृषि मूल्य लागत आयोग' की स्थापना की गई है, जो फसल आने से पहले फसलों के समर्थन मूल्यों का सुझाव सरकार को देता है और अधिकांशतः केन्द्र सरकार गन्ने के साविधिक समर्थन मूल्य (SMP) उसके सिफारशी मूल्य से अधिक ही घोषित करती है। चीनी उद्योग वर्ष 2001-2002 (अक्टूबर-सितम्बर) के लिये गन्ने के SMP मूल्य 6205 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये गए थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1 फरवरी 2001 से केवल BPL को वितरण करने के लिये खुले बाजार मूल्यों से कम कीमत पर चीनी उत्पादन का कतिपय हिस्सा (15%) राज्य सरकारों और सघ राज्य क्षेत्रों को लेवी के रूप में आवंटित किया जाता है। खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी की गई चीनी पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है। 20 अगस्त, 1998 को केन्द्र सरकार ने चीनी उद्योग पर 1931 से लागू लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त कर दी, किन्तु दो चीनी मिलों के बीच 15 किलोमीटर के फासले की शर्त को जारी रखा गया है। नई चीनी मिलों पर क्षमता से सम्बन्धित भी कोई शर्त लागू नहीं की गई है। वर्ष 2000-2001 के बजट में सरकार ने आयकरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी उद्योग की सुविधा से वंचित कर दिया था। सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान चीनी उद्योग को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय किया है। विनियंत्रण की समाप्ति के बाद चीनी की लेवी खरीद की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

चीनी उद्योग की समस्याएँ

- 1 चीनी मिलों द्वारा कुल गन्ना उत्पादन का एक छोटा-सा भाग ही प्रयुक्त कर पाना।
- 2 प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता।
- 3 उत्तम किस्म के गन्ने की कमी।
- 4 उत्पादन लागतों में वृद्धि।

5 मिलो के आधुनिकीकरण की समस्या।

6 मौसमी उद्योग।

7 अनुसंधान की कमी।

8 चीनी मिलो द्वारा कृषको को गन्ने के मूल्य का पूरा-पूरा भुगतान न कर पाना।

सरकारी प्रयत्न—चीनी उद्योग के विकास के लिए धन एकत्र करने हेतु 1982 में एक 'चीनी विकास कोष' की स्थापना की गई थी। इस कोष का उपयोग मिलो के आधुनिकीकरण एवं मिल क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उद्योग में तकनीकी कुशलता के सुधार हेतु कानपुर (उप्र) में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की गई है।

सरकार ने हाल ही में चीनी के निर्यात को डिकैनलाइज (Decanalise) करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप अब चीनी मिलें सीधे ही चीनी का निर्यात कर सकेंगी अभी तक इसका निर्यात केवल इण्डियन सुगर एण्ड जनरल इण्डस्ट्री एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कॉर्पोरेशन (ISGIEIC) के माध्यम से ही होता है।

कोयला उद्योग (Coal Industry):- भारत में कोयले की खोज का श्रेय सभर और हैटली नामक दो अंग्रेजों को जाता है। उन्होंने रानीगंज और वीरभूम क्षेत्रों में कोयला उल्लेखन के लिए 1774 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग्स से आज्ञा मानी थी। यद्यपि उन्हें कोयला का हल्की श्रेणी का मिला, फिर भी उनके प्रयास से देश में कोयला क्षेत्रों का सर्वेक्षण प्रारम्भ हो गया था। 1814 ई. में रानीगंज में ही रूपर्ट जोन्स की रिपोर्ट के आधार पर कोयले की खुदाई शुरू की गई। 1830 ई. में रानीगंज क्षेत्र में कई नई खानों का पता लगाया गया।

भारत में उपलब्ध शक्ति साधनों में कोयला उद्योग का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय कोयला उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। जिस पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है। खाड़ी सकट के पश्चात् इसका महत्व और बढ़ गया। वर्तमान समय के शक्ति के

साधन के रूप उद्योग का महत्व का परिचायक है। कुल ऊर्जा उपभोग के कोयले का अंश 67% है। कुल कोयला उत्पादन में गैर-कोकिंग कोल का भाग लगभग 90% है।

कोयला उत्पादक क्षेत्र

हमारे देश में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1 गोडवाना कोयला क्षेत्र — इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला सोन, दामोदर, गोदावरी, वर्धा आदि नदियों की घाटियों में स्थित है। हमारे देश में प्राप्त होने वाले कुल कोयले का 98 प्रतिशत भाग गोडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कोयला इन्थ्रेसाइट और बिटूमिनस किस्म का होता है। गोडवाना क्षेत्र का अधिकांश कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में मिलता है।

2 तरशियरी कोयला क्षेत्र— इस क्षेत्र से देश में प्राप्त होने वाली कुल कोयले का केवल 2 प्रतिशत कोयला ही प्राप्त होता है। तरशियरी क्षेत्र का कोयला जम्बू-कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कोयला लिग्नाइट किस्म का होता है, जिसे 'भूरा कोयला' भी कहा जाता है।

कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति

अद्यतन स्थिति के अनुसार, कोयला उत्पादन में आज भारतका विश्व में तीसरा स्थान है।

1जनवरी, 2001 को भारत में कोयले के भण्डार का राज्यवार अनुमानित वितरण इस प्रकार है —

राज्य	भण्डार (मिलियन टन में)
आन्ध्र प्रदेश	13,674 90
अरुणाचल प्रदेश	90 23
असम	320 21
बिहार (झारखण्ड सहित)	69,174 59
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	44,139 02
महाराष्ट्र	7,295 56
मेघालय	459 43
नागालैण्ड	19 94
उड़ीसा	51,571 29
उत्तर प्रदेश	1,061 80
प बंगाल	25,918 54
योग	2,13,905 51

देश के कोयला उद्योग में लगभग 800 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है तथा 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 1 जनवरी 2001 तक 21390 55 करोड़ टन कोयले के भण्डार थे, जो 1200 मीटर की गहराई तक 0 5 मीटर या उससे मोटी परत के रूप में विद्यमान थे। भारत में कोयले का उत्पादन 2000—2001 में 309 6 मिलियन टन था।

देश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में रानीगंज, झरिया, पूर्वी व पश्चिमी बोकारो, पेन्च कन्हान, तवाघाटी, जलचर, चन्दा—वर्धा व गोदावरी घाटी है।

ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले के महत्व तथा कोयले की बढ़ती माँग की पूर्ति के लिए आवश्यक निवेश को देखते हुए कोयला उद्योग का 1972 व 1973 में दो चरणों में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किन्तु कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में 9 जून, 1993 को संशोधन कर दिया गया। खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के अन्तर्गत कोकिंग कोल के आयात को अनुमति प्रदान करके आयात शुल्क को 85% से घटाकर 35% कर दिया गया। 1 मार्च, 1996 से केन्द्र सरकार ने कोकिंग कोयले तथा ए बी व सी श्रेणी के गैर-कोकिंग कोयले पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया है। उल्लेखनीय है कि कोयले की कुल आपूर्ति में लगभग 17% भाग कोयले की उपर्युक्त किस्मों का है। वर्तमान समय में भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित दो प्रमुख संस्थानों-कोल इण्डिया लि० (CIL) तथा सिगरेनी कोलरीज द्वारा किया जा रहा है। कोल इण्डिया लि० का देश में कोयले के कुल उत्पादन के लगभग 90 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण है। यह एक धारक कम्पनी (Holding Co.) है तथा इसके अधीन 7 कम्पनियाँ कार्यरत हैं। सिगरेनी कोलरीज आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। कोयले के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत भाग इस कम्पनी से प्राप्त होता है।

तालिका

1 जनवरी, 2001 को भारत में कोयले के भण्डार का राज्यवार

अनुमानित वितरण

राज्य	भण्डार (मिलियन टन में)
आन्ध्र प्रदेश	13,674.90
अरुणाचल प्रदेश	90.23
असम	320.21
बिहार (झारखण्ड सहित)	6,9174.59

मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	44,139 02
महाराष्ट्र	7,259 56
मेघालय	459 43
नागालैण्ड	19 94
उड़ीसा	51,571 29
उत्तर प्रदेश	1,061 80
प बंगाल	25,918 54
योग	2,13,905 51

कोयला मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (2001–2002) तथा दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष (2006–2007) के लिए कोयले की माँग का अनुमान क्रमशः 43 99 करोड़ टन तथा 65 30 करोड़ टन का लगाया है।

रेशम उद्योग (Silk Industry) :- आदिकाल से ही रेशम भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। वर्ष 1999–2000 में देश में कुल रेशम उत्पादन में से मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 91 7% इरी रेशम का 6 4%, टसर रेशम का 1 4% तथा मूगा किस्म की रेशम का उत्पादन 0 5% था। रेशम व्यवसाय कृषि पर आधारित गृह उद्योग है। वर्ष 1999–2000 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लगभग 94 लाख लोग इस उद्योग के जरिए अपनी आजीविका चला रहे थे। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का हिस्सा लगभग 3% है। 2000–2001 के दौरान 1,525 74 करोड़ रुपये मूल्य के रेशमी वस्त्रों का निर्यात किया गया।

विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारम्भ हुआ। भारत में भी रेशम का उत्पादन प्राचीन युग से होता आ रहा है। विश्व के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 16%

रेशम भारत में उत्पन्न होता है। भारत के मुख्यतः 5 राज्यों—कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब तथा जम्मू—कश्मीर में अधिकांश रेशम का उत्पादन होता है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। नए किस्म के रेशमों का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर एवं जम्मू—कश्मीर के पठारी क्षेत्रों में किया जा रहा है।

तालिका से रेशम व इसके उत्पादों का निर्यात

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात मूल्य
1990—91	440 00
1993—94	789 26
1999—2000	1,501 78
2000—2001	1,525 74

रेशम उद्योग के विकास हेतु सरकारी प्रयत्न— भारत में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 1949 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। केन्द्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मैसूर (कर्नाटक) एवं बरहमपुर में की गई है। केन्द्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान मेन्दीपाथर (मेघालय) में एवं केन्द्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची (झारखण्ड) में स्थापित किए गए हैं। इसको और व्यापक बनाने के लिए 13 स्थानों पर क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए गए हैं। नौवीं योजना में सरकार ने रेशम उद्योग के विकास के लिए 302 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

पेट्रोलियम उद्योग [Petroleum Industry] :- पेट्रोलियम के सम्बन्ध में भारत की स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक देश में केवल डिगबोई (असम) के आसपास के क्षेत्र में तेल निकाला जाता था। तब से कई और भागों में तेल निकाला जाने लगा है। भारत के तेल क्षेत्र असम, त्रिपुरा,

मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मुम्बई, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल के तटीय प्रदेशों तथा अण्डमान एव निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है। देश में तेल का कुल भण्डार 13 करोड़ टन अनुमानित किया गया है। किन्तु इतना कुछ होने के बाद भी वर्तमान में तेल का घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकता के हिसाब से काफी कम बैठता है। वर्ष 1950-51 में देश में कच्चे तेल का उत्पादन केवल 25 लाख टन था। जबकि माँग 34 लाख टन थी। वर्ष 2000-2001 में देश में खनिज तेल का उत्पादन 32.43 मिलियन टन रहा था, जबकि अप्रैल-नवम्बर 2001 के दौरान उत्पादन 21.24 मिलियन टन रहा।

डॉलर के रूप में तेल आयात बिल 1998-99 में 63 अरब डॉलर था जो 1999-2000 में बढ़कर 125 अरब डॉलर तथा 2000-2001 में 18 अरब डॉलर हो गया था। कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों में माँग में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2001-2002 में देश में पेट्रोलियम टन रहने की सम्भावना है। जबकि 2000-2001 में यह खपत 100 मिलियन टन अनुमानित थी।

देश में खनिज तेल की कुल आवश्यकता के लगभग 30 प्रतिशत भाग की आपूर्ति ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कुल 32.43 मिलियन टन खनिज तेल का उत्पादन देश में हुआ है। जबकि 2001-2002 में भी यह इतना ही रहने की सम्भावना है। 2001-2002 के दौरान आयात किए जाने वाले अनुमानित 75 मिलियन टन खनिज तेल में सर्वाधिक 45 मिलियन टन का आयात भारतीय तेल निगम (IOC) द्वारा किए जाने की सम्भावना है। जबकि दूसरे स्थान पर 27 मिलियन टन तेल का आयात निजी क्षेत्र की रिलायंस पेट्रोलियम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। ज्ञातव्य है कि देश में कार्यरत 17 रिफायनरियों की कुल वार्षिक शोधन क्षमता 112 मिलियन टन है।

पेट्रोलियम क्षेत्र की स्थिति (मिलियन टन में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-00	00-01	01-02 (अप्रैल-नवम्बर)
खनिज तेल का उत्पादन	33 86	32 72	31 95	32 43	21 24
पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन	61 31	64 54	79 41	95 61	65 82
खनिज तेल का आयात	54 02	39 80	57 80	78 34	—
पेट्रोलियम पदार्थों की खपत	79 80	90 60	97 10	99 60	—
रिफायनरियों का कुल उत्पादन	65 20	68 54	85 96	103 44	70 37
शोधन क्षमता	62 24	—	92 63	112 54	115 0

जिनमे सार्वधिक क्षमता निजी क्षेत्र की रिलायस पेट्रोलियम कम्पनी की रिफायनरी की है. रिलायस पेट्रोलियम की 27 मिलीयन टन वार्षिक क्षमता वाली जामनगर रिफायनरी विश्व मे सबसे बडी तेल रिफायनरी है तेल रिफाइनरियों का वास्तविक निष्पादन 2000-2001 मे यह 95 प्रतिशत रहने की सभावना है देश मे तेलशोधन क्षमता मे तेजी से वृद्धि के लिये पेट्रोलियम क्षेत्र को जून 1998 से लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोल एव डीजल के मूल्यों का निर्धारण पेट्रोलियम कम्पनीयों स्वय ही मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर करेगी

8मार्च 2002 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार पेट्रोल एव डीजल के बिक्री केन्द्र स्थापित करने का अधिकार मौजूदा चार कम्पनीयो (HPCL, BPCL, IOC, IBP) तक ही सीमित नही रहेगा। इन उत्पादो के बिक्री केन्द्र अब अन्य पात्र कम्पनियो द्वारा भी स्थापित किए जा सकेगे इनमे निजी क्षेत्रो की कम्पनियो भी शामिल होगी। यदि इस क्षेत्र मे उनका निवेश कम से कम 2 हजार करोड रुपये का किया गया हो या फिर इतनी राशि का निवेश आगामी 10 वर्षों मे करने की प्रतिबद्धता हो इस प्रकार के विपणन की अनुमति के

लिए रिलायस कम्पनी ने सरकार को आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है।

सीमेण्ट उद्योग — किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए तीन उद्योग आधारभूत उद्योग माने जाते हैं जिनमें लोहा एवं इस्पात उद्योग का स्थान प्रथम, कोयला उद्योग का द्वितीय व सीमेण्ट उद्योग का स्थान तृतीय है। आधुनिक युग में भी सभी परियोजनाएँ सीमेण्ट पर ही आधारित होती हैं। सड़क निर्माण, भवन निर्माण, कारखाना निर्माण, सिंचाई एवं विद्युत् योजनाएँ, आदि सभी में सीमेण्ट की आवश्यकता है।

(II) उद्योग का विकास—भारत में सीमेण्ट का प्रथम कारखाना मद्रास में 1904 में साउथ इण्डिया इण्डस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन वह असफल रहा। अतः प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक सीमेण्ट को आयात किया जाता रहा। 1921-14 के बीच तीन बड़े सीमेण्ट कारखाने स्थापित किये गये— गुजरात में पोरबन्दर नामक स्थान पर टाटा एण्ड सन्स द्वारा इण्डियन कम्पनी के नाम से, मध्य प्रदेश में खटाऊ समूह द्वारा कटनी सीमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पनी के नाम से, व लाखेरी में किलिक निक्सन द्वारा बूदी पोर्टलैण्ड सीमेण्ट कम्पनी के नाम से। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इन तीनों कारखानों की उत्पादन क्षमता 76 हजार टन थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 7 कारखाने और खोले गये। इस प्रकार 1924 में इन सभी की उत्पादन क्षमता 5 लाख टन हो गयी। इसी बीच विदेशों से भी सीमेण्ट आयात किया जाता रहा। इससे उद्योग में आपस में प्रतियोगिता होने लगी। अतः उद्योग ने सरकार की माँग की, लेकिन उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया, फलतः आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए 1925 में इण्डियन सीमेण्ट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन की स्थापना की गयी व 1927 में कंक्रीट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का गठन किया गया जिसका उद्देश्य सीमेण्ट की माँग में वृद्धि करना था। 1930 में इन दोनों संगठनों को मिलाकर सीमेण्ट मार्केटिंग कम्पनी स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों का सीमेण्ट बेचना था।

सन् 1936 में एसोसिएटेड सीमेण्ट (A.C.C.) कम्पनी की स्थापना की गयी

जिसमें डालमियाँ समूह की सीमेण्ट कम्पनियों को छोड़कर अन्य सभी कम्पनियाँ इस कम्पनी की सदस्य बन गयी और उन्होंने अपने सीमेण्ट को बेचने का अधिकार इस कम्पनी को दे दिया। इस प्रकार भारत में दो समूह हो गये— ए सी सी व डालमियाँ। 1936 में राजस्थान में सवाई माधोपुर नामक स्थान पर जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कारखाना खोला गया। इसके बाद 1939 में मैसूर राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर एक कारखाना राजकीय कारखाने के रूप में खोला गया। इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया जिससे उद्योग को अपना उत्पाद बढ़ाने का अवसर मिला। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में 23 कारखाने थे जिसमें से 5 पाकिस्तान में चले गये। इन कारखानों की उत्पादन क्षमता 19.5 लाख टन थी, लेकिन उस वर्ष में इनका उत्पादन 14.7 लाख टन था।

योजनाओं में उद्योग की प्रगति—विभिन्न योजनाओं में सीमेण्ट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया जिसके फलस्वरूप नये-नये कारखाने खोलने की अनुमति दी गयी व पुरानों को अपना विस्तार करने का अवसर दिया गया। प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय 21 कारखाने थे जो द्वितीय योजना के अन्त में 34, तृतीय योजना के अन्त में 38, चौथी योजना के अन्त में 51, पाँचवी योजना के अन्त में 58, छठवी योजना के अन्त में 89 व सातवी योजना के अन्त में 316 हो गये हैं। विगत वर्षों से उद्योग का विकास निम्नवत तालिकानुसार हुआ है।

वर्ष	उत्पादन(लाख टनो में)
1950—51	27
1970—71	143
1990—91	488
1998—99	880
1999—2000	940

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सीमेण्ट का उत्पादन गत 49 वर्षों में लगभग 33 गुना बढ़ा है जो एक उल्लेखनीय प्रगति है। भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति सीमेण्ट उपभोग 4.4 किलोग्राम था जो अब बढ़कर 95 किलोग्राम हो गया है, लेकिन यह अन्य देशों की तुलना में अभी भी कम है। चीन में प्रति व्यक्ति खपत 325 किलोग्राम, जापान में 684 किलोग्राम जबकि विश्व का औसत 217 किलोग्राम है। नवी पंचवर्षीय योजना में सीमेण्ट का उत्पादन लक्ष्य 2001-2002 वर्ष के लिए 1,130 लाख टन रखा गया है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति— भारत में इस समय 115 बड़े व लगभग 300 छोटे सीमेण्ट के कारखाने हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1,100 लाख टन है। इस क्षमता का 85 प्रतिशत निजी क्षेत्र में व शेष 15 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में है। इस उद्योग में 8,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है तथा 3 लाख श्रमिक तथा 10 हजार कार्यालय कर्मचारी (Office Staff) कार्य करते हैं।

भारी इंजीनियरिंग उद्योग (HEAVY ENGINEERING INDUSTRY):-

एक देश के औद्योगीकरण में इंजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज विश्व में जितने भी समृद्ध राष्ट्र हैं उनकी तीव्र प्रगति का छिपा हुआ रहस्य उन देशों के इंजीनियरिंग उद्योग का विकास ही है। विद्वानों का कहना है कि बिना इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के देश की मशीनों का एक पहिया भी नहीं चल सकता है।

भारी इंजीनियरिंग उद्योग में कागज, चीनी, जूट, कोयला, आदि उद्योगों की मशीनें बनाने वाले कारखाने, डीजल इंजन, रेलवे वाहन, शक्तिचालित पम्प, रोडरोलर बनाने वाले कारखाने, मोटरगाड़ियाँ, जीप, ट्रैक्टर व मोटर साइकिल आदि के कारखाने व भारी स्ट्रक्चरल फ़ैब्रिकेशन्स बनाने वाले कारखाने, आदि आते हैं।

(II) उद्योग का विकास— देश में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, लेकिन यह उद्योग स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका और इसका विकास कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इस काल के अधिकांश

उद्योग मरम्मत करने वाले उद्योग थे यद्यपि रेलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कारखाने रेलवे द्वारा अवश्य खोल गये थे। प्रारम्भ में इजीनियरिंग उद्योग का विकास मुख्य रूप से कलकत्ता के आस-पास ही हुआ जहाँ कई प्रख्यात कंपनियों ने कई कारखानों की नींव डाली। द्वितीय विश्वयुद्ध इस उद्योग के लिए एक वरदान के रूप में रहा जिसने उद्योग को विकास करने का अवसर दिया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व यह उद्योग अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। 1939 में भारतीय इजीनियरिंग एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या केवल 58 थी।

योजना में उद्योग की प्रगति – भारत में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारी इजीनियरिंग उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। कई नवीन व आधुनिक कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये। पुराने उद्योगों को पूर्ण विकास करने का अवसर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारी उद्योगों की वस्तुओं का उत्पादन आशातीत गति में बढ़ा। योजनाकाल में भारी इजीनियरिंग उद्योग का विकास निम्न प्रकार हुआ है।

विवरण	उत्पादन (करोड़ रुपये में)				
	1950-51	1970-71	1990-91	1998-99	2000-01
1 मशीन टूल्स(करोड़ रुपये में)	03	430	773	1,333	1226
2 रेलवे वैगन (हजारों में)	Nil	11	25	N A	28
3 ट्रक व यात्री गाड़ियाँ (हजारों में)	17	88	366	642	784
4 मोटर-साइकिल व स्कूटर (हजारों में)	Nil	97	1,843	3,278	3755
5 पावर पम्प (हजारों में)	35	259	519	555	481
6 डीजल इंजन (हजारों में)	6	65	158	432	306
7 पावर ट्रांसफॉर्मर (लाख KVA में)	2	81	366	422	703

8 बिजली के मोटर	10	272	586	710	560
9 सूती वस्त्र उद्योग मशीने	—	30	945	N A	N A
10 चीनी उद्योग मशीनें	—	14	87	N A	N A
11 सीमेण्ट उद्योग मशीने	—	42	276	N A	N A

उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की। यहाँ पर सूती वस्त्र, चीनी व सीमेण्ट के कारखानों के लिए मशीनें, मोटर-साइकिलें व स्कूटर अब बनने लगे हैं जिनका 1950-51 तक कोई नाम भी नहीं था। सभी वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, जैसे, मशीन है कि इस काल में कई महत्वपूर्ण इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की गयी हैं जिनमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड व हेवी कॉरपोरेशन प्रमुख हैं।

उद्योग की वर्तमान स्थिति— 1950-51 में इंजीनियरिंग उद्योग का उत्पादन केवल 50 करोड़ रुपये का था जो 1974-75 में बढ़कर 3,600 करोड़ रुपये व 1998-99 में 86,000 करोड़ रुपये के लगभग हो गया है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 1970-71 वर्ष में 198 करोड़ रुपये का हुआ था जो 1998-99 में बढ़कर 18,371 करोड़ रुपये का हो गया है।

जूट उद्योग (JUTE INDUSTRY) :- भारत की औद्योगिक व्यवस्था में जूट उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले साधनों में से एक साधन है। विश्व की जूट उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत भाग भारत में ही उत्पादित होता है। भारत में जूट 'सोने के रेशे' के नाम से पुकारा जाता है।

(II) उद्योग का विकास— जूट उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। पहले इसको कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जाता था और कच्चे जूट तथा कपड़े (टाट) का निर्यात किया जाता था। आधुनिक जूट मिल की स्थापना सर्वप्रथम 1855 में कलकत्ता के पास रिशरा नामक स्थान पर एक अंग्रेज जॉर्ज आर्कलैण्ड ने एक बंगाली व्यापारी श्याम सुन्दरसेन की साझेदारी का व्यापार

शुरू किया। इसके बाद कलकत्ता के निकट हुगली नदी के आस-पास इस प्रकार के अन्य मिल भी स्थापित किये जाने लगे और 1882 तक ऐसे मिलों की संख्या 22 हो गयी। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक इन मिलों की संख्या बढ़कर 64 हो गयी थी।

प्रथम महायुद्ध के समय इसकी वस्तुओं की माँग बढ़ने से इस उद्योग का काफी विकास हुआ और 1925-26 तक इसके मिलों की संख्या बढ़कर 90 हो गयी, लेकिन विश्वमन्दी से इसके विकास में बाधा उत्पन्न हो गयी, परन्तु द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने से इस उद्योग को विकास करने का पुन अवसर मिला और देश-विभाजन के समय (1947) तक इस उद्योग के मिलों की संख्या बढ़कर 106 हो गयी थी।

देश-विभाजन का इस उद्योग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। जूट उत्पादन क्षेत्र का दो-तिहाई भाग पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में चला गया, जबकि लगभग सभी मिल भारत के हिस्से में आये, तब से कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गयी। अतः जूट के उत्पादन के क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न किया गया जिससे कच्चे जूट का उत्पादन जो 1948 में केवल 17 लाख गॉंठे था वह 1951 में बढ़कर 33 लाख गॉंठे हो गया।

योजनाओं में उद्योग की प्रगति-योजना काल में सरकार का ध्यान मुख्य रूप से तीन बातों की ओर रहा है (i) कच्चे जूट के उत्पादन में वृद्धि, (ii) मिलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अनुमति न देना व (iii) जूट की बनी वस्तुओं – बोरे, टाट, आदि के उत्पादन में वृद्धि करना। गत वर्षों में जूट उद्योग की गति निम्न प्रकार रही है

वर्ष	मिलों द्वारा उत्पादन (लाख टनो में)
1950-51	8.4
1970-71	10.6
1990-91	14.3
1998-99	15.9

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग का उत्पादन घटता-बढ़ता है। इस उत्पादन में घटने-बढ़ने का मुख्य कारण कच्चे जूट का उत्पादन है जो स्वयं घटता-बढ़ता रहता है। नवी पंचवर्षीय योजना में जूट के उत्पादन के लक्ष्य 2001-2002 वर्ष के लिए 17.9 लाख टन रखा गया है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति— “इस समय जो जूट मिल कार्य कर रहे हैं उनमें से 6 मिलों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अतः वे सरकार के पास हैं। इन मिलों में 44,476 करघे हैं।” इस उद्योग में 300 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है व डेढ़ लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यह उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह उद्योग अपने कुल उत्पादन का 62 प्रतिशत जूट के बोरे के रूप में, 20 प्रतिशत टाट के रूप में व शेष 18 प्रतिशत गलीचों व अन्य वस्तुओं के रूप में करता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत ने अपने औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है और वर्तमान में वह विश्व के उन औद्योगिक देशों में गिना जाता है जो औद्योगिक क्षेत्र में उच्च शिखर पर माने जाते हैं। यहाँ पर इस अवधि में हुए औद्योगिक विकास एवं संरचना के परिवर्तनों को अग्र आधारों पर बँटकर अध्ययन कर सकते हैं

(अ) आधारभूत उद्योग

- (1) लोहा एवं इस्पात उद्योग, (2) खान उद्योग,
- (3) मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, (4) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग,
- (5) रसायन उद्योग।

(ब) परिवहन उद्योग।

(स) उपभोक्ता उद्योग।

(द) सुरक्षा उद्योग।

(ई) कुटीर एवं लघु उद्योग।

(अ) आधारभूत उद्योग— आधारभूत उद्योग से अर्थ ऐसे उद्योगों से है जो एक देश के

विकास हेतु परम आवश्यक होते हैं , जैसे लोहा एव इस्पात उद्योग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग व रसायन उद्योग। अब हम इन उद्योगों के विकास एवं संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे

(1) लोहा एव इस्पात उद्योग— लोहा एव इस्पात के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय केवल 2 बड़े कारखाने थे, लेकिन आज 8 हैं। इनमें से 1 निजी क्षेत्र में व 7 सार्वजनिक क्षेत्र में है। 1950-51 में ढलवाँ लोहे का उत्पादन 17 लाख टन, इस्पात सिलिलियों का उत्पादन 15 लाख टन व तैयार इस्पात का 10 टन था जो 2000-01 में बढ़कर क्रमशः 340, 270 व 293 लाख टन हो गया है।

(2) खान उद्योग— यद्यपि खानों से कोयला व अन्य वस्तुएँ निकालना 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही शुरू हो चुका था, लेकिन स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इस उद्योग का काफी विकास हुआ है। खानों में आधुनिकतम मशीनें लगायी गयी हैं तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक प्रबन्ध कर पर्याप्त साज-सज्जा का विकास किया गया है। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि खानों से मिलने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, जैसे कोयले का उत्पादन 1950-51 में 323 लाख टन था। वह 2000-01 में बढ़कर 3,326 लाख टन हो गया, अर्थात् कोयले के उत्पादन में लगभग दस गुने की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कच्चे लोहे का उत्पादन भी जो 1950-51 में 30 लाख टन था 2000-01 में बढ़कर 707 लाख टन हो गया है।

(3) मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग— यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से कुछ वर्ष पूर्व मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत हो गयी थी, लेकिन इसका विकास तो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ही हुआ है। जैसे (i) मशीन टूल्स (Machine Tools) का उत्पादन 1950-51 में केवल 30 लाख रुपये के मूल्य का था जो 2000-01 में बढ़कर 1,226 करोड़ रुपये का हो गया है। इसी प्रकार (ii) पावर पम्प (Power driven Pump) व डीजल इंजन (Diesel Engines) का 1950-51 में उत्पादन क्रमशः 35 हजार व 6 हजार था जो 2000-01 में क्रमशः 4.8 लाख व 31 लाख तक पहुँच गया है।

(4) इलेक्ट्रीकल इजीनियरिंग उद्योग— भारत में प्रथम बिजलीघर 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कर्नाटक राज्य में शिवसमुद्रम नामक स्थान पर बनाया गया था जिसने सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया। इसके लिए सभी प्रकार की मशीनों का आयात किया गया था, लेकिन भारत आज इन मशीनों व मोटरो को स्वयं बना रहा है। 1950—51 में भारत में 2 लाख KVA के पावर ट्रांसफार्मर बनाये गये थे, जबकि 2000—01 में 703 लाख KVA के। इसी प्रकार 1950—51 में एक लाख बिजली के मोटर बनाये गये थे, लेकिन इनका उत्पादन 2000—01 में बढ़कर 56 लाख मोटरे हो गया। बिजली के पखो एवं बल्बों का उत्पादन भी काफी बढ़ा है और इस उद्योग का इस सम्बन्ध में प्रशसनीय विकास हुआ है। 1950—51 में 2 लाख बिजली के पखे, 1 करोड़ 50 लाख बल्ब बनाये गये थे, जबकि 2000—01 में इनका उत्पादन बढ़कर क्रमशः 52 लाख व 449 करोड़ हो गया है।

(5) रसायन उद्योग— भारत के आधारभूत उद्योग में रसायन उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हो गयी थी, लेकिन इसका विकास स्वतन्त्रता — प्राप्ति के पश्चात ही हुआ है। वर्तमान में इस उद्योग का उत्पादन 90,000 हजार करोड़ रुपये है। इस उद्योग को 5 प्रमुख भागों में बाँट सकते हैं

(1) रासायनिक खाद— यह खाद दो प्रकार की होती है— एक तो फॉस्फेटयुक्त व दूसरी नाइट्रोजनयुक्त। यहाँ फॉस्फेटयुक्त खाद का उत्पादन 1906 में व नाइट्रोजनयुक्त खाद का उत्पादन 1938 में प्रारम्भ हुआ है। 1950—51 में नाइट्रोजनयुक्त खाद का उत्पादन 9 हजार टन व फॉस्फेटयुक्त खाद का उत्पादन भी 9 हजार टन था। इस प्रकार दोनों खादों का कुल उत्पादन 18 हजार टन था जो 2000—01 में नाइट्रोजनयुक्त खाद का 1103 लाख टन व फॉस्फेटयुक्त खाद का 375 लाख टन हो गया है। इस समय रासायनिक खाद के कुल 143 कारखाने हैं।

(2) भारी रसायन— भारी रसायन में तीन रसायन आते हैं—गन्धक का तेजाब (Sulphuric Acid), सोडा एश (Soda Ash) व कॉस्टिक सोडा (Caustic Soda)। गन्धक के तेजाब का

उत्पादन 19वीं शताब्दी के अन्त में, सोडा एश व कॉस्टिक सोडे का 1940 में प्रारम्भ हुआ है। पिछले 50 वर्षों में (1950-51 से 2000-01) गन्धक के तेजाब का उत्पादन 27 गुना, सोडा एश का 33 गुना तथा कॉस्टिक सोडे का 118 गुना बढ़ा है। इस समय गन्धक के तेजाब की 109, सोडा एश की 6 व कॉस्टिक सोडे की 38 इकाइयाँ हैं।

(3) औषधियाँ और दवाइयाँ—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय अधिकांश दवाइयों व औषधियों का आयात होता था। 1947 में यहाँ केवल 12 करोड़ रुपये के मूल्य की दवाइयों का उत्पादन हुआ था जो 2000-01 में बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपये मूल्य का हो गया है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में कई कारखाने हैं, जैसे इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड व हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लिमिटेड।

(4) पेट्रो-केमिकल्स—इसका विकास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हुआ है। इसकी वर्तमान में चार बड़ी इकाइयाँ हैं—राष्ट्रीय रसायन उद्योग लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड, नफ्ता प्लांट व हरदीलिया केमिकल्स। 1969 में भारतीय पेट्रो-रसायन लिमिटेड के नाम से एक सार्वजनिक कम्पनी स्थापित की गयी थी।

(5) पेन्ट एवं वार्निश— इस उद्योग का विकास भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हुआ है। इस समय इसकी 26 इकाइयाँ संगठित क्षेत्र में व अनेक छोटी इकाइयाँ हैं। 1951 में इस उद्योग का उत्पादन 34 हजार टन था जो 2000-01 में बढ़कर 250 हजार टन हो गया है।

(ब) परिवहन उद्योग— भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् परिवहन उद्योग का काफी विकास हुआ है। 1950-51 में यहाँ 53,600 किलोमीटर रेलमार्ग था, लेकिन आज उसकी लम्बाई 63,028 किलोमीटर से अधिक है। 1948 में भारत ने पहला डीजल रेल इंजन अमरीका से आयात किया था, लेकिन चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स, कोलकता अब यह इंजन भारत में ही बना रहा है। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 100 डीजल से चलने वाले व 150 बिजली से चलने वाले इंजन बनाने की है। इसी प्रकार पहले भारत रेल के सवारी गाडी के डिब्बे विदेशों से आयात करता था, लेकिन अब यह इण्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बुर (तमिलनाडु)

तथा रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला द्वारा बनाये जा रहे हैं। पहला सवारी गाडी का डिब्बा यहाँ 1955 में बना। प्रति वर्ष यहाँ इन दोनों कारखानों में 2000 गाडी के डिब्बे बनाये जाते हैं। इसी प्रकार डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी भी रेल के इंजन बना रहा है। इसका पहला डीजल इंजन जनवरी 1963 में बनकर तैयार हुआ था। यहां प्रति वर्ष 200 डीजल से चलने वाले इंजन बनाये जाते हैं।

भारत में प्रथम मोटर गाडी 1898 में आयात की गयी थी, लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति से कुछ पहले इनके उत्पादन के लिए प्रबन्ध कर लिये गये थे। इस समय देश में 18 कारखाने कारों, ठेलों व जीपों का उत्पादन 7 लाख 84 हजार तथा स्कूटरों, मोटर साइकिलों व मोपेडों का 37 लाख 55 हजार था।

भारत पहले पानी के जहाज विदेशों से मँगाता था, लेकिन यह हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम द्वारा भारत में ही बनाये जा रहे हैं। इस शिपयार्ड की क्षमता 2 या 3 जहाज प्रति वर्ष बनाने की है जिसको बहुत शीघ्र ही 4 जहाज प्रति वर्ष तक लाया जा रहा है। हवाई जहाज बनाने का पहला कारखाना 1940 में बालचन्द्र हीराचन्द्र ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से स्थापित किया था जिसे बाद में भारत सरकार व कर्नाटक सरकार ने ले लिया। इसका पहला जहाज 1953 में बनकर बाहर आया। 1964 में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को नवीन स्थापित हिन्दुस्तान एरोनोटिक लिमिटेड में मिला दिया गया। वर्तमान में यह कम्पनी वायु सेना व नागरिक उड़्डयन विभाग दोनों के लिए वायुयान बना रही है।

(स) उपभोक्ता उद्योग— स्वतन्त्रता—प्राप्ति के पश्चात् उपभोक्ता उद्योग का काफी विकास हुआ है। वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र नहीं बना रहा है बल्कि ऊनी व कृत्रिम रेशे से आधुनिकतम वस्त्रों का निर्माण कर रहा है। घड़ियाँ जो पहले स्विट्जरलैण्ड या अन्य देशों से आती थी अब H M T (Hindustan Machine tools) नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी व अनेक अन्य निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बनायी जा रही हैं। प्रेशर कुकर हाकिन्स, प्रेस्टीज, प्रिन्स व ऊषा, आदि के नाम बिक रहे हैं। आज भारत बैटरी, साबुन व सौन्दर्य प्रसाधन (Toilet

and Cosmetics), हल्के पेय (Soft Drink), सिगरेट, बिस्कुट व गोली (Biscuits and Confectionary), रोटी (Bread), साइकिले, रेडियो व टेलीविजन, चश्में के फ्रेम व शीशे, फाउन्टेन पेन, पेन्सिल, दियासलाई, आदि सभी में आत्मनिर्भर हैं।

(द) सुरक्षा उद्योग— वैसे तो भारत में सुरक्षा उद्योग की स्थापना प्रथम महायुद्ध के बाद ही हो गयी थी, लेकिन इसका विकास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् ही हुआ है। यहाँ सभी प्रकार की गोलियाँ, तोप के गोले व अन्य बम बनते हैं। साथ ही यहाँ, बन्दूक, मशीन गन, तोप, रडार, लडाकू हवाई जहाज, पनडुब्बी, समुद्री सेना के लिए जहाज, सेना के लिए ट्रक, जीप, मोटर साइकिले आदि सभी कुछ बनाने के कारखाने हैं। जिससे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है।

(ई) लघु उद्योग— स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् लघु उद्योगों के विकास व संरचना में काफी परिवर्तन आया है। पहले कलात्मक व हाथ की वस्तुओं का निर्माण अधिक होता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अधिकांश लघु उद्योगों के मालिक शक्ति एवं आधुनिक औजारों का अधिकतम उपयोग करने लगे हैं तथा उनका उत्पादन प्रमाणित होने लगा है। इससे अब वे वृहत उत्पादन की इकाइयों से टक्कर लेने लगे हैं। 1961 में यह 36 हजार इकाइयाँ लघु उद्योगों के रूप में सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड थी जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 33.7 लाख हो गयी है। इसमें बिना पंजीकृत इकाइयाँ भी शामिल हैं। यह इकाइयाँ 5 हजार वस्तुओं का निर्माण करती हैं। 2000-01 में इन सभी इकाइयों में 6,45,496 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्माण किया है। आजकल लघु उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा 40 प्रतिशत के लगभग ही है, परन्तु आशा है भविष्य में इनका उत्पादन 50 प्रतिशत तक पहुँच जायेगा।

भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारम्भ किया गया है। अब तक नौ पंचवर्षीय, तीन वार्षिक योजनाएँ, तीन वर्ष का अन्तरकाल पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के 51 वर्ष हो चुके हैं। जिसमें नये-नये एवं आधुनिक उद्योग स्थापित हुए हैं। पुराने

उद्योगों का विकास किया गया है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया गया है। श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उद्योगों में भारी मात्रा में पूँजी का विनियोजन किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास निम्न प्रकार हुआ है

प्रथम योजना (1951-56)— प्रथम योजना में औद्योगिक विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि प्रथम योजना मूलतः कृषि विकास पर आधारित थी, लेकिन फिर भी उद्योग एवं खनिज विकास पर 55 करोड़ रुपये सार्वजनिक व्यय के रूप में किये गये। निजी क्षेत्र द्वारा भी अपने उद्योगों के विकास पर 229 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस प्रथम योजना काल में अनेक आधारभूत उद्योग जैसे—सिन्दरी उर्वरक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (HMT), हिन्दुस्तान एन्सेक्टीसाइड्स, पिप्परी पेन्सीलिन प्लांट, हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, एण्टीग्रल कोच फैक्टरी, नेपाल न्यूज प्रिंट, आदि स्थापित किये गये निजी क्षेत्र में भी साइकिल, टाइपराइटर्स, डीजल पम्प एवं इंजिन, मशीनरी औजार, आदि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

द्वितीय योजना (1956-61) — द्वितीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया गया और दृढ़ औद्योगिक प्रगति की नींव रखी गयी। द्वितीय योजना में वृहद उद्योग एवं खनिज विकास पर 938 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना में विकास की दर 66 प्रतिशत रही। इस काल में तीन इस्पात कारखानों — राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की नींव रखी गयी। मैसूर इस्पात, चितरजन रेल कारखाना, पैराम्बूर इटीग्रल कोच फैक्टरी, सिन्दरी कारखाना का विस्तार किया गया। जूट, सूती वस्त्र, चीनी, सीमेन्ट, कागज के कारखानों में काम आने वाली मशीनों के निर्माण की व्यवस्था की गयी। इस द्वितीय योजना काल में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक भी काफी बढ़ा।

तृतीय योजना (1961-66)— इस योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया इसके परिणामस्वरूप भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर एवं नवीन चौथा कारखाना—बोकारो की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया

गया। कोयला खानों की मशीनों के उत्पादन का कारखाना, राँची में भारी मशीन का कारखाना, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना, भारी विद्युत सयन्त्रों की स्थापना, आदि कार्य भी इसी काल में किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र की इण्डियन इक्स एव फार्मेस्यूटिकल्स लि की तीन नवीन इकाइयों की स्थापना भी इसी काल में की गयी। इस योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र में 1,726 करोड़ रुपये उद्योग एवं खनिज के विकास पर व्यय किये गये। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य 11 प्रतिशत वार्षिक रखा गया था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 9 प्रतिशत वार्षिक ही रही।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)– तीन योजनाओं के बाद तीन वार्षिक योजनाएँ अपनायी गयीं। जिनमें कुल मिलाकर 1,510 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं खनिज पर व्यय किये गये। तथा औद्योगिक उत्पादन दर 2 प्रतिशत रही, इस काल में आधारभूत एवं उत्पादक उद्योगों की विद्यमान क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने एवं नवीन क्षमताओं का सृजन करने का प्रयास किया गया।

चतुर्थ योजना (1969-74)– चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग एवं खनिज के विकास पर 2,864 करोड़ रुपये व्यय किये गये इसके अतिरिक्त निजी उद्योगों ने भी 2,250 करोड़ व्यय किये गये। इस काल में अधूरी औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने, विद्यमान इकाइयों की क्षमताओं में वृद्धि करने एवं कुछ नवीन उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। अतः औद्योगिक लाइसेंस नीति में 1970 व 1973 में कुछ सुधार किये गये। बैंको व कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना काल में औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 8–10 प्रतिशत तक रखा गया था, लेकिन औसत वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही।

पॉंचवी योजना (1974-79)– इस योजना में उद्योग एवं खनिज विकास पर 8,989 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना का उद्देश्य 8.1 प्रतिशत वार्षिक दर से औद्योगिक विकास करना था, लेकिन वास्तविक दर 5.9 प्रतिशत ही रही।

छठवी योजना (1980-85)– उद्योगों पर 16,663 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किये गये जिससे इस योजना का विकास दर 52 प्रतिशत रही ।

सातवी योजना (1985-90)– में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 19,708 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय 25,971 करोड़ रुपये का हुआ है। विभिन्न योजनाओं में औद्योगिक विकास दर इस प्रकार रही है— प्रथम योजना 73 प्रतिशत, द्वितीय योजना 66 प्रतिशत, तृतीय योजना 9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना 47 प्रतिशत, पंचम योजना 59 प्रतिशत, छठवी योजना 52 प्रतिशत तथा सातवी योजना 78 प्रतिशत ।

आठवी योजना में उद्योगों पर 48,102 रुपये व्यय हुए हैं जो कुल योजना 97 प्रतिशत बैठता है।

नवी योजना में उद्योगों पर 65,148 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। और औद्योगिक विकास पर 82 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

वर्तमान स्थिति— उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है जो कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन करता है। दूसरा स्थान पश्चिमी बंगाल का है जो 98 प्रतिशत उत्पादन करता है। इसके बाद तीसरा स्थान तमिलनाडु का चौथा स्थान गुजरात तथा पाचवाँ स्थान कर्नाटक का है। भारतीय योजनाओं के 50 वर्षों (1950-51) से 2000-01 में उद्योगों ने काफी प्रगति की है।

इस प्रगति को उद्योगों के उत्पादन आँकड़ों से आकलित किया जा सकता है। यह आँकड़े निम्न प्रकार हैं

		औद्योगिक उत्पादन	
		1950—51	2000—01
1 तैयार इस्पात	(लाख टनो में)	10	293
2 सीमेण्ट	(लाख टनो में)	27	995
3 चीनी	(लाख टनो में)	11	184
4 मशीनी औजार	(करोड़ रुपये में)	0.3	1226
5 सूती वस्त्र	(करोड़ मीटरों में)	421	1972
6 नाइट्रोजन उर्वरक	(हजार टनो में)	9	11,025
7 वनस्पति	(हजार टनो में)	155	1,257
8 कागज व गत्ता	(हजार टनो में)	116	3,090
9 ऐलुमिनियम	(हजार टनो में)	4	640
10 साइकिलें	(हजारों में)	99	14,974

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 50 वर्षों के नियोजन काल में औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ा है। तैयार इस्पात 29 गुना, सीमेण्ट में 37 गुना, चीनी में 17 गुना, मशीनी औजार में 4,087 गुना, नाइट्रोजन 1,125 गुना, वनस्पति में 8 गुना, कागज में 27 गुना, ऐलुमिनियम में 155 गुना व साइकिलों में 151 गुना।

पिछले दस वर्षों में लघु उद्योगों का विकास हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	इकाइयों की संख्या	रोजगार	उत्पादन (वर्तमान मूल्य)
	(लाखों में)	(लाखों में)	करोड़ रुपये में)
1993-94	23.9	139.4	2,41,648
1994-95	25.7	146.6	2,98,886
1996-97	28.0	160.0	4,11,858
1998-99	30.8	171.2	5,20,650
2000-2001	33.7	185.6	6,45,496

इस सात वर्ष की अवधि में इकाइयों की संख्या 23.9 लाख से बढ़कर 33.7 लाख हो गई है। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या भी 139.4 लाख से बढ़कर 185.6 लाख हो गई है। उत्पादन भी बढ़ा है जो इसी अवधि में 2,41,648 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,45,496 करोड़ रुपये हो गया है।

1991 से अब तक वृहत उद्योगों का भी काफी विकास हुआ है। इस विकास को कुछ उद्योगों के आंकड़े देकर ही प्रदर्शित किया जा रहा है, यद्यपि उद्योगों का क्षेत्र काफी विशाल है।

उद्योग	1990-91	2000-01
1 कोयला (लाख टनों में)	2,225	3,326
2 तैयार इस्पात	135	293
3 मशीनरी औजार (करोड़ रुपये में)	773	1,226
4 मोटर गाड़ियां (हजारों में)	366	784
5 मोटर साइकिल स्कूटर आदि (हजारों में)	1,843	3,755
6 डीजल इंजन (हजारों में)	158	306

7	साईकिले	7,044	14,974
8	विद्युत ट्रान्सफॉर्मर (लाख KW मे)	366	703
9	नाइट्रोजन उर्वरक (हजार टनो मे)	6,993	11,025
10	फास्फेट उर्वरक (हजार टनो मे)	2,052	3,745
11	कपडा (करोड वर्ग मीटर मे)	1,543	1,972
12	बिजली उत्पादन (बिलियन) KW	111	499

अन्त मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लघु उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लघु औद्योगिक इकाइयो की संख्या मार्च 1998 मे 34 14 लाख हो गयी। इनके उत्पादनो का मूल्य 4,65,171 करोड रुपये है। इनमे लगभग 167 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है। इनके उत्पादनो के निर्यात का मूल्य अब 43,946 करोड प्रति वर्ष हो गया है। अत उपर्युक्त नीति सम्बन्धी उपायो में भविष्य मे लघु उद्योग क्षेत्र का पर्याप्त विकास होना निश्चित है।

पंचम् अध्याय

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में सरकारी नीति

आजादी के तत्काल बाद ही उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाये गए। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसे तीन अलग-अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया था। नये स्थापित होने वाले बोर्ड थे—अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (अक्टूबर 1952), अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (नवम्बर 1952) और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (1953)। 1954 में उन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपरोक्त बोर्डों के दायरे के बाहर थे और जिन पर उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 लागू नहीं होता था, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा, 1959 में स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अप्रैल 1952 में पुनर्गठन किया गया और जुलाई में नारियल जटा बोर्ड की स्थापना की गई। इस तरह पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में छ बोर्ड काम कर रहे थे और उनके दायरे में सभी लघु और कुटीर उद्योग आते हैं। इन सबको मिलाकर उस समय एक ऐसा सगठनात्मक ढांचा हुआ था जिसके माध्यम से सरकार ने चार क्षेत्रीय लघु उद्योग सेवा सस्थान स्थापित किए। इनके देश में फैली हुई शाखाओं का कार्य लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वित्तीय साधनों की भी पर्याप्त व्यवस्था की थी।

दूसरी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिए जो भी उपाय किये गए हैं। उनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय उपाय निम्नलिखित हैं

- (i) राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग और राज्य स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना की गई।
- (ii) जिला और ब्लाक पर उद्योग अधिकारी नियुक्त किए गए।
- (iii) 1955 में शुरू किया जाने वाला औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और लगभग 60 औद्योगिक बस्तियाँ की स्थापना की गई जहाँ पर कारखानों की स्थापना के लिए बिजली, पानी, यातायात की सुविधा थी।

- (iv) कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गया।
- (v) औद्योगिक सहकारी सहमितियों के संगठन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया।
- (vi) साख, प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह, अच्छे औजार आदि के रूप में लघु उद्योगों को सहायता देने की दिशा में भी कार्य हुआ। जहाँ पहली योजना में लघु उद्योगों के विकास पर केवल 43 करोड़ रुपये व्यय किये गए थे, वहाँ दूसरी योजना में इस कार्य पर 175 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने लघु उद्योगों के बारे में अपनी बुनियादी नीति निर्धारित की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल उसके क्षेत्र को और ज्यादा फैलाया गया। इस योजना में लघु उद्योगों के विकास पर 241 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि प्रस्तावित व्यय की राशि 264 करोड़ रुपये थी। बाद की योजनाओं में इस राशि में काफी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए छठी योजना में परिव्यय 1,780.5 रुपये रखा गया जबकि वास्तविक व्यय 1,945 करोड़ रुपये था। पाचवी तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों का काफी विकास हुआ। सातवी योजना में लघु उद्योगों के लिए 2,752.70 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया जबकि वास्तविक व्यय 3,249 करोड़ रुपये था। आठवी योजना में ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए 6,334 करोड़ रुपये परिव्यय रखा गया जबकि इस योजना में वास्तविक व्यय 7,094 करोड़ रुपये था। लघु इकाइयों की संख्या जो सातवी योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 में 13.56 लाख थी। 1990-91 में बढ़कर 19.38 लाख हो गई। इसी अवधि में लघु क्षेत्र का उत्पादन 57,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,55,340 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जबकि रोजगार 96 लाख लोगों से बढ़कर 124.30 लाख लोगों तक पहुँच गया। जैसाकि ऊपर कहा गया है, 1999-2000 में लघु क्षेत्र का उत्पादन, चालू कीमतों पर 5,78,470 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। अनुमान है कि इस वर्ष इस क्षेत्र में 178.50 लाख लोग कार्यरत थे।

लघु उद्योगों का यह व्यापक प्रसार बहुत-सी नीतियों का परिणाम था। इन नीतियों में विशेष रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

- (i) लघु क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या लगातार बढ़ाई जाती रही है और अब इस क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या 812 तक पहुँच चुकी है।
- (ii) सरकार ने तय किया कि 409 वस्तुओं की खरीद केवल लघु क्षेत्र से की जाएगी।
- (iii) सस्थागत साख के लिए लघु उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया।
- (iv) 'अति लघु' इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिए गए।
- (v) लघु उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल आदि के आयात के लिए विशेष सुविधाएँ दी गईं।
- (vi) लघु उद्योग सेवा सस्थानों, शाखा सस्थानों और प्रसार केन्द्रों के माध्यम से प्रसार सेवाओं को बढ़ाया गया। मई 1986 में लघु उद्योग विकास फंड की स्थापना की गई ताकि लघु उद्योगों के विकास, विवधीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए पुनर्वित्त सहायता (refinance assistance) दी जा सके। बहुत छोटी लघु इकाइयों की सहायता के लिए 1987-88 में राष्ट्रीय इक्विटी-फंड (National Equity Fund) की स्थापना की गई।

1997 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में जनता सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम था। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से एक ही छत तले उद्यमियों को सभी प्रकार की सहायता (जैसे साख, कच्चे माल की खरीदारी, प्रशिक्षण, विपणन इत्यादि) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम को 1 मई, 1979 से लागू किया गया। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं और ये केन्द्र 431 जिलों का काम देख रहे हैं (मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में इनकी स्थापना नहीं की गई है)।

बहुत समय तक लघु उद्योगों को आवश्यकता से बहुत कम साख सुविधाएँ मिलती रही जिसके परिणामस्वरूप इनके विकास में बाधाएँ आती रही। परन्तु 1967 में बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की नीति के बाद से, और विशेष रूप से 1969 में बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद से, इस क्षेत्र को काफी बड़ी मात्रा में ऋण मिलने लगे। मार्च 1999 के अंत तक लघु उद्योगों को कुल 42,591 करोड़ रुपये के ऋण बकाया (outstanding) थे जो कुल बकाया बैंक ऋणों का 1.16 प्रतिशत है। 1999-2000 में बैंको द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों (priority sectors) को जो ऋण दिए गए उनमें लघु उद्यमों का हिस्सा 39.3 प्रतिशत, कृषि का हिस्सा 33.7 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों का हिस्सा 27 प्रतिशत था। लघु इकाइयों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अभी हाल में 'एक सस्था से ऋण लेने की योजना' (इसे (Single Window Scheme कहा जाता है) को और उदार बनाया गया है। अब छोटे-छोटे उद्योगपति एक ही सस्था राज्य वित्त निगम या फिर राज्य उद्योग विकास निगम से ऋण सम्बन्धी सारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। लघु इकाइयों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank) की स्थापना की गई। 1999-2000 में इस बैंक ने 10,435 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। वास्तव में दी गई सहायता 6,995 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, 85 ऐसे जिले चुने गए हैं, जिनमें लघु उद्योगों की ऋण सबधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंको की विशिष्ट शाखाएँ खोली जाएंगी। अति लघु इकाइयों को उपयुक्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1997 में बैंको को निर्देश दिया कि लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों में से 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को दिया जाए जिनमें अधिकतम 5 लाख रुपये तक निवेश किया गया है, 20 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को जिनमें 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का निवेश है, तथा 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयों को जिनमें 25 लाख रुपये से ज्यादा निवेश है। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों की आधारिक संरचना को मजबूत करने के दृष्टिकोण से आठवी योजना में 50 एकीकृत आधारिक संरचना विकास केन्द्र

(Integrated Infrastructure Department Centres) स्थापित करने की बात की गई है।

यह संक्षिप्त वर्णन इस बात को स्पष्ट करता है कि आजादी के बाद लघु उद्योग का अभूतपूर्व विकास हुआ है, विशेष रूप से पिछले पन्द्रह वर्षों में इन उद्योगों ने तेज प्रगति की है। सरकार का दावा है कि ऐसा उसके प्रयासों के कारण सम्भव हुआ है और बहुत से अर्थशास्त्री इस दावे को स्वीकार करते हैं। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस दावे का खण्डन किया है। बम्बई, हैदराबाद तथा जयपुर की लघु इकाइयों का अध्ययन करने के बाद साडेसरा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन लघु उद्योगों को सहायता प्रदान की गई उनकी सम्पत्ति बिना सहायता प्राप्त उद्योगों से बेहतर नहीं थी। उनके अनुसार क्योंकि सहायता प्राप्त उद्योगों को सस्ती कीमतों पर पूँजी उपलब्ध कराई गई इसलिए इस पूँजी का 'अपव्यय' किया गया और कई बार श्रम के स्थान पर इसका प्रतिस्थापन किया गया जो रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं था। सरकारी नीतियों को आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए अरुण घोष इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन नीतियों के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों को तो लाभ हुआ है परन्तु लघु उद्योगों को खास फायदा नहीं हुआ है। अरुण घोष के अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं

- (i) बड़े शहरों और नगरों में स्थापित लघु उद्योगों को सरकारी नीति से अधिक लाभ हुआ है और इन इकाइयों का कुल उत्पादन में हिस्सा बढ़ा है।
- (ii) वित्तीय सहायता का लाभ अधिकतर लघु उद्योगों के एक छोटे से अंश को ही हुआ है।
- (iii) लघु उद्योगों में व्यापक पैमाने पर क्षमता का अल्प प्रयोग और औद्योगिक रूग्णता व्याप्त है।
- (iv) आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र में प्रगति की दर काफी अच्छी रही है परन्तु परम्परागत हस्तशिल्प तथा ग्राम उद्योगों के लिए यह बात नहीं कही जा सकती है (कच्चे माल, साख तथा विपणन इत्यादि के रूप में सहायता लघु उद्योगों की तुलना में ग्रामोद्योग

को बहुत कम प्राप्त हुई है)।

- (v) इस सबके परिणामस्वरूप, यद्यपि लघु औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार अवसरों का प्रसार हुआ है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी के पैमाने को देखते हुए यह नितान्त अपर्याप्त है। शहरी क्षेत्रों में भी लघु उद्योगों में रोजगार अधिकतर बड़े शहरों व बड़े नगरों में ही बढ़ पाया है।

सरकार ने अगस्त 1991 में लघु, अति लघु उद्योगों के विकास के लिए एक नीति में अति लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया, इन उद्योगों पर लगे स्थानिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया, तथा इनकी परिभाषा का विस्तार करके उसमें उद्योग से जुड़े सभी सेवा व व्यावसायिक उद्यमों (service and business enterprises) को शामिल कर लिया गया। लघु क्षेत्र में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अन्य औद्योगिक इकाइयों को (इनमें देश की अन्य इकाइया भी हो सकती हैं तथा विदेशी इकाइया भी हो सकती हैं) यह अनुमति दी गई है कि लघु व अति लघु क्षेत्र की सम्पूर्ण साख मांग को पूरा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक निरीक्षक कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इस सम्बन्ध में आने वाली सारी बाधाओं को दूर किया जा सके। सभी कानूनों व नियमों के पुनः अवलोकन की बात भी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कारण लघु उद्योगों का अहित न हो, उद्यम-क्षमता के विकास व विस्तार के लिए और सुविधाएँ उपलब्ध कराने की बात की गई है, तथा राष्ट्रीय इक्विटी फंड एवं 'एक संस्था से ऋण लेने की योजना' (Single Window Scheme) का विस्तार किया गया है।

लघु औद्योगिक नीति (1991)

अगस्त, 1991 को भारत सरकार ने पृथक् रूप से एक लघु औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय समर्थन दिए जाने, गुणवत्ता में सुधार, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी सुधार, नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आदि

पर विशेष बल दिया गया। साथ ही अति लघु इकाइयों हथकरघा तथा ग्रामीण उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का उल्लेख इस नीति में किया गया है। इस नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं — • अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी पूँजी में भागीदारी की जा सकेगी किन्तु यह कुल शेयर पूँजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। • उद्योगों से सम्बन्धित समस्त सेवा क्षेत्र एवं व्यावसायिक इकाइयों को अब लघु क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। • लघु क्षेत्र द्वारा बेचे गए माल की कीमत वसूली के लिए फैक्ट्रिंग सेवाओं का विकास किया जाएगा। • अति लघु इकाइयों (Tiny units) में पूँजी विनियोग की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। • महिला उद्यमियों की परिभाषा में संशोधन करके यह शर्त हटा दी गई कि ऐसी इकाइयों में महिला श्रमिकों को प्रधानता होनी चाहिए। • लघु उद्योगों में विनियोग की सीमा 60 लाख रुपये तथा सहायक (Ancillary) एवं निर्यतोन्मुख लघु उद्योगों में विनियोग की सीमा 75—75 लाख रुपये निर्धारित की गई है। • लघु क्षेत्र के निर्यातों को समर्थन देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) को प्रमुख संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। • लघु उद्योग क्षेत्रों को जहाँ भूमि आबंटन, विद्युत कनेक्शन में वरीयता एवं तकनीकी उन्नयन सुविधाओं की सुलभता केवल एक बार मिलेगी वही अति लघु उद्योगों को यह भुगतान समस्या को हल करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की सुविधाओं का जाल पूरे देश में बिठाया जाएगा और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से चलाया जाएगा।

लघु उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये है। अति लघु इकाइयों में निवेश की सीमा को 25 लाख रुपये पर अपरिवर्तित रखा गया है। लेकिन उच्च तकनीक एवं निर्यात उद्योगों के लिए लघु उद्योग की सीमा 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

जे सी साडेसरा के अनुसार, यह नई नीति लघु क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है तथा इससे लघु क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।

विवेचन के दृष्टिकोण से साडेसरा इस नीति के प्रस्तावों को दो हिस्सों में बांटते हैं — (i) लघु व अति लघु उद्यमों के लिए नीति।

(ii) ग्रामीण उद्योगों के लिए नीति।

जहाँ तक लघु व अति लघु उद्यमों के लिए नीति का संबंध है, साडेसरा इसके चार ऐसे तत्वों की चर्चा करते हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं—

1 पहली बात तो यह है कि अति लघु इकाई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। अब अति लघु इकाई की निवेश सीमा 5 लाख रुपये होगी (पहले यह 2 लाख रुपये थी)। अब स्थानिक प्रतिबन्ध भी नहीं होंगे (पहले यह प्रतिबन्ध था कि इस प्रकार की इकाइया 50,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों में ही स्थापित की जा सकती हैं) जहाँ पहले उद्योग का अर्थ मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र माना जाता था अब इसके अन्तर्गत उद्योग से जुड़े सेवा व व्यवसायिक उद्यमों को भी शामिल कर लिया गया है। यह अधिक वास्तविक है। इस प्रकार अब हमारे देश में 'लघु उद्योग नीति' न होकर 'लघु व्यवसाय नीति' होगी जो अधिक तर्कसंगत है (अन्य देशों में भी लघु व्यवसाय नीति ही है)।

2 दूसरी मुख्य बात यह है कि अति लघु क्षेत्र की इकाइयों के विकास के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। जहाँ अन्य लघु इकाइयों को लेकर एक बार प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलेगी (जैसे भूमि प्राप्ति के लिए, बिजली के लिए तथा तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण के लिए) वहाँ अति लघु इकाइयों को इस प्रकार की सहायता लगातार प्रदान की जाती रहेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत तर्क यह है कि अति लघु क्षेत्र की इकाइयों को सहायता देकर तेजी से विकास करने योग्य बनाया जाए ताकि ये जल्द अपने पाव पर खड़ी हो सकें और इन्हें भविष्य में कम सहायता की जरूरत पड़े।

3 तीसरा मुख्य परिवर्तन इक्विटी में हिस्सेदारी से संबंधित है। नई नीति में यह व्यवस्था है कि अन्य इकाइया लघु इकाइयों में 24 प्रतिशत तक की इक्विटी का निवेश कर

सकती है। इससे बड़ी व छोटी सभी इकाइयों को (खास तौर पर सहायक औद्योगिक इकाइयों को) काफी लाभ मिल सकता है तथा औद्योगिक क्षेत्र के इन दोनों 'हिस्सों' को एक-दूसरे के और समीप आने का अवसर मिल सकता है। अब लघु इकाइयों को पूरी इक्विटी की व्यवस्था स्वयं नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा, बड़ी औद्योगिक इकाइया भी लघु इकाइयों के अस्तित्व व विकास में रुचि लेगी।

4 चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय-संगठन का नया कानूनी ढांचा आरम्भ किया गया है जबकि अन्य साझेदारों को दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक ही सीमित है। यह परिवर्तन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके परिणामस्वरूप अब लघु उद्योगपतियों के रिश्तेदार व मित्र उन्हें पूंजी देने में हिचकिचाएंगे नहीं क्योंकि उनका अपना दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक ही सीमित रहेगा।

नौवीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि लघु क्षेत्र की, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से, महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु उद्योगों का विकास क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में भी सहायक हो सकता है क्योंकि लघु इकाइयों को कई अलग अलग क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। बाजार की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप लघु इकाइयों के उत्पादन में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं। लघु उद्योगों का विनिर्माण क्षेत्र के कुल वर्धित मूल्य में और देश के कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। नौवीं योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसार, इन सब तथ्यों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि "लघु उद्योगों पर निवेश के दृष्टिकोण से, प्रौद्योगिकी में सुधार के दृष्टिकोण से, आधारिक संरचना उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, विपणन व साख सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से, परीक्षण व किस्म निरीक्षण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से, अधिक जोर दिया जाए।" नौवीं योजना में लघु उद्योगों के लिए स्वीकार की गई युक्ति के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं

(i) लघु उद्योगों की प्रगति और प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सहायता व

समर्थन दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेशी निवेश इन उद्योगों की प्रतिस्थापित न कर सके।

- (ii) बढ़ती हुई प्रतियोगिता स्थितियों का सामना करने तथा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए, न्यूनतम लाभकारी आकार प्राप्त करने के लिए तथा मुद्रा स्फीति को देखते हुए, लघु औद्योगिक इकाइयों की निवेश सीमा को बढ़ाया जाएगा।
- (iii) पैमाने की बचतों, प्रौद्योगिकी में सुधार तथा निर्यात संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लघु-क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची पर पुनर्विचार किया जाएगा।
- (iv) लघु क्षेत्र की इकाइयों को और ज्यादा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (v) लघु उद्योगों, हथकरघा, पावरलूम, नारियल जटा (जिसका प्रयोग रस्सी, चटाई इत्यादि बनाने में किया जाता है) हस्तशिल्प, ऊन इत्यादि में प्रयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी में और सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे।
- (vi) खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन को संगठनात्मक व वित्तीय रूप से और सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि खादी व ग्रामीण उद्योगों की 20 लाख रोजगार योजना के अधीन, और रोजगार अवसर पैदा किए जा सकें।
- (vii) गैर सरकारी (non-formal) तथा ग्रामीण क्षेत्रों को और साख सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई संस्थाओं की व्यवस्था की जाएगी।
- (viii) कृषि, ऊन उद्योग तथा खाद्य-संसाधन (food processing) उद्योग के विकास के लिए खास कदम उठाए जाएंगे।

30 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने लघु उद्योग के क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं

- (i) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए उत्पादन शुल्क की 50 लाख रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना।
- (ii) विनिर्दिष्ट उद्योगों में प्रौद्योगिकी सुधार के लिए दिये गये ऋणों के सबध में 12

प्रतिशत की ऋण सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (credit linked capital subsidy) उपलब्ध कराना।

- (iii) लघु उद्योगों की तीसरी गणना करना जिसमें रूग्णता और उसके कारणों को भी शामिल किया जायेगा।
- (iv) उद्योग से सम्बन्धित सेवा तथा व्यवसाय उद्यम में निवेश की मौजूदा 5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करना।
- (v) प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में दशवी योजना के अन्त तक (ISO) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75 हजार रुपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।
- (vi) लघु उद्योग सघों को परीक्षण प्रयोगशालाओं के विकास तथा संचालन के लिए प्रोत्साहित करना (ऐसे सघों को प्रतिपूर्ति (reimbursement) आधार पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जाच के बाद एक बार 50 प्रतिशत की पूँजी अनुदान दिया जाएगा)
- (vii) सम्मिश्र ऋणों (composite loans) की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।
- (viii) मन्त्रि मंडल के सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रुप का गठन करना जो इस क्षेत्र में लागू कानूनों व नियमों की गहराई से जाच करे तथा निज कानूनों व नियमों की अब सार्थकता नहीं रह गई है उन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक सुझाव दे।
- (ix) चालू समेकित आधारभूत विकास (Integrated Infrastructure Development) योजना को और क्षेत्र में लागू करना तथा सारे देश में इसका विस्तार इस प्रकार करना कि 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो तथा 50 प्रतिशत भूखंड (plots) अति लघु क्षेत्र को उपलब्ध हो।
- (x) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (जो माइक्रो उद्यमों (micro enterprises) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती है तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर पैदा

करती है) के अधीन परिवार की आय पात्रता सीमा (eligibility limit) को 24,000 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रतिवर्ष करना।

इस व्यापक नीति पैकेज को लागू करने की दिशा में हाल के महीनों में कुछ कदम उठाए गए हैं। आर्थिक समीक्षा, 2000-01 में इन कदमों को निम्नलिखित पांच वर्गों में बांटा गया है।

1 संपाश्विक समस्याओं को हल करने तथा प्रौद्योगिकी सुधार को प्रोत्साहित करने की योजनाएँ। (Schemes to address the problem of collaterals and encourage technology upgradation) लघु क्षेत्र के उद्योगों को संपाश्विक (collateral) प्रदान करने में जो कठिनाई होती है उसका समाधान करने के लिए एक साख गारण्टी फंड (स्कीम) की शुरुआत की गई है जो इन उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 25 लाख रुपये तक दिये गये ऋणों की गारंटी देगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए साख गारण्टी ट्रस्ट फंड (Credit Guarantee Trust Fund) की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी में सुधारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 20 सितंबर 2000 को ऋण सम्बद्ध पूँजी सहायता स्कीम (credit Linked Capital Subsidy Scheme) को अनुमोदन प्रदान किया जिसके अधीन लघु उद्योगों के कुछ चुनिंदा उप-क्षेत्रों में विशिष्ट राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिए गए ऋणों पर 12 प्रतिशत की दर से बैंक एडिड (bank aided) पूँजीगत सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री के अनुसार, इस योजना के अधीन अगले पांच वर्षों में लघु उद्योगों को 5,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

2 उत्पाद शुल्क छूट की सीमा बढ़ाना (Enhancing the excise exemption) 1 सितंबर 2000 से लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क छूट की सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ा कर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।

3 ऋण सुविधाओं में सुधार (Improving credit) —लघु उद्योगों को और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

- (i) मिश्रित ऋण स्कीम के अधीन ऋण सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
- (ii) 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो लघु उद्योगों को मिलाने वाली ऋण सुविधाओं का निरीक्षण व मानीटरिंग करती रहेगी।

4 सिले सिलाए वस्त्रों पर से आरक्षण हटाना (Dereservation of readymade garments) सरकार के अनुसार सिले सिलाए कपड़ों पर से आरक्षण हटा देने से इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में सुधार आएगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पाद-विविधीकरण बढ़ेगा, निर्यातों में वृद्धि होगी, विपणन की नई नई रणनीतियां तैयार होगी, तथा रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

5 निवेश सीमा में वृद्धि (Enhancement of investment ceiling) सरकार ने लघु सेवाओं और व्यापार (उद्योग सबद्ध) उद्यमों के लिए निवेश की सीमा को 5 लाख रुपये कर दिया है।

लघु उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक है। पहले हम देख चुके हैं कि इस क्षेत्र ने विगत वर्षों में न केवल उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि कम पूंजी लागत पर व्यापक रोजगार प्रदान करने, उद्यमिता का व्यापक आधार बनाने एवं ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में उद्योग के विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसलिए वृद्धि के अलावा लघु उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी को घटक काफी सशक्त रहा है। इसलिए सरकारी नीतियों में लघु उद्योगों को हमेशा सशक्त समर्थन दिया गया।

विगत वर्षों की औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में

विशेष स्थान दिया जाता रहा है। औद्योगिक नीति सकल्प (इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन) 1948 में लघु उद्योगों पर जोर दिया गया। 1956 के नीतिगत सकल्प में बेरोजगारों के अवसर प्रदान करने, स्थानीय कुशलता और पूँजीगत ससाधनों को जुटाने में लघु उद्योगों की भूमिक को मान्यता दी गई। 1977 के औद्योगिक नीतिगत विवरण में लघु उद्योगों पर बल तथा आनुषंगिक कार्यक्रमों (एनसिलराइजेशन प्रोग्राम) पर जोर दिया गया। इसी वर्ष लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया। इसी नीति में जिला उद्योग केन्द्रों और लघुतम इकाइयों की अवधारणा सामने आई। 1980 के नीतिगत विवरण में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नाभिक सयत्रों (न्यूक्लियस प्लाट्स) और अनुषंगीकरण पर बल दिया गया। लघु उद्योगों के विकास के जरिये ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का कार्यक्रम आर्थिक विकास की रणनीति का एक मुख्य घटक है।

विगत वर्षों की औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों के विकास एवं उसको प्रोत्साहन देने के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों को तैयार करने पर बहुत बल दिया गया। लघु उद्योगों के विकास मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय स्थापित किया गया। साथ ही सभी राज्यों में इसकी शाखाएँ खोली गईं। इसके चलते बड़ी संख्या में विशेष कार्यों के लिए स्वायत्त संस्थानों तथा निगमित निकायों (कारपोरेट बॉडीज) की स्थापना हुई। अभी हाल तक जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 50-50 के आधार पर वित्त पोषक किया गया। राज्य सरकारों ने भी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत उपायों की शुरुआत की। इनमें संस्थानों, औद्योगिक परिसरों तथा विभिन्न सहायता संरचना तथा विस्तार कार्यक्रमों की शुरुआत के कदम शामिल थे।

नई आर्थिक नीतियों की घोषणा के बाद लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उनको मजबूत बनाने के लिए एकमुश्त नीतिगत उपाय लागू किये गए। इस नीतिगत विवरण का एक उद्देश्य यह था कि सरकार के आर्थिक विकास के लक्ष्यों में इस क्षेत्र को महत्त्व देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाय।

नए नीतिगत विवरण में लघु उद्योगों से संबंधित पुरानी नीतियों के कई सिद्धान्तों में निरंतरता दिखाई देती है जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं

- प्राथमिकता क्षेत्र मानकर लघु उद्योग को कर्ज मिले।
- उत्पाद शुल्क में कमी के जरिये वित्तीय रियायत।

नई लघु उद्योग नीति की मुख्य विशेषताएँ

- 1 इसका प्राथमिक उद्देश्य है इस क्षेत्र को जीवित बनाना तथा इसकी वृद्धि को गति देना। इसी क्रम में इस क्षेत्र को विनियंत्रित किया जाएगा तथा नौकरशाही से मुक्त किया जाएगा ताकि इसकी वृद्धि क्षमता के अवरोध हट जाएँ।
- 2 सभी नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं में ऐसा संशोधन किया जाएगा ताकि उनमें लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के हित के विरुद्ध कोई बाधा न रहे।
- 3 लघुतम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग पैकेज तथा उद्योग से संबंधित सेवा एवं व्यापार उद्यमों को लघु उद्योग के रूप में मान्यता
- 4 रियायती कर्ज/आसान कर्च के स्थान पर (कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों को छोड़कर) लघु उद्योग क्षेत्र का पर्याप्तता के आधार पर समुचित ऋण प्रवाह पर बल।
- 5 दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान को 24% तक का शेयर लघु उद्योग में रखने की छूट ताकि लघु उद्योग की पहुँच पूँजी बाजार तक हो।
- 6 लघु उद्योगों के बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करना तथा सीमित साझीदारी कानून बनाने के लिए विधेयक लाना।
- 7 ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत अवसरचना विकास की एक नई योजना लागू करना।
- 8 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल की स्थापना के जरिये बेहतर टेक्नोलॉजी पर बल तथा एस आईडीओ में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर और सशक्त बनाना।
- 9 संस्थानों, अन्य एजेंसियों तथा सहयोग संघ पद्धति के जरिये लघु उद्योगों के विपणन

(मार्केटिंग) को प्रोत्साहन देना।

- 10 अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन।
 - 11 निर्यात विकास केन्द्र (एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट सेटर) की स्थापना के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और मौजूदा समर्थन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
 - 12 गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करना, लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा बेहतर टेक्नोलॉजी को कार्यक्रम का समर्थन देना।
 - 13 महिला उद्यमियों की परिभाषा में परिवर्तन और महिला उद्यमियों का समर्थन।
 - 14 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार।
 - 15 लघु स्तर के उद्यमी स्वतंत्र तथा अवरोधमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें, इसके लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन।
- सभी प्रकार के लघु उद्योगों के लिए समान नीतिगत ढाँचा
 - लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए उत्पादों की आरक्षित सूची
 - सरकारी खरीद में लघु उद्योग के उत्पादों को खरीद तथा मूल्य में प्राथमिकता
- जैसा पहले भी विचार किया जा चुका है कि पूर्व नीतियों के प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ परिवर्तन भविष्य में होंगे, इसके संकेत हैं।

बदलते समय के अनुरूप उपाय

- 1 लघु उद्योग की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए स्थलगत मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीतिगत पैकेज एक हो गया है— चाहे वह इकाई कहीं भी स्थित हो।
- 2 निवेश सीमा में वृद्धि 35 से 60 लाख रुपये की हो गई है इसलिए इस क्षेत्र का कवरेज अधिक हो गया है।
- 3 अलग-अलग इकाई को आर्थिक सहायता देने के बजाय बुनियादी संरचना सहूलियत

देने की रणनीति बनायी गई है। इसके चलते पूँजी निवेश सहायता योजना समाप्त कर दी गई है और उसकी जगह विकास केन्द्र योजना तथा समेकित बुनियादी संरचना विकास योजना लागू की गई है।

- 4 सेवा क्षेत्र को लघु उद्योग में शामिल किया गया है। फिलहाल 5 लाख तक की निवेश सीमा उद्योगों से संबंधित सेवा तथा व्यापार उद्यमों के लिए रखी गई है।
- 5 ये नीतिगत उपाय बड़े उद्योग तथा लघु उद्योग को निकट लाने के लिए हैं। अब बड़े उद्योग 24% तक की हिस्सेदारी लघु उद्योग में कर सकते हैं।
- 6 स्पष्ट किया गया है कि लघुतम क्षेत्र को एकमुश्त तथा निरंतर मौद्रिक तथा वित्तीय दोनों सहायता दी जाएगी। लेकिन आधुनिक लघु उद्योगों को यह सहायता सिर्फ एक बार दी जाएगी। इस तरह लघु उद्योग क्षेत्र में भी परतीकरण किया जा सकेगा।
- 7 यह मान्यता निहित है कि अब लघु उद्योग क्षेत्र में संरक्षण/विनियमन की जगह गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी तथा आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा।

आर्थिक सुधार प्रक्रिया के क्रम में उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिर भी नए नीतिगत उपाय नई आर्थिक नीतियों के अनुरूप ही हैं। ये परिवर्तन हैं और ये बदलेगे नहीं तथा इसकी परिणति नई औद्योगिक पुनर्रचना में होगी। उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते लघु उद्योगों के समक्ष नए अवसर हैं और ये उपाय ऐसे हैं कि लघु उद्योग इन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनें। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनको बढ़ावा, संरक्षण तथा मार्गदर्शन देने की जरूरत पड़ेगी।

लघु उद्योग का आकार तथा उनकी विविधता के चलते लघु उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों तथा उनकी संस्थाओं की ही हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकारों ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित देने के लिए अपनी नीतियों की घोषणा की है। इन नीतियों के अन्तर्गत लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता मिलती

है। इस तरह भारत सरकार का नीतिगत ढाँचा केन्द्र सरकार की अन्य सस्थाओं तथा राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शन है और इसके चलते सभी के प्रयास एक-दूसरे के पूरक हैं।

लघु उद्योगों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के जरिये केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच तालमेल को सस्थानिक रूप दिया जाता है। यह पंजीकरण योजना स्वैच्छिक है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जिला उद्योग केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाये। पंजीकृत इकाइयों प्रोत्साहन तथा सहायता की नीति के अन्तर्गत कई लाभ ले सकती हैं। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता भी उन्हें मिल सकती है।

लघु उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारें भी नीतियाँ तैयार करती हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करती हैं। ये नीतियाँ राज्य में स्थापित जिला केन्द्रों के मध्यम से लागू की जाती हैं। बुनियादी संरचना का विकास निगम, लघु उद्योग निगम, निर्यात निगम तथा अन्य संबंधित संस्थागत एजेंसियों के द्वारा प्रदान की जाती है।

महानगरों को छोड़कर देश के प्रायः सभी जिलों के लिए लगभग 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में केन्द्र की 50% सहायता से मई 1978 में शुरू किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र की परिकल्पना जिला स्तर पर एकल रूप से लघु उद्योगों को एक ही कार्यालय से सेवाएँ तथा समर्थन दिये जाते हैं। ये केन्द्र राज्य तथा केन्द्र सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करते हैं। जिला उद्योग केन्द्रों में लघु उद्योगों का पंजीकरण होता है। इन केन्द्रों का प्रबंध राज्य सरकारें देखती हैं। अब यह योजना राज्य सरकारों को सौंप दी गई है। तथा वित्तीय वर्ष 1993-94 से राज्य सरकारें ही जिला उद्योग केन्द्रों का खर्च वहन कर रही हैं।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम उत्पत्ति

1977 के औद्योगिक नीतिगत विवरण की सिफारिश पर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए। ग्रामीण, पिछड़े इलाको तथा कस्बों में स्थापित कुटीर तथा लघु उद्योगों को जिला स्तर पर सहायता प्रदान करने वाले एक प्रशासकीय ढाँचे के रूप में ऐसे केन्द्रों की स्थापना जरूरी समझी गई। इनका उद्देश्य यह था कि समर्थन सिर्फ महानगरों तथा राजधानियों में सिमटे रहने के बजाय जिला मुख्यालय तक पहुँचे।

उद्देश्य

लघु उद्यमी को जिन सेवाओं तथा समर्थनों—यानी निवेश के पहले, निवेश के दौरान तथा निवेश के बाद—की जरूरत लघु उद्योग के लिए होती है, वे सभी उसे जिला उद्योग केन्द्र से ही मिल जाएँ। इनमें स्थानीय ससाधन का आर्थिक अन्वेषण, कच्चे माल का प्रावधान, ऋण सुविधाओं का प्रबंध, विपणन व गुणवत्ता निवेश, परामर्श तथा विस्तार सेवाएँ सम्मिलित हैं।

क्रियाकलाप

◆ विनियामक

क इकाइयों का पंजीकरण

ख नीति क्रियान्वयन से संबंधित क्रियाकलाप

ग प्रशासकीय कार्य (विवाद निपटान समेत)

◆ केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निगरानी

◆ सरकारी एजेंसियों से मिलनेवाली सहायता के लिए निम्नलिखित मामलों में सिफारिश:

क मशीनरी

ख वित्त

ग सामग्री की खरीद

घ पजीकरण तथा लाइसेंस जारी करना

◆ निम्न मदों के लिए प्रोत्साहन .

क प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना

ख जिला कार्य योजना

ग उद्यमिता विकास

घ सर्वेक्षण

ड परामर्श

च अनुरक्षण सेवाएँ (एस्कॉर्ट सर्विसज)

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उद्योग में परस्पर-संपर्क-सम्बन्ध .

पजीकरण योजना केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय हेतु प्राथमिक स्थागत आधार प्रदान करती है। कई और तरीकों से भी राज्य सरकारों तथा उद्योग समूहों के बीच सबंध बना रहता है। ये निम्नलिखित हैं

1 सलाहकार समितियों/शासी बोर्डों में प्रतिनिधित्व — सस्थानों और उद्योगों के बीच निकट सम्पर्क बनाने के लिए विभिन्न सस्थानों की सलाहकार समितियों/शासी बोर्डों में लघु उद्योग विभाग व उद्योग समूहों से सदस्य बनाये जाते हैं। विभिन्न नीतिगत सलाह निकायों/एजेसियों में लघु उद्योगों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ आशकाएँ रही हैं। वित्तीय सस्थानों तथा व्यापार, उद्योग तथा वित्त से संबंधित विभिन्न सलाहकार सस्थाओं में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

2 संघों/चैम्बरों/परिषदों के साथ पारस्परिक संपर्क —विभिन्न उद्योग समूहों के साथ पारस्परिक संपर्क की स्वस्थ तथा सतुलित पद्धति मौजूद है। इसे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों और ऐसे अन्य मंचों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

3 राज्यस्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एस.एलआईआईसी) -राज्य स्तर पर वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा प्रदत्त आवधिक ऋण (टर्म लोन) एवं कार्यशील पूँजी की निगरानी, बीमार लघु इकाइयों के पुनर्वास पैकेज की निगरानी और ऋण देनेवाली अन्य कार्यवाहियों के लिए समिति का गठन किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थानों, लघु उद्योग विभागों तथा राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं।

4 आकड़ों का संग्रह -विकास आयुक्त (लघु उद्योग (कार्यालय) पंजीकृत लघु इकाइयों के दो प्रतिशत को नमूना मानकर लघु उद्योग के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना करता है। पंजीकरण आँकड़ों के आधार पर लघु उद्योग से संबंधित विभिन्न आँकड़ों को भी जमा किया जाता है। लघु उद्योगों की वृद्धि की निगरानी के लिए ये सारे क्रियाकलाप राज्य उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों के सक्रिय सहयोग से पूरा किया जाता है। लघु उद्योगों से संबंधित द्वितीय अखित भारतीय गणना (सेसस) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अनुकरणीय उदाहरण है।

5 राज्य सरकारों की सहायता सेवाएँ - राज्य/जिला स्तर पर प्रोत्साहन से जुड़ी एजेंसियों को सलाह एवं सूचना वितरण में लघु उद्योग विभाग के लघु उद्योग सेवा संस्थान नोडल एजेंसी (समन्वय करने वाली एजेंसी) के रूप में कार्य करते हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान राज्य एजेंसियों को कई प्रकार की सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। यथा

- परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल)
- राज्य सभाव्यता सर्वेक्षण
- जिला सभाव्यता सर्वेक्षण
- बाजार संबंधी सूचना
- व्यापार सूचना
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं परामर्श

- आधुनिकीकरण अध्ययन
- सयत्र अध्ययन

राज्यों की नीतियाँ तथा स्कीम :—राज्य सरकारें उद्योग निदेशालयों और जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लघु इकाइयों को तकनीकी और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करती हैं। सहायता और सुविधाओं के मुख्य स्रोत हैं

- औद्योगिक परिसरों का निर्माण तथा प्रोत्साहन
- बिक्रीकर में आस्थगन/रियायत
- बिजली के लिए रियायती सहायता
- विभिन्न जिलों में स्थापित नई इकाइयों को पूँजीगत सहायता
- शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपात राशि (मार्जिन मनी) सहायता स्कीम
- औद्योगिक क्षेत्र में भूमि शेडों के आबटन के लिए हायर परचेज स्कीम
- बिजली, पानी कनेक्शन आदि विभिन्न सुविधाओं में प्राथमिकता
- परामर्श तथा तकनीकी सहायता सेवाएँ

राज्य वित्त निगम लघु इकाइयों को आवधिक ऋण (टर्म लोन) प्रदान करते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम उपकरणों को पट्टे पर लेने, सयत्र एवं मशीनरी की खरीद, भूमि विकास, औद्योगिक सम्पदाओं का संवर्धन (प्रोमेशन) और अन्य विकास प्रयासों में सहायता करते हैं।

राज्य वित्त निगमों के उद्देश्यों और क्रियाकलापों की झलक निम्नलिखित दी गई है।

राज्य सरकारों की लघु उद्योगों से संबंधित नीतियों और प्रोत्साहनों की आम संरचना

राज्य वित्त निगमों (एस. एफ. सी.) की विशेषताएँ

- राज्य वित्त निगम जिला स्तर पर लघु और मँझोले उद्योगों को वित्त प्रदान करने और उनको संवर्धित करने के उद्देश्यों से काम करते हैं।
- देश में अभी 18 राज्य वित्त निगम हैं।

- राज्य वित्त निगम औद्योगिक इकाइयों को आवधिक ऋण/पूँजी में हिस्सेदारी/डिबेंचर, गारंटी तथा बिल ऑफ एक्सचेंज की डिसकाउंटिंग भी करते हैं।
- राज्य वित्त निगम भर में 40000 से भी अधिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अभी 88 प्रतिशत से अधिक इकाइयों राज्य वित्त निगम से सहायता प्राप्त है।
- राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों के लिए आई डी बी आई /एस आई डी बी आई की पुनर्वित्त पोषण (रिफाइनंस) की योजनाएँ चलाते हैं।
- अगस्त, 1993 से राज्य वित्त निगमों को एस एस आर बॉन्ड के माध्यम से और ससाधन जुटाने की अनुमति दे दी गई है।

लघु उद्योग के लिए राज्य सरकारों की नीतियों तथा प्रोत्साहन की आम संरचना

- औद्योगिक विकास तथा निवेश निगमों द्वारा औद्योगिक, क्षेत्रों का विकास तथा प्रबंधन।
- नई इकाइयों के लिए नियत निवेश (अधिकतम सीमा तक ही) के 15 से 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश सहायता
- इकाइयों को नियत अवधि (पाँच से दस वर्ष) तक बिक्रीकर को आस्थगन छूट। इस लाभ की मात्रा नियत पूँजी निवेश और कर दायित्वों के द्वारा सीमित है।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपभोग करने पर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी
- महिला एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता योजना
- आसान शर्तों पर शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपात राशि (मार्जिनल मनी) सहायता योजना
- आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए फीजिबिलिटी स्टडी। परामर्श पर आई लागत में सहायता देना

- हायर परचेज अथवा पट्टे पर भूमि/शेड का आबटन
- अनुमति प्रदान करने तथा विवादों के निपटान के लिए जिला/राज्य स्तर पर अधिकारसंपन्न समितियों का गठन
- पिछड़े/उद्योगविहीन जिलों में अग्रणी इकाइयों स्थापित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन
- संयुक्त/सहायता क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य निगमों द्वारा भागीदारी

लघु उद्योग नीति का मूल्यांकन — लघु उद्योग नीति वक्तव्य (1991) में सरकार ने इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक एवं जीवन्त क्षेत्र के रूप में सम्बोधित किया और नई नीति में इस क्षेत्र के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को विनियमन एवं अधिकारीतन्त्रीकरण की अड़चनों से मुक्त करने का निर्णय लिया। अतः नया नारा है "प्रतिस्पर्द्धा" न कि "आरक्षण"। प्रश्न उठता है कि क्या नई नीति एक बेहतर आर्थिक पर्यावरण का विश्वास दिलाती है जिसमें लघु तथा अति लघु क्षेत्र अपनी विकास-क्षमता को पूर्णतया विकसित कर सकेगा।

पहला, उधार की उपलब्धि के प्रश्न को ही लीजिए। सरकार लघु क्षेत्र के लिए "रियायती उधार" के मिथक का प्रचार करती रही है, चाहे रियायती उधार पर ब्याज की दर गैर-रियायती उधार पर ब्याज दर से केवल 0.5 से 1 प्रतिशत ही कम है। परन्तु अब इस मिथक को भी हटाकर यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि साहाय्यिक/सस्ते उधार की अपेक्षा उधार की पर्याप्त उपलब्धि पर बल दिया जाएगा। पहले भी, लघु उद्योगों को सस्ता उधार कहाँ मिलता था, यदि लघु क्षेत्र ऋणों की स्वीकृति के साथ जुड़े हुए भ्रष्टाचार और इनकी प्राप्ति में विलम्ब को भी ध्यान में रखा जाए। परन्तु उधार की उपलब्धि की सद्भावना को छोड़, उधार की मात्रा के बारे में कोई ठोस बात नहीं कही गई। ऐसी कपोल कल्पना से लघु-क्षेत्र का विकास सशक्त नहीं हो जाता। सरकार को यह निश्चित करना चाहिए था कि संस्थानात्मक उधार का कितना भाग प्राथमिकता के आधार पर लघु-क्षेत्र को उपलब्ध कराया

जाएगा। इसे कार्यनीति भी तय करनी चाहिए थी जो सरकारी लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को उधार की स्वीकृति में कम कर सके।

दूसरे, नीति वल्लव्य में ँक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई हैकि किसी अन्य उधम छोटे हो या बडे, भारतीय हो या विदेशी। इस धारणा का मूल आधार यह है कि बाहरी तत्वो को चूकि 24 प्रतिशत की सीमा तक हिस्सा-पूजी में अधिकार दिया गया है, इस कारण वे अल्पसख्या में रहेगे और उनका लघु इकाईयो पर प्रभुत्व कायम नहीं हो सकेगा। दूसरे, बडी या विदेशी फर्मो के इस क्षेत्र में प्रवेश द्वारा बडे पैमाने के उधोगो से लघु क्षेत्र को तकनालाजी का हस्तातरण हो सकेगा। इन तर्को की गहरी छान बीन से पता चलता है कि ये तर्क मिथ्या पूर्ण है। राम के वैपा, भूतपूर्व लघु-स्तर उधोग विकास उपायुक्त इस सबन्ध में लिखते हैं अभी भी, यह कहा जाता है कि बहुत सी लघु-इकाईयों बडी इकाईयो द्वारा अपने नामजद बेनामी स्वामीयो द्वारा नियत्रीत की जाती है यह भय है कि इस नये प्रावधान द्वारा यह स्थिति कानूनी रुप धारण कर लगी और 24 प्रतिशत हिस्सा-पूजी के साथ ँक या दो ऐसे परिवारो को जोडा जो हिस्सो के स्वामी है, लघु इकाई वस्तुतः बडी कम्पनी की (यदि कानूनी रुप में ऐसा न भी हो) ँक अनुषगी कपनी बन जाएगी। सरकार इसे लघु-क्षेत्र का बडे क्षेत्र के साथ समन्वय कहती है किन्तु यह तो लघु क्षेत्र का निर्भरता-माडल (Dependency model) है जिससे वह बडे पैमाने के उधोगो का उपाग बन जाएगा और इस प्रकार बडे उधोगो द्वारा छोटे उधोगो का शोषण होता रहेगा। इस नयी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र में श्रम-विस्थापन प्रभाव (Labour displacement effects) बहुत गम्भीर रुप धारण कर जाएंगे जोकि अभी तक अपनी जनसख्या और परिणामतः श्रमशक्ति की वृद्धि दर को नियन्त्रित नहीं कर पायी है।

जहाँतक बडी इकाइयो को तकनालजी हस्तातरण का प्रश्न है, यह बात बडी सन्देहपूर्ण है कि क्या बडी इकाइयों ऐसी करना चाहेगी। बडी इकाइयों तो छोटे मोटे कार्यों या उप-उत्पादो के लिए छोटी इकाइयो को केवल उप-ठेके पर काम करना चाहती हैं, वे

उन्हे कभी भी अपने बल पर स्वतन्त्र बनने नहीं देना चाहेगी।

तीसरे, छोटी इकाइयों की रूग्णता के बारे में हुए बहुत से अध्ययनों से पता चलता है कि बड़ी फर्में छोटी इकाइयों को समय पर भुगतान नहीं करती, उसके बावजूद इसके वे छोटी इकाइयों से माल प्राप्त कर चुकी होती हैं। अपनी कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने के कारण, ये इकाइयाँ बीमार पड़ जाती हैं और बन्द कर दी जाती हैं क्योंकि बड़ी फर्में कई बार भुगतान में छ माह का और कुछ स्थितियों में एक साल का विलम्ब कर देती हैं। यह आशा की जाती है कि नई नीति ऐसा कानून बनाएगी जिसके अधीन लघु क्षेत्र को 45 दिन के अन्दर भुगतान करना पड़े।

चौथे, सरकारी नीति लघु क्षेत्र में बीमार इकाइयों की बड़ी संख्या के प्रति अनभिज्ञ जान पड़ती है। आर्थिक समीक्षा (1993-94) के अनुसार लघु स्तर क्षेत्र में 246 लाख इकाइयाँ बीमार हैं और बकाया ऋण की राशि, 3,100 करोड़ रुपये है। मूल प्रश्न यह है कि क्या लघु क्षेत्र की इकाइयों में बड़े पैमाने पर रूग्णता को रोका जा सकता है? इसके लिए जरूरी है कि छोटी इकाइयों के प्रबन्ध में अधिक व्यवसायीकरण लाया जाए। यह कहना उचित होगा कि घटिया प्रबन्ध रूग्णता के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि छोटे उद्यमकर्ताओं को उद्यमों के प्रबन्ध के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसा प्रशिक्षण अनिवार्य है क्योंकि छोटे उद्यमकर्ता को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं— उत्पादन की व्यवस्था, वित्त का प्रबन्ध अपने उत्पाद के विक्रय के लिए आदेश प्राप्त करना, सार्वजनिक सम्बन्ध कायम करना, आदि। अतः छोटे उद्यमकर्ता को बहुमुखी प्रशिक्षण देना होगा ताकि वह अपना कार्य भलीभाँति कर सकें।

परन्तु छोटे उद्यमों को बीमार पड़ने से बचाने के लिए यह कही बेहतर होगा कि उद्यमकर्ता सहकारी किस्म का छात्र कायम करें ताकि युवा उद्यमकर्ताओं का उत्पादन के प्रोजेक्टों के चयन में मार्गदर्शन किया जा सके, आदानों के सभरण और उत्पादन की तकनीक के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जा सके और उनकी उत्पाद के विक्रय में सहायता

की जा सके। ये सहकारी समितियाँ उधार की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, छोटे उद्यमकर्त्ताओं की भलाई सहकारीकरण (Co-operativisation) में है, न कि निगमीकरण (Corporatization) में।

अन्तिम, नई लघु क्षेत्र नीति और औद्योगिक नीति मध्यम क्षेत्र का जिक्र तक नहीं करती। जब तक लघु क्षेत्र 60 लाख रुपए की सीमा को पार नहीं करता, यह लघु क्षेत्र के वर्ग में रहता है परन्तु इस सीमा को पार करते ही यह बड़े पैमाने के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। यह उद्योगों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक ढंग नहीं है। चूँकि बहुत सी छोटी इकाइयाँ अपनी विकास-प्रक्रिया में मध्यम क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए यह उचित होगा कि लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों की परिभाषा की जाए। औद्योगिक नीति की दृष्टि से, लघु एवं मध्यम इकाइयों को एक समूह मानना चाहिए। बहुत से देशों में लघु एवं मध्यम क्षेत्र की इकाइयों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। इससे बड़े पैमाने के क्षेत्र के मुकाबले में इस क्षेत्र सम्बन्धी नीति तय करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष यह कि लघु क्षेत्र पर नीति वक्तव्य एक हद तक तो इसे बढ़ावा देता है। इसमें भूमि के आवण्टन, बिजली उपलब्ध कराने आदि में लघु क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इसमें अति लघु क्षेत्र को सस्थानात्मक वित्त में आसानी से प्राप्ति, सहकारी खरीद में प्राथमिकता और श्रम सम्बन्धी कानूनों में ढील की बात कर दी गई है। चूँकि अति लघु क्षेत्र, ग्राम क्षेत्रों में पारम्परिक कौशल की नर्सरी माना जाता है, इसलिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों के पैकेज से अति लघु क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। यह अभिनन्दनीय है। चूँकि अति लघु क्षेत्र का सम्बन्ध दस्तकारों और शिल्पियों के साथ ग्राम तथा नगर क्षेत्रों में है, इस नीति से निर्धनता को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।

इन उज्ज्वल लक्षणों के बावजूद, लघु क्षेत्र नीति का बल लघु-क्षेत्र को बड़े पैमाने के क्षेत्र का एक उपाग बनाना ही है क्योंकि इसमें बड़ी फर्मों को 24 प्रतिशत तक हिस्सा पूँजी का योगदान देने की स्वीकृत दी गई है। यह बात वस्तुतः सन्देहजनक है कि क्या नई नीति

के परिणामस्वरूप छोटे क्षेत्र को तकनालाजी का हस्तांतरण हो सकेगा या इससे बड़े क्षेत्र का नियन्त्रण छोटे क्षेत्र पर बढ़ जायेगा? इस नीति में लघु क्षेत्र की इकाइयों की उपेक्षा एक गम्भीर कमी है और यह आवश्यक है कि सरकार को लघु क्षेत्र की रूग्णता को रोकने के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल रूपया झोक देने से लघु-स्तर क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, इसके लिए तो एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइयों पनप सकें। अतः समय की पुकार यह है कि लघु उद्यमकताओं में सहकारीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, न कि बड़े क्षेत्र के साथ समन्वय के नाम पर निगमीकरण (Corporatization) को। वास्तविक खतरा तो यह है कि बड़े क्षेत्र को फर्जी इकाइयों कायम करके लघु क्षेत्र के नाम पर मिलने वाले प्रोत्साहनों को हथियाने से कैसे रोका जाए और साथ ही देश में अत्यधिक आधुनिकीकरण और स्वचलन (Automation) के विरुद्ध मजदूर सघों के विरोध को कैसे कम किया जाए ताकि श्रम-विस्थापन (Labour displacement) न हो सके। चाहे नीति वक्तव्य में बीमारी का सही विश्लेषण किया गया है परन्तु जो उपचार इसमें सुझाया गया है उससे विकास के साथ न्याय का लक्ष्य प्रभावी रूप से प्राप्त नहीं हो सकता।

सरकार ने 1 सितम्बर 2000 से उत्पादन शुल्क के लिए कर मुक्त सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। क्रेडिट गारन्टी स्कीम (2000) की बिना प्रतिभूति के ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गयी है। 2001-02 बजट के अनुसार लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मई 2003 में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची में से 75 उत्पादों को हटा दिया गया है जिनमें प्रयोगशाला रसायन तथा रीजेन्ट, चर्म एवं चर्म उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन एवं रसायनिक उत्पाद और कागज उत्पाद शामिल हैं। 75 उत्पादों को आरक्षित सूची में से हटाये जाने के बाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची में अब 674 उत्पाद ही रह गये हैं।

षष्ठम् अध्याय

लघु उद्योगों का महत्व एवं समस्याएँ

(IMPORTANCE AND PROBLEMS OF SMALL SCALE INDUSTRIES)

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ पूँजी का अभाव एवं बेरोजगारी का साम्राज्य है, वहाँ लघु उद्योगों आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी पहलुओं से औद्योगिक विकास की आधारशिला है। अत्यन्त अनुकूल पूँजी-उत्पाद अनुपात एवं उच्च रोजगार सम्भावनाएँ लघु उद्योगों की ऐसी विशेषताएँ हैं, जो इनकी उपयोगिता एवं महत्ता में अत्यधिक वृद्धि कर देती हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम पूँजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही अधिकाधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को जीविका प्रदान की जाती है। यही नहीं लघु उद्योग आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को कम करके सम्पत्ति एवं आय की असमताओं को कम करने में सहायक होते हैं। उपभोक्ताओं को माल की विधिवत का लाभ प्रदान करके उन्हें अपनी रुचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं। साधारण तकनीकी ज्ञान, कम पूँजी एवं मानवीय दक्षताओं एवं कलात्मक रुचियों का उपयोग करके लघु उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की लाखों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यही नहीं लघु उद्योगों बड़े उद्योगों के सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) के रूप में कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं।

इस प्रकार लघु उद्योगों का कार्य क्षेत्र अब कलात्मक वस्तुएँ बनाने तथा हाथ की कारीगरी दिखाने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि अनेक दिशाओं में इनका विस्तार हुआ। बदलते समय के अनुसार यांत्रिक शक्ति का उपयोग एवं उत्पादन की आधुनिक रीतियों को अपना कर इन उद्योगों ने अपनी कार्यकुशलता एवं क्षमता दोनों में वृद्धि की है।

भारत में लघु उद्योगों के विकास में वास्तविक गति चतुर्थ योजना के बाद आयी। सन् 1973-74 में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या केवल 4 16 लाख थी। जो छठी योजना के अन्त में 1984-85 में बढ़कर 12 75 लाख हो गयी। तथा यह संख्या 1998 में 30 14 लाख हो गयी।

अविकसित अथवा विकासशील देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों की उपयोगिता और भी अधिक होती है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ पूँजी का अभाव है। तथा धन शक्ति की अधिकता है। लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। भारत में प्राचीन समय से ही लघु उद्योगों की प्रधानता है।

लघु उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व निम्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया जा सकता है –

1 लघु-क्षेत्र का विस्तार और उसका औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा (Industrial Output Expansion of Small-Scale Sector and its share in)- लघु उद्योगों की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन होते रहे हैं। इसलिए इन उद्योगों की दीर्घअवधि में प्रगति का अध्ययन करना सम्भव नहीं है। अप्रैल 1991 में लघु उद्योगों के लिए अधिकतम निवेश सीमा 60 लाख रुपये तथा सहायक इकाइयों के लिए 75 लाख रुपये रखी गयी थी। इन सीमाओं को फरवरी 1997 में बढ़कर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1999 में लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा को 3 करोड़ रुपये से घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1991-92 से 1999-2000 के बीच लघु क्षेत्र के विकास का अनुमान निम्न सारणी में दिये गए आकड़ों की सहायता से लगाया जा सकता है –

सारणी – 1991-92 से 1999-2000 के बीच लघु उद्योगों का निष्पादन

वर्ष	कुल इकाइया लाख में (31 दिसम्बर तक)	चालू कीमतों पर उत्पादन (करोड़ रुपये)	स्थिर कीमतों पर उत्पादन (करोड़ रुपये)	रोजगार (लाख में)	निर्यात (करोड़ रु०)
1991-92	20 82 (6 9)	1,78 699 (15 0)	1,60 156 (3 1)	129 80 (3 6)	13 883 (43 7)
1992-93	22 46 (7 9)	2,09 300 (17 1)	1,69 125 (5 6)	134 06 (3 3)	17 785 (28 1)
1993-94	23 81 (6 0)	2,41 648 (15 5)	1,81 133 (7 1)	139 38 (4 0)	25 307 (42 3)
1994-95	25 71 (8 0)	2,93 990 (21 7)	1,99 427 (10 1)	146 56 (5 2)	29 068 (14 9)
1995-96	27 24 (6 0)	3,56 213 (21 2)	2,22 162 (11 4)	152 61 (4 1)	36 470 (25 5)
1996-97	28 57 (4 9)	4,12 636 (15 8)	2,47 311 (11 3)	160 00 (4 8)	39 249 (7 6)
1997-98	30 14 (5 5)	4,65 171 (12 7)	2,68 159 (8 4)	167 20 (4 5)	44 437 (13 2)
1998-99	31 21 (3 6)	5,27 515 (13 4)	2,88 807 (7 7)	171 58 (2 6)	48 979 (11 5)
1999-00	32 25 (3 3)	5,78 470 (9 7)	3,12 576 (8.2)	178 50 (4 0)	53,975 (अ) (10 2)

टिप्पणी – (1) स्थिर कीमतों पर उत्पादन से यहाँ तात्पर्य 1990–91 की कीमतों पर उत्पादन से है।

(2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

(3) अ—अनुमानित।

लघु उद्योगों की संख्या 1991-92 में 20.82 लाख थी, जो 1999-2000 से बढ़कर 32.25 लाख हो गई। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, प्रत्येक वर्ष में वृद्धि 5 से 8 प्रतिशत की दर से होती है। (1998-99 तथा 1999-2000 को छोड़कर जब वृद्धि मात्र क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत रही) जहाँ तक लघु क्षेत्र के उत्पादन का प्रश्न है यह 1990–91 की कीमतों पर 1991–92 से 1,60,156 करोड़ रुपये था जो 1999–2000 में बढ़कर 3,12,576 करोड़ रुपये हो गया (नौ वर्षों में लगभग दुगना)।

2 रोजगार अवसरों का सृजन (Employment Generation) – कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र लघु उद्योगों का है। भारत की गम्भीर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए (बेरोजगारी की संख्या 1992 में लगभग 1 करोड़ 70 लाख थी,) लघु व कुटीर उद्योगों का महत्व स्वतः सिद्ध है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि जहाँ 1972 से 1987–88 के बीच सारे फैक्ट्री क्षेत्र (जिसमें बड़े आकार, मझोले आकार तथा लघु आकार की इकाइयाँ शामिल हैं) से रोजगार वृद्धि की दर 2.21 प्रतिशत प्रति वर्ष थी वहाँ लघु क्षेत्र की इकाइयों में रोजगार वृद्धि की दर 5.45 प्रतिशत की वर्ष थी। 1972 से 1987–88 के दौरान लघु क्षेत्र 20 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने में सफल रहा। जहाँ तक भविष्य में रोजगार संभावनाओं का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का और विस्तार बहुत कुछ ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रसार पर निर्भर करेगा (ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र फिलहाल 22 प्रतिशत ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराता है) इस गैर-कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख अंश विनिर्माण क्षेत्र है। जिसमें कृषि पर आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा निर्माण-पदार्थों (Construction material) में लगे उद्योग शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों में

अधिक रोजगार प्रसार की सम्भावनाये नजर नही आती परन्तु लघु क्षेत्र मे रोजगार अवसर पैदा करने की बहुत सम्भावनाये है।

3 लघु इकाइयों की कार्य कुशलता (**Efficiency of small scale industries**) — लघु उद्योगो तथा बडे उद्योगो मे से अधिक कार्यकुशल (efficient) कौन है इस बारे मे विवाद है। कुछ अर्थशास्त्रियो के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है। कि लघु उद्योग अधिक कार्यकुशल है जबकि कुछ अर्थशास्त्रियो के अध्ययन इससे ठीक उल्टा निष्कर्ष देते है। इस सम्बन्ध मे सबसे पहला अध्ययन धर तथा लाइडाल का था। उन्होने निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक लघु उद्योग काफी पूजी प्रधान है अर्थात् वे बडे पैमाने के उद्योगो की तुलना मे प्रति इकाई पूजी अधिक रोजगार का सृजन नही करते। उन्होने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लघु उद्योग बडे उद्योगो की तुलना मे श्रमिको को कम वेतन देते है और अक्सर बडे शहरो मे क्रेन्द्रित होते है। उनके अनुसार लघु उद्योगो की तुलना मे कम दक्ष है इसलिए उन्हे बडे उद्योगो की अपेक्षा को पूर्वाधिकार (Preference) देने की आवश्यकता नही है। इसी प्रकार के निष्कर्ष हाजरा तथा साडेसरा के अध्ययनो से प्राप्त हुए। हाजरा ने 1955 तथा 1958 के लिए 17 उद्योगो का अध्ययन किया और पाया कि लघु उद्योगो मे श्रम और पूजी उत्पादकता दोनो ही बडे पैमाने के उद्योगो की तुलना मे कम है। साडेसरा ने 1953—58 के लिए 28 उद्योगो का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुचे कि एक निश्चित निवेश के लिए लघु उद्योग बडे उद्योगो की तुलना मे न तो अधिक रोजगार पैदा करते है और न ही अधिक उत्पादन इसी श्रृंखला मे एक महत्वपूर्ण अध्ययन विश्वनाथ गोल्डार का है जिसमे 1976—77 के लिए 37 उद्योगो को लिया गया है। गोल्डार ने सापेक्षिक श्रम उत्पादकता, सापेक्षिक पूंजी उत्पादकता तथा सापेक्षिक कुल कारक उत्पादकता (जिसे सापेक्षिक दक्षता भी कहा जा सकता है) की गणना की है और पाया है कि बडे उद्योगो की तुलना मे लघु उद्योगो मे कम श्रम उत्पादकता, उच्च पूजी उत्पादकता, कम पूजी गहनता तथा कम कुल कारक उत्पादकता है। उन्होने निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक लघु क्षेत्र बहुत से उद्योगों मे बडे क्षेत्र की तुलना में अदक्ष है।

इन सब अध्ययनों से ऐसा लगता है कि बड़े उद्योग लघु उद्योगों की तुलना में अधिक कार्यकुशल हैं। परन्तु कई अध्ययनों से इससे ठीक उल्टा निष्कर्ष प्राप्त होता है। 1960, 1963, 1964, तथा 1965 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से आकड़े लेकर रामसिंह के अंश ने यह सिद्ध किया है कि लघु क्षेत्र अधिक कार्यकुशल है। स्थिर पूँजी के एक रुपये के निवेश पर लघु उद्योग सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है स्थिर परिसंपत्ति में एक रुपये के निवेश के बदले लघु क्षेत्र में बड़े क्षेत्र की तुलना में 'सात गुणा' उत्पादन होता है। तथा लघु उद्योगों में एक रुपये का निवेश बड़े उद्योगों की तुलना में तीन गुणा से अधिक वर्धित मूल्य (value added) का सृजन करता है इस विषय पर सबसे नया अध्ययन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा नेशनल कौंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की सहायता से किया गया है। इस अध्ययन में 1980 से 1994 तक के आकड़ों का प्रयोग किया गया। इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं —

1 1990—91 से 1994—95 के बीच, कुल औद्योगिक क्षेत्र में निवेशित पूँजी, रोजगार, कुल वर्धित मूल्य तथा उत्पादन में लघु उद्योगों का हिस्सा दिखाया गया है। कुल विनिर्माण क्षेत्र की पूँजी में केवल 7 से 15 प्रतिशत हिस्सा होने पर भी लघु उद्योगों ने कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग एक पाँचवा हिस्सा (लगभग 20 प्रतिशत) तथा कुल वर्धित मूल्य का 13 से 27 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया। जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, लघु उद्योग पूरे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का लगभग 35 से 40 प्रतिशत प्रदान करते हैं। इस प्रकार लघु उद्योगों का रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है।

2 फैक्ट्री सेक्टर की इकाइयों, कुल वर्धित मूल्य रोजगार, पूँजी स्टॉक (स्थिर तथा उत्पादक) तथा पूँजी व श्रम उत्पादकता के लिए व बड़े उद्योगों की चक्रवृद्धि वार्षिक सवृद्धि दरों (compound annual rates of growth) के बारे में 1980—94 के लिए जानकारी दी गई है।

(A) 1980—94 की अवधि में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, लघु व बड़े उद्योगों की निष्पत्ति, बड़े उद्योगों से कम रही है (लघु उद्योगों के कुल उत्पादन की सवृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष रही)

जबकि बड़े उद्योगों के कुल उत्पादन की सवृद्धि दर 9 प्रतिशत प्रतिशत प्रति वर्ष रही। जहां तक रोजगार अवसरों के सृजन का संबंध है, बड़े उद्योगों में रोजगार सवृद्धि दर 0.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना में, लघु उद्योगों में रोजगार सवृद्धि दर 1.3 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। अर्थात्, लघु उद्योगों ने अधिक रोजगार अवसर पैदा किए।

(B) बड़े उद्योगों में निवेशित पूँजी की सवृद्धि दर 6.6 प्रतिशत प्रति वर्ष और लघु उद्योगों में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। 1980–94 की अवधि में बड़े उद्योगों में श्रम उत्पादकता 8.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और लघु उद्योगों में 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी (श्रम उत्पादकता ज्ञात करने के लिए, कुल वर्धित मूल्य को श्रमिकों की कुल संख्या से विभाजित किया गया है।) इसी अवधि में, बड़े उद्योगों में पूँजी उत्पादकता 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और लघु उद्योगों में 2.4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। इस प्रकार, जहां बड़े उद्योगों में श्रम उत्पादकता लघु उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढ़ी, वहां लघु उद्योगों में पूँजी उत्पादकता अपेक्षाकृत जरा अधिक तेजी से बढ़ी।

(C) 1980–95 की अवधि के लिए, सापेक्षिक श्रम उत्पादकता, सापेक्षिक पूँजी उत्पादकता, सापेक्षिक कुल साधन उत्पादकता (relative total factor productivity) तथा सापेक्षिक लाभप्रदता के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

(D) 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि के दौरान सापेक्षिक पूँजी गहनता (जिसे लघु उद्योगों में पूँजी गहनता के बड़े उद्योगों में पूँजी गहनता से अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है) एक से कम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योग, बड़े उद्योगों की तुलना में, प्रति श्रमिक उत्पादन कम है। 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि के दौरान सापेक्षिक श्रम उत्पादकता (जिसे लघु उद्योगों में श्रम उत्पादकता को बड़े उद्योगों में श्रम उत्पादकता से भाग करके प्राप्त किया गया है) एक से कम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योगों में, बड़े उद्योगों की अपेक्षा, प्रति श्रमिक उत्पादन कम है।

(E) 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि के दौरान सापेक्षिक पूँजी उत्पादकता (जिसे लघु

उद्योगों में पूँजी उत्पादकता को बड़े उद्योगों में पूँजी उत्पादकता से भाग करके प्राप्त किया गया है) एक से कम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योगों में, बड़े उद्योगों की अपेक्षा, पूँजी उत्पादकता अधिक है।

(F) सापेक्षिक कुल साधन उत्पादकता के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसा कि सर्वविदित है, जहाँ श्रम उत्पादकता एवं पूँजी उत्पादकता कार्यकुशलता के आंशिक माप हैं, कुल साधन उत्पादकता दक्षता का एक संपूर्ण माप है। 1980-81 से 1994-95 की पूरी अवधि में (1987-88 के वर्ष को छोड़ कर) लघु उद्योगों की अनुमानित सापेक्षिक कुल साधन उत्पादकता एक से अधिक रही है। इसका अर्थ यह हुआ है कि, राष्ट्रीय स्तर पर, लघु उद्योग क्षेत्र, बड़े उद्योग क्षेत्र की तुलना में, अधिक कार्यकुशल है।

(G) लघु उद्योग क्षेत्र की सापेक्षिक लाभप्रदता के आंकड़े दिए गए हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की सापेक्षिक लाभप्रदता को लघु उद्योग क्षेत्र की लाभप्रदता के बड़े उद्योग क्षेत्र की लाभप्रदता से अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। 1980-81 से 1994-95 की पूरी अवधि में (वर्ष 1989-90 को छोड़ कर) लघु उद्योग क्षेत्र की लाभप्रदता एक से अधिक रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़े उद्योग क्षेत्र में लाभप्रदता अधिक है।

4 राष्ट्रीय आय का उचित वितरण (**Equitable distribution of national income**)

लघु उद्योगों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अधिक बेहतर व न्यायोचित वितरण हो सकता है। ऐसा दो कारणों से है एक तो लघु उद्योगों को स्वामित्व बड़े उद्योगों की तुलना में विस्तृत व फैला हुआ है तथा दूसरे, लघु उद्योगों की रोजगार सृजन की सामर्थ्य बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक है। धार व लाइडाल के अनुसार यह तर्क गलत है। उनके अनुसार लघु उद्योगों के श्रमिक प्रायः असंगठित होते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए उद्योगपति इन श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं। भारत में लघु उद्योगों में मजदूरी की दर से लगभग आधी है। इंग्लैंड, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा भारत सभी देशों में लघु उद्योग

आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।

परन्तु यह तर्क इस बात को अनदेखा करता है कि लघु उद्योगों में बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत रोजगार सामर्थ्य है। इसलिए लघु उद्योग बहुत सारे लोगों को आर्थिक विकास के फल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इनकी अनुपस्थिति में ये लोग या तो बेरोजगार रहते हैं या फिर बहुत कम आय वाले रोजगार में लगे रहते हैं।

5 उद्योगों का क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण (Regional dispersal of industries) -

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति पर विचार करते हुए हम स्पष्ट कर आए हैं कि भारत में बड़े उद्योगों का केन्द्रीकरण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा गुजरात में बढ़ रहा है। इससे देश में औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं में और अधिक वृद्धि की सम्भावना है। उद्योगों के केन्द्रीकरण से नगरों में भीड़ तथा आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लघु उद्योगों की स्थापना प्रायः स्थानीय प्रायः स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए की जाती है। अतः हमें सभी राज्यों में सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र की विशेष की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करने में भी समर्थ होते हैं। इसका प्रमाण पंजाब की अर्थव्यवस्था है जहाँ औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध महाराष्ट्र से भी ज्यादा लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं।

6 स्थानीय पूँजी और उद्यम का उपयोग (Utilisation of local capital and entrepreneurial skill)-

देश के विभिन्न भागों में ऐसे बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं जिनकी मांग बड़े उद्योगों द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ साधन बड़े उद्योगों की पहुँच में नहीं होते। लघु उद्योग इन साधनों सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, कस्बों के उद्यमियों की क्षमता का उपयोग लघु उद्योगों में ही हो सकता है। इसी प्रकार, बड़े शहरों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली बचतों को बड़े उद्योगों के लिए संचित कर पाना सम्भव नहीं होता, परन्तु उनकी सहायता से लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। आजादी के बाद भारी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि बिजली, तकनीकी

ज्ञान तथा साख आदि की सुविधाएँ मिल जाने पर अनेक निष्क्रिय साधनों का उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग होने लगता है।

7 औद्योगिक विवादों का कम होना (Less industrial disputes) - लघु उद्योगों के समर्थकों द्वारा प्रायः यह भी तर्क दिया जाता है कि बड़े उद्योगों में लघु इकाइयों की तुलना में औद्योगिक विवाद अधिक होते हैं। श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच सम्बन्ध अच्छे न रहने के कारण उद्योगों में प्रायः हड़ताल व तालाबन्दी की समस्याएँ बनी रहती हैं। इसके विपरीत लघु उद्योगों में यह सब अधिक नहीं होता है। इसलिए उत्पादन की हानि भी अधिक नहीं होती। यह मत भ्रमपूर्ण है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में इकाई बड़ी हो अथवा छोटी, कारखाने का मालिक श्रमिकों का शोषण करता है जिसके कारण श्रम विवाद आवश्यक है। बड़े और लघु उद्योगों में अन्तर केवल इतना है कि बड़े उद्योगों में श्रम सघों की उपस्थिति के कारण श्रमिक अन्याय और शोषण का विरोध करता है, जबकि लघु क्षेत्र में प्रायः वह ऐसा कर पाने में असमर्थ होता है। जिससे श्रम तथा पूँजी के सम्बन्ध प्रकट रूप में खराब मालूम नहीं होते हैं।

8 निर्यात में योगदान (Contribution to exports)- आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों की स्थापना के कारण निर्यात आय में इनका योगदान काफी बढ़ा है। बहुत सारे उद्योगों जैसे तैयार वस्त्र (readymade garments), खेल का सामान, चमड़ा व चमड़े से निर्मित सामान, ऊनी कपड़ों, रसायनों व सहायक पदार्थों तथा इन्जीनियरिंग वस्तुओं इत्यादि में लघु उद्योगों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों के कुल निर्यात 1971-72 में 156 करोड़ रुपये थे जो 1998-99 में बढ़कर 44,437 करोड़ रुपये हो गए। इस प्रकार निर्यात आय में लघु उद्योगों का हिस्सा 1971-72 में 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 31.4 प्रतिशत हो गया।

9. सहायक व्यवसाय के रूप में उपयोग वस्तुओं का निर्माण — हमारे देश में कृषि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख व्यक्ति खेती

पर आश्रित होने के लिए बढ़ जाते हैं जिससे अनार्थिक जोतो का निर्माण होता है। जो विकास के लिए एक समस्या है। इस समस्या के समाधान की दृष्टि से लघु उद्योग बहुत ही उपयोगी है। ये उद्योग धन्धे सहायक उद्योग—धन्धे के रूप में पूर्णकालिक एवं अशकालिक चलाये जाते हैं। ये कृषि के ऊपर आश्रितों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सहायक व्यवसाय के रूप में देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। चरखे के विषय में गांधी जी ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा था—“चरखा बहुसंख्यक लोगों की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन बहुसंख्यक लोग अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता चरखे के विनाश के साथ ही साथ खो चुके हैं। चरखा गावों की कृषि का पूरक है, उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, यह विधवाओं का मित्र है और कृषकों को आलस्य से दूर रखने का साधन है।”

देश के आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का विकास आवश्यक है। लेकिन उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ इनसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूरी की जा सकती। यद्यपि दीर्घकाल में पूंजीगत वस्तु उपभोक्ता की पूर्ति करने में सहायक हो सकती है लेकिन उस समय तक उपभोग वस्तुओं की माँग में इतनी वृद्धि हो जायेगी कि उसे पूरा करना कठिन होगा। इसके परिणामस्वरूप लोगों के जीवन—स्तर में ही सुधार नहीं होगा, बल्कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। आज देश में तेजी से मूल्य वृद्धि का यह भी एक प्रमुख कारण है। इस ओर सिर्फ लघु उद्योग ही सहायक हो सकते हैं। लघु उद्योग अल्प समय में पूँजी की मदद से वृहत् समुदाय की उपभोग वस्तुओं की पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं।

बम्बई के उद्योगपतियों ने 1944—45 में एक योजना तैयार किया जिसमें यह बड़े—बड़े उद्योगपतियों के नाम से सम्बन्धित थी, जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, श्री जी० डी० विरला, श्री जे० आर० डी० टाटा तथा श्री जान मथाई। इस योजना में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के माध्यम से किये जाने पर जोर दिया तथा इसके निम्नलिखित तीन आधार बताये।

- 1 पूँजीगत वस्तुओ के उद्योगो के विकास के बाद उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन—विस्तार के लिए उद्योगो को दुर्लभ मात्रा मे ससाधन प्राप्त होंगे।
- 2 पूँजीगत उद्योगो के विकास से अधिक मात्रा मे लोगो को रोजगार नहीं दिया जा सकता, केवल लघु उद्योग ही बढ़ती जनसख्या को रोजगार देने मे समर्थ हो सकते हैं।
- 3 बड़ी मात्रा मे लघु उद्योगो से वस्तुएँ निर्मित करने मे थोड़ी मात्रा मे विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है।

इसी से बहुत कुछ मिलती जुलती विचारधारा भारतीय योजना आयोग के अर्थशास्त्रियों तथा तत्कालीन साख्यिकी सलाहकार प्रो० पी० सी० महलनवीस के द्वारा भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय अपनाई गई थी।

10 सामाजिक लागत नैतिक पक्ष — लघु उद्योगो के विकास के पक्ष मे एक महत्वपूर्ण बात भारत मे लघु उद्योग यह है कि सामाजिक एव नैतिक दृष्टि से भी महत्व के हैं। बहुस्तरीय उद्योगो मे श्रमिक मशीनो के पुर्जों की भँति काम करता है वहाँ पर कला एव कारीगरो का महत्व बिल्कुल नहीं रह जाता है। बड़े—बड़े औद्योगिक केन्द्रो पर वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जिससे श्रमिको का सामाजिक एव नैतिक स्तर गिर जाता है। इसके विपरीत लघु उद्योग इन सबसे बचाते हैं।

प्रशुल्क आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रो० के० टी० मर्चेन्ट का विचार है कि ग्रामोद्योगो का महत्व सामाजिक मूल्य के आधार पर आँका जाय, न कि व्यावसायिक आधार पर, अर्थात् सामाजिक लागत के सभी महत्वपूर्ण पहलुओ पर विचार करना चाहिये। लेकिन जब हम बृहत् उद्योगो की तुलना करते हैं तो हम केवल व्यावसायिक मूल्य को ही ध्यान मे रखते हैं, न कि सामाजिक मूल्य को। औद्योगिक शहरो मे जल एव वायु—प्रदूषण, गन्दी नालियाँ, समाज—विरोध, गी तत्व आदि सामाजिक कष्ट हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतया इनसे मुक्त हैं, अर्थात् सम्पूर्ण लागत सामाजिक एव आर्थिक दोनो दृष्टियो से देखी जाने चाहिये, न कि केवल व्यावसायिक दृष्टि से। इसके अतिरिक्त यदि लघु उद्योगो के उत्पादन को विस्तार का अवसर प्रदान किया

जाता है तो वे स्वयं ही सामाजिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। वे गँवों एवं कस्बों के साहूकारों एवं महाजनो के शोषण से भी मुक्त हो जाते हैं।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त देश की अर्थ-व्यवस्था में इन उद्योगों का महत्व मुख्यतः निम्न कारणों से भी है—

- 1 युद्ध से सुरक्षा,
- 2 पूँजी एवं कुशलता की गति में वृद्धि,
- 3 श्रम एवं पूँजी का अच्छा सम्बन्ध,
- 4 शहरों की ओर बढ़ने वाली भीड़ में रोक एवं
- 5 क्षेत्रीय विकास में सहयोग आदि।

11 शीघ्र उत्पादन — लघु उद्योगों द्वारा शीघ्र ही उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की कमी को समाप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योगों में फलनाविधि अधिक लम्बी होती है। इनमें उत्पादन देर से प्रारम्भ किया जाता है।

12 राष्ट्रीय सुरक्षा — बड़े उद्योग कुछ विशेष स्थानों पर ही केन्द्रित होते हैं, क्योंकि उनके स्थानीयकरण के लिए कई बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। इसके विपरीत लघु उद्योगों का स्थानीयकरण सरल समस्या है। युद्ध काल में बड़े उद्योगों को शत्रु से बचाना एक कठिन समस्या बन जाती है। जबकि लघु उद्योगों को ऐसा खतरा नहीं होता।

13 अतिरिक्त आय का साधन — विशेषकर बड़े उद्योगों एवं लघु उद्योगों में उचित समन्वय स्थापित कर दिया जाय तो लघु उद्योगों बड़े उद्योग के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जापान में सूती वस्त्र उद्योग का सगठन इसी आधार पर किया गया है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों को माल के विपणन की चिन्ता से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि प्रमुख इकाई सहायक (Ancillary) इकाई द्वारा उत्पादित समस्त माल अथवा उसका अधिकांश भाग स्वयं अपने उत्पादन के लिए खरीद लेते हैं। भारत के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी

औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे ऐसे सहायक उद्योगों की श्रृंखला का निर्माण करें। इधर कुछ वर्षों से उद्योगों के ऐसे सहायकीकरण (Ancillarisation) को भारत के पर्याप्त प्रोत्साहन मिल रहा है।

14 राष्ट्रीय उत्पादन में सहायक — असख्य लघु उद्योग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लघु उद्योगों की उत्पादकता सीमित होती है। यदि लघु उद्योगों के तकनीकी स्तर में कुछ सुधार किया जाय एवं विद्युत से संचालित छोटी मशीनों के उपयोग की सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जायें तो छोटे उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है और उस दशा में राष्ट्रीय उत्पादन में इनसे और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में लघु औद्योगिक क्षेत्र का भाग अब लगभग 40 प्रतिशत हो गया है।

15 प्राविधिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण की सरलता — लघु उद्योगों को संचालित करने के लिए आवश्यक प्राविधिक एवं प्रशिक्षण स्थानीय रूप से ही उपलब्ध की जा सकती है और इसके लिए हमें विदेशी सहायता की बहुत अधिक जरूरत नहीं होती है।

16 व्यक्तित्व एवं कला का विकास — बड़े उद्योगों श्रमिक को एक यन्त्र के समान बना देते हैं। समस्त कार्य मशीन से किया जाता है। तथा श्रमिक उत्पादन में अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लघु उद्योग के श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रदर्शक कर सकता है और कलात्मक निर्माण से उसे एक विशेष आनन्द एवं सतोष का अनुभव होता है।

17 कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी — कृषि का सबसे बड़ा दोष यह है कि जनसंख्या के अनुपात में भूमि का अभाव है। वैकल्पिक व्यवसाय के अभाव में कृषक आधे पेट रह कर भी भूमि के टुकड़े से लगे रहते हैं। इससे एक स्वस्थ एवं नैतिक समाज के निर्माण में बाधा पहुँचती है। यदि गाँवों में लघु उद्योगों में अधिक व्यक्तियों की माँग को बढ़ा दिया जाय तो कुछ समय बाद ही बहुत से व्यक्ति कृषि को छोड़कर इन उद्योगों में लग जायेंगे और इस प्रकार भूमि पर से जनसंख्या का दबाव कम हो जायेगा।

18 आयात पर कम निर्भरता — बड़े उद्योगों स्थापित करने में कमी तकनीक के लिए, तो कमी मशीनों के लिए, तो कमी कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उनको आयात करना पड़ता है। लघु उद्योगों में ऐसी बात नहीं है। न तो मशीनें आयात करनी पड़ती हैं न तकनीक और न कच्चा माल। इस प्रकार आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।

19 विदेशों का अनुभव — संसार के लगभग सभी देशों का अनुभव यह है कि लघु उद्योग देश के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, जापान में 53 प्रतिशत मजदूर ऐसे उद्योगों में लगे हैं। इसी प्रकार अमेरिका में भी 45 प्रतिशत मजदूरों को रोजगार यह उद्योग दे रहे हैं।

भारत में लघु उद्योगों का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 10 प्रतिशत, कुल औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिशत, रोजगार में 32 प्रतिशत एवं देश के निर्यात में 35 प्रतिशत है। लघु उद्योगों के महत्व के कारण ही इन्हें औद्योगिक नीतियों में मुख्य स्थान दिया गया है। अभी तक लघु उद्योगों के लिए 150 लाख वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित था वर्तमान में इनकी संख्या 812 कर दी गयी है तथा यह व्यवस्था की गयी है कि इनके हितों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाया जायेगा।

लघु उद्योगों की समस्याएँ

(Problems of Small Scale Industries)

लघु उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का करना पड़ता है जिनके परिणामस्वरूप कई इकाइयाँ बन्द भी हो जाती हैं। 1987-88 में की गई लघु औद्योगिक इकाइयों की जनगणना से (जिनके परिणाम 1992 में प्रकाशित किये गये) यह पता लगता है कि 31 मार्च 1988 को कुल पंजीकृत 9.87 लाख लघु इकाइयों में से 3.05 लाख इकाइयाँ (जो कुल पंजीकृत इकाइयों का 32 प्रतिशत) बन्द हो चुकी थी। इस प्रकार एक तिहाई लघु इकाइयों को बन्द होना पड़ा था। इनमें से 1.49 लाख इकाइयाँ (अर्थात् आधी इकाइयाँ) काम शुरू होने के पाँच वर्षों के अन्दर-अन्दर ही बन्द करनी पड़ी थी। मार्च 1999 के अन्त तक लगभग 3,06,221 लघु इकाइयाँ अस्वस्थ थी और इनमें बैंकों की बकाया ऋण राशि 4,313 करोड़ रुपये थी।

इनकी कठिनाइयों के बारे में निरन्तर अध्ययन एवं विचार विमर्श किये जाने की आवश्यकता है ताकि उनके निराकरण के लिए उपयुक्त सुझाव दिये जा सकें। वर्तमान समय के लघु उद्योगों को अनेक समस्याओं एवं अभाव के बीच में गुजरना पड़ रहा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं —

1 वित्त तथा साख (Finance and credit) — पूँजी तथा साख का अभाव लघु उद्योगों की प्रधान समस्या है। लघु औद्योगिक इकाइयों का पूँजीगत आधार प्रायः काफी कमजोर होता है क्योंकि इनका संगठन साझेदारी अथवा अकेले स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। घरेलू उद्योग को चलाने वाले कारीगर या तो अपनी थोड़ी-सी पूँजी से काम चलाते हैं या फिर महाजन अथवा व्यापारी से (जो कच्चा माल देता है) ऋण लेते हैं। लघु उद्योगों की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है। परन्तु इन उद्योगों के लिए भी लाभ के फिर से निवेश द्वारा पूँजी को बढ़ा पाना सम्भव नहीं होता।

लघु उद्योगों के लिए सस्थागत वित्त के प्रधान स्रोत हैं उद्योगों के राज्य निदेशालय, राज्य वित्त निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा दूसरे व्यापारी बैंक। यद्यपि लघु उद्योगों को मिलने वाली सस्थागत साख में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन वह इस क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए तथ्या लघु क्षेत्र के विस्तार के सन्दर्भ में अपर्याप्त है।

लघु उद्योगों को ऋण सुविधाओं की उपलब्धि में सुधार लाने के दृष्टिकोण से, रिजर्व बैंक ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसने 30 जून 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने कुल 126 सुझाव दिए जिसमें से रिजर्व बैंक 40 सुझावों को स्वीकार कर चुका है। अति लघु क्षेत्र को और वित्तीय सहायता प्रदान के लिए उद्देश्य से 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में यह व्यवस्था की गई कि बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग कंपनियों को जो ऋण इस क्षेत्र की सहायता के लिए दिए जाएंगे उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण माना जाएगा। जैसाकि ऊपर कहा गया है, लघु व अति लघु क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने

के लिए 2000-01 में कई कदम उठाए गए जैसे मिश्रित ऋण स्कीम के अधीन ऋण सीमा को 25 लाख ऊपर तक बढ़ाना, ऋण गारण्टी योजना इत्यादि।

लघु की इकाई जो अच्छी तरह जानी जाती है कि ये मुख्यतः सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं रहती है। इनमें से अधिकांश अपने उत्पादों के माँग की या तो स्थानीय बाजार पड़ोसी बाजार या दूर के बाजार या संयुक्त बाजार के अपने सामानों के माँग पर निर्भर रहती है। इन लघु इकाइयों का प्रारम्भिक विनियोग मुख्यतः स्वयं के फण्ड या उधार फण्ड मुख्यतः रिश्तेदारों, साथियों और साहूकारों से प्राप्त करती है। बहुत सी कम बैंक या सरकारी स्रोतों से प्राप्त करती है।

लघु इकाई अपने स्वयं के फण्ड और उधार फण्ड गैर बैंकिंग और गैर सरकारी सेक्टर पर अधिक निर्भर करती है। क्योंकि इसका कारण उधार देने वाली संस्था जैसे बैंक एवं सरकारी वित्तीय कार्पोरेशन इन लघु इकाइयों को पेशगी देने के सामान्यतः अनिच्छुक होती है। ये लघु इकाइयाँ ऐसी स्थिति में नहीं होती हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर का गारण्टी दे सकें। वैसे ही जब छोटा कर्ज सरकारी एजेंसियों दे सकती हैं नियम इतने कष्टकारी हैं कि अधिकांश उद्यमी जो अशिक्षित हैं या कोई शिक्षित हैं इन सुविधाओं का प्रयोग करने में सन्देह करते हैं और इससे वे वित्त कम मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए वे उधार ऋण से स्वयं को लेना पसन्द करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग जो लघु उद्योगों के प्रबल उद्यमी बनने के उचित क्रम में सामान्यतः पहले ही धन संचित कर चुके हैं जब वे दूसरे फर्म में काम करते थे। इसी कारण प्रमुख प्रबल श्रमिकों से आशा है कि उन्हें व्यवसाय सेवा के कुछ वर्षों बाद प्रारम्भ करना चाहिए।

लघु उद्योगपतियों के पास अपने स्वयं के पर्याप्त फण्ड पूँजी विनियोग के लिए नहीं है और न ही वे प्राप्त कर सकते हैं। फण्ड की कमी उन्हें आधुनिक मशीनरी और टूल्स, अच्छी संस्थाओं से मरम्मत और औजार पूर्ण कारखाना उपयोग में लाना कठिन बना देता है। इससे अधिक वे अच्छी किस्म के कच्चे माल नहीं खरीद सकते हैं और अच्छे किस्म के कच्चे पदार्थों

या निमित्त माल का स्टॉक रखने अपने सामानों को आकर्षित बनाने स्वयं के बिक्री संस्थान या सुरक्षित डिपॉजिट तैयार करना कठिन बना देता है जबकि यह आवश्यक है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन विस्तार अवधि ऋणों के निर्णय के लिए कई माह लेती है। यदि कोई एक प्रोजेक्ट शीघ्र आरम्भ करता है। बैंक भी ऋण प्राप्त करने के आवेदनो पर शीघ्र विचार नहीं करती। ये भी कोई प्रोजेक्ट को विलयन करने एवं एडवॉन्स सुविधाओं को अधिकृत करने के लिए एक माह से तीन माह का समय लेती है। उनकी सहायता प्रारम्भिक पूँजी या भविष्य खर्चों के लिए कठिनाई से प्राप्त होती है। ये केवल लघु स्तर इकाइयों की पूँजी आवश्यकता के लिए प्राप्त होती है।

2 कच्चे माल की उपलब्धि (Raw material availability) - अधिकांश लघु उद्योग कच्चे माल के लिए स्थानीय स्रोतों पर निर्भर है। हथकरघा उद्योग सूत की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहता है। ये व्यापारी बुनकरों को प्रायः इस शर्त पर कच्चा माल बेचते हैं कि बुनकर कपड़ा उन्हीं को बेचेगा। प्रायः ये व्यापारी बुनकरों का दोहरा शोषण करते हैं। एक ओर तो ये बुनकरों से कच्चे माल की अधिक कीमत लेते हैं और दूसरी ओर उन्हें माल की कम कीमत देते हैं।

लघु उद्योगों में पहले छोटी-मोटी वस्तुओं का ही उत्पादन होता था जिनके लिए कच्चा माल प्राप्त कर पाना कोई समस्या नहीं थी। परन्तु जब से आधुनिक लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है और ये उद्योग नई वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं, तब से इनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कर पाना कठिन हो गया है। अनेक लघु उद्योग आयात किए जाने वाले कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। देश के सामने विदेशी विनिमय के संकट की स्थिति में इस प्रकार के कच्चे माल का आयात न हो पाने पर समय-समय पर लघु उद्योग को भारी हानि हुई है।

3. मशीनें तथा दूसरे उपकरण (Machines and other equipment)-

अधिकांश लघु औद्योगिक इकाइयों में यन्त्र तथा दूसरे उपकरण पुराने हो चुके हैं। इस

कारण से इन उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की क्वालिटी जहा घटिया होती है वहा लागत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त लघु इकाइया लोगो की बदलती हुई रुचियो, फैशनो इत्यादि की ओर भी विशेष ध्यान नहीं देती। अत लघु औद्योगिक इकाइयो मे जितनी जल्दी हो सके आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। यह काम तभी हो सकता है जब तकनीकी सहायता का जाल बिछा दिया जाए। बेहतर तकनीको के प्रयोग द्वारा न केवल लघु इकाइयो की उत्पादक कार्यकुशलता मे सुधार होगा अपितु लोगो की बदलती हुई रुचियो के अनुसार उत्पादन मे परिवर्तन किए जा सकेगे।

4 क्षमता का अल्प प्रयोग (Under-utilisation of capacity)- लघु क्षेत्र की इकाइयो मे क्षमता के अल्प प्रयोग के बारे मे 1987-88 की दूसरी जनगणना मे आकडे दिए गए है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि लघु इकाइयो के काफी क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए 1987-88 मे क्षमता प्रयोग बिजली मशीनरी व पुर्जो के उद्योग मे 41 प्रतिशत, चमड़ा-उत्पादो मे 58 प्रतिशत, परिवहन उपकरण व पुर्जो मे 60 प्रतिशत, अन्य विनिर्माण उद्योगो मे 30 प्रतिशत तथा धातु उत्पादो मे 32 प्रतिशत था। सभी लघु इकाइयो को कुल मिलाकर देखा जाए तो क्षमता उपयोग करीब 48 प्रतिशत बैठता है। इससे पता चलता है कि लघु औद्योगिक इकाइयो मे स्थापित क्षमता का लगभग आधा ही प्रयोग हो पाता है। इस प्रकार आधी क्षमता बेकार पडी रहती है।

5 विपणन की समस्याएँ (Problems of marketing) - भारतीय लघु उद्योगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास बिक्री के लिए सगठन नहीं है। प्राय लघु इकाइयो द्वारा मानक वस्तुओं का भी उत्पादन नहीं किया जाता। इसलिए उनका माल बड़ी इकाइयो की तुलना मे सहज ही बिक नहीं पाता।

बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से लघु उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक वस्तुओं का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है। आरक्षित मदों की संख्या 77 से बढ़ते-बढ़ते 836 तक पहुँचा दी गई (अब इनकी संख्या 812 है) व्यापार विकास प्राधिकरण

तथा राज्य व्यापार निगम लघु उद्योगों को विपणन प्रदान कर रहे हैं। 1955 में स्थापित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी सरकारी आर्डर प्राप्त करने में तथा निर्यात बाजार ढूँढने में लघु इकाइयों की सहायता कर रहा है।

6 अस्वस्थता की समस्या (Problem of sickness) - अस्वस्थ लघु इकाइयों के संदर्भ में दो मुख्य मुद्दे हैं

- (i) बहुत सी अस्वस्थ इकाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें चला पाना व्यवहार्य नहीं रह गया है ,
- (ii) ऐसी अस्वस्थ लघु इकाइयों का पुनर्वास (rehabilitation) जिन्हें दोबारा चला सकने की संभावना है। जहाँ तक पहले मुद्दे का सवाल है, देश में 31 मार्च 1999 तक 3.06 लाख अस्वस्थ लघु इकाइयाँ थीं। इनमें बैंकों का 4,313 करोड़ रुपये फंसा हुआ है। जहाँ तक दूसरे मुद्दे का प्रश्न है, बैंकों ने पता लगाया है कि केवल 18,692 लघु इकाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। इनमें बैंकों की 377 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि है। परन्तु अस्वस्थ इकाइयों का पुनर्वास एक महंगा विकल्प है। इसमें बकाया राशि का पुनर्सूचीकरण (re-scheduling), देय ब्याज पर रियायतें, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीकरण उन्नयन के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करना, नए सिरे से कार्यशील पूँजी इत्यादि उपलब्ध कराना शामिल है।

7 उपयुक्त आकड़ों की अनुपलब्धि (Poor data base)- एक और समस्या यह है कि लघु क्षेत्र के लिए उपयुक्त आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लघु – उद्योग के लिए जानकारी के दो स्रोत हैं लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organisation) तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation)। लघु उद्योगों के लिए संपूर्ण जानकारी इनमें से किसी स्रोत के पास नहीं है। SIDO द्वारा जो औद्योगिक जनगणना (industrial census) की जाती है। उसके आकड़े केवल वर्ष 1972 तथा 1987–88 के लिए उपलब्ध हैं। चालू अनुमान प्राप्त करने के लिए इन्हें आधार मान कर फिर आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। SIDO द्वारा लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रति वर्ष जो

अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं (यथा इस क्षेत्र में कितनी इकाइया कार्यरत हैं, उनका उत्पादन क्या है, उनमें कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है, इत्यादि) इनकी बहुत सी सीमाएँ हैं क्योंकि ये आकड़े आंशिक जानकारी पर आधारित होते हैं। अपजीकृत लघु इकाइयों के बारे में सूचना का आधार बहुत कमजोर है और इनके बारे में जानकारी महज अनुमानों पर आधारित होती है। CSO संपूर्ण लघु व ग्रामीण उद्योगों के लिए सर्वेक्षण करता है। परन्तु इन सर्वेक्षणों में लघु उद्योगों का वर्गीकरण निवेश सीमाओं के आधार पर नहीं किया जाता (जो इन उद्योगों की परिभाषा के लिए आवश्यक है)। इन सर्वेक्षणों में उन इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनमें 10 से कम श्रमिक काम करते हों (अर्थात् वे उत्पादन इकाइया जिन्हें उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) में शामिल न किया गया हो) इन सर्वेक्षणों से जो आकड़े प्राप्त होते हैं उनमें से लघु उद्योगों के लिए अलग से आकड़े इकट्ठा करना संभव नहीं होता (उपलब्ध आकड़ों में लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के मिलेजुले आकड़े होते हैं) इसके अलावा ये सर्वेक्षण 5 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं इसलिए अन्य वर्षों के लिए प्राप्त आकड़े बहिर्वेशन (extrapolation) की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों से जानकारी महज 1978—79, 1984—85, 1989—90 तथा 1994—95 के लिए उपलब्ध है। जैसा कि लघु उद्योग विकास की रिपोर्ट में कहा गया है कि "लघु उद्योगों की तेज प्रगति और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन उत्पादन के लिए नियमित रूप से आकड़े एकत्रित करने व उनका संशोधन करने की स्थायी व्यवस्था की जाए। प्रति वर्ष उत्पादन की विभिन्न दिशाओं में कई लघु उद्यम स्थापित होते हैं और प्रति वर्ष कई मौजूदा उद्योग या तो अपना विस्तार करते हैं या फिर विविधीकरण करते हैं। उचित नीति—निर्धारण तभी संभव है जब इनके लिए नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके।"

8 अन्य समस्याएँ (Other problems) - लघु उद्योगों की उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य समस्याएँ हैं प्रबन्धकीय क्षमता का अभाव, सस्ती बिजली का उपलब्ध न होना, बदलती हुई रुचियों के साथ उत्पादों में परिवर्तन न हो पाना, स्थानीय करों का भार

तथा बड़े के साथ प्रतियोगिता।

पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को 1987-88 में जो दूसरी जनगणना की गई थी उससे पता चलता है कि 31 मार्च, 1988 तक जो 3.05 लाख इकाइया बन्द हो गई थी उनमें से 1.48 लाख इकाइया (अर्थात् आधी इकाइया) वित्तीय व विपणन संबंधी कठिनाइयों के कारण बन्द हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, लघु उद्योगों के विकास में कई कारक बाधक रहे हैं जैसे पुरानी तकनीकी, कच्चे माल की अपर्याप्त व अनियमित पूर्ति, संगठित बाजार प्रणाली का अभाव, बाजार स्थिति के बारे में अपूर्ण जानकारी, कामकाज का असंगठित व अव्यवस्थित स्वरूप, साख की अपर्याप्त उपलब्धि, बिजली व अन्य आधारिक सुविधाओं की कमी, प्रबन्धकीय व तकनीकी कौशल की कमी, इत्यादि। इन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न एजेंसियों बनाई गई हैं उनमें परस्पर सहयोग व तालमेल का अभाव है। सतत प्रयासों के बावजूद गुण तथा श्रेणी में सुधार लाने व एकरूपता बनाए रखने के बारे में जागृति नहीं लाई जा सकी है। कुछ राजकोषीय नीतियों के परिणामस्वरूप इन उद्योगों की क्षमता का विखंडन होकर अनार्थिक रूप से उत्पादन होने लगा है। इन सब कारकों की वजह से लागते बढ़ी हैं जिससे घरेलू बाजार और निर्यात बाजारों में इन उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है।

9 आर्थिक सुधारों तथा सार्वभौमिकरण के बुरे प्रभाव (Adverse effects of economic reforms and globalisation) - नब्बे के दशक में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं जैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, आरक्षण में कमी, देशीय व विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्कों में कमी, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, इत्यादि। इन सुधारों का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि नब्बे के दशक में लघु उद्योगों की सचयी वार्षिक वृद्धि दर आर्थिक सुधारों से पूर्व के वर्षों की तुलना में कमी रही है। उदाहरण के लिए, लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि दर जो 1985-91 में 7.56 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, 1991-97 के दौरान कम

हो कर 6.53 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई। इसी अवधि में उत्पादन की संवृद्धि दर 20.47 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम हो कर 18.57 प्रतिशत प्रति वर्ष, रोजगार की वृद्धि दर 5.47 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम हो कर 4.27 प्रतिशत प्रति वर्ष, तथा निर्यात की वृद्धि दर 28.40 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम होकर 23.52 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई।

अब विश्व व्यापार संगठन (WTO) की शर्तों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने परिमाणात्मक प्रतिबंधों (Quantitative restrictions) को समाप्त कर दिया है। इससे लघु उद्योगों के लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी क्योंकि अब उनके उत्पादों को सस्ती व गुणात्मक रूप से बेहतर विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। चीन से हो रहे सस्ते आयातों का दबाव बहुत से लघु उद्योग अभी से अनुभव करने लगे हैं। फलस्वरूप लघु उद्योगों को उचित वित्त प्रोत्साहन, सरकारी नीति न बनाये जाने के कारण इन्हें कई संकटों से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे लघु उद्योगों का विकास जिस अनुपात में होना चाहिए, उस अनुपात में नहीं हो पा रहा है।

સપ્તમ્ અધ્યાય

प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

औद्योगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वर्द्धमान प्रतिफल के मान सीमाओं को सतत सृजन किया जाता है तथा उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। लघु उद्योगों के विकास के फलस्वरूप ही आर्थिक विकास तीव्रतर होता है। उत्तर प्रदेश भारत का मुख्य प्रदेश है जहाँ पर भूत, वर्तमान एवं भविष्य अत्यन्त सुन्दर ढंग से मिले हुए हैं। इस प्रदेश की एक विशेष औद्योगिक नीति है। राज्य का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण इसके प्राचीन समय के वैभव को प्रकट करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वृद्धि दर 2.3% रहा। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि सम्बन्धी बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया गया एवं ऊर्जा, यातायात, संचार इत्यादि में सहायक रचनात्मक सहयोग देकर 1.7% वृद्धि दर प्राप्त किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों के औद्योगीकरण के क्षेत्र में 5.7% की वृद्धि दर अंकित किया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 की वृद्धि दर 3.4% रही। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सेक्टर की वृद्धि दर 9.4% में अत्यधिक वृद्धि हुई। छठी योजना में 11.8% की बढ़ोतरी हुई। सातवी योजना के मध्य तक 12.5% से अधिक वृद्धि प्रकाशित हुई। जो कि औद्योगिक वृत्त खण्ड के साथ विनियोजित थी। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सामान्यतः छोटे प्रकार की इकाइयों की संख्या वर्ष 1988-89 के अन्त तक 11,000 से बढ़ाकर 19,6,220 से ऊपर हो गयी।

सातवी पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता से अधिक की 12.5% वृद्धि हुई जो आठवी योजना तक जारी रही है। केवल सातवी योजना के मध्य तक 4616 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त विनियोजन के लिए ख्याति प्राप्त हुई।

आठवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सेक्टर में सर्वत्र 7.3% की वृद्धि दर का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग उत्पादकता एवं इकोनॉमिक बई बिल्टी के ऊँचे स्तर में प्रवेश करेगा। लघु उद्योगों में 5.6% की वृद्धि का लक्ष्य है।

UPFC पिछले तीन वर्षों में एक अवधि उधार सस्थाओं की संख्या को मार्गदर्शक के रूप में बनाये रखा एवं साथ ही साथ 4071 इकाइयों की 1700 करोड़ रुपये से अधिक ऋण अनुमोदित किया गया। UP SIDC राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करता है इसने 2240 एकड़ से ऊपर भूमि पर 107 औद्योगिक क्षेत्र 43 जिलों में स्थापित किया। निगम राज्य के सभी जिलों को औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव करे। इस योजना में केन्द्र, राज्य सरकार एवं IDBI संयुक्त रूप से वित्त देने के लिए जुड़े हुए हैं। UP STC, U P सीमेन्ट कार्पोरेशन, यूपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन, इत्यादि की तरह राज्य के विभिन्न उद्योगों को बढ़ाने का वातावरण किया गया। सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 25%, 15% एवं 10% की दर से क्रमशः A, B एवं C श्रेणी के जिलों में सहज थी। राज्य निगमों द्वारा निम्न और योगदान दिया जा रहा है—

- (1) बिक्री कर में छूट।
- (2) एक न्यूनतम 15 लाख रुपये की 15% विषयों की एक विशेष प्रतिष्ठित इकाई "Zero Industry Tensil" में कैपिटल सब्सिडी को सहज बनाया गया।
- (3) चुँगी से मुक्ति।
- (4) 100% निर्यातक ओरियन्टेड इकाइयों के लिए कैपिटल सब्सिडी।
- (5) केन्द्रीय यातायात आर्थिक सहायता पहाड़ी क्षेत्रों में माल के यातायात के लिए 75% आर्थिक सहायता।
- (6) नये उद्योगों के प्रभावी ऊर्जा में पाँच वर्ष के लिए कर मुक्त ऊर्जा।

सिगलविण्डो फैसिलिटी — विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में मध्यम एवं बड़े उद्योगों की समस्याओं के समाधान करने में सहयोग देने के लिए राज्य सरकार ने बिना लाभ आधार पर एवं सघ उद्योग बन्धु के नाम से बनाया। 1987 के अन्त तक हाई पावर कमेटी न्यायालय में लघु उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए भी एक माह में एक बार सभा करती है। राष्ट्रीय झुकाव एवं पूर्णता को ध्यान में रखकर राज्य सरकार विशिष्ट युद्ध कौशल एवं उद्योगों

के विशिष्ट सेक्टरों की योजना बना रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अपनी पूर्णता के अन्तिम वर्ष बहुत शीघ्र नवी योजना के कार्य में परिणित हो जायेगी। औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विशेष कार्यदल 8 सेक्टरों से अधिक में स्थापित किये गये हैं। पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों के महान विकास के लिए आकर्षित पैकेज साहस के साथ दुहराये गये। आधुनिकीकरण के लिए साहस पूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। ऊर्जा के बचत, प्रदूषण नियंत्रण एवं पूँजी उगाही अनुपात औद्योगिक सेक्टर में महान उत्पादकता बढ़ाया गया। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि राज्य को 21 वीं सदी में ले जाने के लिए कुछ प्रस्ताव व्यापक रूप से तैयार किये जा रहे हैं। जो आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षेत्र एवं राज्य के बड़े हिस्से में औद्योगिक क्षेत्र फैलाये जाने का विचार किया जा रहा है।

उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शीघ्र ही राज्य अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में उच्च औद्योगिकीकरण के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च औद्योगिकीकरण में आर्थिक सुधार के क्षेत्र में गर्व का स्थान प्राप्त करेगा।

अर्थव्यवस्था के प्रारम्भिक इतिहास में एवं औद्योगिक इतिहास के पूर्व लघु उद्योगों को बहुत सकीर्ण एवं सीमित अर्थों में प्रयोग किया जाता था। ये उद्योग तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। उन्नत देशों में इन उद्योगों का व्यापार विस्तृत है। एवं बड़े स्तर के उद्योगों के सहायक रूप में विकसित हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार लघु स्तर औद्योगिक बोर्ड के द्वारा एक कार्यरूप परिभाषा ग्रहण की गई जिसके अनुसार "सभी इकाइयों या कार्यालय जिसका पूँजी विनियोजन पाँच लाख से कम है एवं 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देती है, जब शक्ति प्रयोग हो रही हो।"

इधर सोसाइटी एण्ड इकोनॉमिक स्टडीज इन कैपिटल फार मीडियम एण्ड स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज द्वारा प्रमाणित की गई। इसी प्रकार की परिभाषा स्माल स्केल बुलेटिन के द्वारा जारी की गई जिसमें भी 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा एवम् श्रमिकों की संख्या भी सीमित रही।

कमेटी आन द स्टेट इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन इन वेस्ट बंगाल के विचार मे लघु उद्योग वे इकाइयाँ है जिनकी प्रोसेसिंग कैपिटल पूँजी 10,000 रुपये से अधिक हो और 1 लाख तक हो।

दिसम्बर 1966 मे लघु स्तर इकाई की परिभाषा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बोर्ड द्वारा परिवर्तित की गई है जो निम्न है –

“लघु स्तर उद्योगो के अन्तर्गत वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं जिनकी पूँजी विनियोग 75 मिलियन रुपये से अधिक न हो एव रोजगार मे श्रमिको की सख्या का कोई आपेक्ष न हो”।

भारत सरकार ने लघु उद्योगो के सम्बन्ध मे व्यवस्थित ढाँचा बनाने के लिए सन् 1972 मे एक कमेटी नियुक्त की कमेटी ने यह सुझाव दिया कि लघु उद्योग सेक्टर को निम्नलिखित

- (1) Tiny Unit Industry
- (2) Small Scale Industry
- (3) Ancillary

1974 मे लघु स्तर बोर्ड की 32 वी मीटिंग मे लघु स्तर उद्योग की परिभाषा पर पुन विचार किया गया। बोर्ड द्वारा दी गई पुन विचारित परिभाषा की सस्तुतियो को भारत सरकार ने स्वीकार किया एव इसे 1 मई 1974 से लागू किया जो इस प्रकार है –

“एक लघु उद्योग वह है जिसका प्लाण्ट एव मशीनरी पर विनियोग 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। 21 दिसम्बर 1977 मे घोषित औद्योगिक नीति मे एक नयी श्रेणी के उद्योगो अर्थात् अति लघु उद्योगो से परिचय कराया। यह व्यवस्था किया गया है कि “जिसकी मशीनरी एव साज सामानो मे एक लाख रुपये से अधिक का विनियोग है और 1971 की गणना के अनुसार 50,000 से कम जनसख्या वाले कस्बे मे स्थित हो”।

1980 मे पूँजी विनियोग और निर्गम मे मूल्य वृद्धि के कारण सरकार ने अति लघु, लघु एव इन्सीलरी उद्योगो मे पूँजी विनियोग सीमा बढ़ाने का निर्णय किया। इसकी सशोधित

परिभाषा इस प्रकार है —

- 1 अति लघु — “व्यवसाय जिसकी स्थायी सम्पत्तियों में प्लांट एवं मशीनरी पर पूँजी विनियोग 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
- 2 लघु स्तरीय उद्योग — व्यवसाय जिनकी स्थायी सम्पत्तियों में प्लांट एवं मशीनरी या तो स्वामी के अधिकार में या पट्टे द्वारा या किस्त द्वारा हो, पर विनियोग 20 लाख रुपये से अधिक न हो।
- 3 एनसीलरी उद्योग — व्यवसाय जिसकी स्थाई सम्पत्तियाँ 25 लाख से अधिक न हो और काम में (A) शिल्पकर्म के हिस्से, साधको, औजारों (B) सेवाओं का प्रतिपादन या पूर्ति का उद्देश्य या उनके उत्पादन का 50% या कुल सेवाओं जैसा दूसरी श्रेणियों के उत्पादन के सम्बन्ध में हो सकता है।

लघु उद्योगों की परिभाषा में पुनः मार्च 1985 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार प्लांट एवं मशीनरी पर सीलिंग जो 1980 में निर्धारित की गयी उसे 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख किया गया। इस प्रकार वे समस्त इकाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं। जिनमें स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में सयन्त्र एवं मशीनरी पर 60 लाख रुपये से अधिक पूँजी नहीं लगी है लेकिन छोटे पुर्जे, उपकरण, सयन्त्र या मशीनरी पर या मरम्मत का कार्य करने वाली इकाइयों की दशमे 75 लाख रुपये तक पूँजी विनियोजित करने वाली इकाइयों को भी लघु उद्योगों की परिभाषा के अन्तर्गत रखा गया है।

वर्तमान में लघु उद्योगों में पूँजी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर तीन करोड़ रु कर दी गई है।

लघु उद्योगों का औचित्य

- 1 आर्थिक विकास — प्रत्येक देश के आर्थिक प्रगति में लघु उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लघु उद्योग विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं। आर्थिक विकास में विकेंद्रित उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। और यही प्रति व्यक्ति आय ही देश की कुल

राष्ट्रीय आय होती है जो कि आर्थिक विकास का मापदंड हैं।

- 2 रोजगार — लघु उद्योगों के विकास के पक्ष में जो तर्क दिये जाते हैं उनमें रोजगार की वृद्धि का तर्क स महत्वपूर्ण है। लघु उद्योग में रोजगार क्षमता वृहन्त उद्योगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः भारत जैसी विकास शील अर्थव्यवस्था में जहाँ पर पूँजी की दुर्लभता है एवं श्रम बाहुल्यता है वहाँ पर लघु उद्योग ही बेरोजगारी समस्या का उचित समाधान कर सकते हैं।
- 3 आय वितरण — लघु उद्योग धन के समान वितरण के सहायक होते हैं। वृहद उद्योगों के विकास के राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ इने गिने उद्योगपतियों के हाथ में केन्द्रित हो जाता है। इस कारण आर्थिक असमानता है। इस ओर लघु उद्योग ही उपयोगी हो सकते हैं जो कि समानता का वातावरण तैयार करते हैं।
- 4 स्थानीय ससाधनों का विदोहन — लघु उद्योग अपसंचित धन एवं कौशल आदि छिपे हुए साधनों के उपयोग करने में सहायक होते हैं।
- 5 सहायक व्यवस्था के रूप में — सहायक व्यवस्था के रूप में देश के आर्थिक विकास में कुल भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योग अल्पसमय में अल्प पूँजी की मदद से वृहद समुदाय के उपभोग वस्तुओं की पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं।
- 6 शीघ्र उत्पादन उद्योग — इसमें धन विनियोग करने पर शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। लघु उद्योगों प्रारम्भ करने एवं बाजार में वस्तुओं के प्रवाह के बीच की अवधि थोड़ी होती है। इस प्रकार भारी उद्योगों की तुलना में लघु उद्योग फलदायक होते हैं।
- 7 सामाजिक लागत नैतिक पक्ष — लघु उद्योग सामाजिक विस्थापन असंतोष एवं अशान्ति को रोकते हैं। जो भारी उद्योगों के मध्यम से होने वाले औद्योगिकरण के बाद आती है।
- 8 वर्ग संघर्ष से बचाव — लघु उद्योगों में मालिक एवं मजदूर में व्यक्तिगत सम्पर्क

रहता है। तथा उनके परस्पर सम्बन्ध भी अच्छे रहते हैं। अतः वर्ग संघर्ष की कम सम्भावना रहती है।

- 9 तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता — बड़े उद्योगों में पूँजी एवं आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। किन्तु लघु उद्योगों में कम कुशलता की आवश्यकता रहती है।
- 10 कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन — कलात्मक सुन्दर एवं कीमती वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग से ही सम्भव है।
- 11 शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के पूरे प्रभाव से सुरक्षा —
- 12 आयात पर कम निर्भरता
- 13 निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका — इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान देना वांछित ही नहीं बल्कि आवश्यक है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1647 इकाइयों द्वारा 29898 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 3446 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2,824 इकाइयों द्वारा 48,382 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 5016 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया। इस योजना की अवधि में 14 औद्योगिक आस्थानों का निर्माण कराया गया। इस योजनावधि में आवश्यक प्रयासों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, तकनीकी, व्यापारिक एवं प्रशासनिक प्रकृति के बैटिल नेक बनाये गये हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कई विचारों को ध्यान में रखकर 25 करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रामीण एवं लघु स्तर के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। इस योजना अवधि में 3383 करोड़ रुपये का विनियोग कर 4,842 इकाइयों द्वारा 1,14,431 लोगों को रोजगार प्रदान करके 10149 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया। ऋण एवं अनुदान के रूप

मे 77 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 1963-64 के दौरान दी गयी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं लघु स्तर के उद्योगों के विस्तार कार्यक्रम उत्पादन तकनीकों के विस्तार विक्रेन्दीकरण एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को उत्साहित करने का मुख्य लक्ष्य गया। इस योजनावधि में पूरक उद्योगों का विकास किया गया। इस योजनावधि में 12,851 इकाइयों द्वारा 249 करोड़ रुपये का उत्पादन कर 1,60,027 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इस योजना में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लघु उद्योग निदेशालय में एक सारणीयकी एवं प्रलेख पोषण प्रकोष्ठ की स्थापना 1973-74 में हुई।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में लघु स्तर के उद्योगों के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इस योजना के अन्त तक लघु इकाइयों की संख्या 47,943 थी जिसमें अनुमानित उत्पादन 983 करोड़ रुपये एवं 5,38,270 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। इसी अवधि में जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ हुआ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। 1976-77 में क्राफ्टमैन योजना एवं प्रदेश के विशिष्ट हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार योजना 1978-79 योजना से प्रारम्भ की गयी। इसी योजना अवधि में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना गाजियाबाद में की गयी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के अधिकाधिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित होने वाले 504 वस्तुओं को आरक्षित कर दिया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 के फलस्वरूप 1,10,710 लघु स्तर की इकाइयों की स्थापना की गयी। 1,10,710 इकाइयों में 676 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया। जिसमें उत्पादन 2,143 करोड़ रुपये एवं 9,20,756 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए हैं। योजना में वृद्धि दर 11.8% वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम की स्थापना की गयी। इस निगम द्वारा गोष्ठी, मार्जिन, मनी योजना तकनीकी प्रशिक्षण योजना एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण योजनाएँ चलायी जाती हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में लघु स्तर इकाइयों को लगाने का एक लाख का लक्ष्य रखा

गया। जिसके समक्ष 1,05,541 इकाइयाँ लगायी गयी। जिसमे 2,043 करोड रुपये का अनुमानत उत्पादन जिसके समक्ष 1,05,541 इकाइयाँ लगायी गयी। जिसमे 2,043 करोड रुपये अनुमानत का उत्पादन हुआ। 5,24,304 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। सभी मार्जिन ऋण योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 10% अधिकतम् 3 लाख रुपये जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 10% उद्यमियों को अपने स्त्रोतों से लगाया जाना अपरिहार्य है। वर्ष 1990-91 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम समय बद्ध प्रणाली से चलाया गया। 1990-91 के अन्त तक 43,067 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कराया गया। 872 व्यक्तियों को उद्योग लगवाकर लाभान्वित कराया गया। वित्तीय वर्ष 1992-93 में 48,883 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कराया गया। एवं 7,738 व्यक्तियों को उद्योग लगवाकर लाभान्वित किया गया। लघु उद्योग आधुनिकीकरण निधि योजना-उ० प्र० शासन ने औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु इस योजना को प्रस्तावित किया। उक्त तिथि का सृजन राज्य के समेकित निधि से आन्तरिक धनराशि एवं राज्य सरकार एवं भारत सरकार की वित्तीय सस्थाओं के अशदान से किया जायेगा। इस ब्याज की धनराशि से योजना के अन्तर्गत चुने गये। 14 उद्योगों को वृहद् एवं सूक्ष्म अध्ययन करा कर वर्ष 1992-93 तक प्रत्येक उद्योग की कम से कम दो इकाइयों को लाभ पहुँचाया गया।

“अ” “ब” “स” श्रेणी के पिछड़े जनपदों को उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा वर्ष 1990-91 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य पूँजी उत्पादन योजना प्रारम्भ की गयी। 1994-95 में लघु उद्योगों के लिए 500 लाख रुपये आय व्यय का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना भी आठवीं योजनावधि में प्रारम्भ किया गया। ब्लाक पायनियर इकाइयों को राज्य पूँजी उत्पादन योजना जो 1990 में प्रारम्भ की हुई। इस योजना के अन्तर्गत 4,97,219 रुपये की धनराशि औद्योगिक इकाइयों को वितरित की गयी।

इस प्रकार आठवी पंचवर्षीय योजना में 2,550 करोड़ रुपये पूँजी विनियोजित कर 1,65,000 इकाइयों द्वारा 14.85 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।

भावी कार्यक्रम

- 1 अवस्थापन सुविधाओं का विस्तार।
- 2 औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था।
- 3 औद्योगिक क्षेत्र का रख रखाव।
- 4 प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना।
- 5 कम्प्यूटरीकरण का विस्तार।
- 6 संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं का लगाया जाना।
- 7 रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन।
- 8 नई औद्योगिक इकाइयों को ब्रिकी कर छूट।

लघु इकाइयों का प्रारम्भिक विनियोग मुख्यतः स्वयं के फण्ड या उधार फण्ड मुख्यतः साहूकारों से प्राप्त करती है। ये लघु इकाइयों ऐसी स्थिति में नहीं होती कि ये बैंकिंग सेक्टर की गारण्टी दे सकें। बैंक एव फाइनेन्स कॉर्पोरेशन विस्तार अवधि ऋण प्राप्त करने के आवेदनो पर विचार नहीं करती है। यह मामले लघु उद्योगपतियों को बहुत कठिन बना देती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी परिभाषा के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयों को तब रूग्ण माना जायेगा। जब उसे पिछले वर्ष में नकद हानि हुई एव चालू लेखा वर्ष में भी उसे नकद हानि की सम्भावना हो और इन सही नकद हानियों के कारण उसकी निबल सम्पत्तियों में 50% या इससे अधिक हास हुआ है। उसे लगातार ब्याज की चार तिमाही किस्तों अथवा सावधि ऋण के मूल धन की दरे छमाही किस्तों का भुगतान करने में चूक की हो एव बैंक में उसकी ऋण सीमाओं के परिचालन में निरन्तर अनियमितताएँ हो, अपेक्षाकृत बड़ी लघु इकाइयों के विषय में उपयुक्त शर्तें पूरी होनी चाहिए जब कि अति लघु तथा विकेन्द्रीकृत

इकाइयों के मामले में किसी एक शर्त का होना पर्याप्त होगा।

लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रमुख योजनाएँ

1 आई डी बी आई की पुनः वित्त योजनाएँ — उद्योग प्रारम्भ करने की पूँजी की आवश्यकता, पुनर्वासन के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की आवश्यकता एवं कानूनी उत्तरदायित्व मिलाने के लिए विद्यमान विवरित आवश्यकता जहाँ प्राथमिक उधार सस्थाएँ IDBI के मूलऋण के सम्मुख पुनः वित्त अपने स्वयं के स्रोतों से अदा करता है। IDB पुनर्वासन पुनः वित्त पर ब्याज 9% प्रतिवर्ष होगी।

2. रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने हेतु केन्द्र सरकार की मार्जिन मनी योजना — योजना के अन्तर्गत अधिकतम सीमा प्रति इकाई 5000 रुपये होगी। लघुतर इकाइयों के लिए 7.5 से अधिक नहीं कुछ दशाओं में 90% तक दी जाती है। कुल अवधि 9 वर्षों से अधिक ही होगी।

3 रूग्ण लघु एवं लघुतर औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासन करने हेतु राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना — इस योजना का क्रियान्वयन दो माध्यम द्वारा कराया जाता है।

(a) यू पी एफ सी द्वारा वित्तपोषित इकाइयों हेतु योजना का क्रियान्वयन यू पी एफ सी द्वारा किया जाये।

(b) अन्य मामलों में योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाये।

4 लघु उद्योग आधुनिकीकरण निधि योजना — प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों की क्षमता एवं कार्यशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उ० प्र० शासन ने औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु इस योजना को प्रस्तावित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं लघुतर रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के अभिज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी—

1 वह लघु एवं लघुतर औद्योगिक इकाई जो पूर्व लेखा वर्ष में नकद हानि में रही हो। एवं

चालू वित्तीय वर्ष में हानि में रहने की सम्भावना हो तथा 50% से अधिक क्षय संचयी नकद हानि के कारण हुआ हो।

2 लिए गये ऋण की ब्याज की निरन्तर 4 तिमाही किस्तों अथवा टर्मलोन पर मूल धनराशि की दो छमाही किस्तों के भुगतान में असमर्थ रही हो एवं बैंक के साथ साख सीमाये रखने पर निरन्तर अनियमित रही हो।

लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई के मामले में उपयुक्त निर्धारित शर्तों के पूरा होना पर्याप्त होगा। एवं लघुत्तर इकाई के मामले में उपयुक्त कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए।

योजना के अन्तर्गत अधिकतम सहायता प्रति इकाई 50 रुपये होगी। अतिरिक्त स्वीकृत किया गया मार्जिन मनी ऋण सामान्यतः पुनर्वास योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण हेतु मार्जिन मनी का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लघुत्तर इकाइयों के मामले में यह सीमा 75% होगी। अपवादात्मक मामलों में लघु स्तरीय इकाइयों के लिए यह धनराशि 75% बढ़ायी जा सकती है। लघुत्तर इकाइयों को 90% तक इस प्रतिबन्ध के साथ की धनराशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

5 राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना — इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों के अभिज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी—

1 वह लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाई जो पूर्व लेखा वर्ष में नकद हानि में रही हो एवं चालू वित्तीय वर्ष में हानि रहने की सम्भावना हो एवं 50 या अधिक क्षय संचयी नकद हानि के कारण हुआ हो।

2 लिये गये ऋण के ब्याज की निरन्तर चार तिमाही किस्तों अथवा टर्मलोन पर मूल धनराशि की दो छमाही किस्तों के भुगतान में असमर्थ रही हो। और बैंक के साथ साख सीमा बनाये रखने में निरन्तर अनियमित रही हो। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई के मामले में उपयुक्त निर्धारित शर्तों का पूरा होना पर्याप्त होगा एवं लघुत्तर इकाई के मामले में उपयुक्त में से कोई एक शर्त पूर्ण होनी चाहिए।

योजना के अन्तर्गत लघु एव लघुतर इकाई के पुनर्वास हेतु अभिज्ञापन हो जाने के पश्चात् उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार इकाइयों के निम्नलिखित सीमा एव शर्तों के अधीन सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। योजना के अन्तर्गत केवल उन इकाइयों को जो व्यवहारिक तौर पर सभाव्य समझी जाती है पुनर्वास हेतु हस्तगत किया जायेगा। इकाई व्यवहार्य तब मानी जायेगी यदि बैंक, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्र सरकार तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों, जैसी भी स्थिति हो, सहायता पैकेज आरम्भ करने से 5 वर्ष से अत्यधिक अवधि में बिना छूट की माग किये निर्धारित एव एक लघु स्तरीय इकाई रूग्ण विचार की जाती है। यदि यह पूर्व लेखा वर्ष में हानि सहना एव संभवतः लगातार चालू लेखा वर्षों में पूँजी हानि से ग्रस्त हो एव इसके शुद्ध सम्पत्ति के 50% या अधिक के विद्यमान लगातार बढ़ते हुए पूँजी हानि के कारण कमी एव क्षय, लगातार चार क्रमागत ब्याज किस्तों में त्रुटि या दो अर्द्धवार्षिक अवधि की किस्तों में गलती एव बैंक के साथ इसके क्रेडिट सीमाओं से व्यवसाय में दीर्घकालीन अनियमितताएँ हो। यदि उपरोक्त स्थिति में से किसी एक स्थिति को पूर्ण करता है तो वह लघु इकाई रूग्ण कही जायेगी।

एक मध्यम आकार की औद्योगिक इकाई रूग्ण समझी जा सकती है— पुनर्वासन सहायता के कम से कम 3 वर्ष पूर्व से उत्पादन करता है, निरन्तर प्राथमिक लेखा वर्ष में पूँजी हानि का होना।

उद्योगों में रूग्णता विभिन्न कारकों के कारण उठती है। मास में कई उद्योग औद्योगिक रूग्णता की समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ राज्यों में यह अनुमानित है कि लगभग 50% इकाई रूग्ण हैं। जैसे बिहार में 36,000 लघु स्तर इकाइयों 55% रूग्ण हैं लगभग 50,000 उद्यमी एव 5 लाख प्रभावित हैं। राज्य उद्योग डाइरेक्टोरेट के सर्वेक्षण के अनुसार 1977 में 30 प्र० में 47,000 इकाइयों में 13,000 इकाइयों रूग्णता थी। तमिलनाडू में 50%, केरल में 36% रूग्ण थी। दूसरे प्रदेशों में यह संख्या 30% से 35% तक ही अनुमानित थी। भारत में 6 राज्यों में बड़ी संख्या में रूग्ण इकाइयों हैं, उनके नाम — उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु,

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक है। जून 1979 से दिसम्बर 1979 के अन्त तक लघु उद्योगों अनुबधित भुगतान के दायित्व का निर्वाह कर सके।

(b) मार्जिन मनी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को ऋण के रूप में राज्य स्तरीय पुनर्वासन समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। ऋण उन इकाइयों को स्वीकृत किया जायेगा जो उद्योग निर्देशालय, हथकरघा निर्देशालय में पजीकृत हो एवं पिछले सात वर्ष के अन्दर स्थापित किये गये हों।

(c) योजना के अन्तर्गत अधिकतम सहायता सीमा प्राप्ति इकाई 50 हजार रुपये होगी। अतिरिक्त स्वीकृत किया गया मार्जिन मनी ऋण सामान्यतः पुनर्वास योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं में बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण आवश्यक मार्जिन मनी का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लघुतर इकाइयों के मामले में यह सीमा 75% होगी। अपवादात्मक मामले में लघु स्तरीय इकाइयों के लिए यह धनराशि 75% बढ़ायी जा सकती है। तथा लघुतर इकाइयों को 90% तक इस सीमा तक इस प्रतिबन्ध के साथ की धनराशि 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(d) मार्जिनमनी योजना के अन्तर्गत इकाइयों को सहायता दी जायेगी। जो पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं/व्यवसायिक बैंको द्वारा पुनर्वासन पैकेज के अंश के रूप में होगा। मे रूग्ण इकाइयों की संख्या क्रमशः 16,805 एवं 20,975 हो गयी थी।

सन् 1980 में कुल 24,550 औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण थी जिनकी संख्या 1991 में बढ़कर 2,23,809 हो गयी एवं उसी अवधि में बकाया ऋण राशि 1809 करोड़ रुपये से बढ़कर 10768 करोड़ रुपये हो गयी। इन अवधियों में 74% की वृद्धि हुई। इसकी ओर बकाया ऋण राशि 22% की वृद्धि हुई। इसकी ओर बकाया ऋण राशि 22% की वृद्धि हुई। वर्ष 1991 में कुल 2,23,809 रूग्ण इकाइयों में से 2,21,472 औद्योगिक इकाइयाँ लघु क्षेत्र की थी जब कि सन् 1980 में इनकी संख्या 2792 मात्र थी।

श्रेणी	औद्योगिक रूग्ण इकाइयों की संख्या	बैंक ऋण की बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
लघु औद्योगिक इकाइयाँ	2,21,4,172	2,792 04
मध्यम वृहत् रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ (रूग्ण)	1,461	5,105 57
मध्यम वृहत् औद्योगिक इकाइयाँ	876	2,870 21
योग	2,23,807	10,769 82

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु, लघुत्तर ग्रामीण एवं पूरक औद्योगिक द्वारा उत्पादन की तकनीकी में वृद्धि भरना एवं उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन पद्धति में सुधार लाकर उसकी कार्य क्षमता, गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी का उच्चाकरण करना है ताकि स्वदेशी एवं विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने की क्षमता बढ़ सके।

उक्त तिथि का सृजन राज्य के समेकित निधि ने अन्तरिम धनराशि एवं राज्य सरकार एवं भारत सरकार के वित्तीय सस्थाओं के अशदान से किया जायेगा। यह योजना 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1995 तक अथवा जब तक कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समाप्त न की जाएँ, चलती रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत इकाइयों को निम्न सुविधाएँ दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

- 1 इकाई स्तर के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकतम रूपय प्रति इकाई अनुदान दिया जायेगा।
- 2 इकाई के लिए वांछित ऋण एवं कार्यशील पूँजी की व्यवस्था बैंक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा कराई जायेगी।
- 3 इकाई द्वारा वांछित अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था हेतु मशीनों के मूल्य का 15% पूँजी उत्पादन, जिसकी अधिकतम सीमा 1 30 लाख रुपये होगी, दिया जायेगा। इन खरीदी गई मशीनों हेतु लिए गये ऋण पर 4% की दर से ब्याज अनुदान भी दिया जायेगा, जिसकी

अधिकतम सीमा रुपये 20,000 प्रति वर्ष के हिसाब से पाँच वर्ष में दिया जायेगा।

4 जो लघु उद्योग इकाइयों आईएसआई चिह्नित उत्पादों के उत्पादन हेतु मशीन लगायेगी उन्हें मशीनों की लागत का 50% या रुपये 50,000 जो भी कम हो, उत्पाद के आई एस आई चिह्न प्राप्त के पश्चात अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन की व्यवस्था हेतु उ० प्र० शासन से प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय बैंक में जमा किया जायेगा। जमा धन से प्राप्त ब्याज की धनराशि से ही योजना का संचालन किया जायेगा। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में आधुनिकीकरण निधि के लिए रुपये 11 00 लाख, वर्ष 1990-91 हेतु रुपये 150 लाख, वर्ष 1991-92 हेतु रुपये 10 00 लाख तथा कुल रूपया 171 00 लाख शासन द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमें से रुपये 161 00 लाख को आहरित करके दिनांक 18 सितम्बर 1991 को तीन माह हेतु इलाहाबाद बैंक में 16% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जा चुका है। जिसमें से शासन ने 1991-92 में योजनान्तर्गत रुपये 39 00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया जिसमें रुपये 10 लाख की स्वीकृत वर्ष 1991-92 हेतु पहले से ही प्राप्त हो चुकी थी। इस तरह से वर्ष 1991-92 में योजनान्तर्गत रुपये 200 लाख की धनराशि हो जायेगी जिसे ब्याजदयी सस्था में जमा करके करीब रुपये 32 लाख ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। इस ब्याज की धनराशि से योजना के अन्तर्गत चुने गये 14 उद्योगों का वृहत् एव सूक्ष्म अध्ययन कराके वर्ष 1992-93 तक प्रत्येक उद्योग की कम से कम दो इकाइयों को रुपये 1 00 लाख की दर से योजना के अन्तर्गत प्रावधानिक लाभ पहुँचाया जायेगा।

राज्य पूँजी उत्पादन योजना — “अ”, “ब” व “स” श्रेणी के पिछड़े जनपदों में उद्योग लगाने हेतु राज्य पूँजी उत्पादन का दिया जाना शासन द्वारा 1990-91 में औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश के पिछड़े जनपदों में उद्योग स्थापित करने वाली नई इकाइयों को अनेक अचल पूँजी विनियोजन पर राज्य पूँजी उत्पादन प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। यह योजना 1995 तक लागू होगी। यह उत्पादन अ, ब, स के जनपदों को क्रमशः अचल पूँजी

निवेश का 20% किन्तु अधिकतम 20 लाख रुपये, 15% किन्तु अधिकतम 15 लाख रुपये, 10% किन्तु अधिकतम 10 लाख रुपये कतिपय शर्तों के साथ दिया जायेगा इस योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में 460 करोड़ रुपये की शासन ने स्वीकृत जारी की थी। जिसमें अभी तक रुपये 3,97,47,350 32 धनराशि व्यय हो चुकी है। तथा रुपये 62,52,640 68 पी एल ए में जमा है जिसके लिए शासन को 31 दिसम्बर तक व्यय की अवधि बढ़ाने के लिए लिखा गया है। वार्षिक योजना ने इस मद के अन्तर्गत 135 करोड़ रुपये की धनराशि 1991-92 हेतु स्वीकृत की गयी है। वार्षिक योजना 1991-92 हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय होने की संभावना है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखकर वार्षिक योजना 1992-93 के लिए आम बजट में 180 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। विगत वर्षों में औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय धनराशि के आधार पर ही 1993-94 हेतु आय व्ययक के लिए 25 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। वर्ष 1994-95 में लघु उद्योगों के लिए 500 लाख रुपये आय व्ययक का प्रावधान प्रस्तावित है। एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना .— इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के स्थापना की संभावनाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से मार्जिन मनी ऋण योजना या वितरण करने का प्राविधान उन औद्योगिक इकाइयों के लिए है। जिनकी परियोजना लगान में मशीन सयन्त्र उपकरणों का मूल्य 60 लाख रुपये अधिक न हो और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित मार्जिन ऋण योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण की सुविधा अनुमान्य नहीं है। इस योजना का लाभ वर्तमान को भी अनुमान्य है जो अपनी इकाई की वर्तमान उत्पादन क्षमता में 25% की वृद्धि करने के उद्देश्य से इकाई का विस्तार करती है। एवं लघु इकाई की सीमा का उल्लंघन न होता है। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 10% अधिकतम 3.00 लाख रुपये जो भी कम हो, मार्जिन मनी ऋण के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 10% उद्यमियों को अपने स्रोतों से लगाया जाना अपरिहार्य है।

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों के परियोजना लागत का

15% तक ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसके सदस्य सचिव महाप्रबन्धक जिलाउद्योग केन्द्र एवं अन्य सदस्य सम्बन्धित संयुक्त निर्देशक, उद्योग सम्बन्धित वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि एवं अपर जिलाधिकारी विकसित करते हैं।

अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार को समय-समय पर इन्हें वित्तीय सुविधा देती रहे। जो इकाइयाँ बन्द हो चुकी हैं उस पर भी विचार करे। कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सरलीकरण करे। लघु उद्योग विकास बैंको को समय-समय पर कम ब्याज दर पर, न्यूनतम ऋण प्रक्रिया करके प्रदत्त करे। जिससे लघु उद्योगों का अधिक से अधिक विकास हो सके।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिया जा सकता है :-

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आर्थिक विकास के मुख्य स्रोतों में से एक स्रोत लघु उद्योग का भी माना जाता है। वर्ष 1991 में जब वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने उदारवाद तथा भूमण्डलीकरण की नीतियों की घोषणा की, तो देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन तेजी से होने लगा तथा देश में कार्यरत लघु उद्योगों की स्थिति निरंतर खराब होती गयी, जिसका परिणाम यह हुआ है कि वर्ष 2000 तक देश में बेरोजगारी की फौज तीन करोड़ का आकड़ा पार कर गयी।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु उद्योगों की स्थिति सुधारने हेतु नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन में लघु उद्योगों के लिए एक पैकेज की घोषणा की। घोषित पैकेज देश में बढ़ते बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रादुर्भाव को रोक पाने में कितनी सार्थक भूमिका निभाता है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, अपितु इतना जरूर है कि भारत की केन्द्रीय सरकार ने देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले लघु उद्योगों के विकास की ओर इस पैकेज के माध्यम से बहुत की कम ध्यान दिया है।

लघु उद्योगों की आधारभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है और जब तक

सरकार इन आधारभूत समस्याओं का निराकरण सरकार पूरे मनोयोग से नहीं करती, तब तक लघु उद्योगों के माध्यम से देश का आर्थिक विकास होना सदेह के घेरे में ही रहेगा। जापान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सम्पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से तहस-नहस हो चुका था। वह अब अपने 55 वर्ष की विकास यात्रा के दौरान विश्व का एक शक्तिशाली देश बन चुका है। जापान की आर्थिक सफलता के पीछे वहाँ के नागरिकों में राष्ट्रवाद के साथ-साथ लघु उद्योगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यदि भारत को आर्थिक रूप से एक सम्पन्न राष्ट्र बनाना है, तो लघु उद्योगों की ओर सरकार को सम्पूर्ण मन से प्रयास करने की आवश्यकता है।

फरवरी 1998 से लघु उद्योगों में उन इकाइयों को शामिल किया जाता है, जिसमें तीन करोड़ रुपये से कम की पूँजी विनियोजित की जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित इस पैकेज की घोषणा उन सिफारिशों पर आधारित है, जो कि केन्द्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों की एक समिति द्वारा लघु उद्योगों की समस्याओं को जानने के लिए बारह सूत्रीय इस पैकेज के इस पिटारे में क्या है ? जरा देखें। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रादुर्भाव के कारण भारतीय लघु उद्योग की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः सरकार ने वर्ष 1998 में लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को तीस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गयी। पूँजी की समस्या से जूझ रहे लघु उद्योग के लिए पूँजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कम्पोजिट ऋण सीमा को दस लाख रुपये से बढ़ाकर 26 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे उत्पादक सावधि ऋण तथा कार्यशील पूँजी प्राप्त कर सकेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में अब दस लाख रुपये तक निवेश वाले सेवा व व्यवसाय उपक्रमों को भी शामिल किया जा सकेगा। जिससे उन्हें भी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध होगा।

लघु उद्योगों में तकनीकी विकास के लिए विशेषज्ञों की एक अंतरमंत्रालयीय समिति बनाने की घोषणा की है, जो कि तकनीकी विकास तथा उन्नत उत्पादन के बारे में सिफारिशें

करेगी तथा कुछ चयनित क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन के लिए निवेश पर बारह प्रतिशत की पूँजी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। हथकरघा के क्षेत्र के लिए 447 करोड़ रुपये की जायेगी। हथकरघा क्षेत्र को विकसित करने का दृढ़ सकल्प दर्शाया गया है। 125 करोड़ रुपये की पूँजी से क्रेडिट गारंटी कोष ट्रस्ट की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान कर दिये गये हैं। लघु उद्योगों के उत्पादन में उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए आई एस ओ 900 प्रमाण पत्र के लिए आगामी छह वर्ष तक प्रत्येक इकाई के लिए 75000 रुपये का अनुदान जारी रखा जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सरकार लघु संगठनों को एक मुश्त 50 प्रतिशत पूँजी अनुदान स्वरूप प्रदान करेगी।

खादी उत्पादों के भूमण्डलीय स्तर पर विपणन करने के लिए उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले खादी उत्पादों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए एक अलग पैकेज देने का मन बना रही है। अभी इन उत्पादों पर छूट जारी रहेगी। हथकरघा क्षेत्र के वित्त विपणन, डिजाइन के मामले में सहयोग के लिए सरकार ने दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को मजूरी दी है। तकनीकी उन्नयन के लिए ऋणों को मजूरी दी है। तकनीकी उन्नयन के लिए ऋणों को वरीयता के आधार पर निर्धारित किया जाये तथा लक्षित वार्षिक कारोबार की 20 प्रतिशत कार्यशील पूँजी भी रियायती दरों पर ऋण के रूप में प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा बुनकरों को व्यापक रूप से वित्तीय व ढाचागत सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

लघु क्षेत्र की वृद्धि दर आगामी वित्त वर्ष में 9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जोकि अब तक 82 प्रतिशत थी। निर्यात वृद्धि दर 9—10 प्रतिशत के स्तर पर लायी जायेगी। इंस्पेक्टर राज के कारण हतोत्साहित लघु उद्योगों को राहत देने के कारण हतोत्साहित लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज के कारण हतोत्साहित लघु उद्योगों को राहत देने के लिए एक समूह का गठन किया जायेगा, जो तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 1990 में लघु उद्योग से संबंधित

गणना की गयी थी। प्रभावी नीति निर्धारित और कार्यान्वयन के लिए नई गणना अनिवार्य प्रतीत हो रही है। इसलिए नई गणना का फैसला किया गया है, जिससे समस्या का समाधान हो। लघु उद्योगों को बीमारी का निदान करने की बात इस पैकेज में कही गयी है।

सरकार लघु उद्योगों में इन्स्पेक्टरराज तथा ऋण प्रवाह पर चिंतित है। उद्योगपतियों ने सरकार द्वारा घोषित इस पैकेज का स्वागत किया है तथा आशा व्यक्त की है कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क छूट सीमा बढ़ाने, कम्पोजिट ऋण सीमा बढ़ाने, तकनीकी उन्नयन करने तथा इन्स्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए 125 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना बहुत ही मामूली है तथा इस कोष को अभी 750 करोड़ रुपये जोकि 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सके, तक करने की माग भी चैंम्बर ऑफ कॉमर्स ने की है।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर अपना कोई दृष्टिकोण नहीं दिया है। पैकेज में दिए गए फैसलों से सरकार लघु उद्योग के निर्धारित विकास लक्ष्य व प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर सकेगी। अति लघु क्षेत्र को तो इस पैकेज का लाभ प्राप्त ही नहीं हो सकेगा।

सासदों और मंत्रियों को सरलता विनम्रता सेवा त्याग और बलिदान की भावना से ओत प्रोत होना चाहिये, जनता और देश की सेवा निस्वार्थ, निर्लिप्त और निस्पृह भाव से करनी चाहिए, जनता के दुख दर्द और कष्ट से उनका हृदय भीगा रहना चाहिए परन्तु इस देश में उल्टी गंगा बह रही है। सासद और मंत्री राजा महाराजाओं की तरह रहना चाहते हैं उन्हें अपनी सुख सुविधा और आराम की चिन्ता है न की जनता की। देश—प्रेम देश भक्ति, देश सेवा और जनसेवा से वे कोसों दूर रहना चाहते हैं। जनता का सुख दर्द उनके हृदय का नहीं छूता। काश! गांधी एक बार पुनः जन्म ले, इस उल्टी गंगा के प्रवाह को रोके और देश के इन तथा कथित कर्णधारों में सरल और सादे जीवन जनता के प्रति सेवा और बलिदान तथा देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत करे।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं —

1 उपयुक्त उद्योगों का चुनाव — उद्योगों की स्थापना के पूर्व इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि हम ऐसे लघु उद्योगों की स्थापना करें जिनके विकास की संभावनाएँ भविष्य से अधिक हों और वे उद्योग बिना किसी रुकावट के विकसित होते चले जाएँ। बहुत से ऐसे वस्तुएँ हैं जो लघु उद्योगों के द्वारा अधिक लाभकारी ढंग से तैयार की जा सकती हैं। जैसे वे वस्तुएँ जिनमें विशेष कला कौशल की आवश्यकता होती है। जो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए होती हैं। अथवा जो बड़े उद्योगों के काम में आती हैं या जिनकी माँग स्थानीय या अनियमित होती है। अथवा जिनका अलग अलग रुचियों या पसंद के अनुसार होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जिनसे बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक गौढ़ सामग्री प्राप्त होती है या जिनकी प्रक्रिया से वजन या आकार में वृद्धि होती है। अतः इस प्रकार से सम्बन्धित लघु उद्योगों को विशेष ध्यान देना चाहिए।

जापान की विकेन्द्रीकरण, विभेदीकरण एवं इधर उधर वितरण की नीति लघु स्तर के उद्योगों एवं वृहद स्तर के उद्योगों में बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रचलित है। उपठेकेदारी जापान में अत्यधिक प्रचलित है। विशेषकर विशेष किस्म के कागज निर्माण, कलम काटने वाली वस्तुएँ और हल्के इंजीनियरी उत्पाद आदि।

2 वित्त व्यवस्था — वित्त किसी भी औद्योगिक इकाई का रक्त होता है अर्थात् कोई भी कार्य बिना उचित वित्त की व्यवस्था के नहीं किया जा सकता। लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता के प्रवृत्ति के सन्दर्भ में अशोक मेहता खादी एवं ग्रामोद्योग समिति ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे, “पूँजी की आवश्यकता उन्हें पर्याप्त कच्चे माल के स्टॉक एवं लघु स्तर पर यन्त्र एवं कुल पुर्जे इत्यादि के लिए होती है।” लेकिन समिति ने साख या वित्तीय सहायता का कोई अनुमान नहीं बताया। स्थाई पूँजी एवं चालू पूँजी इन दोनों में से ग्रामोद्योग में चालू पूँजी की अपेक्षा कई गुना होती है। अतः हम थोड़ी से अतिशयोक्ति के साथ कह सकते हैं। कि लघु उद्योगों में पूँजी से तात्पर्य चालू पूँजी से होता है। इन उद्योगों की वित्त

व्यवस्था के समय पर ध्यान देना अवश्य दिया जाना चाहिए।

यह बात प्रायः कही जाती है कि खादी एव ग्रामोद्योग तत्काल वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने में अनुपयुक्त है। खादी एव ग्रामोद्योग के अनुयायियों द्वारा यह देखा गया है। ये एक ग्रामीण बैंक के पक्ष में हैं। इस प्रकार की विशेषीकृत संस्थाओं के पक्ष में काफी विचार व्यक्त किये गये हैं। जब तक वित्त व्यवस्था का कोई विशेष अभिकरण नहीं होगा, तब तक ग्रामीण बुनकरों तक साख नहीं पहुँच सकेगी। वर्तमान में यह विकल्प भारतीय स्टेट बैंक के रूप में प्राप्त हो गया है। जो स्थानीय या चालू दोनों वित्त प्रदान कर रहा है इसके अतिरिक्त इस दिशा में राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अलग विशिष्ट संस्थाएँ स्थापित करें। साथ ही वाणिज्य एव सहकारी बैंकों को इस विशेष भाग लेना चाहिए।

3 औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना — लघु उद्योग सहकारी समितियों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए। क्योंकि सबसे अधिक सहायता औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास से ही मिल सकती हैं इन उद्योगों के माल के क्रय विक्रय उत्पादन तथा ऋण आदि की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयों व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के कारण होती है। यदि ये लोग आपस में सहकारी समितियों के माध्यम से करें तो उत्पादन, वित्त एव क्रय सम्बन्धी अनेक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अतः हमें औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना एव विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में केन्द्रीय एव राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन सरकारों को चाहिए कि वे समितियों की वित्त उपलब्धि, कच्चा माल एवं देश विदेश में माल की पूर्ति में सहायता प्रदान करें।

4 औद्योगिक शिक्षा एव प्रशिक्षण की व्यवस्था — लघु उद्योगों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि इन उद्योगों में लगे लोगों को उचित शिक्षण एव प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जिससे कि वे आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों के प्रयोग से अधिकतम लाभ उठा सकें।

5 उत्पादन तकनीक में सुधार — इन उद्योगों के विकास के लिए इनकी उत्पादन तकनीक में सुधार लाना अनिवार्य है। ये उद्योगों उत्पादन तकनीक में सुधार से ही वृहत् उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना कर सकेंगे। एवं उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएँ सस्ते दामों में प्रदान कर सकेंगे। इन सुधार के लिए विभिन्न स्थानों पर यंत्रों को प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सयन्त्रों की मरम्मत तथा पुर्नस्थापना के लिए भी पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिए। इस दृष्टि से सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए कि प्रत्येक लघु उद्योग इकाई अपनी वार्षिक आय का एक निश्चित प्रतिशत एक इसका उपयोग आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर होगा तथा यह कोष कर मुक्त होगा।

6 बाजार एवं ब्रिकी सम्बन्धी सुधार — इन उद्योगों के विकास के लिए ब्रिकी एवं विपणन सम्बन्धी सुधार की अति आवश्यक है। यदि उत्पादित माल बाजारों में उचित मूल्य पर नहीं बिक पाता तो उत्पादकों में निराशा की भावना जागृत होती है जो कि विकास के लिए एक अवरोध है। अतः ब्रिकी एवं मण्डी के क्षेत्र में सुधार एवं विकास की ओर यथोचित ध्यान देना आवश्यक है।

कुछ सीमा तक सहकारी ब्रिकी के आधार पर इस समस्या के सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हमारे उत्पादकों को चाहिए कि वे उपभोक्ताओं की रुचि एवं फैशन के अनुसार ही उत्पादन करें। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि हम विदेशी खरीददारों एवं अपने ग्रामीण उपभोक्ताओं की रुचियों को देखें एवं तब उनके अनुसार वस्तुएँ निर्मित करें। इसके लिए परिवहन की सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा। सरकार एक ऐसा अभिकरण स्थापित करे जो उत्पादकों के माल को उचित मूल्य पर बेचने में सहायता करे और सरकार स्वयं भी माल को बड़ी मात्रा में खरीदे।

7 उच्च कोटि तथा नवीनतम डिजाइनों की वस्तुएँ — हमारे लघु उद्योगों के लिए आवश्यक है कि घटिया या निम्न किस्म का माल न उत्पादित करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अभिशाप है। इन उद्योगों को चाहिए कि वे उच्चकोटि का अच्छा माल

तैयार करे। सरकार इस ओर सहायता कर दे एवं उत्पादन की जॉच के बाद मुहर लगा दे। लेकिन सरकार को इस कार्स के लिए अपने भष्ट सरकारी विभागो एवं कर्मचारियो पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ डिजाइनो मे सुधार लाना आवश्यक है। इस दिशा मे एक राष्ट्रीय सस्था की आवश्यकता है।

8 लघु एवं वृहतस्तरीय उद्योगो का सीमा निर्धारण — लघु उद्योगो के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि इन उद्योगो एवं वृहत् उद्योगो के कार्य क्षेत्र अलग अलग बॉट दिये जाये जिससे कि इन दोनो के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सके। जिन क्षेत्रो मे लघु उद्योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा को समाप्त करते है। वहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण उद्योगो का विकास तेजी से किया जा सकता है यदि वे बड़ी एवं मध्यम आकार की इकाइयो के साथ जोड दिये जाये। सहायक उत्पादक ग्रामीण उद्योगो के माध्यम से ही होनी चाहिए।

9 बड़े उद्योगों की प्रतियोगिताओं से बचाव — लघु उद्योगो के विकास के सम्बन्ध मे सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन उद्योगों को बड़े उद्योगो की प्रतिस्पर्धा से बचाने की व्यवस्था करे। सरकार इस बात को मानती है। कि इन उद्योगो को सरकारी सहायता द्वारा ही बड़े उद्योगो की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है। जैसे कि कुछ क्षेत्रो को लघु उद्योगो के लिए सुरक्षित रखना, इनको अतिरिक्त छूट का अनुदान देना, मिल उद्योग पर उप कर लगाना इत्यादि। कई लघु उद्योगो की सहायता के लिए सरकार ने एक या कई उपायो को अपनाया है। कुछ लोगो का मत है। कि सरकार की यह नकारात्मक नीति ठीक नहीं है। उनका कहना है कि लघु उद्योगो मे सुधार लाकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाकर उनमे विकास करना चाहिए। मिल उद्योगो पर अतिरिक्त बोझ लादकर नहीं, लेकिन इस सुधार कार्य मे कुछ समय लगेगा। अतः कुछ समय तक के लिए इस नीति को अपनाया अति आवश्यक है। ऐसा करने लघु उद्योगों बड़े उद्योग की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ पायेंगे। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए इन उद्योगो का विकास होना अति आवश्यक है।

केन्द्र सरकार लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए जल्दी ही एक सम्मिलित कानून बनाने की तैयारी में है ताकि उन्हें इस समय के समस्त कानूनों के जजाल और इस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके। यह जानकारी लघु उद्योग राज्य मंत्री वसुधरा राजे ने उत्तर भारत के प्रमुख वाणिज्य सङ्गठन पी एच डी वाणिज्य उद्योग मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्पर्क करके दी।

श्रीमती राजे ने इसी सङ्घ में लघु उद्योगों के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण पर रेहन की छूट देने के लिए गारंटी कोष की योजना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 40 लाख रुपये तक का ऋण देने और उस पर 12 प्रतिशत की सब्सिडी देने जैसे योजनाओं का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंको, ग्रामीण बैंको और राज्य वित्त निगमों को ऋण मजूर करने के लिए पहले से अधिक अधिकार दिए गये हैं।

इससे पहले श्री जैन ने श्रीमती राजे का ध्यान लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व और लघु इकाइयों को एक करोड़ रुपये सालाना के कारोबार तक उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने की सलाह दे। उल्लेखनीय है कि केलकर समिति ने छूट की यह सीमा 50 लाख रुपये के कारोबार तक कर दी है। पीएचडी की विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों की ओर से भी लघु उद्योगों के लिए और ज्यादा माफिक नीतियों और नियमों की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग के सचिव श्री ठटेजा ने देश में लघु इकाइयों का मध्यम इकाइयों का आकार लेने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि लघु से मध्यम आकार लेने की प्रक्रिया सहज और परिस्थितियों की मांग पर आधारित होनी चाहिए। इसी सदर्भ में उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र की मांग को देखते हुए हैडलूम और निटवेयर क्षेत्र की लघु इकाइयों में निवेश की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की गयी है। उन्होंने उद्योग मंडल से सुझाव मांगा कि इस प्रकार और किस किस क्षेत्र में निवेश की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार काफी उत्साहपूर्वक लघु उद्योगों के लिए विभिन्न ढंग से प्रयत्नशील है। यदि यही स्थिति बनी रही एवं योजनाबद्ध रूप में सरकार इनकी समस्याओं के निराकरण में

प्रयत्नशील रही तो निश्चय ही ये उद्योग कुछ समय कि बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना उचित स्थान ग्रहण कर देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सहायक सिद्ध हो सकेंगे और अपना लक्ष्य पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए उठाये गये अन्य कदम

1 लघु उद्योगों इकाइयों द्वारा महसूस की जा रही आनुवांशिक समस्याओं को हल करने में उद्देश्य से और प्रौद्योगिकी के उन्नयन को प्रोत्साहित करने वाली दो नई स्कीमें हैं —

(A) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी फंड (स्कीम) ऋण गारंटी स्कीम वाणिज्यिक बैंकों से ही तरीकों से कार्य करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी प्रदान करने के लिए जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा दी गयी गारंटी सहित अन्य कोई सम्पांशिक गारंटी नहीं होगी।

(B) प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण सम्बद्ध पूंजीगत आर्थिक सहायता स्कीम सरकार ने इस स्कीम को दि० 20 सितम्बर 2000 को अनुमोदित किया है। जिमें कतिपय उप क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिन्हें एस एफ सी कहा गया है। इनके द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर 12% दर से एडिड पूंजीगत सहायता स्वीकार्य होगी।

2. लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क 1 सितम्बर 2000 से 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।

3 लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदम निम्नलिखित हैं .—

(A) मिश्रित ऋण स्कीम सीमा 25 लाख रुपये तक बढ़ा दी गयी है।

(B) 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

(C) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता के अर्न्तगत लघु उद्योगों को

दिये जाने वाले ऋण के प्रवाह की मानीटरिंग के लिए एक समिति गठित की है।

- (D) लघु सेवाओं एवं व्यापार उद्यमों के लिए निवेश की सीमाओं को बढ़ाया जाना— यह सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दी गयी है। समय में निपटान की व्यवस्था हेतु सशोधन किया गया है। और अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण इकाइयों को लाभ पहुँचाना इसका उद्देश्य है। इन दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ ये हैं ये भेदभाव रहित और विवेकाधिकार भिन्न हैं और कि ये दिशा निर्देश दो श्रेणियों अर्थात् 5 करोड़ रुपये से नीचे और 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले सभी क्षेत्रों के एन पी ए पर समान रूप से अलग-अलग लागू होते हैं। 31 मार्च 1997 को निम्नस्तरीय के रूप में वर्गीकृत एन पी ए को भी दिशा ये निर्देश कवर करते हैं। लेकिन ये एन पी ए बाद में श्रेणिबद्धता के अभाव में सदेहास्पद बन गये थे। अधिकांश लघु उद्योग इकाइयों प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत कवर होगी अर्थात् 5 करोड़ रुपये से कम वाली श्रेणी में सदेहजनक अथवा श्रेणीहीन ऋणों के लिए विच्छेदन की तारीख 31 मार्च 1997 है। यह एक समय में निपटान की सुविधा 31 मार्च 2001 तक प्रचालन में रहेगी।
- (E) राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी योजनाओं का आरम्भ किया जाय जो महिला उद्यमियों को अधिक से अधिक उद्योग चलाने के लिए प्रेरित करे अर्थात् उन्हें इस ओर अधिक सुविधाएँ प्रदान किया जाए जिससे महिला उद्यमी अधिक से अधिक संख्या में इस ओर आकृष्ट हो सकें।
- (F) औद्योगिक आस्थानों को बाजार के आस पास ही स्थापित किया जाए जिस प्रकार आवास आवंटित किये जाते हैं। उसी प्रकार उन्हें परिवहन सुविधाएँ भी आसान किस्तों में उपलब्ध कराया जाए जिससे उद्यमी इस ओर आकृष्ट होंगे और उनकी परिवहन की समस्या का समाधान हो सकेगा।
- (G) लघु उद्योगों द्वारा अपने मालों के गुणवत्ता पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

यद्यपि गुण चिन्हाकन योजना वर्ष 1945 से लघु उद्यमियों के उत्पादन एवं कलात्मक वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने एवं इसके विपणन के प्रोत्साहन हेतु प्रारम्भ की गयी है।

- (H) राज्य स्तर पर उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाये एवं साथ ही साथ श्रमिकों की कार्य अवधि दशाओं पर नियन्त्रण रखा जाए। सप्ताह में एक दिन अवकाश अवश्य निर्धारित किया जाये।
- (I) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के क्रिया कलापों को बेहतर बनाया जाए। ऋण देने के प्रावधानों को और सरल बनाया जाए। विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज की दर में एकरूपता होनी चाहिए।
- (J) एक ही संस्थाओं द्वारा भी एक ही दर से ब्याज लेना चाहिए। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं दिये गये ब्याज की दर अधिक है। इन्हें अपने ब्याज की दरों में कमी लानी चाहिए। जिससे उद्यमियों को ऋण लेने एवं अदा करने में आसानी हो। दूसरे उद्यमी भी ऋण लेने की ओर आकर्षित होंगे। ब्याज की दर कम रखने से बहुत से लोग इस ओर आकृष्ट होंगे।
- (K) बैंक या वित्तीय संस्थाओं को उद्यमियों की जरूरत के अनुसार ऋण देना चाहिए। प्रायः माग की मात्रा से कम और कई किस्तों में ऋण देती है। परन्तु उद्यमियों को पूँजी की एक साथ आवश्यकता पड़ती है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं ने जिन उद्योगों को ऋण प्रदान किया है उन्हें चाहिए कि समय-समय पर उन उद्योगों में जाकर उनकी प्रगति का निरीक्षण करे कि पूँजी का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं।
- (L) प्रशासन द्वारा विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में और विस्तार किया जाए। नये विद्युत स्टेशनों का निर्माण कराया जाये इसके साथ विद्युत चोरी पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाए। प्रायः कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी की जाती है। जिससे विद्युत की कमी उत्पन्न होती है। इसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ता है।
- (M) लघु उद्योगों को अपने लाभ बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास करने चाहिए। अपने उद्योगों

मे समय-समय पर नयी-नयी तकनीकी को अपनाना चाहिए।

लघु उद्योग की इकाइयों को पुर्नवास की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने लघु उद्योगों के लिए नीतिगत पैकेज में घोषित किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया जायेगा कि वह वर्तमान में रूग्ण चल रही है लेकिन सम्भवत व्यवहार्य लघु उद्योग की इकाइयों की पुर्नवास के लिए ससोधित दिशा निर्देश जारी करे।

30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज का विवरण इस प्रकार है—

- 1 लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में सुधार लाने के लिए सीमा शुल्क की 50 लाख रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर एक करोड रुपये करना।
- 2 लघु उद्योग मंत्रालय तथा ए आर आई द्वारा 12 वर्षों के अन्तराल के बाद लघु उद्योगों की तीसरी गणना करना। इस गणना में रूग्णता एवं इसके कारणों को भी शामिल किया जायेगा।
- 3 उद्योग से सम्बन्धित सेवा एवं व्यवसाय उद्यम में निवेश की मौजूदा 500 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1000 लाख रुपये करना।
- 4 प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में दशवी योजना के अन्त तक आई एस ओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75,000 रुपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।
- 5 लघु उद्योग सघों को परिक्षण प्रयोगशालाओं के विकास एवं संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाये। ऐसे सघों को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जाँच के बाद एक समक्ष 50% का पूँजी अनुदान दिया जायेगा।
- 6 चालू समेकित आधारभूत विकास योजना के कवरेज को बढ़ाना ताकि यह देश में उत्तरोत्तर रूप में सब क्षेत्रों को कवर करे और जिसमें 50% आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 50% अति लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित होंगे।
- 7 सम्मिश्रण ऋणों की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।

लघु उद्योग क्षेत्र का समग्र निष्पादन

वर्ष	यूनिटों की संख्या (लाख में)	(करोड़) उत्पादन वर्तमान मूल्य पर	(करोड़) उत्पादन स्थिर मूल्य पर	रोजगार (लाख)	निर्यात (वर्तमान मूल्य पर) करोड़ रु०
1991-92	20.82	1,78,699	1,60,156	129.80	13,883
	(6.9)	(15.0)	(3.1)	(3.6)	(43.7)
1992-93	22.46	2,09,300	1,69,125	134.06	17,785
	(7.9)	(17.1)	(5.6)	(3.3)	(28.1)
1993-94	23.81	2,41,648	1,81,133	139.38	25,307
	(6.0)	(15.5)	(7.1)	(4.0)	(42.3)
1994-95	25.71	2,93,990	1,99,427	146.56	29,068
	(8.0)	(21.7)	(10.1)	(15.2)	(14.9)
1995-96	27.24	3,56,213	2,22,162	152.61	36,470
	(6.0)	(21.2)	(11.4)	(4.1)	(25.5)
1996-97	28.57	4,12,636	2,47,311	160.00	39,248
	(4.9)	(15.8)	(11.3)	(4.8)	(7.6)
1997-98	30.14	4,65,171	2,68,159	167.20	43,946
	(5.5)	(12.7)	(8.4)	(4.5)	(12.0)
1998-99	31.21	5,27,515	2,88,807	171.58	48,979
	(3.6)	(13.4)	(7.7)	(2.6)	(11.5)
1999-00	32.25	5,78,470	3,12,576	178.50	53,975
	(3.3)	(9.7)	(8.2)	(4.0)	(10.2)

टिप्पणी — कोष्ठक में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि करते हैं।

आबिद हुसैन समिति ने सुझाव दिया, सभी लघु स्तर उद्यमों के लिए एक ही कानून होना इस सम्बन्ध में लाभदायक होगा क्योंकि लघु स्तर उद्यमों को बहुत से मंत्रालयों की अपेक्षा एक

ही मंत्रालय से सम्बन्ध रखना पड़ेगा। ऐसे अधिनियम का कार्यन्वयन सामान्य प्रशासन एवं न्याय प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। लघु स्तर इकाइयों की अधिकाधिक इकाइयों की स्थापना के लिए सुझाव दिया जाता है कि आयकर अधिनियम के अधीन इन इकाइयों के "वेतन एवं मजदूरी के" 125% की भारी कटौती की इजाजत होनी चाहिए।

संरक्षणवाद के उदारवाद की नीतियों की ओर परिवर्तन ने भारतीय बड़े पैमाने के उद्योग एवं बहुराष्ट्रीय निगमों को लघु स्तर उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने में सहायता दी है। इस अतिवादी मार्ग का परिहार करना होगा क्योंकि इससे लाभ की अपेक्षा अधिक हानि हुई है। देश को मध्यमार्ग अपनाना होना एवं आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ चयनात्मक उदारीकरण की इजाजत देनी होगी। राज्य सरकार, उद्योग निदेशालय एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों में लाभ बढ़ाने के लिए एक कार्य दल बनाया जाये। जो विभिन्न उद्योगों में जा कर उनका सर्वेक्षण करे और पता लगाये कि लाभ बढ़ने का क्या कारण है।

लघु स्तर इकाइयों के उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए कीमत प्राथमिकता नीति को लघु स्तर इकाइयों को हित की सुरक्षा करने के लिए एक स्थायी उपाय बनाया गया। इस प्रकार लघु स्तर इकाइयों द्वारा निर्मित की गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में 10% की कीमत प्राथमिकता के उपाय को हटा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप लघु स्तर इकाइयों के विक्रय पर दुष्प्रभाव पड़ा है। यह एक अनावश्यक कदम था एवं अब इस बात की जरूरत है कि इस उपाय को पुनः लागू किया जाये।

सरकार ने लघु स्तर इकाइयों एवं अनुपगी उद्यम सम्बन्धी विलम्बित भुगतान अधिनियम (Delayed Payment to SSI & Ancillary undertakings Act, 1993) का संशोधन करने का निर्णय किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से भुगतान को प्रधान उधार दर का 1.5 गुना कर दिया गया। अतः आलोचकों का मत है कि विलम्बित भुगतान कानून लागू ही नहीं हुआ है। बहुत सी लघु स्तर इकाइयों को बन्द होने से बचाने के लिए इस कानून की धाराओं का प्रभावी रूप से पालन करना बहुत आवश्यक है।

स्रोत

अध्याय—1

- भारतीय अर्थव्यवस्था— जे एन मिश्रा, पृ० 410
- भारतीय अर्थव्यवस्था— डा० अनुपम अग्रवाल, पृ० 57
- C S O, Manufacturing Interprises survey (1994-95)
- भारतीय रिजर्व बैंक करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997-98)
- भारत सरकार आर्थिक समीक्षा (2000-2001)
- Planning Commission, second Five year Plan Page No 47
- Report of the village and Scale industries Committee (1955) Page 45
- भारत-2002
- भारत-2003

अध्याय—2

- भारतीय अर्थव्यवस्था — जे एन मिश्रा, पृ० 506
- भारतीय अर्थव्यवस्था — के पी एम सुन्दरम, पृ० 519, 520
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण — 1994-95
- भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एव विश्लेषण—
प्रो० एस एन लाल, पृ० 238
- आर्थिक समीक्षा — 1994-95 पृ० 157
- Small Industries Development Book of India, Op cit, Page 29
- भारत मे लघु उद्योग, विकास आयुक्त
उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पृ० 19,24

- Growth and Financing of Small Scale Industries in U P Page No 32
- उ० प्र० मे उद्योगो का विकास पेज न० 25
- उ० प्र० मे उद्योगो का विकास समीक्षा, 1991-92
- उद्योग निदेशालय उ० प्र०, नियोजन एव अनुसन्धान प्रसारण कानपुर।
- Planning Commission, Ninth Five year Plan (1997-98) vol II
- Economic Survey , 1997-98
- Planning Commission, Screen Five year Plan vol II Page 132
- Government of India economic Survey, 1995-96
- Government of India Economic Survey 1994-95
- भारत 2002
- भारत 2003

अध्याय -3

- वित्तीय प्रबन्ध- डॉ० एच के सिंह, पृ० 350,351
- भारत मे लघु उद्योग, विकास आयुक्त,
- उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार 1997
- भारतीय अर्थव्यवस्था-वी के पुरी, पृ० 472, 473
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण- 1994-95
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण- 1997-98
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण- 2001-02
- भारत - 2003
- वित्तीय प्रबन्ध - डॉ० माता बदल शुक्ला, पृ० 192
- भारतीय अर्थशास्त्र- डॉ एस सी जैन, पृ० 301

- नौवी पचवर्षीय योजनाए (1997–2002)
- भारत मे उद्योगो का सगठन, प्रबन्ध एव वित्त—डॉ० आर एस कुलश्रेष्ठ
- लघु उद्योग और स्वरोजगार परियोजनाएँ भाग—2
प्रधान मन्त्री रोजगार (योजनान्तर्गत)
- भारतीय रिजर्व बैंक, करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997–98)
- भारत सरकार आर्थिक समीक्षा — (2000–01)
- Government of India, Economic Survey, 1995-96
- Economic survey - 1997-98
- Planning Commission, Eight Five Year Plan roll II, Page 132
- The Hindu Survey of India Industry 1996, Page 37
- Government of India, Economic Survey 2000-01 (Delhi 2001), Page 142
- The Hindu Survey of Indian Industry 1999 Page 219
- Small Scale Industries- rasant DEsar (Himalya Publishing house)
- Planning Commission, ssecond Five year Plan page 47
- Report of the village and small & scale Industries Committee 1955 page 45
- The Rule of small Interprises in India Economic development Page 11
- Annual Srvey of Industries (1994-95)
- Economic Survey (1999-2000) Page No 126
- Report on Planning Commission 2002
- Annual Survey of Industries (1994-95)
- The National Small Industries Corporation Limited July- September 2001
- I BA Bulleton June 2002 rol xxiv Page No 6

अध्याय –4

- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ बट्टी विशाल त्रिपाठी पृ0 370, 378, 384
- भारतीय अर्थशास्त्र – डॉ एस सी जैन, पृ0 301
- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ अनुपम अग्रवाल, पृ0 57
- भारत मे लघु उद्योग, विकास आयुक्त, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार-1997
- भारतीय अर्थव्यवस्था – वी के पुरी, पृ0 474
- भारत, आर्थिक सर्वेक्षण-1994-95
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण-1997-98
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण-2001-02
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण-2003
- भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एव विश्लेषण- प्रो एस एन लाल, पृ0 2 38
- भारतीय रिजर्व बैंक, करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997-98)
- भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा 2000-01
- योजना 2003 (जनवरी)
- उद्यमिता 2003 (अगस्त)

अध्याय-5

- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ वी के पुरी, पृ0 473
- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ जगदीश नारायण मिश्रा, पृ0 509
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 1994-95
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 1997-98
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 2001-02
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 2002-03

- नौवीं पंचवर्षीय योजनाएँ (1997–2002) roll II, पृ० 609
- आर्थिक समीक्षा, 1994–95, पृ० 157
- भारतीय अर्थव्यवस्था– डॉ बट्टी विशाल त्रिपाठी, पृ० 378, 384
- Small Scale Industries - vasant Desai (Himalya Poblishing house)
- R B I Report on Currency and Finance, 1997-98 and IDBI on Development Banking in India, 2000
- C S O Manufacturing Enterprises Survey (1994-95)
- Report of the village and small Scale Industries committee 1955 Page 45
- The Role of small Enterprises in India, economic Development Page 11

अध्याय –6

- भारत में लघु उद्योग विकास आयुक्त, उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार 1997
- भारतीय अर्थशास्त्र– डॉ एस सी जैन, पृ० 301
उद्यमिता – (अगस्त) 2003
- भारत 2001
- भारत 2002
- भारत 2003
- भारतीय रिजर्व बैंक, करेंसी एवं वित्त की रिपोर्ट (1997–98)
- आर्थिक समीक्षा 1994–95, पृ० 157
- योजना (नवम्बर) 2003, पृ० 16
- Annual Survey of Industries (1994-95)
- Partiya gota Derpran 2002
- Economic Survey (1999-2000), roll II, Page 665

- Report on Planning commission 2002
- Small Industries, Development Bank of India, SIDBI, Report on small Industries Sector 1999 (Lucknow, 1999)

अध्याय — 7

- भारतीय अर्थव्यवस्था— डॉ अनुमप अग्रवाल, पृ0 57, 62
- भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एव विश्लेषण— प्रो एस एन लाल, पृ0 238
- भारतीय अर्थशास्त्र— डॉ एस सी जैन, पृ0 157
- आर्थिक समीक्षा 1994—95, पृ0 157
- आर्थिक समीक्षा 2000—01, पृ0 201
- Planning Commission, ninth Five year plan (1997-2002) roll- II
- Reoport on Planning Commission 2002
- Annual Survey of Industrires (1994-95)
- Annual Survey of Industries (2002-03) India, 2000 Page 563
- Reoport on Industrial Development Banking of India-1998-99
- Economic Survey 1999-2000, Page No 126
- The Role of Small Enterprises in India, Economic Development Page 11
- Small Scale Industries - Vasant Desai (Himalya Publishing house)
- The Hindu Survey of India Industries
- Government of Inida, First Five year Plan (1951-56)
- Government of India, Second Five year Plan (1956-1961)
- Government of India, Third Five year Plan (1969-1974)
- Government of India, Fifth Five year Plan (1975-1979)

Government of India, Sixth Five year Plan (1980-1985)

Government of India, Approach Paper to the

ninth Five year Plan (1997-2002) (Delhi 1996), Page 69

Arun Ghosh, "Government Policies Concerning Small Industries Scale An Appraisal", in K P Suri(ed), I bid , Page 318

The Role of Small Enterprises in Economic Development (New Delhi 1971)

The Hindu Survey of India Industries 1996, Page 237

परिशिष्ट — 1

लघु उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय तथा औद्योगिक विकास निगमों की सूची

1 स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया

मुख्य कार्यालय

लखनऊ

‘विकास दीप’ छठी और सातवीं मजिल, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ—226019,

फोन 234112, 233962, 236531, 236532, 244128, टेलेक्स 0535—2467,

फैक्स 239084

क्षेत्रीय कार्यालय

मुंबई

नरीमन भवन, तेरहवीं मजिल, 227, विनय के शाह मार्ग, नरीमन प्वाइंट,

पोस्ट बैग न 9977, मुम्बई—400021

फोन न 2851280, 2851282, 2851274—78, टेलेक्स न 011—85016,

फैक्स 204448

कलकत्ता

44, शेक्सपीयर सरणी, पाचवीं मजिल, पोस्ट बैग न 16038, कलकत्ता—700017,

टेलि न 2476818—20, टेलेक्स न द्वारा आई डी बी आई 021—2736, 4652,

फैक्स द्वारा आई डी बी आई 473593

गुवाहटी

आई डी बी आई बिल्डिंग, जी एस रोड, सेटीनल के सामने, गुवाहटी—781005,

फोन 62545, टेलेक्स न 0235—2533,

फैक्स द्वारा आई डी बी आई 61853

मद्रास

टेम्पल टावर, पॉचवी मजिल, 476, अन्ना सलाई, नदनम, पोस्ट बैग न 1312,

मद्रास-600035

फोन 450286, टेलेक्स 041-7532,

फैक्स द्वारा आई डी बी आई 454103

नई दिल्ली

वाई एम सी ए कल्चरल सेटर, 1, जयसिंह रोड, पोस्ट बैग न 192, नई

दिल्ली-110001

फोन 344037, 344067, 3747120, 343821, टेलेक्स 031-61513,

फैक्स 344071

2 नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

मुख्य कार्यालय

एन एस आई.सी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020

क्षेत्रीय कार्यालय

- 1 प्रेस्टिज चैम्बर्स, कल्याण स्ट्रीट, मुंबई-400009
- 2 20, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, कलकत्ता-700069
- 3 615, अन्ना सलाई, मद्रास-600006
- 4 अम्बिकागिरि नगर, बेनाझावर रोड, कानपुर-208002

3 राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ

इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आई एफ सी आई)

बैंक ऑफ बडौदा बिल्डिंग, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया,
मेकर चैम्बर्स चार, आठवी मजिल 222, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021

एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड
एक्सप्रेस टावर्स, दसवी मजिल, नरीमन प्वाइंट,
मुम्बई-400021

इंडस्ट्रियल रिकस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
19, नेताजी सुभाष रोड (दूसरी मजिल),
कलकत्ता-700001

इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(आई सी आई सी आई)
163, बैबवे रिक्लेमेशन, मुम्बई-400020

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आई डी बी आई.)
नरीमन भवन 227, वी के शाह मार्ग, बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम,
नरीमन प्वाइंट, पोस्ट बैग न 10020, मुम्बई-400020

4 राज्यों की विकास और वित्तीय सस्थाएँ

आंध्रप्रदेश

आंध्रप्रदेश हैंडिक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैदराबाद ए पी
पीसगाह काम्पलेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500001

आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
10-2-289/21, शांति नगर,
हैदराबाद-500028

आंध्रप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
एग्रो भवन, 10-2-3, ए सी गार्ड्स,
हैदराबाद-500004

आंध्रप्रदेश स्टेट नान-रेजीडेड इन्डियन इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
परिश्रम भवनम, बशीर बाग,
हैदराबाद-500029

आंध्रप्रदेश आई एन डी एल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
परिश्रम भवनम, 5-9-58/बी, बशीर बाग, पोस्ट बैग न 1049
हैदराबाद-500029

आंध्रप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
परिश्रम भवनम, बशीरबाग, हैदराबाद-500029

आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड
5-9-58/बी, परिश्रम भवनम, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद-500029

आंध्रप्रदेश स्माल स्केल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
5-110-174, फतेह मैदान रोड,
हैदराबाद-500004

आध्रप्रदेश स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन

5-9-194, चिराग अली लेन,

हैदराबाद-500001

असम

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेन्ट ऑफ असम, गुवाहाटी, असम

असम फाइनेन्शियल कारपोरेशन

यू टी रोड, गणेशगुडी, ओहारल्ली,

गुवाहाटी-781005

असम स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

बामुनिमैदान, गुवाहाटी-781021

असम एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

उलूबाडी, गुवाहाटी-781007

नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड

मोनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदान, गुवाहाटी-781021

असम इंडस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

जू रोड, गुवाहाटी-781024

बिहार

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेन्ट ऑफ बिहार, पटना, बिहार

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, दूसरी मजिल, पूर्वी गाधी मैदान, पटना-800004

बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन लिमिटेड
फ्रेजर रोड, पटना-800001

बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
पश्चिमी गाधी मैदान, बिस्कोमान बिल्डिंग (एनेक्स-1)
पटना-800004

बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
बिस्कोमान बिल्डिंग, पश्चिमी गाधी मैदान, पटना-800004

बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
बिस्कोमान बिल्डिंग, पश्चिमी गाधी मैदान, पटना-800004

बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
बदर बगीचा, पटना-800001

चडीगढ
चडीगढ स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
9-ए, मध्य मार्ग, सेक्टर 7-सी, चडीगढ-160017

दिल्ली
दिल्ली फाइनेन्शियल कारपोरेशन
सरस्वती भवन, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
एन ब्लॉक, बाम्बे लाइफ बिल्डिंग, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001

गुजरात
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात,
अहमदाबाद, गुजरात

गुजरात इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
चुन्नीबाई चैम्बर्स, दीपाली सिनेमा के पीछे, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380009

गुजरात इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन
भवानी चैम्बर्स, तीसरी मजिल, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380009

गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
गुजरात चैम्बर्स बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

गुजरात स्टेट हैडीक्राफ्ट एंड मॅडलूम डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
सन्यास आश्रम के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

गुजरात स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
भगवती चैम्बर्स, गुजरात विद्यापीठ के सामने, आश्रम रोड,

गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
जलदर्शन बिल्डिंग, आर सी मार्ग, अहमदाबाद-380009

हरियाणा

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेन्ट ऑफ हरियाणा, 30, बेज बिल्डिंग, सेक्टर 17, चण्डीगढ़-160017

हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन

एस सी ओ 40-41, सेक्टर 17 ए, पी बी न 22, चण्डीगढ़-160017

हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

सिबल बिल्डिंग, सेक्टर 17 डी, चण्डीगढ़-160017

हरियाणा फाइनेन्शियल कारपोरेशन

बेज न 17, 18, 19, सेक्टर 17 ए, चण्डीगढ़-160017

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, हरियाणा

30, बेज बिल्डिंग, सेक्टर-17, चण्डीगढ़-160017

हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

15556, सेक्टर 18-डी चण्डीगढ़-160018

हिमाचल प्रदेश

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेन्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, निगम बिहार, शिमला-171002

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन

शालीग्राम भवन, खालिनी, शिमला-171004

हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन
किशोर भवन, सर्कुलर रोड, हिमरस, शिमला-171004

हिमाचल प्रदेश मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन
शिमला (एच पी)-171004

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन
सर्कुलर रोड, हिमरस, शिमला

हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
किशोर भवन, द माल, शिमला (एच पी)

जम्मू और कश्मीर
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर (जे एड के)

जे एड के स्टेट इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन
ड्राबु हाउस, रामबाग, श्रीनगर-190001

जे एड के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन,
करन नगर, श्रीनगर

कर्नाटक
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, बंगलूर, कर्नाटक

कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवेलपमेंट बोर्ड
राष्ट्रोत्थानपरिषद् बिल्डिंग, न 14/3, नरूपथुगा रोड, बगलूर-560002

कर्नाटक लेदर इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
चौथी मजिल, पी यू बिल्डिंग, एमजी रोड, बगलूर-560001

कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
एमलिन हेवन, 30, रेसकोर्स रोड, बगलूर-560001

कर्नाटक स्टेट हैडीक्राफ्ट डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
वेब्स कॉम्पलेक्स, 26, महात्मा गांधी रोड, बगलूर-560001

कर्नाटक स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
एममिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजाजी नगर,
बगलूर-560044

कर्नाटक लेदर इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
14, लक्ष्मी बिल्डिंग, जे सी रोड, बगलूर-560002

कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट एंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
एम एस आई एल हाउस, 36, कनिघम रोड, बगलूर-560052

केरल

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ केरल, तीसरी मजिल, विकास भवन, त्रिवेंद्रम-695033

केरल फाइनेन्शियल कारपोरेशन
के एफ सी बिल्डिंग, बेल्लयाम्बालम, त्रिवेन्द्रम-695002

केरल इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
शीमा बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, पी बी 0 न 1820, कोचीन-682016

केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
केस्टन रोड, कावदियार, त्रिवेन्द्रम-695001

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स
तीसरी मजिल, विकास भवन, त्रिवेन्द्रम-695033

केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
केल्ट्रन हाउस, वेल्लयाम्बालम, त्रिवेन्द्रम-695001

केरल स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड एम्पलॉयमेंट कारपोरेशन
लिमिटेड
हाउसिंह बोर्ड बिल्डिंग, शातिनगर, त्रिवेन्द्रम-695001

मध्यप्रदेश
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ मध्यप्रदेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
पचानन, मालवीय नगर, भोपाल-462001

मध्यप्रदेश स्टेट एग्री-इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
न्यू मार्किट, तात्या टोपे नगर, भोपाल-462001

मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
पचानन, मालवीय नगर, भोपाल-462003

मध्यप्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन
फाइनेन्स हाउस, बाम्बे-आगरा रोड, इंदौर-452001

महाराष्ट्र
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
न्यू एक्सेलसियर बिल्डिंग, पाचवाँ और नौवाँ तल,
ए के नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन
मारोल इंडस्ट्रियल एरिया, महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400094

स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड
पहली मजिल, निर्मल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021

महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड
प्लॉट न 214, बैकबे रिकलेमेशन, रहेजा सेन्टर, तेरहवी मजिल,
नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400001

महाराष्ट्र स्माल स्केल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
कृपानिधि, 9 डब्लू हीराचद मार्ग, बैलार्ड इस्टेट, मुंबई-400038

ओडिसा

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर, ओडिसा

ओडिसा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कारपोरेशन
आई डी सी ओ टावर्स, जनपथ, भुवनेश्वर-751007

ओडिसा स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन

ओ एम पी स्क्वायर, कटक-753003

इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिसा लिमिटेड
पी बी न 78, भुवनेश्वर-753005

ओडिसा स्माल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

बाराबती स्टेडियम, कटक-753005

पाडिचेरी

पाडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रोमोशन डेवेलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन
लिमिटेड

38 रोम्यॉ रोलॉ स्ट्रीट, पाडिचेरी-605001

पंजाब

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब

पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

सेक्टर 17-बी, 95-98 बैंब स्क्वायर, चडीगढ-160017

पंजाब स्टेट इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

बत्रा बिल्डिंग, सेक्टर 17, पोस्ट बैग न 11, चडीगढ-160017

पंजाब एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

कोठी न 117, सेक्टर 18-ए, पी बी न 20, चडीगढ-160017

उद्योग सहायक

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, 17 बेज बिल्डिंग, सेक्टर-17,

चडीगढ

पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

एस सी ओ 54, 55 और 56, सेक्टर 17-ए, चडीगढ-160017

राजस्थान

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर, राजस्थान

राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर-302005

राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर-302005

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट एंड मिनरल डेवेलपमेंट
कारपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

तमिलनाडु
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, मद्रास, तमिलनाडु

स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड
51 / 52 ग्रीम्स रोड, मद्रास-600006

तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
अरुल मनानी, 27 हवाईट्स रोड, मद्रास-600004

तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
735, अन्ना सलाई, मद्रास-600002

तमिलनाडु स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
4, हवाईट्स रोड, मद्रास-600014

त्रिपुरा
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा

त्रिपुरा स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
अगरतला-799001

त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
अगरतला-790001

उत्तरप्रदेश
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ उत्तरप्रदेश, उद्योग भवन, जी टी रोड,
कानपुर-208002

- 5 प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू पी लिमिटेड,
जावर भवन एनेक्सी, दूसरी मजिल, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
- 6 यू.पी. इंडस्ट्रियल लिमिटेड
पाचवी मजिल, हैडलूम भवन, जी टी रोड, कानपुर,
- 7 यू पी एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
बी-27, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
8. यू पी. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
117 / 130, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
- 9 उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड
नवचेतन केन्द्र पहला तल, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
- 10 यू पी फाइनेन्शियल कारपोरेशन
14 / 88, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001

- 11 यू पी. स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
बी-15, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005

पश्चिम बंगाल

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज

गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता

वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कारपोरेशन

12-ए, नेताजी सुभाष रोड, तीसरा-चौथा तल, कलकत्ता-700001

वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
224, ई, आचार्य जगदीशचन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-700001

वेस्ट बंगाल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

6 ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वायर, तीसरी मजिल, कलकत्ता-700012

वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

23 ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001

नया सचिवालय भवन (नौवी मजिल) 1, किरण शंकर राय रोड, कलकत्ता-700001

परिशिष्ट-2

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) से जुड़े विकास एवं टेक्नोलॉजी
संस्थानों की सूची

मुख्य कार्य

लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता, सहायता सेवाएँ, सूचना सेवाएँ
परामर्श, कार्यशाला सुविधाएँ, प्रशिक्षण आदि प्रदान करना

- 1 अडमान और निकोबार द्वीपसमूह
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्रांच),
पोर्ट ब्लेयर
- 2 असम
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट,
इंडस्ट्रियल इस्टेट बामूनीमैदान, गुवाहाटी-781021
एस टी डी-031-31152, टेलेक्स-235-2379
- 3 आंध्र प्रदेश
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट,
नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद-560037
एस टी डी 0842-278131, टेलेक्स 425-6628
ए पी एस एक्स,
- 4 अरुणाचल प्रदेश
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्रांच)
आर के मिशन हॉस्पिटल, इटानगर-791113
- 5 बिहार
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, इंडस्ट्रियल इस्टेट,
पटना-800013, एस टी डी-0612-62208

बिहार (मुजफ्फरपुर)

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, बेला इन्डस्ट्रियल इस्टेट,
पीओ आर के आश्रम,

मुजफ्फरपुर, एस टी डी -0621-242486

बिहार (राँची)

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, इंडस्ट्रियल इस्टेट,
कोकर, राँची

8 दिल्ली

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ऑपोजिट ओखला
इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, एस टी डी -011-6847223
टेलेक्स-3175424 एसआईएसआईआईएन

9 दादर और नागर हवेली

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच)
मसूत, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिलवसा-396230

10 गोवा

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, औधी मापरी बिल्डिंग,
पीओ बॉक्स न-334, मारगाओ, पणजी-403601,
एस टी डी -0832-22438

11 गुजरात

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, हर्षिद्ध चैम्बर्स,
चौथी मजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014
एस टी डी -0272-447147, टेलेक्स-0121-6314
जी यू ई एक्स आई एन

12. हिमाचलप्रदेश

स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, जनक कुटी,
चबाघाट, सोलन-178218, एस टी डी -01792-2265

- 3 हरियाणा
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट,
एस सी एफ 137-138
अर्बन इस्टेट, सेक्टर-13 करनाल-132001
एस टी डी -0814-23665
- 14 जम्मू और कश्मीर
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 181, करन नगर
श्रीनगर-190010, एस टी डी -0194-31077
- 15 कर्नाटक
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, राजाजी नगर,
बगलूर-560044, एस टी डी -0812-351581,
टेलेक्स-845-2328
- 16 केरल
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, कजनी रोड,
कृष्ण विहार, पी ओ अयानतोले, त्रिचूर-680003,
एस टी डी -0431-20638, टेलेक्स-0887-214
एस आई ए डी आई एन
- 17 मध्य प्रदेश
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 10, इंडस्ट्रियल इस्टेट,
पोलोग्राउड, इंदौर-452003, एस टी डी -0731-33303
टेलेक्स-0735-209-एस आई एम पी आई एन
- 18 महाराष्ट्र
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, कुर्ला अंधेरी रोड,
साकी नाका, मुम्बई-400072, एस टी.डी -022-6367090,
टेलेक्स-011-79006-एम एस सी एक्स

- 19 महाराष्ट्र (नागपुर)
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, सदर,
नागपुर-435007, एस टी डी -0712-533352
- 20 मिजोरम
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, केलिश हाउस
रिपब्लिक वेग, आइजोल-1 एस टी डी -0364
- 21 मणिपुर
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, शेड न सी-17 और 18,
बिट न 23, इंडस्ट्रियल इस्टेट, टेकयेलपट, इम्फाल-795001,
एस टी डी -03852-220584
- 22 मेघालय
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्रांच) मेफेर फैक्टरी के पास,
शॉर्ट राउंड रोड, शिलांग-793001, एस टी डी -0364
- 23 नगालैंड
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्रांच), इंडस्ट्रियल इस्टेट,
डीमापुर-797112, एस टी डी -03862
- 24 ओडिसा
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, कणिका रोड, तुलसीपुर,
कटक-753008, एस टी डी -0671-23219, टेलेक्स-676-229
- 25 पंजाब
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, इंडस्ट्रियल एरिया 'बी',
लुधियाना-141003, एस टी डी -0161-403225
- 26 पांडिचेरी
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, (एक्सटेंशन सेक्टर)
तट्टनचावडी, पांडिचेरी-605009
- 27 राजस्थान
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 22, गोडाउन,

- इंडस्ट्रियल इस्टेट, जयपुर-302001, एस टी डी -0141-375653,
टेलेक्स-0365-2654, एसआईएसआई आई एन
- 28 सिक्किम
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, टाडोग हाउसिंग कालोनी,
पीओ टाडोग, गगतोक, सिक्किम-737102
- 29 तमिलनाडु
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 65/1, जी एस टी रोड,
गुड्डुडी, मद्रास-600032, एस टी डी -044-2341785,
टेलेक्स-041-26075
- 30 त्रिपुरा
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच), 21, हरीश ठाकुर रोड,
अगरतला-799001, एस टी डी -0381-6570
- 31 उत्तरप्रदेश
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ए-107, इंडस्ट्रियल इस्टेट,
कालपी रोड, कानपुर-282004, एस टी डी -0381-6570,
टेलेक्स-0325-284-एसआईएसआई के पी
- 32 उत्तरप्रदेश (आगरा)
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ए-208, कमला नगर, आगरा-282005,
एस टी डी -0562-72188
- 33 इलाहाबाद
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ई-17/18, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नैनी,
इलाहाबाद, (यू पी)
- 34 पश्चिम बंगाल
स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 111 और 112, बी टी रोड,
कलकत्ता-700035, एस टी डी -033-527594
टेलेक्स-21-29550 एस.आई.एसआई एनआई

टूलरूम कार्य

उद्योगों के लिए टूल डाई, जिग्स तथा फिक्सचर्स का डिजाइन एवं उत्पादन करना, उपकरणों के उत्पादन में परामर्श एवं परीक्षण सेवाएँ देना, कामगारों को प्रशिक्षित करना।

- 1 सेट्रल इस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, बालगीर,
हैदराबाद-500037
- 2 सेट्रल टूलरूम, ए-5, फोकल पाइंट,
लुधियाना-141-10
- 3 सेट्रल इस्टिट्यूट ऑफ हैड टूल्स, जी टी रोड, बाइपास,
जालंधर-144006
- 4 सेट्रल टूलरूम एण्ड ट्रेनिंग सेटर, बन हुगली इंडस्ट्रियल एरिया,
कलकत्ता-700035
- 5 टूलरूम एंड ट्रेनिंग सेटर, वजीरपुर,
दिल्ली-110057
- 6 इण्डो-जर्मन टूलरूम, हर्षिद्व चैम्बर्स, चौथी मजिल, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380014
- 7 गवर्नमेंट टूलरूम एंड ट्रेनिंग सेटर, राजाजी नगर, इंडस्ट्रियल एरिया,
बगलूर-560044
- 8 इण्डो-जर्मन टूलरूम (औरंगाबाद),
कुर्ला अंधेरी रोड, साका नाका,
बम्बई-400072
- 9 सेट्रल टूलरूम एंड ट्रेनिंग सेटर, इनर सर्किल रोड न 3,
काट्रेक्टर्स एरिया, हिसतपुर,
जमशेदपुर-83100

- 10 सेंट्रल टूलरूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भवुनेश्वर, विकास सदन,
कालेज स्क्वायर, सी टी सी-3,
कटक-753003

प्रोडक्ट एण्ड प्रोसेस डेवेलपमेंट सेंटर

एक विशेष उत्पाद समूह में तकनीकी खाई को भरने के लिए और आर एंड डी (शोध एवं विकास) की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु पीपीडीसी की स्थापना की गई थी।

मुख्य कार्य

उत्पाद और प्रक्रिया में सुधार, नए और प्रवर्तित उत्पाद की रूपरेखा, बेहतर पैकेजिंग तकनीक का विकास, मानवशक्ति विकास और प्रशिक्षण केन्द्र

- 1 प्रोडक्ट-कम प्रोसेस डेवेलपमेंट सेंटर
फॉर सेरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्रीज, कूनहरटोली, दूसरी लेन, पुरुलिया रोड,
राँची-834010 (बिहार)
- 2 प्रोडक्ट-कम-प्रोसेस डेवेलपमेंट सेंटर,
स्पोर्ट्स गुड्स एंड लीजर टाइप इक्विपमेंट, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी-250002
- 3 प्रोडक्ट-कम प्रोसेस डेवेलपमेंट सेंटर, (फाउडरी एंड फॉरजिंग)
एफ-166, कमला नगर, आगरा (यूपी)-282006
- 4 इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर,
ग्राम रामनगर, कानीवा, जिला नैनीताल (यूपी)
- 5 प्रोडक्ट-कम प्रोसेस डेवेलपमेंट सेंटर
फार एसेशियल ऑइल्स एण्ड परफ्यूम इंडस्ट्रीज, कन्नय,

- 6 सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लास इंडस्ट्रीज,
फिरोजाबाद (उत्तरप्रदेश)
- 7 इन्स्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ टेक्निकल मेजरिंग इस्ट्रूमेन्ट्स (आईडी ई एम आई)
स्वातंत्र्यवीर तात्या टोपे मार्ग, चूना भट्टी, सायन पी ओ, मुम्बई-400022

सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर

मुख्य कार्य

फुटवियर इंडस्ट्रीज के लिए मानवशक्ति प्रशिक्षण, फुटवियर में डिजाइन का विकास

- 1 सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, 428, कोशलपुर एग्री बाइपास रोड,
आगरा-282005
- 2 सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, 65/1, जी एस टी रोड, गुडडी,
मद्रास-600032

मुख्य कार्य

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु उद्योगों में प्रलेखों और सूचनाओं का प्रसार, विकास अधिकारियों और औद्योगिक विस्तारण स्टाफ को प्रशिक्षण

- 1 नेशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग
(एनआईएसआईटी), यूसुफगदा, हैदराबाद-500045
- 2 इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर,
नीलोखेरी (हरियाणा)-132117
- 3 नेशनल इन्स्टिट्यूट फॉर आन्ट्रेप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट
(एनआईईएसबीयूडी), एनएसआईसी कैम्पस,
ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, ओखला, नई दिल्ली-110020

प्रशिक्षण कार्यो को संयोजन, प्रशिक्षण मे सहायक सामग्री का विकास
और प्रशिक्षण सकाय मे कुशलता का विकास

परिशिष्ट – 3

तकनीकी परामर्श देनेवाली सस्थाओ की सूची

- 1 आध्रप्रदेश
आध्रप्रदेश इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
परिश्रम भवनम, आठवी मजिल, ईस्टर्न विग, 5-958/बी, बशीर बाग,
हैदराबाद-500029
फोन 33058, 33616, तार एपीआईटीसीओ
- 2 असम
नार्थ ईस्टर्न इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
मोनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदान, गुवाहाटी-781021
फोन 31141, 31142, 31143, 25462, 27422, टेलेक्स 0235-330
तार एनईआईटीसीओएल
- 3 बिहार
बिहार इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
उद्योग विकास भवन, छठी मजिल, रामचरित्र सिंह पथ, बेली रोड-पटना-800001
फोन 53065, 53976, तार बीआईटीसीओ
- 4 गुजरात
गुजरात इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
नेप्चून टावर, आश्रम रोड, पो बी न 209, अहमदाबाद-380009
फोन 407617-18, 407658, तार उद्योगसलाह
- 5 हरियाणा
हरियाणा इडस्ट्रियल कन्सल्टेंट्स लिमिटेड,
459, सेक्टर-14, सोनीपत-131001, फोन . 3707, तार हरिकोन

- 6 हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
न्यू ब्रिज वियू इस्टेट, द माल शिमला-171001,
फोन 2488, 4537, तार कंसल्टेन्ट्स
- 7 जम्मू-कश्मीर
जे एड के इंडस्ट्रियल एड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
नसीब भवन, पुरानी मडी, पीबी न 84, जम्मू-180001, फोन 47565
तार जेकेइटको
- 8 कर्नाटक
टेक्निकल कंसल्टेसी सर्विस आर्गनाइजेशन ऑफ कर्नाटक,
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एड कामर्स, राष्ट्रोत्थान परिषद भवन, छठी मजिल,
नरुपातुगा रोड, बगलूर-560002
फोन 258516, 285590, 771150, तार आरईसीएसओके
- 9 केरल
केरल इंडस्ट्रियल एड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
शीमा बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, कोचीन-682016
फोन 354180, 360408, तार कंसल्टेन्ट्स
- 10 मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
पी बी न 339, गगोत्री, टीटी नगर, भोपाल-462003
फोन 64616, 66313, 66768, टेलेक्स 705-249, तार एमपीसीओएन
- 11 महाराष्ट्र
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एड आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
कुबेर चैम्बर्स, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411007
फोन 52122, तार एमआईटीओओएन

- 12 मणिपुर
नार्थ-ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कंसल्टेड्स लिमिटेड,
इम्फाल अर्बन को.आ बैंक बिल्डिंग, एम जी एवेन्यू, इम्फाल-795001,
तार एनईसीओएन
- 13 पंजाब
नार्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
एस सी ओ न 131-132 पहली मजिल, सेक्टर 17-सी,
चडीगढ़-160017, फोन 31993, तार एनआईटीसीओएन
- 14 ओडिसा
ओडिसा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
प्लॉट न 4, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751007
फोन 53684, टेलेक्स 0675-292, तार ओआरआईटीसीओ
- 15 राजस्थान
राजस्थान कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
देवी निकेतन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
फोन 79207, तार कंसल्टेट
- 16 तमिलनाडु
इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन आफ तमिलनाडु
लिमिटेड,
50-ए, ग्रीम्स रोड, मद्रास-600006
फोन 470324, टेलेक्स 041-7736, तार टीएएन कंसल्ट
- 17 उत्तरप्रदेश
यू पी. इंडस्ट्रियल कंसल्टेड्स लिमिटेड,
पॉचवी मजिल, हैण्डलूम भवन, जी टी रोड, कानपुर-208002